

आय-कर के प्रारम्भिक सिद्धान्त (ELEMENTS OF INCOME-TAX)

[भारतीय विश्वविद्यालयों के बी० कॉम० के विद्यार्थियों के लिये]

लेखक

रूपराम गुप्त, एम० ए०, ए० सी० ए०

चारटर्ड एकाउन्टेन्ट

[रिटायर्ड प्रिंसिपल तथा प्रोफेसर ऑफ अकाउन्टेन्सी,
सेठ जी० बी० पोद्दार कॉलेज, नवलगढ़ (राजस्थान)]

एव

विष्णूसरन गुप्त, एम० कॉम०, एल-एल० बी०, एफ० सी० ए०

चारटर्ड एकाउन्टेन्ट

वैस्टर्न कचहरी रोड,

पंचम सशोधित एव पारवर्द्धित संस्करण

आगरा बुक स्टोर

प्रकाशक, विक्रेता एकाग्र

आगरा

अजमेर

इलाहाबाद

कानपुर

दिल्ली

जागपुर

पटना

मेरठ

लखनऊ

वाराणसी

१९५६]

[मूल्य ५.०० रुपये]

प्रकाशक :
आगरा बुक स्टोर
रावतपाड़ा, आगरा ।

प्रथम	हिन्दी	संस्करण	१९५४
द्वितीय	संशोधित	„	१९५५
तृतीय	„ :	„	१९५७
चतुर्थ	„	„	१९५८
पंचम	„	„	१९५९

मूल्य पाँच रुपये

Printed on paper of
The Titaghur Paper Mills Co Ltd , Calcutta ,
Supplied by
Mr Gopinath Bhargava, Branch Manager, Delhi

मुद्रक :
गुलाबचन्द अग्रवाल, बी० कॉम०
अग्रवाल प्रेस, आगरा ।

विषय-सूची

अध्याय		पृष्ठ
✓ १—विषय प्रवेश ✓	..	१ X
✓ २—कर-दायित्व ✓	.	११ X
✓ ३—पूँजी और ऋगम ✓	..	१६ X
✓ ४—कर-मुक्त आय ✓	..	२४ X
✓ ५—कर-योग्य आय की गणना (१) .	..	३० X
✓ ६—कर-योग्य आय की गणना (२) ✓	अ. १	५० X
✓ ७—ह्रास M		७८ X
८—कुल आय और कुल विश्व आय M		८४
९—उद्गम स्थान पर कर-कटौती		१०८
१०—कर-निर्धारण की कार्य-विधि M	११३
११—कर-दातागण (१) M		१३२
१२—कर-दातागण (२) M		१५१
१३—कर की गणना M	.	१६६
✓ १४—दोहराने के प्रश्नोत्तर	...	२१३

पंचम संस्करण की भूमिका

लेखको के लिए यह बड़े प्रोत्साहन की बात है कि इस पुस्तक का पिछला संस्करण इतनी शीघ्रता से बिक गया है ।

इस संस्करण के तैयार करने में, सम्पूर्ण पुस्तक को १९५६ के फाइनल एक्ट द्वारा आय-कर सन्निधिम में किये गये सशोधनों के प्रकाश में, बड़ी सावधानी से सशोधित किया गया है ।

एक नया अध्याय जिसमें दोहराने के उत्तर सहित ३१ प्रश्न दिये गये हैं तथा एक अध्याय उद्गम स्थान पर कर-कटौती का जोड़ दिया गया है ।

पूर्ण विश्वास है कि प्रारम्भिक विद्यार्थी इस पुस्तक को रोचक और उपयोगी पायेंगे ।

वैस्टर्न कचहरी रोड,
मेरठ
१ अगस्त १९५६

रूपराम गुप्त
विश्वसूचन गुप्त

प्रथम संस्करण की भूमिका

यह पुस्तक आय-कर सन्निधिम का परिचय मात्र है और मुख्यतः उन विद्यार्थियों के लिए है जो इस विषय का अध्ययन प्रारम्भ करते हैं, विशेषतः उनके लिए जो विभिन्न विश्वविद्यालयों की बी० कॉम० परीक्षा के लिये तैयारी कर रहे हैं ।

भारतीय आय-कर अधिनियम बड़ा जटिल विषय है किन्तु फिर भी उसे एक विश्लेषित रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है । प्रत्येक आवश्यक स्थान पर उपयुक्त उदाहरण भी दिये हैं ताकि विद्यार्थी उसे सरलता से समझ लें ।

यह आशा की जाती है कि प्रस्तुत पुस्तक आय कर सन्निधिम के विषय का अध्ययन प्रारम्भ करने वालों के लिए सचमुच में उपयोगी प्रमाणित होगी ।

नवम्बर १९५६ }
१-१-५४ }

रूपराम गुप्त

भारतवर्ष में आय-कर (Income Tax) सन्निधिम सन् १९२२ के आय-कर अधिनियम (Income Tax Act of 1922) में मिलता है। सन् १९२२ में इस अधिनियम के पास होने के समय से लेकर अब तक, समय-समय पर और विशेष रूप से सन् १९३९ में, इसके अन्दर बहुत से संशोधन और परिवर्तन किये जाते रहे हैं।- आय-कर से सम्बन्धित जिन धाराओं का इस पुस्तक में हवाला दिया गया है, वे सब इसी अधिनियम की धाराएँ हैं।

सन् १९२२ का आय कर अधिनियम सम्पूर्ण भारतवर्ष पर लागू होता है। आय-कर व्यक्ति की आय पर लगाया हुआ कर है। आयकर अधिनियम की धाराएँ ३ और ४ कर-निर्धारण सम्बन्धी धाराएँ हैं। यह कर पहली अप्रैल से आरम्भ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष (Financial Year) के लिये गत वर्ष की आय पर लगाया जाता है। वित्तीय वर्ष (१ अप्रैल से अगली ३१ मार्च तक) को ही कर-निर्धारण-वर्ष (Assessment Year) अथवा कर-वर्ष (Tax Year) कहा जाता है।

प्रत्येक कर-निर्धारण-वर्ष में, १ अप्रैल से पहले संसद (Parliament) द्वारा पास किये हुये वार्षिक वित्त-अधिनियम (Annual Finance Act) के अनुसार वर्ष के लिए निश्चित की गई दरों के हिसाब से ही आय-कर लगाया जाता है। यह कर निम्न पर लगाया जाता है —

- (क) व्यक्ति विशेष,
- (ख) संयुक्त हिन्दू परिवार,
- (ग) कम्पनी,
- (घ) स्थानीय सत्ता (Local authority),
- (ङ) स्वयं फर्म पर अथवा फर्म के हिस्सेदारों पर अलग-अलग रूप से, और
- (च) दूसरे किसी जन-मण्डल (Other association of persons) पर,

अथवा मण्डल के सदस्यों पर पृथक-पृथक।

जिस आय पर कर लगाया जाता है, वह आय गत वर्ष (Previous Year) की होती है न कि कर-निर्धारण वर्ष (Assessment Year) की, और इसकी गणना अधिनियम के आदेशों के अनुसार की जाती है।

आय-कर अधिनियम कर-निर्धारण की प्रणाली और दायित्व स्थापित करता है, किन्तु वार्षिक वित्त अधिनियम (Annual Finance Act) के पास हुए बिना कर-दायित्व स्थिर नहीं हो सकता। आय-कर गत वर्ष (Previous Year) की आय पर लगाया जाता है, किन्तु उस पर कर-निर्धारण वर्ष (Assessment Year) के कानून के अनुसार विचार किया जाता है न कि उस कानून के हिसाब से जो कि उस वर्ष प्रचलित था जिसकी आय पर कि कर लगाया जा रहा है।

परिभाषाएँ (Definitions)

धारा २ के अन्तर्गत आय-कर अधिनियम में व्यवहृत कतिपय महत्व को परिभाषाएँ दी गई हैं, जिनमें से मुख्य परिभाषाएँ निम्न प्रकार हैं—

कृषि आय (Agricultural Income)

धारा २(१)

आय-कर अधिनियम के अनुसार 'कृषि-आय' उस जमीन की आय मानी जाती है जो कृषि के काम में लाई जाती हो तथा जिस पर सरकार को लगान और स्थानीय सत्ता को कर दिया जाता हो। जब तक उपयुक्त दोनों शर्तें लागू न हो, जमीन की किसी आय को कृषि आय नहीं कहा जा सकता। कृषि शब्द में बनारोपण (Forestry) का भी बोध होता है। यदि कोई जमींदार अपनी जमीन पर पेड़ लगाता है और उनसे उसे आय होती है, तो यह आय कृषि आय मानी जायगी, बशर्ते कि उस जमीन से लगान वसूल किया जाता हो। किन्तु जो जंगली पेड़ अपने आप उग गये हों, उनकी लकड़ी, छाल, फूल-पत्तियों आदि की आय कृषि-आय में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि जब तक जमीन पर किसी प्रकार की खेती-काश्त नहीं की जाती तब तक उस जमीन को कृषि कार्य के हेतु काम में लाया नहीं कहा जा सकता। निम्न प्रकार की आय भी कृषि-आय के क्षेत्र में नहीं आती —

- (1) हाट बाजारों, घाट अथवा मछली क्षेत्रों से होने वाली आय।
- (II) सिंचाई के लिए पानी मुहैया (Supply) करने से आय।
- (III) पत्थरों की खानों से होने वाली आय
- (IV) खानों से प्राप्त होने वाली 'रायल्टी' से आय।
- (V) ईंट बनाने के लिए जमीन बेचने से होने वाली आय।
- (VI) किसी कृषि फार्म के मैनैजर के रूप में मिलने वाला पारिश्रमिक।

निम्न मदों से होने वाली आय कुछ अंशों में कृषि आय है और कुछ अंशों में कृषि आय नहीं—

(अ) भारत में विक्रेता द्वारा पैदा और निर्मित की गई चाय को बेचने से हुई आय ।

(ब) किसी चीनी कारखाना कम्पनी की आय, जिसके अपने निजी कृषि फार्म हैं तथा जो कारखाने के लिए अपनी ही ईख पैदा करती है ।

उस प्रत्येक व्यक्ति को हुई आय कृषि आय नहीं कही जा सकती कि जिसके हाथों जमीन की पैदावार पहुँचती है । केवल जमीन के मालिक, आसामी अथवा भूमि बन्धक रखने वालों का ही भूमि में हित रहता है और उन्हीं को जमीन पर कृषि कार्य द्वारा जमीन से आय प्राप्त हुई कही जा सकती है । यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से, जिसने जमीन पर जोत-बोकर पैदावार की है, खड़ी फसल खरीद लेता है और उसे काट कर फायदे से बेचता है, तो इस प्रकार प्राप्त हुआ लाभ कृषि आय नहीं माना जाता ।

आय-कर-दाता (Assessee)

आय-कर दाता वह व्यक्ति है, जिसे कर अदा करना होता है । मृत व्यक्ति की आय पर आय कर निर्धारण के लिए, उसके कानूनी रूप से जायज उत्तराधिकारी को भी आय-कर-दाता (Assessee) माना जाता है । यदि कोई व्यक्ति जिसे किसी दूसरे व्यक्ति की आय में से कर काटना चाहिए, कर नहीं काटे अथवा काट लेने के उपरान्त उसे सरकार को अदा नहीं करे तो उस व्यक्ति को भी आय-कर-दाता माना जायेगा

व्यक्ति (Person) २६

आय-कर के मतलब के लिए, करदाताओं को उनकी स्थिति के अनुसार निम्न प्रकार वर्गित किया जाता है — व्यक्ति विशेष (Individual), हिन्दू अविभाजित परिवार, फर्म, कम्पनी, स्थानीय अधिकारी और अन्य जन-मण्डल ।

‘व्यक्ति’ शब्द में एक अविभाजित हिन्दू परिवार, स्थानीय सत्ता, कम्पनी और एक जन-मण्डल (Association of persons) शामिल है । स्थानीय सत्ता के अन्तर्गत म्युनिस्पल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पोर्ट ट्रस्ट आदि सस्थाएँ आती हैं । व्यक्ति शब्द में एक नाबालिग अथवा पागल व्यक्ति भी शामिल होता है ।

गत वर्ष (Previous year)

व्यक्ति कर-दाता को अपनी गत वर्ष की आय पर ही कर अदा करना होता है, इसलिए गत वर्ष की परिभाषा बड़ी महत्वपूर्ण है । गत वर्ष से आशय उन बारह महीनों से है, जो आय-कर-निर्धारण वर्ष (Assessment Year) के पहले ३१ मार्च को समाप्त होते हैं । किन्तु यदि किसी आय-कर-दाता का हिसाबी वर्ष (Accounting year) पूर्ण के वित्तीय वर्ष के दौरान में किसी अन्य तिथि पर समाप्त होता है, तो यही हिसाबी वर्ष उसका गत-वर्ष माना जायेगा । उदाहरण के लिये, वह अपना गत वर्ष सवत

साल, दिवाली साल, दशहरा साल अथवा कलेंडर वर्ष के अनुसार रख सकता है। गत वर्ष की समाप्ति पूर्व वित्तीय वर्ष (Preceding financial year) के अन्दर ही अथवा उसके साथ ही अवश्य हो जानी चाहिए।

आय के भिन्न-भिन्न साधनों के लिए कर-दाता द्वारा अपनी आय के प्रत्येक साधन के सम्बन्ध में वास्तव में माने गये हिसाबी वर्ष के आधार पर, पृथक्-पृथक् गत वर्ष रखे जा सकते हैं। लेकिन इस नियम की दो मर्यादाये हैं —

(१) एक बार अपना गत वर्ष निश्चय कर लेने के पश्चात् उसे अगले वर्षों के लिए बदला नहीं जा सकता, जब तक कि ऐसा करने के लिए इनकम टैक्स ऑफीसर को मजबूरी न मिल जावे। इस प्रतिबन्ध का उद्देश्य टैक्स की चोरी पर अकुश रखना है और दूसरी ओर इस बात की सावधानी भी रखना है कि कहीं दुहरा आयकर-निर्धारण (Double assessment) न हो जाय,

(२) यदि आय की कोई मद विशेष किसी सामेदारी के लाभ में प्राप्त हुए भाग के रूप में है तो उस मद के लिये गत वर्ष वही माना जायगा, जो फर्म ने रखा है। यह बन्धन उस दशा में लागू होता है जबकि फर्म पर इकाई के रूप में कर लगाया गया हो।

नये व्यवसायों के लिये गत-वर्ष, व्यापार आरम्भ करने की तिथि से आने वाले ३१ मार्च तक (अथवा, यदि आय-कर दाता चाहे तो, उसके हिसाबी साल के अन्त तक) माना जाता है। यदि किसी व्यापार की हिसाबी तिथि (Accounting date) आने वाली ३१ मार्च के बाद पड़ती है, तो ऐसी दशा में यह समझा जायेगा कि उस व्यापारी का कोई गत वर्ष नहीं है। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यवसायी अपना व्यवसाय १ जून १९५७ को आरम्भ करता है और प्रथम वर्ष का हिसाब-किताब ३१ मई १९५८ तक के लिये बनाता है, तो वह ३१ मई तक समाप्त होने वाले वर्ष को मान सकता है। ऐसी दशा में १९५८-५९ के आय-कर-निर्धारण वर्ष के लिए कोई गत वर्ष नहीं होगा, क्योंकि ३१ मई १९५८ तक समाप्त होने वाले प्रथम हिसाबी वर्ष के लाभ पर १९५९-६० के आय-कर-निर्धारण वर्ष में कर लगाया जायगा।

आय कर लगने वाले क्षेत्र (Taxable Territories)

आय-कर लगने वाले क्षेत्र से आशय सम्पूर्ण भारतवर्ष का है।

आय (Income)

आय-कर अधिनियम का उद्देश्य आय पर कर लगाना है, किन्तु 'आय' शब्द की परिभाषा वह नहीं करता। हाँ, वह इस शब्द से दैनिक व्यवहार में समझे जाने वाले अर्थ को इस प्रकार विस्तृत करता है कि उसमें कुछ ऐसी प्राप्तियाँ भी आ जाती हैं, जिन्हें आम तौर पर आय नहीं कहा जा सकता। ऐसी प्राप्तिओं की चर्चा आगामी अध्याय में यथा-
आय की जायगी।

निश्चित साधनो द्वारा नियमित रूप से जो सामयिक द्राव्यिक (Monetary) आय होती है उसे आय मानते हैं। आय का साधन गेसा होना जरूरी नहीं है कि वह निरन्तर उत्पादक बना रहे, बल्कि वह ऐसा होना चाहिये कि जिसका उद्देश्य निश्चित फल प्रदान करना हो और जिससे 'आँधी के आम' सदृश आय की गणना नहीं हो। आय के इन साधनो को अधिनियम में नौकरी, विनियोग, मकान-जायदाद, व्यवसाय वाणिज्य, अन्य साधन तथा पूँजी लाभ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आय की तुलना किसी पेड़ के फलो अथवा किसी जमीन से मिलने वाली फसल से की गई है। आय से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धान्त निम्न प्रकार हैं।

(१) अगर कोई प्राप्ति विशेष (Particular receipt) ऐसी है जिसका साधन स्थिर नहीं किया जा सकता, तो इस प्राप्ति को कर-योग्य-आय नहीं माना जा सकता। उदाहरणस्वरूप, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी सड़क पर घूम रहा है। यदि मार्ग में उसे ५,००० की थैली पड़ी हुई मिले और वह उसे उठाकर अपने कबजे में करले, तो उसकी यह प्राप्ति आय के अन्तर्गत शामिल नहीं की जा सकती, क्योंकि इसका साधन स्थिर नहीं है।

(२) कर लगाने की दृष्टि से इस बात को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता कि अमुक व्यक्ति को आय गैर कानूनी रूप से पैदा की गई है। यह रगल करना मूलतः पूर्ण है कि कर केवल ईमानदारी से कमाई हुई आय पर लगता है और बड़बानी से प्राप्त आय पर लगने से बच जाती है। आय-कर अधिनियम कानूनी ढंग से कमाई हुई आय पर ही लागू होगा, यह कोई बन्धन नहीं है। यह अधिनियम अबैध आय पर भी समान रूप से लागू होता है।

(३) आय द्रव्य के अथवा द्रव्य तुल्य वस्तु के रूप में (Money's worth) प्राप्त की जाती है। द्रव्य-तुल्य प्राप्ति आय की प्राप्ति ही समझी जायगी।

(४) यह कोई जरूरी नहीं कि आय नियमित रूप से प्राप्त हो। एक इकट्ठी रकम की प्राप्ति भी आय हो सकती है। वह पारिश्रमिक, जो आय है यदि वह कई वर्षों पर फैला कर दिया जावे, तब भी आय ही गिना जायगा जबकि वह केवल एक बार में एक मुश्त चुका दिया जाय, उदाहरण के लिये वष का वेतन जो एक मुश्त पेशगी चुका दिया गया हो।

(५) आयकर के उद्देश्य के लिये, किसी प्राप्ति (receipt) की प्रकृति सदैव के लिए उस समय निश्चित हो जाती है जबकि वह प्राप्त की जाती है। कोई प्राप्ति (receipt), जो प्राप्त होने के समय आय के अन्तर्गत नहीं आती, बाद में भी आय के रूप में सम्मिलित नहीं की जा सकती। जैसे, किसी फर्म को एक ग्राहक से एडवांस स्वरूप कोई रकम प्राप्त हुई। उसे कई वर्षों तक वापस नहीं माँगा जाता और अन्त में फर्म क

पूँजी खाते (Capital Account) में जमा करली जाती है। ऐसी परिस्थिति में पूँजी खाते की यह जमा रकम फर्म की आय में शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि वह रकम, जब आहूक से प्राप्त हुई थी, तो आय के रूप में प्राप्त नहीं हुई थी।

(६) आय बाहर से ही प्राप्त होनी चाहिए। कोई म्युचुअल सस्था (जैसे कोई क्लब) ऐसे आपसी कार्यों में सलग्न हो सकती है, जिससे कर-अयोग्य (Non-taxable) आधिव्यय उदय होता हो और वही सस्था किन्हीं ऐसे गैर आपसी कार्यों (Non-mutual activities) में भी सलग्न हो सकती है, जिनकी आय कर लगने योग्य हो। अतः सदस्यों के एक क्लब में ऐसा आधिव्यय, जो सदस्यों द्वारा विभिन्न मुख सुविधा के लिए चुकाये गये शुल्क एवं अन्य चन्दों से उदय हो, आय नहीं होती और न एक सामाजिक क्लबों से यही आशा की जा सकती है कि वह अपने सदस्यों से कई व्यापार करेंगे। किन्तु क्लब पर उस आय के लिये जो उसे गैर सदस्यों से शुल्क व चन्दों के रूप में प्राप्त हो, और जो पूँजी सम्पत्तियों (जैसे विनियोग) से प्राप्त हो, कर लगाया जा सकता है।

कमाई हुई आय (Earned Income)

कुछ प्रकार की आय, जैसे वेतन, व्यावसायिक आमदनी अथवा व्यापार के लाभ, वैयक्तिक परिश्रम (Personal exertion) से प्राप्त होती है। किन्तु इसके विपरीत अन्य प्रकार की आय, जैसे जायदाद की आय, सिव्योरिटिथो पर मिलने वाला ब्याज,

लाभांश (Dividend), ऐसा कोई परिश्रम किये बिना ही प्राप्त हो जाती है। वैयक्तिक परिश्रम से प्राप्त आय कमाई हुई आय कही जाती है और ऐसी कमाई हुई आय पर करारोपता व्यवस्था में मानव यन्त्र की घिसावट (Depreciation) के रूप में कुछ रियायत दी जाती है। कमाई हुई आय पर, बिना कमाई हुई आय की अपेक्षा कर-भार (Incidence of taxation) कुछ हल्का होता है।

कमाई आय की छूट (Earned income Allowance)

३१ मार्च १९५७ तक अतिरिक्त-कर के लिये कमाई आय की छूट का कोई आयोजन न था। हाँ, आय कर के सम्बन्ध में ₹५,००० रु० से कम 'कमाई हुई आय' के लिये २०% या ४,००० रु० अधिकतम छूट का आयोजन था। इस रकम से अधिक आय वालों के लिये ४,००० रु० की छूट ₹५,००० रु० से जितना रकम अधिक हो उसके २०% की दर से कम कर दी गई है। इस प्रकार यदि कमाई हुई आय ₹५,००० रु० है, तो छूट बिल्कुल भी नहीं मिलेगी।

१ अप्रैल १९५७ से यह पद्धति बिल्कुल बदल दी गई है। अब तो सब आय पर एक आदर्श अनुसूची से आय कर तथा अतिरिक्त कर की दरें लगाई जाती हैं तथा कमाई हुई आय की अपेक्षा न कमाई आय पर अधिक सर-चार्ज लगाया जाता है। इसका

अर्थ यह हुआ कि कमाई आय की छूट अब आय-कर व अतिरिक्त कर दोनों के लिये प्राप्त होगी ।

१९५६ के फाइनेंस एक्ट के अनुसार, कुल आय पर आय-कर और अतिरिक्त-कर प्रथम तो दरो में गणना किये जायेंगे और निम्न दरो से सर-चार्ज लगाया जायेगा ।

(अ) कमाई हुई आय पर सामान्य सरचार्ज कुल आय पर लगे आय-कर तथा अतिरिक्त कर का ५% । तथा अतिरिक्त सरचार्ज आय-कर और अतिरिक्त-कर का ५% यदि कमाई हुई आय १००,००० रु० में अधिक हो, तथा

(ब) न कमाई हुई आय पर आय-कर और अतिरिक्त-कर का १५% विशेष सरचार्ज, ऐसी आय कुल आय के सबसे ऊपर के हिस्से (top brackets) में मानी जाती है ।

यह सरचाज जब ही लागू होगा जब कि ऊँची छूट पाने वाले हिन्दू अविभाजित परिवार को कुल आय, १५,००० रु० से तथा अन्य किसी दशा में ७,५०० रु० से अधिक हो । यह सीमा कुल आय में १,५०० रु० तक शामिल इक्विटी अशो पर लाभांश से बढ़ा दी गई है ।

कमायी हुई आय के सम्बन्ध में रियायत केवल उसी दशा में प्राप्त हो सकती है जब कि आय-कर-दाता एक व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार या ~~अरविभाजित~~ फर्म अथवा कोई अन्य जन-समूह हो । किन्तु एक कम्पनी, स्थानीय सत्ता (Local authority) या रजिस्टर्ड फर्म की आय किसी भी दशा में कमाई हुई आय नहीं हो सकती । कम्पनियों और स्थानीय सत्ताओं को पृथक् करने का कारण यह है कि इनका निर्जीवी स्वरूप होने से आय प्राप्ति में कोई वैयक्तिक परिश्रम (Personal exertion) नहीं होता और एक रजिस्टर्ड फर्म को पृथक् करने का कारण यह है कि ऐसी फर्म में कर-निर्धारण (Assessment) भागीदारों पर अलग अलग होता है, फर्म पर नहीं ।

सभी धैतन, जिनमें पेंशन तथा पूव सेवाओं के बदले में प्राप्त होने वाले एलाउन्स आदि शामिल हैं, कमायी हुई आय हैं । स्वीकृत प्राविडेन्ट फंड की दशा में मालिक का चन्दा तथा प्राविडेंट फंड खाते पर ब्याज (यदि कोई हो) जो कि किसी कर्मचारी के कर्मचारी के वेतन के रूप में उसकी कुल आय में सम्मिलित हो, कमाई आय मानी जाती है । व्यापार, व्यवसाय, अथवा किसी पेशे से होने वाली आय कमायी हुई है, बशर्ते उस व्यापार व्यवसाय का संचालन कर दाता स्वयं करता हो, किन्तु कोर्ट ऑफ वाट्स अथवा किसी ट्रस्टी द्वारा संचालित व्यापार से कर-दाता को होने वाली आय कमाई हुई आय नहीं है । अन्य साधनों से आय कमाई हुई आय तभी मानी जायगी जब कि वह वैयक्तिक

परिश्रम (Personal exertion) से उर्जाजित की गई हो, जैसे डायरेक्टर की फीस, पुस्तको से मिलने वाली रॉयल्टी आदि ।

रजिस्टर्ड और अरजिस्टड फर्मों का भेद आयकर दाता (Assessee) में सम्बन्धित एक आगामी अध्याय में स्पष्ट किया गया है ।

कम्पनी, फर्म, हिन्दू अविभाजित परिवार कुल आय (Total Income), कुल विश्व आय (Total World Income) आदि शब्दों की व्याख्या आगामी अध्यायों में यथावसर की जायगी ।

आयकर प्राधिकारी (Income Tax Authorities)

भारतवर्ष में आयकर सन्धियम को सुधार रूप से प्रशासित तथा कार्यान्वित करने का कार्य निम्नलिखित प्राधिकारियों को सौंपा गया है :—

(१) सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (Central Board of Revenue)

केन्द्रीय सरकार ने कतिपय मदस्यों के इस बोर्ड की स्थापना आय-कर, उत्पादन-कर, चुंगी आदि से प्राप्त सरकारी आय पर नियन्त्रण करने के लिए की है । इस बोर्ड के एक सदस्य को संपूर्ण भारतवर्ष के आयकर-विभाग का नियन्त्रण सौंपा गया है । वह उस विभाग का अध्यक्ष है और भारत सरकार इस व्यक्ति की सिफारिशों पर ही कमिशनर, असिस्टेंट कमिशनर, और इन्कम टैक्स आफीसरो की नियुक्ति करती है । किन्तु बोर्ड को अपीलेंट असिस्टेंट कमिशनरों के अपील सम्बन्धी कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है ।

(२) डायरेक्टर ऑफ इन्स्पेक्शन (Director of Inspection)

केन्द्रीय सरकार जितने ठीक समझे उतने डायरेक्टर ऑफ इन्स्पेक्शन नियुक्त कर सकती है और उन्हें किसी दूसरी आयकर-सत्ता के ऐसे कार्य करने होंगे जो उनको सौंपे जायें । हाँ, उन पर सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का नियन्त्रण रहेगा । ये अपने अधीन इन्कम टैक्स आफीसरो के लिये कर निर्धारण के किसी मामले में ऐसे नियम, जो भी वे ठीक समझे, पथ प्रदर्शन के हेतु जारी कर सकते हैं । पूछताछ के उद्देश्य के लिये उनको वे तमाम अधिकार होंगे जो इन्कम-टैक्स आफीसरो को पूछताछ करने के सम्बन्ध में मिले होते हैं ।

‘डायरेक्टर ऑफ इन्स्पेक्शन’ वाक्यांश में एडीशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इन्स्पेक्शन नियुक्त हुए व्यक्ति भी शामिल होते हैं ।

(३) कमिशनर ऑफ इन्कम टैक्स

(Commissioner of Income Tax)

किसी राज्य अथवा अन्य क्षेत्र के आयकर-विभाग का अध्यक्ष कमिशनर ऑफ

इन्कम टैक्स कहलाता है। इस अधिकारी की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा होती है। आयकर सम्बन्धी कार्य के संचालन हेतु जो अधिकार उसे दिये गये हैं, उनका बरतन आयकर अधिनियम में किया गया है। इसी के हाथों अपने अधिकार-क्षेत्र के आयकर विभाग का सामान्य नियन्त्रण और संचालन होता है।

(४) अपीलेट असिस्टेंट कमिशनर

(Appellate Assistant Commissioner)

अपीलेट असिस्टेंट कमिशनर सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सीधे नियन्त्रण में होता है और उसका प्रमुख कार्य इन्कम-टैक्स आफिसरों के निर्णयों के विरुद्ध अपीले सुनना है। इस अधिकारी के अधिकार क्षेत्र को 'रेंज' (Range) कहा जाता है। 'रेंज' के अन्दर कई इन्कम-टैक्स आफिसरों के अधिकार क्षेत्र आते हैं।

(५) इन्स्पेक्टिंग असिस्टेंट कमिशनर ऑफ इन्कम टैक्स

(Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax)

इन्स्पेक्टिंग असिस्टेंट कमिशनर, कमिशनर ऑफ इन्कम टैक्स के नियन्त्रण में कार्य करता है और इसका प्रमुख कार्य अपने क्षेत्राधीन इन्कम टैक्स आफिसरों के कार्य का निरीक्षण करना है। कुछ मामलों में इन्कम टैक्स आफिसरों को दण्ड (Penalty) अथवा अभियोग (Prosecution) चलाने से पूर्व इस असिस्टेंट कमिशनर से अनुमति लेनी पड़ता है। यद्यपि कर-निर्वाण (Assessment) में उसका प्रत्यक्ष कोई हाथ नहीं, तथापि आय-कर निर्धारण की सामान्य कार्य-विधि में हस्तक्षेप करने और इन्कम टैक्स आफिसर को आवश्यक निर्देश देने का अधिकार उसे प्राप्त है।

(६) इन्कम टैक्स आफिसर (Income Tax Officer)

इन्कम टैक्स आफिसर ही वास्तविक कर-निर्वाण-कर्ता अधिकारी होता है। वही कर निर्धारित करता है, कर-दाता से कर की माँग करता है और वसूल करता है। इसके अधिकार आय-कर अधिनियम द्वारा निर्धारित हैं और उसका अधिकार क्षेत्र जिसे डिस्ट्रिक्ट (District) कहा जाता है, सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सलाह से कमिशनर द्वारा निश्चित किया गया है। जब किसी इन्कम टैक्स आफिसर की पदोन्नति अपीलेट असिस्टेंट कमिशनर के पद पर हो जावे, तो वह अपने पूर्व निर्णयों और आदेशों के विरुद्ध अपील को सुनवाई नहीं कर सकता। ऐसे मामले किसी दूसरे अपीलेट असिस्टेंट कमिशनर के पास भेजे जाते हैं।

(७) इन्कम टैक्स इन्स्पेक्टर (Income Tax Inspector)

इन्कम टैक्स इन्स्पेक्टर केन्द्रीय सरकार के नियमों एवं आदेशों के अधीन कमिशनरों द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। वे ऐसे सब कार्य करते हैं जो उन्हें इन्कम टैक्स

अफीसर या कोई अन्य आय-कर-अधिकारी, जिसके अधीन वे काम करने के लिये नियुक्त किये जायें, करने के लिये सौंपे ।

(८) अपीलेंट ट्रिब्यूनल (Appellate Tribunal)

आय-कर विभाग के प्रशासन एवं संचालन कार्य से पृथक् 'अपीलेट ट्रिब्यूनल' की स्थापना की गयी है । इसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करती है और वह इसमें जितने सदस्य रखना उचित समझती है, रखती है । इसमें या तो जुडिशियल सदस्य होते हैं अथवा एकाउण्टेंट सदस्य, किन्तु इसका सभापति कोई जुडिशियल सदस्य ही होना है । इस ट्रिब्यूनल की प्रत्येक बैच में एक जुडिशियल मैम्बर तथा दूसरा एकाउण्टेंट मैम्बर होता है, और प्रत्येक बैच भारतवर्ष के किसी एक भिन्न भाग की आय-कर सम्बन्धी अपील की सुनवाई करती है । किसी अपील पर विचार करते समय जब बैच के दोनों सदस्यों में मतभेद हो और उनकी एक राय नहीं होती तो ऐसी दशा में ट्रिब्यूनल के सभापति द्वारा तीन सदस्यों की बच बना दी जाती है ।

अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर के निर्णयों के विरुद्ध की गई अपील की सुनवाई इस अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा होती है । अपील के तथ्य (Facts) सम्बन्धी प्रश्नों पर ट्रिब्यूनल का निर्णय अन्तिम (Final) होता है । हाँ, यदि इसके सन्नियम सम्बन्धी प्रश्नों के निर्णयों से आय-कर-दाता सन्तुष्ट न हो, तो केवल सन्नियम सम्बन्धी प्रश्नों (Points of Law) पर पुनर्विचार करने के लिये मामलों को हाईकोर्ट में भेजा जा सकता है ।

धारा ३ के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति से उसकी कुल आय (Total Income) के सम्बन्ध में आय-कर लिया जाता है, जबकि धारा ४ में कुल आय के क्षेत्र की व्याख्या की गयी है। किसी व्यक्ति की कुल आय को उसके निवास स्थान (Residence) के हिसाब से निश्चय किया जाता है जबकि निवास स्थान का आशय उसके गत वर्ष के निवास स्थान से है।

कर-दाताओं का निवास स्थान (Residence of Assesseees)

निवास-स्थान के विचार से आय-कर दाताओं को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है—

- (अ) व्यक्ति जो भारत में निवास नहीं करते हो।
- (आ) व्यक्ति जो भारत में निवास करते हो किन्तु वहाँ के साधारण निवासी (resident but not ordinarily resident) न हो।
- (इ) व्यक्ति जो भारत में निवास करते हो और वहाँ के साधारण निवासी (resident and ordinarily resident) हो।

कोई आय-कर-दाता किस वर्ग में आता है, इसका निर्णय कई बातों पर निर्भर है, जिन पर आय-कर निर्धारण के हेतु, प्रत्येक वर्ष पुनर्विचार किया जाता है। परिस्थितियों के अनुसार आय-कर दाता किसी एक वर्ष के लिये निवासी (resident) और दूसरे वर्ष के लिये परदेशी (non-resident) हो सकता है।

इनमें से प्रत्येक वर्ग पर एक भिन्न आधार पर कर लगाया जाता है। आय-कर-दाता व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, कम्पनी, फर्म अथवा कोई अन्य जन-मण्डल हो सकता है। इनके निवास-स्थान (residence) का निश्चय निम्नलिखित नियमों के द्वारा होता है।

व्यक्ति (Individual)

कोई व्यक्ति किसी वर्ष विशेष में भारत का निवासी तभी माना जायगा जब कि—

(अ) वह भारत में उस वर्ष कुल मिला कर कम से कम १८२ दिन रहा हो, या
(आ) वह भारत में उस वर्ष कम से कम १८२ दिन से कोई रहने का मकान रखता हो, बशर्तें वह उस वर्ष में कम से कम एक दिन के लिये अवश्य ही कर लगने वाले क्षेत्र में उपस्थित रहा हो, या

(इ) वह भारत में (अ) उस वर्ष से पहले चार वर्षों के अन्दर कम से कम ३६५ दिन उपस्थित रहा हो और (ब) उस वर्ष में कम से कम एक दिन के लिए तो अवश्य ही कर लगने वाले क्षेत्र में आया हो, परन्तु उसका यह आगमन संयोगवश अथवा आकस्मिक (Casual Visit) न होना चाहिए, या

(ई) वह भारत में उस वर्ष रहा हो और इनकम टैक्स अफसर को यह इत्मीनान हो गया हो कि वह भारत में आने की तारीख से कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिये रहने के इरादे से आया है।

यदि किसी व्यक्ति पर उपर्युक्त चार शर्तों में से कोई भी शर्त लागू नहीं होती, तो वह परदेशी (non-resident) माना जायगा। किन्तु यदि इन शर्तों में से कोई भी शर्त लागू होने के कारण वह व्यक्ति निवासी ठहरता है, तो उसे निवासी किन्तु साधारण निवासी अर्थात् कच्चे निवासी (resident but not ordinarily resident) की श्रेणी में रखा जायगा। पक्का निवासी अर्थात् 'निवासी और साधारण निवासी' (resident and ordinarily resident) होने के लिए उसे निम्न दो और शर्तों को पूरा करना होगा—

(अ) कि वह उस वर्ष से पूर्व के दस वर्षों में कम से कम नौ वर्ष उपर्युक्त शर्तों के अनुसार कर लगने वाले क्षेत्र में निवासी (resident) रहा हो।

(आ) कि वह उस वर्ष के पहले ७ वर्ष के दौरान में कुल पर दो वर्षों से अधिक अवधि तक कर लगने वाले क्षेत्र में रहा हो।

उदाहरण

(१) एक व्यक्ति भारत में लगभग २५ वर्षों तक रहने के पश्चात् अप्रैल १९५६ में इंग्लैंड चला गया और फरवरी १९५९ में किसी वैतनिक पद पर नियुक्त होकर कर लगने वाले क्षेत्र में पुनः वापस आ गया।

३१ मार्च १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में वह भारत में १८२ दिन की अवधि के लिये नहीं रहा, न उसका यहाँ कोई मकान ही था। किन्तु १९५८-५९ से पूर्व

के ४ वर्षों में वह ३६५ दिनों से अधिक समय रहा और उसका वापस आना सयोगवश भी न था। इसीलिये वह १९५८-५९ के लिये निवासी (resident) माना जायगा।

इसके अतिरिक्त १९५८-५९ से पूर्व के १० वर्षों में से ९ वर्षों के लिये वह कर लगने वाले क्षेत्र में निवासी रहा और १९५८-५९ से पूर्व ७ वर्षों में से २ वर्ष से अधिक समय वह यहाँ रहा है। इसलिये सन् १९५८-५९ के लिये उसे पक्का निवासी (resident and ordinarily resident) माना जायगा।

(२) उपर्युक्त उदाहरण के सिलसिले में ही, मानलें कि वह व्यक्ति अप्रैल १९५६ के बजाय मार्च १९५६ में ही इंग्लैंड चला जाता है (और सब बातें पूर्ववत् रहती हैं) तो १९५८-५९ के लिये वह कच्चा निवासी (resident but not ordinarily resident) माना जायगा, क्योंकि पूर्व के १० वर्षों में से ९ वर्षों के लिये वह निवासी नहीं था।

(३) ईरान में व्यवसाय करने वाले एक पंजाबी व्यापारी को, जिसका कर लगने वाले क्षेत्र में बाप-दादों का कोई मकान नहीं है किन्तु जो हर दूसरे-तीसरे साल लगभग दो महीने के लिये कर लगने वाले क्षेत्र में आता है, परदेशी (non-resident) माना जायगा।

(४) एक व्यक्ति अफ्रीका में कारोबार चलाता है, कर लगने वाले क्षेत्र में उसका पैतृक मकान है और वह नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष लगभग २ महीनों के लिए आता है, तो ऐसी दशा में उसे कच्चा निवासी (resident but not ordinarily resident) माना जायगा क्योंकि पूर्व के (preceding) ७ वर्षों में वह कर लगने वाले क्षेत्र में २ वर्षों से अधिक समय तक नहीं रहा।

(५) कलकत्ता के एक जूट मिल का यूरोपियन मैनेजर कर लगने वाले क्षेत्र में पहले-पहल १५ वर्ष पूर्व आया और ३ वर्ष पहले उसने १५ महीने (मार्च १९५७ से मई १९५८ तक) की छुट्टियाँ स्वीजरलैंड में बिताईं। तो ऐसी दशा में उसे १९५१-६० वर्ष के लिये पक्का निवासी (resident and ordinarily resident) माना जायगा।

(६) एक अमेरिकन ६ वर्ष पहले भारत आया था तथा ३ वर्ष पूर्व वह अमेरिका ४ महीने की छुट्टी पर गया था। वह निवासी तो है लेकिन कच्चा निवासी है, क्योंकि वह पिछले दस वर्षों में से ९ वर्षों में निवासी नहीं रहा है।

नोट:—किसी व्यक्ति का किसी वर्ष के लिए निवास जानने के लिये उसकी पूर्व दस वर्षों की आने और जाने की तारीखों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिये। यदि वह दो वर्षों के लिये परदेशी रहा है तो वह निवासी तथा पक्का निवासी नहीं हो सकता।

हिन्दू अविभाजित परिवार (Hindu undivided families)

हिन्दू अविभाजित परिवार का निवास-स्थान निर्धारित करना इस बात पर निर्भर है कि उसकी देखभाल और प्रबन्ध कहीं स होता है। भारत में इसे निवासी (resident) तभी माना जायगा जबकि इसकी देखभाल और प्रबन्ध का कोई भाग (any portion) भारत में अवस्थित हो। लेकिन यदि परिवार की देखभाल, प्रबन्ध और नियन्त्रण पूर्ण रूप से भारत से बाहर हो तो उस दशा में परिवार को विदेशी (non-resident) माना जाता है। परिवार के पक्का निवासी (ordinarily resident) माने जाने के लिये यह जरूरी है कि इसका कर्त्ता या प्रबन्धक भारत का पक्का निवासी हो।

कम्पनियाँ (Companies)

कम्पनी को भारत में किसी वर्ष के लिये निवासी समझा जायगा, यदि (अ) यह भारतीय कम्पनी है, अथवा (ब) उस वर्ष में उसका प्रबन्ध एवं नियन्त्रण पूर्ण रूप से भारत में हो : यदि वह निवासी है तो वह पक्का निवासी समझा जायगा।

भारत से बाहर की प्रतिस्थापित कम्पनियाँ भारत में जब ही निवासी होंगी जबकि उनका संचालन व नियन्त्रण पूर्ण रूप से भारत में हो। साथ ही वे सब कम्पनियाँ जो भारत में प्रतिस्थापित हुई हैं निवासी कम्पनियाँ होंगी चाहे कुछ स्थितियों में प्रबन्ध एवं नियन्त्रण भारत से बाहर ही क्यों न स्थित कर दिया गया हो।

कम्पनी का प्रबन्ध एवं नियन्त्रण उस स्थान पर स्थित माना जाता है जहाँ संचालक कम्पनी के व्यस्यार को करने के लिए मिलते हैं, प्रतिवेदन (reports) प्राप्त करते हैं, कम्पनी की पॉलिसी निश्चित करते हैं, लाभांश घोषित करते हैं, इत्यादि।

फर्म तथा अन्य जन-मण्डल

(Firms and other Association of Persons)

किसी फर्म अथवा जन-मण्डल को निवासी (resident) तभी माना जायगा जबकि उसके प्रबन्ध, नियन्त्रण और संचालन का कोई अंश (any portion) भारत में अवस्थित हो। लेकिन जब उसका प्रबन्ध, नियन्त्रण और संचालन पूर्ण रूप से भारत के बाहर से होता हो, तो उसे परदेशी (non-resident) माना जायगा। यदि कोई फर्म अथवा जन-मण्डल भारत में निवासी है, तो उसे पक्का निवासी (ordinarily resident) माना जायगा।

नोट.—पक्के निवास-स्थान (ordinarily resident) की उपयुक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि केवल व्यक्ति तथा हिन्दू सयुक्त परिवार ही कच्चे निवासी (resident but not ordinarily resident) हो सकते हैं। यदि कोई कम्पनी,

फर्म अथवा जन-मण्डल किसी कर लगने वाले क्षेत्र का निवासी है, तो वह आवश्यक रूप से उस क्षेत्र का पक्का निवासी (ordinarily resident) हो जाता है ।

कर भार (Incidence of Tax)

पक्के निवासी व्यक्ति

(Person resident and ordinarily resident)

ऐसे व्यक्तियों का निम्न प्रकार की आय पर कर देना पड़ता है —

(अ) उस आय पर जो गत वर्ष भारत में प्राप्त हुई है अथवा प्राप्त मानी गई हो भले ही वह भारत के अन्दर अथवा बाहर पैदा की गई है ।

(आ) उस आय पर जो गत वर्ष में भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई अथवा उपार्जित की हुई या उदय हुई समझी जावे भले ही वह भारत के अन्दर अथवा बाहर प्राप्त की गई हो ।

(इ) उस आय पर जो गत वर्ष भारत के बाहर उदय और प्राप्त हुई, लेकिन उस वर्ष के अन्दर भारत में लाई गई हो ।

(ई) आय जो गत वर्ष भारत के बाहर उपार्जित और पैदा हुई किन्तु उस वर्ष भारत में नहीं लाई गई, और

(उ) उन तमाम रकमों पर जो गत वर्ष से पहले किन्तु १ अप्रैल १९३३ के बाद भारत के बाहर उपार्जित की हुई बिना कर लगी आय में से भारत में लाई गई हो ।

कच्चे निवासी व्यक्ति

(Person resident but not ordinarily resident)

ऐसे व्यक्तियों को निम्न प्रकार की आय पर कर देना पड़ता है —

(अ) उस आय पर जो गत वर्ष भारत में प्राप्त हुई थी या प्राप्त हुई मानी गई है भले ही वह भारत के अन्दर अथवा बाहर पैदा की गई हो ।

(आ) उस आय पर, जो गत वर्ष भारत में पैदा हुई या उपार्जित की गई है अथवा पैदा हुई या उपार्जित हुई मानी गई है, भले ही वह भारत के अन्दर अथवा बाहर प्राप्त की गई थी ।

(इ) उस आय पर जो गत वर्ष भारत से बाहर उपार्जित और प्राप्त की गई किन्तु उस वर्ष के भीतर ही भारत में ले आई गई है ।

(ई) आय जो गतवर्ष भारत के बाहर (चाहे भारत में न लाई गई हो) पैदा अथवा उपार्जित की गई है, वशतें यह आय भारतवर्ष में नियन्त्रित होने वाले किसी व्यापार या भारत में ही स्थापित किसी पेशे से पैदा हुई हो ।

(उ) उस कुल रकम पर जो गतवर्ष से पहले किन्तु १ अप्रैल - सन् १९३३ के पश्चात्, भारत के बाहर उपार्जित की हुई बिना कर लगी आय में से कर लगने वाले क्षेत्र में लाई गई है ।

१९५९-६० कर-निर्धारण वर्ष से पहले निवासी की दशा में भारत से बाहर पैदा हुई या अर्जित हुई वह आय जो भारत को न भेजी जाय, ४,५०० रु० तक की सीमा तक कर-मुक्त थी । भारत के वर्तमान आर्थिक विकास में यह छूट अनावश्यक है अतएव यह छूट अब समाप्त कर दी गई है ।

वेतन-आय के सिलसिले में इस छूट की समाप्ति उद्गम स्थान पर कटौती के हेतु १ अप्रैल १९५९ से लागू होगी । लेकिन कर-निर्धारण (Assessment) के हेतु यह १ अप्रैल १९६० से लागू होगी ।

सभी निवासियों ((residents) को १ अप्रैल १९३३ के पश्चात् होने वाली बिना कर लगी पिछली विदेशी आय के उस भाग पर कर देना पड़ेगा जो भारत में लायी जाय । यह इस सामान्य नियम का एक अपवाद है कि किसी भी कर-निर्धारण वर्ष (any assessment year) में केवल गत वर्ष, (previous year) की आय पर ही कर लगता है । यहाँ आय गत वर्ष की आय नहीं, बल्कि गत वर्ष से पहले के किन्हीं वर्षों की आय है ।

आय को 'प्राप्त करने' (receipt) और उसे 'अन्दर लाने' (bringing in) में एक अन्तर है । एक बार प्राप्त की हुई आय दूसरी बार प्राप्त नहीं की जा सकती और जो आय भारत से बाहर एक बार प्राप्त करली गई है, उसका भारत में स्थानान्तरण 'दुबारा प्राप्त होना' नहीं बल्कि इस क्षेत्र में 'लाई हुई आय' मानी जायगी ।

परदेशी व्यक्ति (Persons not resident)

परदेशी (non resident) की निम्न आय पर कर लगता है —

(अ) उस आय पर जो भारत में गत वर्ष में प्राप्त हुई है, अथवा जिसका भारत में प्राप्त होना माना गया है भले ही वह भारत के अन्दर या बाहर पैदा की गई हो ।

(आ) उस आय पर जो गतवर्ष में भारत में उपार्जित की गई है या उत्पन्न की गयी है अथवा जिसका उपाजन और पैदा होना भारत में माना गया है भले ही वह भारत के अन्दर अथवा बाहर प्राप्त की गई थी ।

परदेशी (non-resident) को अपनी विदेशी आय (Foreign income) पर आय-कर नहीं देना पड़ता, चाहे वह उसे भारत में ही क्यों न ले आवे। इस बात को अच्छी तरह ध्यान से समझ लेना चाहिये कि परदेशी की विदेशी आय उसी हालत में कर लगाने योग्य है जबकि वह भारत में की जावे, किन्तु जब वह भारत के बाहर प्राप्त की जावे और बाद में भारत में लायी जाय तो इस पर कर नहीं लग सकता। आय की प्राप्ति (receipt) का आशय हमेशा पहली प्राप्ति से होता है।

“प्राप्त हुई मानी गई” (deemed to be received) वाक्यांश के अन्तर वे आय आती हैं जिन्हें सन्नियम द्वारा प्राप्त हुआ माना जाता है यद्यपि यथाथ में ऐसी कोई प्राप्ति नहीं होती, जैसे उद्गम स्थान पर कर काट लेना। जब उद्गम स्थान (source) पर किसी की आय (जैसे वेतन) में से कर काट लिया जाता है, तो कर की वह रकम, जिसे काट लिया गया है, उस व्यक्ति को प्राप्त हुई मानी जाती है यद्यपि वास्तव में वह उस रकम को प्राप्त नहीं करता।

भारत में उपाजित अथवा पैदा हुई मानी गई” (deemed to accrue or arise in India) इस वाक्यांश के अन्तर्गत वे आय मानी जाती हैं जो यथार्थ में उपाजित और पैदा हुई नहीं होती, किन्तु सन्नियम में उन्हें ऐसा मान लिया है। निम्न-लिखित रूपों में आय कर लगने वाले क्षेत्रों में उपाजित और पैदा हुई मानी जाती हैं—

(क) वेतन, चाहे वह कहीं चुकाया जावे, यदि वह भारत में कमाया गया है।

(ख) भारतीय कम्पनियों द्वारा भारत से बाहर उस सीमा तक चुकाये गये लाभांश (dividend) जहाँ तक कि वे भारत में पहले ही से कर लगे लाभों से वितरित किये गये हैं।

(ग) भारत में रहने वाली पत्नी को अपने परदेशी (non-resident) पति की बिना कर लगी आय में से मिलने वाली रकम। ऐसी रकम पत्नी की आय मानी जायगी।

(घ) भारत में व्यापारिक सम्बन्धों के कारण अथवा अन्य साधनों द्वारा पैदा होने वाली आय। इन मामलों में आय वास्तव में भारत के बाहर उपाजित हो सकती है किन्तु उसे भारत के अन्दर उपाजित माना जाता है।

परदेशियों की दशा में, भारत में अर्जित या अर्जित समझी जाने वाली आय पर लगने योग्य है। वास्तविक अर्जन (actual accrual) कर पर दायित्व सम्भूता तो बड़ा सरल है, लेकिन ‘समझी जाने वाली’ (Deemed) वाक्यांश भ्रम दा कर देता है।

सन्नियम के अनुसार साधारणतः एक परदेशी पर केवल इस कारण ही कोई कर दायित्व नहीं होगा कि वह एक भारतीय व्यापारी से आयात अथवा निर्यात करता है।

हाँ, यदि वह 'प्रधान से प्रधान' (Principal to Principal) आधार पर कार्य करे, तो बात दूसरी है। वास्तव में कर-दायित्व तभी उदय होता है जबकि एक परदेशी फर्म किसी 'निवासी' फर्म या व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में अपनी ओर से क्रय-विक्रय करने या कोई अन्य कार्य करने (जैसे भुगतान संग्रह करने) के लिये नियुक्त करता है। ऐसी दशाओं में स्वभावतः ही परदेशी भारत में अपनी कार्यवाहियों के कारण, जो कि वह प्रतिनिधि द्वारा करता है, कुछ लाभ उठाता है और इसलिये यह उचित है कि वह कर का कुछ दायित्व भी उठाये।

सारांश

(Summary)

भिन्न-भिन्न प्रकार की आय के विचार से निवासियों (residents) और परदेशियों (non-residents) के कर दायित्व को इस प्रकार सक्षिप्त किया जा सकता है—

(१) सभी आयकर दाताओं को भारत में प्राप्त हुई आय पर (चाहे वह यहाँ कमाई गयी है अथवा बाहर) कर लगेगा।

(२) सभी आयकर दाताओं की भारत में कमाई हुई आय पर (चाहे यहाँ प्राप्त हुई है अथवा बाहर) कर लगेगा।

(३) भारत के बाहर कमाई और प्राप्त की हुई किन्तु उसी वर्ष भारत में लायी गयी आय पर सब निवासियों (Residents) को कर देना पड़ेगा।

(४) सभी निवासियों को बिना कर लगी विदेशी आय पर, जो भारत में लाई गई है, लाने के वर्ष में कर लगेगा।

(५) आय जो किसी भी स्रोत से भारत के बाहर कमाई गई हो लेकिन जो भारत में न ही प्राप्त की गई हो और न ही लाई गई हो, पक्के निवासियों की दशा में कर योग्य होगी।

(६) कच्चे निवासी (resident not ordinarily resident) की आय पर, जो भारतवर्ष के बाहर ऐसे किसी व्यापार से कमायी गयी है जिसका नियन्त्रण और प्रबन्ध भारत में ही हुआ है किन्तु जो भारत में न तो प्राप्त ही की गयी और न लायी गयी है, कर लगेगा।

यह बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए कि जो व्यक्ति कच्चे निवासी है उन पर पक्के निवासियों की तरह ही कर लगता है। हाँ, उनके लिये एक खास छूट अवश्य है। कच्चे निवासी की भारत में न भेजी हुई आय पर तब तक कर नहीं लगेगा जब तक कि यह आय भारत से संचालित व्यापार, पेशे या व्यवसाय से पैदा न हुई हो।

विषय-सूची

अध्याय	पृष्ठ
१—विषय प्रवेश	१ X
२—कर-दायित्व	११ X
३—पूँजी और आगम	१६
४—कर-मुक्त आय	२४ X
५—कर-योग्य आय की गणना (१)	३० X
६—कर-योग्य आय की गणना (२)	५०
७—ह्रास	७५
८—कुल आय और कुल विश्व आय	८४
९—उद्गम स्थान पर कर-कटौती	१०८
१०—कर-निर्धारण की कार्य-विधि	११३
११—कर-दातागण (१)	१३२
१२—कर-दातागण (२)	१४१
१३—कर की गणना	१६३
१४—दोहराने के प्रश्नोत्तर	२१३

भाग रेलवे लाइन के बराबर जाता था। रेलवे ने इस जमीन से खुदाई बन्द कर देने के लिए उस कम्पनी को मुआवजे के रूप में एक मुश्त रकम दी। यह प्राप्ति पूँजी-प्राप्ति है, क्योंकि वह एक पूँजी सम्पत्ति (मिट्टी के मँदान) की क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त हुई है।

एक अन्य कम्पनी ने कुछ जमीन खरीदी, जिस पर मकान बनाकर बेचे जा सके, किन्तु म्युनिस्पल बोर्ड ने उस जमीन पर मकान बनाने की अनुमति नहीं दी, जिसके लिये कम्पनी को मुआवजा दिया गया। मकान बनाकर बेचने के व्यापार में जमीन व्यापारिक सम्पत्ति (Trading Asset) अथवा चल-पूँजी (Circulating Capital) होती है, इसलिये जो क्षति-पूर्ति प्राप्त हुई वह आगम प्राप्ति है।

(२) जब कोई प्राप्ति किसी आय के साधन की प्रतिस्थापना (Substitution) के रूप में प्राप्त हुई है तो वह पूँजी-प्राप्ति होगी, किन्तु यदि वह आय के ही बदले में प्राप्त हुई हो तो उसे प्राप्ति माना जायगा।

एक नौकर को अपने मालिक से नौकरी खत्म कर देने के हजाने में जो रकम प्राप्त होती है, वह पूँजी-प्राप्ति होगी, क्योंकि वह आय के साधन की पुनर्स्थापना के रूप में है। किन्तु कर्मचारी को अपनी पूर्व सेवाओं के स्वरूप मिला पुरस्कार (gratuity) अतिरिक्त पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त आय है।

एक कम्पनी ने आग से अपने कारखाने और मशीनरी की हानि तथा उसके स्वरूप बन्द हो जाने से होने वाले लाभ की हानि से संरक्षण के लिये बीमा कराया। कारखाने और मशीनरी की हानि के लिए क्षति स्वरूप मिलने वाली बीमे की रकम पूँजी-प्राप्ति है किन्तु लाभ की हानि के लिए मिलने वाली रकम आगम-प्राप्ति है, क्योंकि पहली (पूँजी) प्राप्ति तो एक पूँजी सम्पत्ति की पुनर्स्थापना के रूप में है और दूसरी प्राप्ति आय के बदले में है।

किसी कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन आगम-प्राप्ति है, क्योंकि वह उसकी पूर्व सेवाओं के मुआवजे के रूप में है। किन्तु पेंशन के बदले में मिलने वाली एक मुश्त रकम पूँजी प्राप्ति है, क्योंकि यह एक पूँजी सम्पत्ति (पेंशन पाने के अधिकार) के बदले में है।

एक कम्पनी ने, जिसके पास खडिया की खाने थी, किसी खरीदार ने दस वर्षों तक खडिया की एक निश्चित मात्रा देने का सौदा किया। कुछ अरों पश्चात् खरीदार ने आगे माल नहीं लेना चाहा। खडिया कम्पनी ने उसे सौदे के दायित्व से बरी करते हुये एक मुश्त रकम लेना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार प्राप्त हुई रकम आगम प्राप्ति होगी, क्योंकि यह प्राप्ति उस होबे वाली आय के बदले में है, जो सौदा खत्म न होने की हालत में उसे प्राप्त होती।

किरायेदारों से मकान मालिक को मिलने वाली 'पगड़ी' आगम-प्राप्ति है, क्योंकि यह किराये का अग्रिम भुगतान है।

एक व्यक्ति कई वर्षों से किसी मैनुफैक्चरिंग कम्पनी के माल का वितरक था । कम्पनी ने यह एजेन्सी खत्म कर दी और एजेंट को क्षति-पूर्ति के रूप में रकम दे दी । एजेंट को मिलने वाली यह रकम पूँजी-प्राप्ति है, क्योंकि वह उसे आय के साधन (एजेन्सी) की क्षति-पूर्ति में मिली है ।

यदि कोई रेलवे यात्री रेल-दुर्घटना में मर जाता है अथवा हमेशा के लिये अप्रगु हो जाता है, तो क्षति-पूर्ति के रूप में रेलवे कम्पनी द्वारा मिलने वाली रकम पूँजी-प्राप्ति है, क्योंकि वह आय के साधन (जिवंदगी) की क्षति-पूर्ति में प्राप्त हुई है । दूसरी ओर, यदि वह कुछ समय के लिये ही हाथ पैर से बेकार हो जाता है, और उस अवधि में आय का नुकसान उठाना पड़ता है तो ऐसी हालत में, मिलने वाली क्षति-पूर्ति की रकम आगम प्राप्ति होगी, क्योंकि वह रकम केवल आय की प्रतिस्थापना के रूप में है ।

(३) किसी सम्पत्ति के क्रय-विक्रय सम्बन्धी सौदे में, सम्पत्ति के स्वामी का क्या उद्देश्य (motive) रहा है, यह इस बात को तय करेगा कि प्राप्ति आगम-सम्बन्धी है या पूँजी सम्बन्धी । यदि सम्पत्ति-विनियोग के रूप में है, तो बेचने से होने वाली प्राप्ति पूँजी-प्राप्ति कहलायेगी । दूसरी ओर, यदि यह सम्पत्ति लाभ पर बेचने के लिए रखी हुई (Held for profit) समझी जाय, तो विक्रय राशि आगम-प्राप्ति मानी जायगी, क्योंकि वह सौदा व्यापार के रूप में हुआ है ।

अश और प्रतिभूतियों के बेचने से मिलने वाला लाभ पूँजी-प्राप्ति के रूप में है, बशर्ते कि विक्रेता एक ऐसा विनियोगकर्त्ता है जो अपने धारण (Holding) का रोककरण कर रहा है । किन्तु यही आय उस दशा में आगम-प्राप्ति मानी जायगी, जबकि वह अशो और प्रतिभूतियों में सट्टा (Speculation) कर रहा हो ।

एक व्यक्ति काफी मात्रा में सोना खरीदता है और इसके लिये वह मियाद (maturity) से पूर्व ही अपने स्थायी जमा खाते (Fixed Deposit) में से रुपया निकाल कर अथवा कर्जा लेकर रकम जुटाता है । सोना खरीद लेने के बाद वह उसे बेच देता है । सोना बेचने से हुई आय आगम-प्राप्ति है, क्योंकि वह व्यवहार एक व्यापारिक प्रयास है ।

व्यय (Expenditure)

यह निश्चित करना भी सरल नहीं है कि कोई व्यय विशेष पूँजी व्यय है अथवा आगम-व्यय । बहुत से मामलों में तो यह भेद इतना सूक्ष्म होता है कि इनके अन्तर की सीमा रेखाओं को स्पष्ट करना भी कठिन है । इस भेद को समझने के लिये व्यापार की प्रकृति, सौदे का सही स्वरूप तथा व्यय के उद्देश्य भी विचार करना आवश्यक है । निम्नलिखित सिद्धान्तों को लाभ करने पर यह भेद भली-भाँति समझ में आ जायगा ।

(१) जब कोई व्यय व्यापार के लिये किसी स्थाई सम्पत्ति अथवा कोई स्थायी लाभ प्राप्त करने के लिये किया गया है, तो वह पूँजी व्यय होगा, जैसे स्थायी सम्पत्ति को क्रय करने का व्यय अथवा किसी लाइसेंस या एजेन्सी प्राप्त करने में हुआ व्यय ।

किसी व्यापारिक चिह्न (Trade Mark) के रजिस्ट्रेशन कराने का व्यय आगम व्यय है । ट्रेडमार्क की रजिस्ट्री की मियाद ७ वर्ष तक रहती है, उसके बाद उसे पुन नया (renew) कराया जाता है इसलिए इसमें स्थायित्व नहीं है, जिसका होना पूँजी व्यय कहलाने के लिये जरूरी समझा जाता है ।

(२) किसी कर-दाता द्वारा स्वयं को किसी पूँजी-दायित्व (Capital liability) से मुक्त करने के लिये किया हुआ भुगतान पूँजी-व्यय होता है, जबकि कर-दाना द्वारा स्वयं को किसी वार्षिक आगम भुगतान (Annual Revenue Payment) के दायित्व से मुक्त करने की दृष्टि से किया गया भुगतान आगम-व्यय कहलायेगा ।

किसी कम्पनी ने एक नये जहाज के निर्माण और क्रय के लिये ठेका दिया । व्यापार में उस समय भारी मदी आ जाने और यह दिखाई देने के कारण कि जहाज चलाने से लाभ नहीं हो सकेगा, उस कम्पनी ने निर्माताओं को कुछ रकम देते हुए इस ठेके को खारिज कर लिया । इस रूप में जो रुपया दिया गया वह पूँजी व्यय है, क्योंकि यह रकम कम्पनी द्वारा एक पूँजी दायित्व (अर्थात् जहाज के लिये भुगतान करने) से मुक्त होने के लिए दी गई है ।

कर-दाता द्वारा किसी अलाभप्रद (Disadvantageous) एजेन्सी के ठहराव से मुक्ति पाने के लिए दी हुई रकम अथवा वार्षिक पेंशन के दायित्व के निपटारे में किसी कर्मचारी को दी गई रकम आगम-व्यय है ।

(३) किसी स्थायी सम्पत्ति की प्राप्ति अथवा उसके सुधार में किया जाने वाला व्यय पूँजीगत व्यय है, किन्तु यदि रुपया देने से किसी भी स्थायी सम्पत्ति में कोई बदल (alteration) नहीं हुई, तो यह व्यय आगम व्यय होगा, क्योंकि वह पूँजी सम्पत्ति के पोषण (Maintenance) की लागत मात्र है ।

एक कम्पनी ने पुरानी और मरम्मत-तलब हालत में मशीनरी खरीदी और उसे अपने काम में लेने से पूर्व ठीक-ठाक करा लिया । मशीनरी की मरम्मत और ठीक-ठाक कराने में हुआ व्यय पूँजी व्यय है, क्योंकि इसके द्वारा स्थायी सम्पत्ति में सुधार हुआ है ।

व्यापारी गण अपनी सम्पत्ति को कायम रखने, तथा उस पर अपने वर्तमान हक की रक्षा करने के लिए आग्रह मुकद्दमे लड़ते रहते हैं । इन मुकद्दमों में हुए व्यय से किसी स्थायी सम्पत्ति का निर्माण नहीं होता, बल्कि वे सम्पत्ति की रक्षा करने तथा उसे कायम रखने के सामान्य खर्च हैं । अतः ये व्यय आगम-व्यय हैं ।

हानियाँ (Losses)

पूँजी हानि और आगम हानि के मध्य भेद स्पष्ट करना सरल कार्य नहीं है। आगम-हानि के अन्तर्गत निम्न हानियाँ आती हैं—

(1) किसी आगम सम्बन्धी प्राप्ति (revenue receipt) की हानि, या

(11) व्यापारिक स्कन्ध की हानि, या

(111) वह हानि जो व्यापार करते हुए और व्यापार के परिणाम स्वरूप (incidental to) हो। वह न केवल व्यापार से सम्बन्धित हो अपितु वह वास्तव में व्यापार के फलस्वरूप भी हो।

जो हानि आगम-हानि (revenue loss) नहीं है, पूँजी-हानि (capital) होगी। नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं।

(क) अग्नि, दीमक या चोरी से हुई व्यापारिक स्कन्ध (stock-in-trade) की हानि आगम-हानि है, जैसे डाकुओं द्वारा ले जाया गया एक साहूकार का रुपया-पैसा (जो उसका व्यापारिक स्कन्ध है।)

(ख) किसी कर्मचारी के छल-साधन (defalcations) से व्यापार को हुई हानि एक व्यापारिक हानि है और कर-दाता उसकी घटोत्तरी के लिए माँग करने का अधिकारी है।

(ग) १२ बजे दोपहर में कुछ डाकू किसी कपड़े के व्यापारी की दुकान में घुस आते हैं और तमाम नकदी लूट कर भाग जाते हैं। इस प्रकार की हानि पूँजी-हानि है, क्योंकि एक कपड़े के व्यापारी के लिये नकदी उसकी पूँजी के एक अंश के रूप में है, व्यापारिक स्कन्ध (stock-in-trade) के रूप में नहीं।

(घ) कर्मचारी द्वारा दुकान के कार्य-काल में की गयी चोरी, आगम हानि होगी, क्योंकि यह व्यापार से सम्बन्धित है (being incidental to trade) किन्तु दुकान के समय के बाद यदि कोई कर्मचारी दुकान में घुसकर चोरी करता है, तो उसका यह कार्य चोर-डाकुओं द्वारा की गयी चोरी के समान ही है और इसलिये ऐसी हानि पूँजी-हानि है।

(ङ) किसी व्यक्ति द्वारा एक मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी की एजेन्सी प्राप्त करने के लिए जमा की गई रकम पूँजी-व्यय है। यदि वह जमा की हुई रकम कम्पनी के दिवालिया हो जाने से मारी जावे तो इस प्रकार की हानि पूँजी-हानि होगी।

कर-मुक्त आय (Incomes Exempt From Tax)

कर से मुक्त-आय दो प्रकार की है। कुछ आय केवल कर से ही मुक्त नहीं है, बल्कि उन्हें कुल आय (total income) में भी शामिल नहीं किया जाता, किन्तु कुछ आय कर से तो मुक्त अवश्य है, लेकिन उन्हें कुल आय में शामिल करना पड़ता है।

(१) आय जो कर से मुक्त है और कुल आय में शामिल नहीं की जाती

(१) किसी धर्म-पुण्य सम्बन्धी कार्य जैसे शिक्षा, चिकित्सा या सामान्य जनता के हितार्थ किसी अन्य कार्य के लिये, ट्रस्ट या किसी अन्य कानूनी दायित्व के अन्तर्गत धारण की हुई (Held) जायदाद (किसी भी प्रकार की जायदाद, जिसमें एक व्यापार शामिल है) से प्राप्त की गई आय कर से मुक्त है और कुल आय में भी शामिल नहीं की जाती। यदि वह किसी धार्मिक कार्य के लिये है तो वह किसी प्राइवेट धार्मिक कार्य से सम्बन्धित न होनी चाहिये। इस अपवाद के लागू होने के लिये कुछ बन्धन लगाये गये हैं। वे इस प्रकार हैं —

(अ) वह आय सम्पूर्ण रूप से किसी धर्म या पुण्य सम्बन्धी कार्यों में ही लगाई जानी चाहिये।

(आ) पुण्य कार्य साधारणतः भारत में की गई किसी बात से सम्बन्धित होना चाहिये।

(इ) यदि आय ऐसी आय है जो किसी पुण्यार्थ सस्था के ओर से चलाये गये व्यापार से हुई है, तो वह तभी मुक्त होगी जब वह पूर्णतः उस सस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में इस्तेमाल की जाय और जब या तो व्यापारिक कार्य स्वयं उस सस्था का प्रारम्भिक उद्देश्य हो या व्यापार सम्बन्धी कार्य मुख्यतः हितार्थियों (beneficiaries) द्वारा चलाया जाता है। उदाहरण के लिये, किसी अनाथालय का औद्योगिक स्कूल, जो फर्नीचर बनाता और बेचता तथा जिसमें कार्य विद्यार्थी स्वयं करते हैं।

✓(२) किसी धर्मार्थ सस्था द्वारा प्राप्त ऐच्छिक चन्दे, जो पूरात धर्मार्थ कार्यों में लगाये जाये ।

✓(३) किसी स्थानीय सत्ता की आय, जैसे म्यूनिसिपल बोर्ड । किन्तु किसी स्थानीय सत्ता द्वारा अपने क्षेत्र के बाहर प्रदान की गई वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त लाभ कर योग्य होंगे ।

(४) १९२५ का भारतीय प्रॉवीडेण्ट फण्ड कानून जिस प्रॉवीडेण्ड फण्ड को लागू होता हो उसके रुपये से ली गई प्रतिभूतियों का व्याज ।

(५) वह विशेष भत्ता या लाभ (जो मनोरजन भत्ता नहीं है और न 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत कर लगने योग्य है), जो किसी पद या नियुक्ति के कर्त्तव्यों को पूरा करने के खर्चों के सम्बन्ध में स्वीकार किया गया हो, उस सीमा तक कर मुक्त है, जिस तक कि वह उस कार्य के लिये वास्तविक रूप से किया जाय । यह अपवाद उन मामलों में लागू होता है जहाँ नियोक्ता और कर्मचारी का सम्बन्ध आवश्यक रूप से नहीं हो । जब किसी कर्मचारी को भत्ता दिया जाता है, तो धारा ७ के आदेश लागू होंगे ।

(६) भारतीय मालिक से प्राप्त रास्ते का निशुल्क या कम मूल्य पर प्राप्त मूल्य जो एक अन्तर्गत कर लगने के लिए प्राप्त करता है वह कुछ शर्तों के अन्तर्गत कर मुक्त है । इसी तरह की छूट भारतीय कर्मचारी को उसके घर के गाँव या शहर (जो भारत में स्थित है) जाने के लिए भी मिलती है ।

(७) आकस्मिक आय (Casual Income) । 'आकस्मिक (Casual)' शब्द केवल सयोगवश प्राप्त आय के लिए ही लागू हो सकता है, जो बिना किसी आशा अनुबन्ध या परिश्रम से मिले वह आय आँवी के आम अथवा अन्य प्रकार की आकस्मिक प्राप्ति के रूप में होनी चाहिए, जैसे कोई कीमती चीज पड़ी मिल जाये या शत जीतने में मिली रकम अथवा सयोगवश मिला उपहार । निम्न आय आकस्मिक आय नहीं है —

(अ) वे प्राप्तियाँ जो किसी व्यापार में या किसी व्यवसाय, पेशे या अन्य काम को करने से उदय हो ।

(ब) वे प्राप्तियाँ जिनका स्वरूप आकस्मिक नहीं है, और

(स) वे प्राप्तियाँ जो किसी कर्मचारी को अतिरिक्त पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त हों ।

निम्न उदाहरणों में हुई आय आकस्मिक आय नहीं है, क्योंकि वह या तो किसी व्यापार, व्यवसाय अथवा किसी पेशे से उदय होती है या वह किसी कर्मचारी के पारिश्रमिक में अतिरिक्त आमदनी स्वरूप है । यह ध्यान रहे कि व्यापार के रूप में किया गया केवल एक प्रयत्न (single adventure) भी व्यवसाय सम्झा जायगा, जैसे —

(अ) अ, एक रुई का एक व्यापारी, किसी रुई की फर्म के कारबार को बन्द करने के लिए नियुक्त किया जाता है और इस सेवा के लिए उसे कमीशन प्राप्त होता है।

(आ) अ एक साहूकार है। यदि उसके कजदार रुपया वापस नहीं कर पाते हैं, तो वह कर्ज की अदायगी में उनकी चल-अचल सम्पत्ति ग्रहण कर लेता है। इसी तरह वह एक अच्छी जमीन पा जाता है, जिसे वह लाभ में बेच लेता है।

(इ) अ सरकारी दफ्तर में एक बलक है। उसे किसी प्रकार सुराग लगता है कि सोने का दाम ऊपर जायेगा। वह अपने सम्बन्धियों से रुपया उधार लेकर १०० तोले सोना खरीद लेता है और बाद में उसे फायदे पर बेचकर लाभ उठाता है।

(ई) एक जमींदार किसी बड़े भू-भाग को खरीद लेता है, जिसे वह मकान बनाये जाने योग्य 'प्लॉटो' में बांट लेता है और उन्हें लाभ में बचता है।

(उ) अ किसी बीमा कम्पनी का कर्मचारी है। वह बोनस के रूप में २ महीने का वेतन प्राप्त करता है।

(ऊ) अ को, जो किसी कम्पनी का सेक्रेटरी है, कम्पनी के बोर्डर बेचने में अतिरिक्त सेवाएँ देने के कारण पुरस्कार (Gratuity) प्राप्त होता है।

निम्न उदाहरणों में आय आकस्मिक आय है क्योंकि वह न तो किसी व्यापार या व्यवसाय से उदय होती है और न वह किसी कर्मचारी के पारिश्रमिक में अतिरिक्त आमदनी स्वरूप ही है—

(अ) अ अपने रहने के लिये एक मकान खरीदता है और बाद में उसे लाभ में बेच लेता है।

(ब) एक व्यक्ति लॉटरी में इनाम पाता है।

(स) अ अपने किसी सम्बन्धी से कोई धनराशि बतौर भेंट (Gift) प्राप्त करता है।

(द) कृषि-आय (Agricultural Income)। वह आय जो कृषि-आय के अन्तर्गत आती है। (जिनका वर्णन प्रथम अध्याय में किया गया है।) कर से मुक्त है।

(६) स्वीकृत प्रॉवीडेंट फण्ड की आय (Income of a recognised Provident Fund)। स्वीकृत प्रॉवीडेंट फण्ड क्या है, इसकी चर्चा आगामी अध्यायों में की जायगी।

(१०) (अ) प्रीवी पर्स के रूप में किसी भारतीय नरेश को मिलने वाली धनराशि तथा (ब) विदेशी सरकार (Foreign Government) के कंसल (Consuls), ट्रेड कमिश्नर्स तथा अन्य आफिसीयल प्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त किया गया पारिश्रमिक।

छूट (ब) केवल पूर्ण-समय के प्रतिनिधियों तथा उनके स्टाफ के सदस्यों के लिए जो कि विदेशी सरकार के नागरिक हैं, को मिलेगी लेकिन यह उनके लिए नहीं मिलेगी जो कि अवैतनिक (Honorary) रूप में कार्य कर रहे हैं।

(११) उस नेपाली मिलिट्री फोर्स के सदस्य का वेतन, जो भारतीय यूनिन में सेवा कर रहा है ।

(१२) १ अप्रैल १९४६, और ३१ मार्च १९५६ के बीच बनवाये किसी मकान की आय जो 'मकान जायदाद से आय' शीर्षक के अन्तर्गत प्रभारित Charge) को जा सकती है । (अर्थात् उस मकान से आय, जो व्यापारिक कार्यों के लिये प्रयोग नहीं किया जाता), मकान बनाने की तारीख से दो कर-निर्धारण वर्षों के लिये कर से मुक्त है ।

(१३) मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक अनुसन्धान संस्था की श्रम्य भी कर से मुक्त। जो ३१ मार्च सन् १९४९ के बाद अर्जित हो और उम संस्था के हित में ही गवाई जाये ।

(१४) विदेशी व्यापारी के कर्मचारी का पारिश्रमिक उदाहरण के लिए एक विदेशी फर्म द्वारा भारत में काम करने के लिए दिये गये (deputed) टेक्नीशियन (Technician) का पारिश्रमिक कर-मुक्त है, बशर्ते (अ) कर्मचारी भारत में कुल ९० दिन से अधिक न रुके, तथा (ब) विदेशी साहस, जो ऐसे व्यक्ति को भेजता है, भारत में किसी व्यापार या व्यवसाय में नहीं लगा हुआ (engaged) है ।

(१५) पोस्टल बचत खाते पर ब्याज तथा नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, ट्रेजरी बिल्स डिपॉजिट, तथा नेशनल प्लान सर्टिफिकेट से प्राप्तियाँ ।

(१६) सरकार अथवा स्थानीय सत्ता अथवा एक भारतीय औद्योगिक इकाई द्वारा परदेशी व्यक्ति से अथवा भारत से बाहर स्थापित संस्था से लिए गये ऋण पर क़ायम किया गया ब्याज ।

(१७) लोकसभा के अथवा प्रान्तीय विधान सभा अथवा उनकी किसी सभा के सदस्य द्वारा प्राप्त किया गया दैनिक भत्ता ।

(१८) केन्द्रीय सरकार या प्रान्तीय सरकार द्वारा गैलेन्ट्री अवार्ड्स जैसे वीर चक्र, हावीर चक्र, परमवीर चक्र तथा अशोक चक्र प्राप्त करने वालों को नकद या किस्म में दिया गया भुगतान ।

(१९) किसी व्यक्ति को हिन्दू अविभाज्य कुटुम्ब के सदस्य के नाते हुई आय ।

२) आय-कर और अतिरिक्त कर से मुक्त किन्तु कुल आय में शामिल की जाने वाली आय

• (१) किसी सहकारी समिति की आय, हाँ, तब नहीं जब कि वह बीमा व्यापार लाती हो ।

(२) किसी सहकारी समिति से उसके सदस्यों द्वारा प्राप्त लाभांश ।

(३) कुल आय में शामिल की जाने वाली वह आय जो आय कर से मुक्त है लेकिन अतिरिक्त कर से नहीं

(१) किसी सरकारी कर्मचारी के वेतन में से उसे एन्युइटी (Annuity) अथवा उसके स्त्री-बच्चों के भरण-पोषण के हेतु आयोजन करने के लिए सरकार जो रकम काटे वह भी आय-कर मुक्त है। हाँ, कटी हुई रकम वेतन के पाँचवें हिस्से से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(२) कर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों पर मिलने वाला व्याज।

(३) अरबिस्टड फर्म अथवा कोई अन्य जन-मण्डल (other association of persons) द्वारा मिलने वाले लाभ का हिस्सा, जिस पर फर्म अथवा जन-मण्डल ने पहले ही कर चुका दिया है।

(४) आयकर-दाता के जीवन पर अथवा उसकी पत्नी या पति के जीवन पर (या एक संयुक्त हिन्दू परिवार की दशा में किसी भी पुरुष सदस्य अथवा उसकी पत्नी के जीवन पर) लिए गये बीमा या डेफर्ड ऐन्युइटी (deferred annuity) के प्रीमियम की रकम कर से मुक्त है परन्तु कुल आय में शामिल होगी, बशर्ते प्रीमियम की वार्षिक रकम, बोनस को छोड़ते हुए, बीमा की रकम के १० प्रतिशत से अधिक न बैठे।

(५) स्टैज्यूटरी प्राविडेंट फण्ड में कर्मचारी द्वारा दिया गया अशदान।

(६) स्वीकृत प्राविडेंट फण्ड में कर्मचारी द्वारा दिया गया अशदान, बशर्ते कि यह राशि उसके वार्षिक वेतन के पाँचवें भाग या ८,००० रु० जो भी कम हो, से अधिक न हो।

(७) स्वीकृत सुपरअन्युएशन फंड (approved superannuation fund) में कर्मचारी द्वारा दिया गया अशदान।

जरूरी नोट.—(१), (४), (५), (६), तथा (७) एक साथ लेकर व्यक्ति की दशा में कुल आय के चौथाई या ८,००० रु०, जो भी कम हो, अधिक नहीं होना चाहिए तथा हिन्दू अविभाज्य परिवार की दशा में कुल आय के चौथाई या १६,००० रु० जो भी कम हो, से अधिक नहीं होना चाहिए।

पुण्यार्थ दिये गये दान (Charitable Donations)

१ अप्रैल १९५३ को या इसके बाद कर दाता द्वारा भारत में धर्मार्थ कार्य-के लिये स्थापित किसी संस्था या फण्ड को, जो किसी ट्रस्ट के अधीन है या एक कम्पनी अथवा समिति के रूप में रजिस्टर्ड कराली गई है या सरकार अथवा किसी स्थानीय सत्ता द्वारा संचालित है या कोई यूनिवर्सिटी अथवा अन्य स्वीकृत शिक्षण-संस्था है, और जो नियमित, हिसाब-किताब रखती है किन्तु जो किसी जाति विशेष के लाभ के

लिए नहीं है, दी गई रकम आय-कर से मुक्त है। किन्तु इस छूट के लिये कुछ प्रतिबन्ध भी है :—

(अ) दान में दी हुई कुल रकम २५० रु० से कम न हो, और

(आ) दान में दी हुई कुल रकम कर-दाता की कुल आय (जो कर मुक्त भाग को घटाने के बाद बचे, जैसे अनरजिस्टर्ड फर्म की आय का भाग, जीवन बीमे का प्रीमियम आदि) का $\frac{1}{20}$ या १,००,००० रु० दोनों में जो कम हो उससे अधिक न हो।

उक्त छूट-प्राप्त दान या चन्दे की रकम आय-कर-दाता की कुल आय में शामिल की जायेगी और उस पर छूट की रकम (Amount of relief) कर की सामान्य दर से निकालनी चाहिये।

हाँ, कम्पनियों को छोड़कर अन्य कर-दाताओं के लिये यह छूट आय-कर और अतिरिक्त कर दोनों के लिये है। कम्पनियाँ, केवल आय-कर से मुक्ति की माँग कर सकती हैं।

आय कर अधिनियम की धारा ६ के अनुसार छ शीर्षको (Heads) के अन्तर्गत कर लगता है, जो इस प्रकार हैं — (१) वेतन, (२) प्रतिभूतियों पर मिलने वाला ब्याज (३) मकान जायदाद से आय, (४) व्यापार, पेशा, व्यवसाय अथवा उद्योग से लाभ, (५) अन्य साधनों से प्राप्त आय और (६) पूँजी लाभ। प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य आय की गणना किस प्रकार की जानी चाहिये यह ७, ८, ९, १०, ११ और १२ (बी) धाराओं में बताया गया है प्रत्येक शीर्षक से प्राप्त आय की गणना के हेतु अलग-अलग रीतियों (Methods) की व्यवस्था है और जो छूटे और रियायतें दी जाती हैं वे भी प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत समान नहीं हैं। यदि आय के किसी शीर्षक के अन्तर्गत एक से अधिक मदे हैं, जैसे मकान जायदाद की कई मदे, तो इन भिन्न-भिन्न मदों से प्राप्त आय एक साथ रखी जायगी और स्वीकृत कटौतियों की कुल योग से गणना की जायगी।

(१) वेतन (Salaries)

धारा ७ के अनुसार, आय-कर-दाता को अपने वेतन या मजदूरी पर, जो उसे देय है, कर देना पड़ेगा, चाहे वह उसे प्राप्त हुई है या नहीं। १ अप्रैल १९३९ तक केवल उसी वेतन पर आय-कर लगता था, जो कर दाता द्वारा प्राप्त कर लिया जाय, किन्तु इस तारीख के पश्चात् वह वेतन, जो कर-दाता को देय हो, कर-योग्य माना जाने लगा है भले ही उसकी प्राप्ति हुई हो या नहीं।

जहाँ सेवा दी जाती है, वही से वेतन की आय उदय होती है। यदि वह व्यक्ति भारत में काम-काज या नौकरी-चाकरी करता है, तो उसे इसी स्थान में वेतन उदय होता है किन्तु यदि वह कर लगने वाले क्षेत्रों के बाहर काम में लगा है, तो वेतन एक विदेशी आय (Foreign Income) है।

धारा ७ के अन्तर्गत कर लगने वाला वेतन वह वेतन है जो सरकार, स्थानीय सत्ता, कम्पनी, कोई अन्य सार्वजनिक संस्था अथवा कर-क्षेत्र के किसी व्यक्तिगत अन्य

स्वामी (Private employer) द्वारा दिया जाय। इसलिए विदेशी सरकार द्वारा दिये हुये वेतन या पेशन पर इस धारा के अनुसार कर नहीं लगता, किन्तु धारा १२ के अनुसार अन्य साधनों द्वारा प्राप्त आय के रूप में, उन पर कर लगेगा।

परदेशी सरकारी नौकरो को चुकाए गए वेतन का करारोपण

एक व्यक्ति, जो कि भारत का निवासी नहीं है, पर उस आय पर, जो कि भारत से बाहर उदय होती है, कर नहीं लगता। इसलिये सरकारी नौकरो पर, जो कि भारत से बाहर लगाये जाते हैं, और जो कि कुछ समय बाद परदेशी हो जाते हैं, उस वेतन के लिए, जो कि वे बाहर ही लेते हैं, कर नहीं लगता।

धारा ४ (१) के एक्सप्लेनेशन २ A के अनुसार ऐसे वेतन पर जो कि भारत के नागरिक सरकारी नौकरो को भारत के राजस्व में दिए जाए (लेकिन वेतन से तमाम भत्ते तथा अन्य सुविधाओं को, जो कि भारत से बाहर रहने के लिये दी गई हैं, को निकाल कर) कर देना होगा, चाहे वे भारत से बाहर कितनी ही अवधि के लिए रहे।

उद्गम स्थान पर कटौती के लिए यह नियम १ अप्रैल १९५९ से लागू होगा लेकिन कर-निर्धारण के लिये यह १ अप्रैल १९६० से लागू होगा।

वेतन के अन्तर्गत जिन आय पर कर लगेगा वे निम्न प्रकार हैं—

(१) वेतन के लिये एक मुश्त रकम, घटौती अथवा परिवर्तन, (A lump sum paid in commutation, reduction or substitution of salary) में मिली रकम, पेन्शन अथवा नौकरी के अन्य लाभ (other profits of employment) ये सब वेतन की आय की तरह ही समझी जाती है।

(२) वेतन के हिसाब में अपने मालिक से ली हुई पेशगी (Advance), उस तिथि को, जिस दिन कि पेशगी ली गई है, प्राप्य वेतन (Salary due) ही समझी जायगी। अन्य पेशगियाँ जो कर्मचारी अपने स्वामी से ले, जैसे मकान बनाने के सम्बन्ध में ली हुई पेशगी, वेतन के अन्तर्गत शामिल नहीं की जायेगी, क्योंकि यह पेशगी ऋण के रूप में है।

(३) कोई बोनस, एन्यूइटी (Annuity), पेंशन, कमीशन, फीस, ग्रेचुटी (Gratuity), प्रर्क्विजिट (Perquisite) व अन्य दूसरे एलाउन्स, अथवा वेतन के स्थान में या उसके अतिरिक्त अन्य कोई लाभ, कर लगने वाले वेतन के अन्तर्गत आता है। इस प्रकार वेतन की परिभाषा बहुत विस्तृत हो जाती है और यह मालूम करना कठिन हो जाता है कि पारिश्रमिक का कौनसा रूप इसमें शामिल नहीं किया गया है।

(४) मकान के किराये का भत्ता (भले ही उसकी रकम कितनी भी हो) या मालिक द्वारा दिये हुए निःशुल्क मकान का मूल्य (Value), यह मूल्य बिना सजे हुये मकान के लिये कर्मचारी के वेतन के १० प्रतिशत से और सजे हुए मकान (Furnished house) के लिये वेतन के १२.३% से अधिक न होना चाहिये।

(५) किसी कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारी को, जो उसका डायरेक्टर है या जो कम्पनी में कोई विशेष हित रखता है, निशुल्क या रियायती दर पर दी गई किसी सुविधा या किसी लाभ का मूल्य। *20% vote 4th year for bonus & salary*

(६) किसी कर्मचारी को (जिसे उक्त चौथा नियम लागू नहीं होता) मालिक द्वारा निःशुल्क या रियायती दर पर दी गई सुविधा या किसी लाभ का मूल्य जबकि कर्मचारी के वेतन की आय (ऐसे सब लाभों का मूल्य, जो मौद्रिक भुगतान Monetary payment से, आयोजित नहीं है, अलग रखते हुये, ₹८,००० रु० से अधिक हो ।

(७) मालिक द्वारा किसी दायित्व के सम्बन्ध में दी गई कोई रकम, जिसे वह नहीं चुकाता तो खुद कर्मचारी को चुकानी पड़ती ।

(७) किसी कर्मचारी द्वारा अपने मालिक अथवा पूर्व मालिक से मिली रकम भले ही वह उसे पूरा रोजगार की हानि के क्षति-पूर्ति स्वरूप या किसी अन्य प्रतिफल के लिये प्राप्त हुई हो ।

(८) अस्वीकृत प्रोविडेंट फण्ड (Unrecognised Provident Fund) अथवा किसी अन्य फण्ड से प्राप्त हुआ भुगतान, उस भाग को निकालते हैं जो स्वयं कर्मचारी द्वारा दिये गये अंश दान (Contribution) और उस पर ब्याज की वापसी है ।

कर-मुक्त वेतन (Tax-free Salary) — जहाँ कि कर-मुक्त वेतन दिया जाए वहाँ पर कर्मचारी को अपनी कुल आय में ग्राँस वेतन जोड़ना होगा अर्थात् वास्तविक मिला हुआ वेतन तथा उसकी ओर से मालिक द्वारा दिया गया कर । इस बात से कि मालिक स्वेच्छा से या सविदा के कारण कर वहन कर रहा है, से कोई अन्तर नहीं पड़ता । हाँ यह अवश्य है कि मालिक द्वारा दिये गये कर की कर्मचारी को क्रेडिट (Credit) मिल जाएगी ।

कर-मुक्त वेतन को ग्रास करने की विधि 'कर-गणना' के अध्याय में समझाई गई है ।

दायित्व का आधार (Basis of Liability)

यदि किसी प्रकार का कोई भुगतान, जो कि वेतन में शामिल है, देय (due) हो जाता है, तो भले ही उसी वर्ष, जिसमें कि वह देय हुआ है, चुकाया जावे या नहीं, उसको उस वर्ष की आय के रूप में कर-निर्धारण के लिये विचार में लेना पड़ेगा तथा जिस वर्ष में वह चुकाया जाये उस वर्ष की आय के रूप में कर-निर्धारण करना गलत होगा 'भुगतान कर आधार' (Payment basis) तो ऐसी रकमों के लिये विचार में लिया जाता है, जो कि देय (Due) नहीं हुई ? जैसे कि वेतन की मद में से पेशगी ले लेना ।

कटौतियाँ (Deductions)

वेतन से कर योग्य आय निकालने के लिये निम्नलिखित कटौतियाँ दी जाती हैं

(१) कर्मचारी अपने कर्तव्यों के लिये आवश्यक पुस्तकें व अन्य प्रकाशनों की खरीद पर खर्च की रकम, जो ५०० से अधिक नहीं होगी ।

(२) धारा ४/३ (v1) में परिवर्तन के अनुसार, मनोरंजन भत्ते अब कर मुक्त नहीं हैं । इसलिये मनोरंजन भत्ते की राशि वेतन की आय में सम्मिलित की जानी चाहिये । लेकिन जोड़ने के बाद उसमें से निम्न छूट मिलेगी . —

(अ) सरकारी कर्मचारी की दशा में वेतन (विशेष भत्ते, लाभ या अन्य को छोड़ कर) के पाँचवें हिस्से या ५००० रु०, जो भी दोनों में से कम हो । यह छूट तब भी मिलेगी चाहे कर्मचारी को १ अप्रैल १९५५ से पहले यह भत्ता मिलता हो या न मिलता हो ।

(ब) अन्य कर्मचारी की दशा में वेतन (विशेष भत्ते, लाभ या अन्य को छोड़ कर) के पाँचवें हिस्से या ७,५०० रु०, जो भी दोनों में से कम हो (लेकिन भत्ते की रकम से न बड़े) । यह छूट केवल तब ही मिलेगी जब कि कर्मचारी अपने वर्तमान मालिक से १ अप्रैल १९५५ के पहले से लगातार यह भत्ता प्राप्त कर रहा हो ।

(३) कर-दाता द्वारा अपने रोगार के आशय के लिये स्तैमाल की गई निजी सवारी के सम्बन्ध में, उस खर्च और सामान्य टूट-फूट के यथोचित भाग की छूट मिलेगी, जो कि प्राइवेट कार्य से पृथक केवल रोजगार के आशय के लिये इस्तैमाल करने में हुई हो ।

हाँ, यह कटौती तब उपलब्ध न होगी जबकि कर-दाता को कुछ सवारी भत्ता (Conveyance allowance) मिलता है, चाहे पृथक या वेतन के एक ही भाग के रूप में हो, क्योंकि सवारी भत्ता कर मुक्त है ।

(४) कर्मचारी द्वारा अपनी नौकरी की शर्त के अन्तर्गत वास्तव में खर्च की गई ऐसी रकम, जो पूर्णतः उसके कर्तव्यों के पालन के लिये ही है और आवश्यक भी है ।

इसलिये, जहाँ एक इञ्जीनियर या एक बीमा एजेंट को उसके नौकरी के शतनामे के अनुसार, अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए, कार रखना जरूरी है तो ऐसी दशा में उन कर्तव्यों की पूर्ति के हेतु किये गये कार के खर्चों की छूट दी जायगी ।

उदाहरण

(१) अ (बम्बई के किसी बैंक का मैनेजर जिसे १००० रु० मासिक वेतन मिलता है) १ दिसम्बर १९५५ को पूरे वेतन पर छ महीने की छुट्टी पर स्विट्ज़रलैण्ड

गया। दिसम्बर १९५८ से जनवरी १९५९ के महीने का वेतन उसे स्विट्जरलैण्ड में ही भेजा गया, किन्तु छुट्टी की शेष अवधि का वेतन उसे जून १९५९ में बम्बई आकर ही प्राप्त हुआ।

३१ मार्च १९५९ को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिये उसकी वेतन से आय १२,००० रु० मानी जायेगी जो उसकी प्राप्य रकम (Amount due) है, १०,००० रु० नहीं, जो कि उसने वास्तव में प्राप्त किये हैं।

(२) १ जून १९५८ को एक व्यापारिक फर्म ने किसी व्यक्ति को २५० रु० मासिक वेतन तथा उसके द्वारा प्राप्त होने वाले ऑर्डरों पर ५ प्रतिशत कमीशन के आधार पर, सैल्समैन नियुक्त किया। नौकरी पर रखने के तीन महीने बाद उसे नौकरी से अलग कर दिया गया और हजति के रूप में उसे ३,००० रु० दिया गया। नौकरी की अवधि में उसके द्वारा जो ऑर्डर प्राप्त किये गये उनकी रकम १२,५०० रु० थी।

३१ मार्च १९५९ को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिये वेतन से होने वाली उसकी आय ७५० रु० तीन महीने का वेतन, ६२५ रु० कमीशन और ३,००० रु० हजाना इस प्रकार कुल ४,३७५ रु० थी।

(३) कई वर्षों से स एक फर्म में २०० रु० मासिक वेतन पर कार्य कर रहा था। किन्तु १ जुलाई १९५८ को वह छुट्टी में आकर नौकरी से अलग हो गया। वह अस्वीकृत प्रॉवीडेंट फण्ड का सदस्य भी था, जिसे स्वामियों ने चला रखा था। खुद अपने माहवारी वेतन से कटायी हुआ हिस्सा तथा उसका ब्याज दोनों की रकम इस फण्ड में ३,४५० रु० थी। नौकरी से अलग होने पर उसे प्रॉवीडेंट फण्ड से ५,७५० रु० दिये गये। १ अक्टूबर १९५८ को १८० रु० मासिक वेतन पर उसे एक और नौकरी मिल गयी।

३१ मार्च १९५९ को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिये वेतन से होने वाली उसकी आय निम्न प्रकार निकाली जायगी—

पुराने मालिक के यहाँ से ३ महीने का वेतन	६००
अस्वीकृत प्रॉवीडेंट फण्ड प्राप्ति (मालिक द्वारा दिया हुआ भाग और उस पर ब्याज)	२,३००
नये मालिक के यहाँ ६ महीने का वेतन	१,०८०
	<hr/>
	३,९८०

(४) एक बैंक के मैनेजर को ५,००० रु० मासिक वेतन तथा १ अप्रैल १९५२ से ५,००० रु० वार्षिक मनोरंजन भत्ता दिया जाता है। ३१ मार्च १९५९ को समाप्त हुए वर्ष के अन्तर्गत उसने ६५० रु० 'बैंकिंग लॉ तथा प्रेक्टिस' की किताबें खरीदी।

(अ) १९५९-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिये उसकी वेतन आय निकालिए।

(ब) क्या उसमें कोई अन्तर होगा यदि उन्हें ८,००० रु० वार्षिक मनोरंजन भत्ता दिया जाए।

		₹०
(अ) वर्ष के लिए वेतन		₹०,०००
वर्ष के लिए मनोरजन भत्ता		५,०००
		<u>₹५,०००</u>
घटाओ—अपने कर्त्तव्यों के लिए		
पुस्तकों की लागत	५००	
मनोरजन भत्ता	<u>५,०००</u>	५,५००
	वेतन से आय	<u>₹९,५००</u>
(ब) वर्ष के लिए वेतन		₹०,०००
वर्ष के लिए मनोरजन भत्ता		८,०००
		<u>₹८,०००</u>
घटाओ—अपने कर्त्तव्यों के लिए		
पुस्तकों की लागत	५००	
मनोरजन भत्ता (वेतन		
के १/५ या ७,५०० ₹०		
जो भी कम हो)	<u>७,५००</u>	८,०००
	वेतन से आय	<u>₹०,०००</u>

(५) अ महोदय एक कॉलेज के प्रिन्सिपल हैं। उन्हें १,००० ₹० मासिक वेतन और १०० ₹० मँहगाई प्राप्त होती है। १ दिसम्बर १९५८ को अपनी पुत्री के विवाह के लिए उन्होंने ८ महीने का वेतन पेशगी लिया और कॉलेज के अधिकारियों से इस काय के लिये ३,००० ₹० बतौर कर्जें भी लिए। गत वर्ष १९५८-५९ के लिये उनका वेतन क्या है ?

	₹०
वेतन और मँहगाई ८ मास की	८,८००
८ महीने का पेशगी वेतन	<u>८,८००</u>
वेतन से हुई कर योग्य आय	<u>₹७,६००</u>

ऋण-स्वरूप ली हुई ३,००० ₹० की रकम वेतन के अन्तर्गत कर लगने योग्य नहीं है।

वेतन निवासी व परदेशी दोनों को चुकाया जाना होता है। यह भारत में कमाया जा सकता है और यहाँ ही या बाहर चुकाया जा सकता है, या यह भारत के बाहर कमाया जा सकता है और वहाँ ही या भारत में चुकाया जा सकता है, या वेतन भारत से बाहर कमाया तथा प्राप्त किया जा सकता है जो कि उसी या अगले वर्ष भारत में लाया जाए।

(६) ३१ मार्च १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में निजी कर्मचारी (non-Govt employee) की दशा में कौनसा वेतन कर योग्य है जबकि प्राप्त कर्त्ता (अ) पक्का निवासी, (ब) कच्चा निवासी, तथा (स) परदेशी हो।

(१) वेतन दिल्ली में कमाया व वहाँ ही चुकाया	५,००० रु०
(२) वेतन नेपाल में कमाया व दिल्ली में चुकाया	५,००० रु०
(३) वेतन दिल्ली में कमाया लेकिन नेपाल में चुकाया	५,००० रु०
(४) वेतन नेपाल में कमाया व नेपाल में चुकाया	५,००० रु०
(५) वेतन नेपाल में कमाया व नेपाल में चुकाया लेकिन दिल्ली में गत वर्ष में लाया गया	५,००० रु०
(६) वेतन ३१ मार्च १९५५ वर्ष में नेपाल में कमाया व चुकाया लेकिन दिल्ली को मार्च १९५६ में लाया गया।	५,००० रु०

क्योंकि कर-भार कर-दाता के निवास पर निर्भर करता है, वेतन निम्न प्रकार से कर योग्य होगा :—

	पक्के निवासी	कच्चे निवासी	परदेशी
(१)	रु०	रु०	रु०
(२)	५,०००	५,०००	५,०००
(३)	५,०००	५,०००	५,०००
(४) ४,५०० रु० से अधिक	५,०००	५,०००	५,०००
(५)	५००	—	—
(६) रकम जिस पर भूत में कर नहीं लगा	५,०००	५,०००	—
	४,५००	५,०००	—

प्रॉविडेंट फण्ड (Provident Funds)

प्रॉविडेंट फण्ड, जिसका एक वैतनिक कर्मचारी सदस्य हो सकता है, तीन प्रकार के होते हैं।

(१) स्टेन्च्यूटरी प्रॉविडेंट फण्ड :—ये वे फण्ड हैं, जिन पर १९२५ का प्रॉविडेंट फण्ड अधिनियम लागू होता है, जैसे स्थानीय सत्ताओं (Local Authorities) अथवा यूनिवर्सिटी आदि द्वारा स्थापित प्रॉविडेंट फण्ड।

यदि कोई व्यक्ति इस फण्ड का सदस्य हो तो केवल उसका ही भाग (Contribution) आय-कर की दरें निकालने के लिए उसकी कुल आय में शामिल किया जाता है और मालिक के भाग पर तथा उसके (कर्मचारी के) हिसाब में जमा धन राशि की ब्याज पर विचार नहीं किया जाता। ऐसे किसी फण्ड में कर्मचारी का भाग (Contribution) तथा उसके जीवन बीमा का प्रीमियम (यदि कोई है) उस कर्मचारी की कुल आय के चौथे हिस्से या १०,००० रु० तक, जो भी दोनों में कम हो, आय-कर से तो मुक्त हैं, किन्तु अतिरिक्त-कर से नहीं। ऐसे किसी फण्ड का सदस्य के हिसाब में जमा धन जब सदस्य को मिलता है तो उस पर प्राप्तकर्ता को कर नहीं देना पड़ेगा और न उसे कुल आय में ही शामिल किया जायगा।

(२) स्वीकृत प्रॉविडेंट फण्ड (Recognised Provident Fund)—स्वीकृत प्रॉविडेंट फण्ड वह फण्ड है जो धारा ५८ (C) की शर्तों को पूरा करता है

और जिसे कमिश्नर ऑफ इनकमटैक्स की स्वीकृति मिल चुकी है। एक स्वीकृत प्राँवीडेण्ट फण्ड से सम्बन्धित आय-कर के निम्न आयोजन हैं—

(१) कर्मचारी की कुल आय में कर्मचारी के वेतन के १०% तक मालिक का अशदान नहीं जुड़ेगा, लेकिन मालिक का अशदान जो १०% से अधिक हो कर्मचारी की कुल आय में वेतन के ही भाग के रूप में सम्मिलित होगा।

(२) प्राँवीडेण्ट फण्ड खाने पर जमा ब्याज कमचारी की कुल आय में नहीं जुड़ेगा, अगर यह ब्याज कर्मचारी के वेतन के तिहाई या प्रस्तावित दर ६% से अधिक न हो। ब्याज जो इन दोनों सीमाओं से अधिक हो कमचारी की कुल आय में वेतन के भाग के रूप में सम्मिलित होगा।

(३) कर्मचारी का प्राँवीडेण्ट फण्ड में स्वयं का अशदान आय-कर से (अतिरिक्त कर से नहीं) मुक्त है, बशर्ते यह राशि वार्षिक वेतन के पाँचवें भाग या ७,००० रु०, जो भी दोनों से कम हो, से अधिक न हो।

(४) कर्मचारी के रिटायर होने पर जो एकत्र धन प्राप्त होता है वह भी कर से मुक्त है और यह कुल आय में नहीं जोड़ा जायेगा बशर्ते कर्मचारी ने मालिक की लगातार ५ साल तक सेवा की है।

• (५) कर्मचारी को उसके द्वारा चुकाए गये जीवन बीमा प्रीमियम के हेतु रिबेट प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन उसका प्राँवीडेण्ट फण्ड में स्वयं का अशदान तथा बीमा प्रीमियम दोनों मिला कर उसकी कुल आय के चौथाई या ७,००० रु०, जो भी कम हो, से अधिक न हो।

(३) अस्वीकृत प्राँवीडेण्ट फण्ड (Unrecognised Provident Fund).—किसी प्राइवेट फण्ड में, जिसे आय-कर विभाग से मान्यता प्राप्त नहीं है, कमचारी द्वारा दिया हुआ अशदान आय-कर से मुक्त नहीं है और कमचारी को इस प्राइवेट फण्ड से मिला एकत्रित धन भी (कर्मचारी का स्वयं का चन्दा और उस पर प्राप्त ब्याज की रकम निकालते हुए) कर लगने योग्य है, क्योंकि यह धन उस वर्ष के वेतन का एक भाग ही समझा जायगा। लेकिन अस्वीकृत फण्ड के सदस्य द्वारा जीवन बीमा के लिए दिये हुए प्रीमियम पर, सामान्य नियम के अनुसार छी छूट मिलेगी।

उदाहरण

* किसी व्यक्ति को ६०० रु० मासिक वेतन प्राप्त होता है। इसका ८% वह प्राँवीडेण्ट फण्ड में अपना अशदान देता है और मालिक का चन्दा १२% है। मालिक ने उसे रहने के लिए बिना किराये का मकान भी दे रखा है जिसका वार्षिक किराये का मूल्य ६०० रु० है और उसे १२०० रु० मालिक से बोनस के प्राप्त हुए।

५% वार्षिक की दर से ४५० रु० उसके प्राँवीडेण्ट फण्ड खाते में ब्याज के जमा हुए ।

उसने २,००० रु० जीवन बीमा प्रीमियम के चुकाये ।

उसका १९५९-६० कर निर्धारण वर्ष के लिये कर दायित्व बतलाइये यदि वह (अ) १९२५ के प्राँवीडेण्ट फण्ड अधिनियम के अनुसार स्थापित फण्ड का सदस्य है, (ब) स्वीकृत प्राँवीडेण्ट फण्ड का सदस्य है अथवा (स) अस्वीकृत प्राँवीडेण्ट फण्ड का सदस्य है ।

१९५९-६० के लिये दायित्व

(अ) वेतन—कुल आय के रूप में	रु०
कर-मुक्त आय —	९,०००
प्राँ० फण्ड में स्वय का चन्दा	
(७,२०० रु० का ८%)	५७६
जीवन बीमा प्रीमियम (प्राँ० फण्ड	
चन्दे तथा प्रीमियम ९,००० रु०	
के चौथाई तक सीमित)	१६७४
	<u>२,२५०</u>
(ब) वेतन	९,०००
मालिको का प्राँ० फण्ड में चन्दा (१०% से अधिक	
अर्थात् ७,२०० रु० का २%)	१४४
प्राँवीडेण्ट फण्ड पर जमा ब्याज (लेकिन यह वेतन	
के तिहाई या ६% के प्रतिवर्ष से कम है)	
	<u>कुल आय ९,१४४</u>
कर मुक्त आय :	
स्वय का प्राँ० फण्ड में चन्दा	५७६
जीवन बीमा प्रीमियम (प्राँ० फण्ड	
चन्दे तथा प्रीमियम ९,१४४ रु०	
के चौथाई तक सीमित	१,७१०
	<u>२,२८६</u>
(स) वेतन-कुल आय के रूप में	९,०००
कर मुक्त आय	
जीवन बीमा प्रीमियम (कुल आय के	
चौथाई तक सीमित)	२,०००

जीवन बीमा प्रीमियम (Life Insurance Premiums)

जो प्रीमियम कर-दाता या उसकी पत्नी या पति (अथवा हिन्दू अविभाज्य परिवार की दशा में किसी पुरुष सदस्य या उसकी पत्नी) के जीवन बीमे (या डेफ़र्ड

एन्सूइटी खरीदने) के लिये दिया गया है, आय-कर से (लेकिन अतिरिक्त कर से नहीं) मुक्त है, बशर्ते—

(अ) वार्षिक प्रीमियम, बीमा कराये हुए धन के, जिसमें बोनस की रकम न मिली हो, १०% से अधिक न हो। यह सीमा डेफर्ड एन्सूइटी खरीदने की राशि पर लागू नहीं होगी, तथा

(ब) वार्षिक प्रीमियम तथा किसी कर-मुक्त प्राँवीडेण्ट फण्ड के चन्दे की रकम दोनों मिलाकर, यदि कर-दाता व्यक्ति है, तो उसकी कुल आय के चौथे हिस्से या ८,००० रु०, जो भी कम हो, से और यदि कर-दाता हिन्दू अविभाज्य परिवार है तो, उस परिवार की कुल आय के चौथे भाग अथवा १६,००० रु० से अधिक न हो।

किन्तु यदि कर-दाता ने अपने प्राँवीडेण्ट फण्ड से कोई रकम जीवन बीमा का प्रीमियम भुगतान करने के लिये निकाली है, तो उस रकम पर आय-कर की कोई छूट नहीं मिलेगी और भारतीय आय-कर से मुक्त आय में से चुकाए गये प्रीमियम के लिये कोई भी छूट नहीं मिलेगी।

उद्गम स्थान पर कटौती (Deduction of Tax at Source)

यह एक अगले अध्याय 'उद्गम स्थान पर कर-कटौती' में समझाया गया है।

(२) प्रतिभूतियों का ब्याज (Interest on Securities)

धारा ८ के अनुसार कर-दाता को प्रतिभूतियों की 'ब्याज' शीर्षक के अन्तर्गत सरकारी प्रतिभूतियों तथा सावजनिक सस्थाओं और कम्पनियों के ऋण-पत्रों (debentures) के ऊपर मिलने वाले ब्याज के सम्बन्ध में कर देना होता है। यद्यपि प्राप्त्य ब्याज (Interest receivable) कर लगने योग्य है तथापि ऐसा ब्याज उस समय तक उस व्यक्ति की आय नहीं कही जा सकती जब तक वह उस व्यक्ति को सचमुच न मिल जाये। किन्तु, जहाँ ब्याज किसी ऐसे व्यवसाय के लाभ का एक भाग है, जो लेखाकर्म की व्यापारिक पद्धति (Mercantile system of Accountancy) व्यवहार में लाता है, तो इस दशा में उस पर 'उगजन होने के आधार' (accrual basis) पर कर लगेगा।

यह बताना भी यहाँ आवश्यक है कि लाभांशों (dividends) के रूप में हिस्सों (shares) से होने वाली आय पर, प्रतिभूतियों के ब्याज की भाँति कर नहीं लगेगा। लाभांशों पर, अन्य साधनों से होने वाली आय के रूप में, कर लगता है। इस विषय पर आगे चलकर चर्चा की जायेगी।

ब्याज सहित व्यवहार—प्रतिभूतियों पर ब्याज दिन प्रति दिन पैदा हुआ नहीं माना जाता है बल्कि एक निश्चित तिथि पर पैदा होता है। जब प्रतिभूति ब्याज सहित

खरीदी जाती है तो चुकाई गई कीमत में पिछली ब्याज तिथि से क्रय की तिथि तक का ब्याज भी सम्मिलित होता है लेकिन क्रेता पर अगली व्याज तिथि पर पूर्ण ब्याज पर कर लगेगा और उसे उस द्वारा विक्रेता को दिये गये ब्याज पर कोई छूट पाने का अधिकार नहीं है। इसी कारण से ब्याज सहित विक्रेता को प्राप्त हुए ब्याज पर कर नहीं देना होता है।

आय कर के लिये सामान्य नियम यह है कि व्याज तिथि पर जो प्रतिभूति का मालिक है उस पर ही कर लगेगा।

। कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ—कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज आय-कर से (अतिरिक्त-कर से नहीं) कर-मुक्त है लेकिन यह आय-कर कर की दर निकालने के लिये उसकी कुल आय में जोड़ा जाता है। फिर भी कुछ सरकारी प्रतिभूतियों, जैसे पोस्ट ऑफिस सैंव सार्टिफिकेट, नेशनल सेविंग्स सार्टिफिकेट, नेशनल ज्ञान सार्टिफिकेट तथा ट्रेजरी डिपॉजिट रिसीट्स आदि से ब्याज आय-कर व अतिरिक्त कर दोनों से मुक्त है और कुल आय में नहीं जोड़ा जाता।

कर-मुक्त डिबेंचर—जब कर-मुक्त डिबेंचर कम्पनी द्वारा जारी किए जाएँ तो अशधारियों के लिए उनको प्राप्त ब्याज पर कम्पनी कर अदा करती है तथा ऋणपत्रधारी, न केवल उस रकम पर जो उन्हें प्राप्त हुई है, बल्कि उस रकम पर भी जो कर के रूप में कम्पनी ने वहन की है, कर देगे, क्योंकि ऐसा आय-कर ऋणपत्रधारियों को प्राप्त हुई ऋण पत्रों से आय का भाग है।

कटौतियाँ—प्रतिभूतियों के ब्याज से प्राप्त होने वाली कर-योग्य आय की गणना के लिये निम्न कटौतियाँ (deductions) स्वीकार की जाती है,—

(1) ब्याज के संग्रह हेतु (for collecting of interest) किसी बैंकर द्वारा ऐसे ब्याज से काटी गई या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे ब्याज की वसूली के लिये पुरस्कार स्वरूप दी गई कोई उचित धन राशि।

(11) प्रतिभूतियों की खरीद के निमित्त विशेष रूप से उधार लिए हुए ऋण का ब्याज।

जब कर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदने के लिए ऋण लिया जाए तो ऐसे ऋण पर ब्याज कर-मुक्त प्रतिभूतियों के ब्याज से घटाना चाहिए।

यह भी सत्य है कि इस मद में हानि हो, क्योंकि ऐसे ऋण पर ब्याज ऐसी प्रतिभूतियों के ब्याज से बढ़ सकता है। ऐसी हानि दूसरे मद के अन्तर्गत आय से काटी जा सकती है।

प्रतिभूतियों के विक्रय पर होने वाला हानि-लाभ

जहाँ कर-दाता के पास प्रतिभूतियाँ विनियोग (Investment) के रूप में हों 'व्यापार सम्पत्ति' (Trading Asset) के रूप में नहीं, तो विनियोगों में परिवर्तन करने के उद्देश्य से उनको बेच देने पर जो हानि-लाभ हो वह पूर्ण हानि-लाभ होगा। दूसरी ओर जहाँ कर-दाता प्रतिभूतियाँ खरीदने और बेचने का व्यवसाय करता है, उस दशा में वह प्रतिभूतियों को अपने पास 'व्यापार सम्पत्ति' अर्थात् व्यापारिक स्कन्ध (Stock-in-trade) के रूप में रखता है और इन प्रतिभूतियों के बेचने से होने वाला हानि-लाभ आगम-हानि लाभ (Revenue Profit or loss) है। उसके व्यवसाय के हानि-लाभ की गणना करने के लिये, जो प्रतिभूतियाँ प्रत्येक हिस्साबी वर्ष की समाप्ति पर उसके पास रह जायें, उनका मूल्य व्यापारिक स्कन्ध के रूप में एक रूप आधार पर (On a Uniform basis) मापना चाहिये।

उद्गम स्थान पर कर की कटौती (Deduction of Tax at Source)

यह एक अगले अध्याय 'उद्गम स्थान पर कर-कटौती में सम्भाला गया है।

उदाहरण

(१) अ के विनियोग (Investments) ३१ मार्च १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में निम्न प्रकार थे —

(क) ४०,००० रु० ३½% सरकारी पेपर, (ख) २०,००० रु० ५% म्युनिस्पाल ऋण-पत्र, (ग) ६०,००० रु० ४½% पोर्ट ट्रस्ट बॉण्ड्स। उसके बैंक ने ब्याज संग्रह करने के लिये १० रु० बतौर कमीशन लिये। पोर्ट ट्रस्ट के बॉण्ड्स खरीदने के लिये उसने कर्जा लिया था। इस कर्ज का ब्याज में उसने ७०० रु० दिये। प्रतिभूतियों के ब्याज से प्राप्त होने वाली आय में कर योग्य आय निकालिये —

सभी विनियोगों की ब्याज	रु०	रु०
घटाया बैंक कमीशन	१०	४,१००
ऋण पर ब्याज	७००	७१०
प्रतिभूतियों के ब्याज से कर लगने योग्य आय		४,३९०

१,५०० रु० में से आय-कर उद्गम स्थान पर ३०% की दर से काटा जायगा।

(२) १ अप्रैल १९५८ को ब के विनियोग निम्न प्रकार थे —

(क) ६०,००० रु० ३½% सरकारी ऋण, (ख) ६०,००० रु० ३% पोर्ट ट्रस्ट बॉण्ड्स (ग) ८०,००० रु० ५% इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ऋण-पत्र, और (घ) ३०,००० रु० किसी इलेक्ट्रिक सप्लाय कंपनी के ५% ऋण-पत्र।

१ अगस्त १९५८ को, उसने २०,००० रु० ३% सरकारी बॉण्ड्स ६२½ व्या० रु०

(ब्याज सहित Cum Dividend or c d) पर खरीदे। इन पर १ जून और १ दिसम्बर को ब्याज प्राप्त होता है।

ब्याज सग्रह के लिए बैंक का कमीशन २५ रु० था। प्रतिभूतियों के ब्याज से होने वाली आय में कर लगने योग्य कितनी है ?

१ अप्रैल १९५८ को रखे हुये विनियोगों पर ब्याज	१०,०००
३ वर्ष के लिये ३% सरकारी बॉण्ड्स का ब्याज	३००
	१०,३००
घटाया बैंक कमीशन	२५
प्रतिभूतियों के ब्याज से होने वाली कर-योग्य आय	१०,२७५-

(३) १ अप्रैल १९५८ को स के विनियोग निम्न प्रकार थे —

(क) ६०,००० रु० ४% उ० प्र० सरकार को ऋण, (ख) ३०,००० रु० ५% इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, (ग) २०,००० रु० ५% जूट मिल कम्पनी ऋण-पत्र (घ) १५,००० रु० ६% प्रीफेस शेअर्स, एक शुगर मिल कम्पनी में।

१ सितम्बर १९५८ को उसने जूट मिल के ऋण-पत्र (debentures) बेच दिये और ४०,००० रु० ४% पोर्ट ट्रस्ट बॉण्ड खरीद लिये। इस कार्य के लिये उसने बैंक से ६% वार्षिक पर २०,००० रु० का ऋण लिया। प्रतिभूतियों के बेचने खरीदने में बैंक का कमीशन १% और ब्याज-सग्रह का कमीशन १५ रु० था। ब्याज से होने वाली आय में से कर लगने योग्य आय निकालिये। ब्याज १ जनवरी और १ जुलाई को मिलता है।

१ वर्ष के लिये ४% उ० प्र० ऋण का ब्याज	२,४००
१ वर्ष के लिये ५% इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ऋण-पत्रों का ब्याज	१,५००
३ वर्ष के लिये ४% जूट मिल ऋण-पत्रों का ब्याज	५००
३ वर्ष के लिये ४% पोर्ट ट्रस्ट बॉण्ड्स का ब्याज	८००
	५,२००

ब्याज-सग्रह या कमीशन घटाया	१५	
७ मास की बैंक से लिये ऋण की ब्याज	७००	७१५
प्रतिभूतियों के ब्याज की कर-योग्य आय		४,४८५

प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय के लिये बैंक का कमीशन नहीं घटाया जायगा। क्योंकि वह पूँजी-व्यय (Capital expenditure) है।

प्रतिभूतियाँ विनियोग के रूप में हैं, इसलिये जूट मिल के ऋण पत्रों के बेचने में हुए हानि लोभ-योगी विचार में नहीं लिया जायगा।

(४) एक हिन्दू अविभाज्य परिवार के पास ७% कर-मुक्त ५,००० रु० के एक बीनी मिल के ऋण-पत्र है उसकी प्रतिभूतियों से ब्याज से कर योग्य आय क्या होगी ?

हिन्दू अविभाज्य परिवार ने ३५० रु० कर-मुक्त ब्याज प्राप्त किया। कर-मुक्त ब्याज पर कम्पनी ने आय कर ३०% चुकाया है। इसलिए परिवार की प्रतिभूतियों से ब्याज की कर योग्य आय ५०० रु० (३५० रु० का १००/७० होगी)।

(३) जायदाद की आय (Income from Property) X

धारा ६ के अनुसार, आय-कर-दाता को अपनी जायदाद के वास्तविक वार्षिक मूल्य (Bonafide Annual Value) पर आय कर देना पड़ता है। जायदाद के अन्तर्गत मकानात और उससे लगी हुई जमीन समझी जाती है, जिसका कर-दाता स्वयं मालिक है। इसमें जायदाद के उस भाग को सम्मिलित नहीं किया जायगा, जिसे वह अपने व्यवसाय के लिये, जिसके लाभ पर कर लगता है, प्रयोग में लाता हो। इस मद के अन्तर्गत केवल जायदाद के स्वामी पर ही कर लग सकता है। यदि किसी व्यक्ति को किसी ऐसी जायदाद से आय होती हो, जो पट्टे पर उसके कब्जे में है, तो इस आय पर 'अन्य साधनों से प्राप्त आय' के अन्तर्गत आय-कर लगता है। इसी प्रकार उस जमीन से होने वाली आय पर जो मकान के साथ लगी हुई नहीं है, 'अन्य साधनों से प्राप्त आय' की भाँति ही कर लगेगा।

जबकि कर-दाता का वह मकान-जायदाद का भाग, जोकि व्यापार में प्रयोग किया जाता है, व्यापार के किसी कर्मचारी को किराए पर दे दिया जाए जिसका वहाँ पर रहना व्यापार के कुशल कार्य-कलाप के लिये आवश्यक है तो उस कर्मचारी से प्राप्त किराया व्यापार से आय के रूप में कर-देय होगा यह आय मकान जायदाद की आय नहीं मानी जायगी।

मकान-जायदाद से आय क्योंकि एक अलग मद है अतएव मकान-जायदाद से प्राप्त किराया किसी अन्य मद में नहीं ले जाया जा सकता चाहे वह मकान व्यापार के दौरान में किराए पर उठाया गया हो तथा वह किराया किसी व्यापारिक संस्था का लाभ ही हो।

वार्षिक मूल्य (Annual Value)

आय किसी तारीख विशेष को प्राप्त हुई या प्राप्य (due) मानी जाती है। किन्तु मकानातो के मामले में कर-योग्य आय मालूम करने की विधि दूसरी है। वह यह है कि कर लगने योग्य आय कुछ अनुमानित अंक (Gross Notional Figure) के द्वारा, जिसे वास्तविक वार्षिक मूल्य (Bonafide Annual Value) भी कहते हैं, मालूम की जाती है। यह जरूरी नहीं है कि ऐसा अंक वह धन हो जो किसी जायदाद के किराये में सचमुच में प्राप्त हो। वास्तविक वार्षिक मूल्य जायदाद का वह मूल्य है जिस पर वह किराये पर उठाई जा सकती है अर्थात् वह मूल्य जिस पर खुले बाजार में जायदाद किराये पर दी जा सकती है। म्यूनिसिपल शहरो में, जहाँ स्थानीय कर वास्तविक वार्षिक मूल्य के आधार पर समय-समय के मूल्यांकन (Periodical Valuation) द्वारा अदा किये जाते हैं, म्यूनिसिपलिटि द्वारा निर्धारित किये गये मूल्य की, आय-कर के उद्देश्य के लिये, वास्तविक वार्षिक मूल्य से तुलना की जा

सकती है। हाँ, जब वास्तविक रूप में प्राप्त हुए किराये म्यूनिसिपल मूल्यमूल्य से बहुत अधिक बैठते हो, तो ऐसी दशा में वास्तविक रूप में प्राप्त किराया ही वास्तविक वार्षिक मूल्य माना जायगा।

जायदाद का वार्षिक मूल्य निम्न समायोजन करने के बाद निकाला जायगा।—

(अ) जहाँ जायदाद किसी किरायेदार के पास है और उस पर स्थानीय सत्ता द्वारा लगाये गये कर (जिसमें सेवा कर जैसे पानी कर, कन्जर्वेंसी कर आदि सम्मिलित हैं) वसूल किये जाते हैं तो ऐसी दशा में वार्षिक मूल्य निश्चित करने के लिये ऐसे करो का आधा भाग काट दिया जायेगा। निम्न उदाहरण से यह स्पष्ट हो जायेगा कि इस नियम के अनुसार वार्षिक मूल्य किस प्रकार निर्धारित किया जाता है।

किरायेदार द्वारा दिया जाने वाला किराया ६,००० रु० वार्षिक है। जायदाद पर स्थानीय-करो की अदायगी में ६०० रु० दिए जाते हैं, जिसमें से २०० रु० किरायेदार, मकान मालिक को ६,००० रु० देने के अतिरिक्त, सीधे स्थानीय सत्ता को देता है। जायदाद का वापक मूल्य क्या होगा।

	रु०
मालिक को प्राप्त हुई किराये की रकम	६,०००
उसकी ओर से किरायेदार द्वारा दिये	
हुए स्थानीय करो की रकम	२००
कुल किराया जो प्राप्त हुआ	६,२००
घटाया स्थानीय करो का आधा	३००
वार्षिक मूल्य	<u>५,९००</u>

(ब) जहाँ जायदाद कर दाता के निजी निवास के लिए काम में आ रही हो, तो उस दशा में जायदाद का वार्षिक मूल्य पहले तो इस प्रकार निकाला जायगा कि मानो वह जायदाद किसी किरायेदार को उठा दी गई हो और जो रकम इस प्रकार निकले उसके आधे या १८०० रु०, दोनों में से जो कम हो, उसे घटा देते हैं। परन्तु यदि इस प्रकार घटाकर निकली रकम मालिक की कुल आय के १०% से अधिक बैठे तो जायदाद का वार्षिक मूल्य उसकी कुल आय का १०% मान लिया जायेगा। यदि जायदाद में केवल एक ही रहने का मकान है और उसे मकान मालिक, कहीं बाहर काम पर रहने के कारण, अपने रहने के लिए रखता है, जो खाली रहता है, तो इसका वार्षिक मूल्य कुछ भी नहीं होगा। किन्तु यदि इस मकान में साल भर में कुछ समय तक निवास किया गया है, तो इसका वार्षिक मूल्य अनुपातिक (proportionate) होगा। लेकिन किसी भी दशा में ऐसी जायदाद से हानि नहीं दिखाई जा सकती।

कटौतियाँ (Deductions)

जायदाद की कर लगने योग्य आय मालूम करने के लिये वार्षिक मूल्य में से निम्न-लिखित कटौतियाँ स्वीकृत की गई हैं—

(१) वार्षिक मूल्य का छठा भाग मरम्मत के लिये काट दिया जायेगा चाहे मरम्मत पर कुछ खर्चा हुआ हो या नहीं। यह छूट (Allowance) पूरी रकम से उस दशा में भी दी जावेगी जबकि जायदाद खाली पड़ी रहने के लिये कोई छूट (Allowance for vacancies) दी गई हो।

हाँ, जहाँ किरायेदार ने मरम्मत की लागत वहन करना स्वीकार कर लिया है वहाँ मरम्मत की छूट 'वार्षिक मूल्य' और 'चुकाये गये किराये' में अन्तर तक ही सीमित है लेकिन वह वार्षिक मूल्य के १/६ भाग से अधिक नहीं हो सकती। प्रस्तुत अध्याय में दिया गया अन्तिम उदाहरण इस बात पर प्रकाश डालता है।

(२) जायदाद को नुकसान पहुँचने के खतरो (risk) (जैसे, आग, भूकम्प, बिजली गिरने, गृह-युद्ध आदि) की हानि से बचाव के लिये कराये गये बीमो का प्रीमियम।

(३) जायदाद के रहन (mortgage) पर ब्याज या कोई अन्य पूँजी प्रभार जो जायदाद पर हो। धन किस उद्देश्य के लिये उधार लिया गया था यह विचारणीय न होगा। *धारा ८(१) 15*

(४) जायदाद पर कोई ऐसा वार्षिक भार (Annual charge) जो पूँजीगत भार नहीं है।

(५) जायदाद के खरीदने, बनवाने या मरम्मत कराने के लिए जो ऋण लिया गया है उसका ब्याज।

(६) यदि जायदाद की जमीन का कोई किराया दिया जाता है, तो ऐसे किराये की रकम। *धारा ८(१) 15*

(७) जायदाद पर दी जाने वाली किसी मालगुजारी (Land revenue) की रकम। *धारा ८(१) 15*

(८) संप्रहण व्यय, जो वार्षिक मूल्य या वास्तविक रकम (दोनों में जो कम हो) का ६% होगा। *धारा ८(१) 15*

(९) जायदाद खाली पड़े रहने के सम्बन्ध की छूट (Vacancy Allowance), जो वार्षिक मूल्य का वह भाग है जो जायदाद खाली पड़ी रहने की अवधि के अनुपात में हो। *धारा ८(१) 15*

यदि मिलने वाली छूटें (Admissible allowances) जायदाद के वार्षिक मूल्य से अधिक बैठें तो यह जायदाद से हानि हुई दूसरे शीर्षको के अन्तर्गत उसे होने वाली आय में से काटा जा सकता है।

जहा जायदाद सयुक्त स्वामित्व मे हो और इन स्वामियों के हिस्से निश्चित हो, तो उन पर व्यक्तियों के सघ (Association of persons) के रूप मे कर-निर्धारण नहीं होगा, बल्कि प्रत्येक मालिक के हिस्से पर उसकी कुल आय के अंश के रूप में कर लगेगा ।

कर-मुक्त जायदाद की आय (Exempted Property Income)–

निम्न प्रकार के मकान जायदाद से होने वाली आय-कर से मुक्त रखी गई है—

(१) वह मकान जो कृषि कार्य मे काम आने वाली भूमि के बिल्कुल निकट स्थित है और कृषि कार्यों की देखभाल के हेतु रहने के लिये आवश्यक हो ।

(२) कर-दाता द्वारा अपने व्यापार के लिये इस्तैमाल किया जाने वाला मकान या जायदाद, जिसके लाभो पर कर लगता हो ।

(३) वह मकान जो १ अप्रैल १९४६ और ३१ मार्च १९५६ की अवधि मे बनकर तैयार हुआ है और जिसे व्यापारिक कार्यों के लिए प्रयोग नहीं किया गया है, वह इस प्रकार तैयार हो जाने के बाद के दो कर-निर्धारण वर्षों (Assessment Years) के लिये आय-कर से मुक्त या ।

उदाहरण

(१) अ एक सरकारी दफ्तर मे बलक है । उसे २५० रु० मासिक वेतन मिलता है । उसके पास ४०,००० रु० ३% सरकारी प्रतिभूतियाँ है । वह एक बड़े मकान का मालिक भी है, जिसका म्युनिस्पल मूल्यांकन ८०० रु० है । इस मकान का एक तिहाई भाग उसने ३० रु० मासिक किराये पर उठा रखा है और शेष भाग को अपने इस्तैमाल मे रखा है । अपनी बहिन की शादी के लिये उसने कर्जा लिया था जिसके लिये मकान रेहन रखा है । कर्ज पर साल भर मे ३०० रु० ब्याज हुआ, मकान के सम्बन्ध मे १५० रु० म्युनिस्पल कर दिये गये ।

जायदाद की आय मे कर लगने योग्य आय निकालिये और यह भी बताइये कि ३१ मार्च १९५६ को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए उसकी कुल आय क्या है ?

	रु०	रु०
किराये पर उठे तिहाई भाग का किराया	३६०	
घटाया अनुपातिक म्युनिस्पल करो का एक तिहाई	<u>२५</u>	
किराये पर उठे मकान का वार्षिक मूल्य		३३५
स्वयं के इस्तैमाल में आने वाले भाग का मूल्य, जो उसी तरह निर्धारित किया गया है, जिस प्रकार कि किराये पर उठे भाग का	६७०	
घटाया उसका आधा (स्टेच्युटरी अलाउन्स)	<u>३३५</u>	<u>३३५</u>

जायदाद का ग्राँस वार्षिक मूल्य

घटाया १/६ मरम्मत के लिये	१११	
बन्धक का ब्याज	३००	४११
जायदाद से कर-योग्य आय		<u>२५६</u>
१ वेतन		३,०००
२ प्रतिभूतियों का ब्याज		१,४००
३ जायदाद से आय		<u>२५६</u>
कुल आय		<u>४,६५६</u>

मालिक द्वारा धरे हुये मकान का वार्षिक मूल्य उसी तरह निर्धारित किया जाता है, जिस तरह की किराये पर उठी हुई जायदाद का, और तब इस प्रकार निर्धारित की गई रकम में से उसका आधा या १,८०० रु० जो दोनों में कम हो, उसे घटा दिया जाता है लेकिन निज के निवास में काम आने वाली जायदाद का इस प्रकार निश्चित किया गया वार्षिक मूल्य जायदाद के मालिक की कुल आय के १०% से अधिक नहीं होना चाहिये ।

(२) कॉलेज के एक प्रोफेसर को ८०० रु० मासिक वेतन मिलता है । वह स्वीकृत प्राँवीडेण्ट फण्ड में अपने चन्दे का अपने वेतन का ६३% कटता है और कॉलेज की ओर से भी इतनी ही रकम उसके फण्ड में मिलाई जाती है । ३१ मार्च १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में प्राँवीडेण्ट फण्ड के हिसाब की ब्याज (४% वार्षिक से ६७२ रु० हुई ।

प्रोफेसर महोदय दो मकानों के भी मालिक है, जिनमें से एक (जिसका म्यूनिसिपल मूल्यांकन ८०० रु० है, वे अपने रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं और दूसरा (जिसका म्यूनिसिपल मूल्यांकन १००० रु० है) १०० रु० मासिक किराये पर उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति को उठा रखा है । दोनों मकानों पर उन्होंने जो खर्चे किये हैं, वे निम्न प्रकार हैं —

	रु०
म्यूनिसिपल कर	१८०
किराये पर उठाये गये मकान की माल-गुजारी (land revenue)	४०
अग्नि बीमा का प्रीमियम	१२०
अपने रहने वाले मकान की मरम्मत के निमित्त लिये कर्जे पर ब्याज	२००
अपने रहने के मकान में बिजली के फिटिंग को और कई स्थानों पर कराने का खर्चा	२५०

इन प्रोफेसर महोदय की जायदाद की आय में कर लगने योग्य प्राय, इनकी कुल आय और ३१ मार्च १९५६ को समाप्त होने वाले गत वर्ष के बिये करमुक्त आय बतलाई है । यह मान लीजिए कि किराये पर उठा मकान दो महीने खाली पड़ा रहा और १०,००० रु० के कराये हुए अपने जीवन बीमे पर (जो ८,००० रु० के लिये था) उन्हें ८५० रु० प्रीमियम के दिये ।

	₹०	₹०
किराये पर उठे मकान का किराया	१,२००	
घटाओ म्युनिस्पल कर का आधा (म्युनिस्पल मूल्यांकन के अनुसार)	५०	
किराये पर उठी जायदाद का वार्षिक मूल्य रहने के मकान का किराया मूल्य (म्युनिस्पल मूल्यांकन का ६/५, जैसा कि किराये पर उठी जायदाद के सम्बन्ध में होना है)	६६०	११५०
घटाया म्युनिस्पल कर का आधा	४०	
	६२०	
घटाया आधा (स्टेच्युटरी अलाउन्स)	४६०	४६०
दोनों मकानों का वार्षिक मूल्य		१,६१०
घटाया १/६ मरम्मत के लिये	२६६	
मालगुजारी	४०	
ऋण पर ब्याज	२००	
अग्नि बीमा प्रीमियम	१२०	
खाली पड़े रहने की छूट जो किराये पर		
• उठे मकान में वार्षिक मूल्य का १/६ है	१६१	८१६
जायदाद से कर योग्य आय		७६१
१ वेतन		६,६००
२ जायदाद से कर योग्य आय		७६१
कुल आय		१०,३६१

आयकर से मुक्त आय

१ प्रा० फण्ड में स्वयं का चन्दा	६००
२ जीवन बीमा प्रीमियम (बीमे के १०% तक तथा प्रीमियम और प्रा० फण्ड चन्दे दोनों मिलाकर कुल आय के चौथे भाग तक सीमित)	८००
	१४००

प्रा० फण्ड में मालिक का चन्दा जो कि कर्मचारी के वेतन के १०% से कम है तथा प्रा० फण्ड खाते पर ब्याज जो कि कर्मचारी के वेतन के एक तिहाई से तथा ६% प्र० वर्ष से कम है कुल आय में सम्मिलित नहीं होगा।

बिजली फिटिंग विस्तार व्यय पूँजी व्यय है जो जायदाद से कर योग्य आय मालूम करने के लिए नहीं घटाया जायेगा।

(३) X एक मकान का, जिसका वार्षिक मूल्य ८,००० ₹० है, स्वामी है। उसने इसे Y को ७,००० ₹० वार्षिक पर उठा दिया है। Y मरम्मत की लागत स्वयं उठाने को तैयार हो जाता है। मकान के सम्बन्ध में X के छूट योग्य (admissible) खर्च, मरम्मत-व्ययों को छोड़ते हुए २,५०० ₹० हुए। इस मकान की कर-योग्य आय क्या है ?

यदि मकान को ६००० रु० में उठाया जाता, तो क्या अन्तर पड़ता ?

जहाँ किरायेदार मरम्मत व्यय स्वयं वहन करने को तैयार हो गया है, वहाँ मरम्मत की छूट वार्षिक मूल्य और चुकाये गये किराये के अन्तर तक सीमित है लेकिन वार्षिक मूल्य के १/६ से अधिक नहीं हो सकती। इस नियम के अनुसार, प्रश्न में वर्णित मकान की कर-योग्य आय इस प्रकार होगी —

वार्षिक मूल्य	रु०
घटाओ.—मरम्मत के लिये छूट, जो	८,०००
वार्षिक मूल्य और चुकाये गये	
किराये का अन्तर है, और	
वार्षिक मूल्य के १/६ से	
अधिक नहीं है।	१,०००
'अन्य व्यय	२,५००
कर योग्य आय	<u>४,५००</u>

अथवा

वार्षिक मूल्य	रु०
घटाओ — मरम्मत के लिये छूट जो कि	८,०००
वार्षिक मूल्य और चुकाये गये	
किराये का अन्तर है लेकिन	
वार्षिक मूल्य के १/६ तक	
सीमित है	१,३३३
अन्य व्यय	२,५००
कर योग्य आय	<u>४,१६७</u>

(४) व्यापार, पेशा अथवा व्यवसाय के लाभ

(Profits of Business, Profession or Vocation)

व्यापार में कोई भी वाणिज्य (Trade), लेन-देन (Commerce) या वस्तु उत्पादन अथवा अन्य कोई भी प्रयत्न, जो वाणिज्य, व्यापार या वस्तु-उत्पादन की प्रकृति का हो, शामिल है। इसका अर्थ यह हुआ कि एकाकी सौदे (isolated transaction) के लाभ भी, यदि वह एक वाणिज्य सम्बन्धी प्रयत्न है, कर लगने योग्य होंगे। पेशा वह है जिसमें साधारणतः दिमागी योग्यता की आवश्यकता होती है, जैसे कोई डाक्टर, इंजीनियर, वकील या लेखपाल आदि। व्यवसाय (Vocation) से अभिप्राय किसी अन्य काम से है, जो कोई व्यक्ति अपनी जीविका उपाजन के लिए करे, जैसे कोई दलाल, बीमा एजेंट, गायक, चोर आदि।

धारा १० के अन्तर्गत, करदाता को अपने व्यापार, व्यवसाय या पेशे के लाभों पर कर देना पड़ेगा। इस शीर्षक के अन्तर्गत कर लगने योग्य आय निर्धारित करने के निम्नलिखित नियम हैं :—

(१) एक “व्यक्ति” (individual) ही जो कि कोई व्यापार चलाता है, इस शीर्षक के अन्तर्गत कर चुकाने के लिए दायी है। व्यापार के स्वामित्व की बात का महत्व नहीं अपितु करदाता द्वारा उसका चलाया जाना महत्वपूर्ण है। हाँ, यह आवश्यक नहीं है कि करदाता भौतिक रूप से (Physically) या अपने ही हाथों से व्यापार को चलावे। ‘व्यापार चलाने का अधिकार’ मात्र ही पर्याप्त है।

(२) इस धारा के अन्तर्गत कर प्रत्येक पृथक् व्यापार के लाभों पर अलग-अलग नहीं अपितु करदाता द्वारा चलाये जाने वाले सभी व्यापारों के सम्पूर्ण लाभ पर इकट्ठा लगाया जाता है। इसका यह अर्थ है कि जहाँ करदाता दो या अधिक व्यापार चलाता है, वहाँ वह एक की हानि को दूसरे के लाभ से पूरी कर सकता है (set off losses)।

(३) यह आवश्यक है कि व्यापार, व्यवसाय अथवा पेशा गतवर्ष के दौरान में ही किसी भी समय तक चलाया जावे, भले ही पूरे वर्ष न चला हो। जब गतवर्ष में व्यापार बिल्कुल ही नहीं चलाया गया है तो व्यापार या व्यवसाय के समापन में उत्पन्न हुआ लाभ, जो कि केवल सम्पत्ति बेचने से प्राप्त हो, कर-योग्य (Taxable) नहीं होता।

(४) आय कर के आशय के लिये, प्रत्येक वर्ष अपने में 'पूर्ण' हिसाबी वर्ष होता है और आय-कर अधिकारी केवल उस वर्ष में हुई आय को ही विचार में ले सकते हैं, भारी लाभ या हानियाँ नहीं ।

(५) यदि किसी पिछले कर-निर्धारण वर्ष में कर दाता को किसी हानि, व्यय या दायित्व के सम्बन्ध में कोई छूट दी गई है और बाद को कर दाता ने ऐसी हानि, व्यय या व्यापारिक दायित्व के सम्बन्ध में भुगतान, हर्जाना या क्षति प्राप्त कर ली हो, तो ऐसी प्राप्ति की रकम उस वर्ष का लाभ माना जायगा, जिसमें कि वह इस प्रकार प्राप्त हुई ।

(६) एजेन्सी की समाप्ति के लिये प्राप्त हुई क्षति-पूर्ति उस वर्ष का लाभ मानी जायगी जिसमें वह प्राप्त हुई ।

व्यापार, व्यवसाय या पेशे से होने वाला लाभ, आय-कर की दृष्टि से, वही लाभ नहीं होता जो कर-दाता अपने हिसाब की किताबों में दिखाये । कुछ खर्चों की मदें, जिनका लाभ कमाने से सम्बन्ध नहीं है, अस्वीकृत कर दी जाती है । ह्रास सम्बन्धी छूट नियमों के अनुसार दी जाती है । पूँजी प्राप्तियाँ और पूँजी व्यय भी निकाल दिये जाते हैं तथा वे खर्च, जो व्यक्तिगत हैं अथवा दान-पुण्य के लिए हुए हैं, स्वीकार नहीं किये जाते । हिसाब की किताबों में दिखाये गये लाभ के अको से कर योग्य लाभ की रकम निकालने से पहले इन सब मदों के सम्बन्ध में आवश्यक सुधार (Adjustment) कर लेना चाहिये ।

कटौतियाँ (Deductions)

धारा १० के अनुसार जो कर लगाया जाता है, यह व्यापार, व्यवसाय या पेशे की सकल प्राप्तियों (Gross receipts) पर नहीं अपितु इनके लाभ पर लगता है । लाभ क्या है, इसकी सन्नियम में कोई परिभाषा नहीं की गई है । किन्तु आय-कर अधिनियम की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुये, व्यापारिक लेखाकर्म (Commercial accounting) के सिद्धान्तों पर ही लाभों को निश्चित किया जाता है । किसी व्यापार व्यवसाय या पेशे के कर लगाने योग्य लाभ मालूम करने के लिए कुछ सामान्य सिद्धान्त नीचे दिये जाते हैं :—

(१) आय कर-दाता द्वारा नियमित रूप से हिसाब-किताब रखने की जिस विधि का अनुसरण किया गया हो, उसी के अनुसार लाभ निकालना चाहिए । हाँ, इस विधि से वास्तविक लाभ (True Profits) निकालना सम्भव होना चाहिये । लेखाकर्म सम्बन्धी विभिन्न ढंग इस अध्याय में आगे समझाये गये हैं ।

(२) उन खर्चों को, जिनकी छूट स्पष्ट दे दी गई है, सकल प्राप्तियों में से घटा देना चाहिए, किन्तु अस्वीकृत खर्चों को इस प्रकार नहीं घटाना चाहिए ।

(३) कुछ अत्यावश्यक खर्च, जिन्हे न तो स्पष्टतः स्वीकृत किया गया है और न अस्वीकृत ही, और व्यापारिक हानियाँ (भले ही वे स्पष्टतः स्वीकृत न की गई हों) भी सकल प्राप्तियों में से घटा देनी चाहिए बशर्तें ये खर्च और हानियाँ वास्तविक रूप में व्यापार से सम्बन्धित (Incidental to trade) हों ।

(४) कटौतियाँ केवल उन्हीं खर्चों और नुकसानो के लिये स्वीकृत की जा सकती हैं, जो सम्बन्धित हिसाबी वर्ष (Relevant accounting year) में हुए हों । किसी वर्ष विशेष का कर लगने योग्य लाभ मालूम करने के लिए, उसके पूर्व अथवा बाद के वर्ष में किये गये खर्च या कमाये हुए लाभ से कोई मतलब नहीं होता ।

(५) हिसाबी वर्ष के शुरू होने के पूर्व बन्द हुए किसी व्यापार से सम्बन्धित किसी दूसरे पृथक रूप से चालू व्यापार के लाभ में से नहीं घटाये जा सकते । उस बन्द हुए व्यापार के खर्च पूँजी हानि हो जाते हैं ।

(६) किसी व्यापार के लाभो की गणना करते समय, सट्टे की हानियाँ केवल सट्टे के लाभो से पूरी की जा सकती हैं । जहाँ सट्टे के व्यवहार व्यापार के रूप में किये जाते हैं तो यह व्यापार अन्य व्यापारो से बिल्कुल पृथक समझा जावेगा ।

एक सट्टे के व्यवहार का अर्थ ऐसे व्यवहार का है जिसमें किसी वस्तु (स्टॉक एवं शेयर्स शामिल करते हुए) की खरीद बिक्री का अनुबन्ध बिना वस्तु या प्रलेख की वास्तविक सुपुर्दगी या हस्तांतरण हुए निबटा दिया जाता है । विभिन्न वस्तुओं में या विभिन्न बाजारों में सट्टे के व्यवहार एक माने जाते हैं ।

“हैजिंग कन्ट्रैक्ट” (Hedging Contract) सट्टा नहीं माना जाता ।

स्पष्ट स्वीकृत कटौतियाँ (Deductions expressly allowed)

धारा १० (२) के खण्ड (i) से (XV) तक में वे विभिन्न कटौतियाँ दी हुई हैं, जिन्हे स्पष्टतः स्वीकार किया गया है । वे व्यापारिक खर्च जो दूसरे खण्डों में नहीं आते, खण्ड (XV) में आ जाते हैं । ये छूटें (Allowances) निम्न प्रकार हैं —

(१) उस भवन या स्थान (Premises) का किराया, जहाँ व्यापार चलाया जाता है । यदि उस भवन या स्थान का काफी भाग कर-दाता अपने रहने के काम में लाता है, तो केवल किराये की अनुपातिक रकम ही व्यापारिक व्यय के नाते कम की जायगी । यदि कोई फर्म किसी सार्वजनिक को, उसका मकान या स्थान इस्तेमाल में लेने के लिए, किराया देती है, तो यह किराया फर्म के लाभ में से घटा दिया जायगा ।

(२) उस स्थान या भवन की मरम्मत का खर्चा, जिसमें कर-दाता किरायेदार को रक्कम में रहता है और जिसकी मरम्मत के खर्च का उसने दायित्व ले रखा है । यदि स्थान या मकान का काफी भाग कर-दाता अपने निवास के लिए इस्तेमाल में लाता

है, तो केवल मरम्मत के खर्चों का अनुपातिक भाग ही व्यापारिक व्यय के रूप में कम किया जायगा ।

(३) व्यापार के लिए उधार ली हुई पूँजी का ब्याज, किन्तु वह ब्याज, जो किसी परदेही को दी गई है और जिसमें से उच्चतम दर में आय-कर नहीं काटा गया है नहीं घटायी जायगी । कम द्वारा किसी साझीदार को उसकी पूँजी या ऋण पर दी गई ब्याज भी नहीं घटायी जायगी ।

(४) व्यापार के काम में आने वाले भवन, गोदाम, मशीनरी, सयन्त्र, फर्नीचर, सक्न्ध अथवा स्टोर्स की हानि या नष्ट के खतरे (Risk) के लिए बीमा कुराने की बीमा किस्त (Premium) ।

(५) व्यापार के काम में आने वाले मकान, मशीनरी, फर्नीचर एवं सयन्त्र के सम्बन्ध में चालू मरम्मत (Current repairs) का खर्चा । चालू मरम्मत से अभिप्राय उस मरम्मत से है जो इन वस्तुओं को काम योग्य (Serviceable) स्थिति में बनाये रखने के लिए जिसकी आवश्यकता साधारण घिसन एवं टूट-फूट के कारण पड़ जाती है, थोड़े-थोड़े समय पर करानी पड़े । इसमें पुर्जों के मामूली परिवर्तन का व्यय भी शामिल किया जा सकता है, बशर्त वह ऐसी व्यापक प्रकृति का न हो कि उनसे उस वस्तु का रूप (Identity) ही बदल जाय ।

(६) व्यापार के काम में आने वाले भवन, मशीनरी, प्लाट, फर्नीचर का ह्रास । यह प्रसंग अगले अध्याय में विस्तार से समझाया गया है ।

(७) ह्रास की पूरी छूट प्राप्त होने से पूर्व किसी भवन, मशीनरी या प्लाट के बेचने पर हुई हानि । इस पर भी आगामी अध्याय में प्रकाश डाला गया है ।

(८) व्यापार के काम में आने वाले मृतक या बेकार जानवरो को बेच देने पर हुई हानि

(९) व्यापारिक स्थान के ऐसे भाग के सम्बन्ध में मालगुजारी, स्थानीय महसूल या म्यूनिसिपल कर, जो व्यापार के काम में आता हो ।

(१०) कर्मचारियों को दिया गया बोनस या कमीशन, बशर्त उसकी रकम उचित हो ।

(११) डूबे ऋण की रकम (Bad Debts), जहाँ हिसाब किताब व्यापारिक लेखा-कर्म के सिद्धान्तानुसार रखा जाता हो । लेकिन छूट की रकम उस रकम से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो आय-कर-दाता ने वास्तव में अपने हिसाब-किताब में अपलिखित (written off) की है । यदि कर-दाता को प्राप्य ऋण (Debt due to the assessee) व्यापार के लिये आकस्मिक (incidental) नहीं है, (जैसे किसी व्यापारिक दूरदर्शिता के विचार से किसी ग्राहक को दिया गया कोई ऋण) तो उस पर छूट नहीं मिल सकेगी । यदि

द्वे ऋण की रकम, जिसे एक वर्ष छूट दे दी गई हो, किसी दूसरे वर्ष वसूल हो जाय, तो वह उस वर्ष का कर योग्य लाभ मानी जायगी ।

(१२) व्यापार से सम्बन्धित किसी वैज्ञानिक खोज पर किया गया कोई रेवेन्यू व्यय ।

(१३) किसी वैज्ञानिक खोज करने वाली संस्था को दिया गया चन्दा, जो व्यापार से सम्बन्धित अनुसंधान कार्य करती हो ।

(१४) वह सारा पूँजी व्यय, जो व्यापार से सम्बन्धित किसी वैज्ञानिक अनुसंधान पर किया गया हो, लगातार और बराबर की किस्तों में व्यय करने के वर्ष से आगामी पाँच वर्षों तक घटाने दिया जायगा ।

(१५) अन्य व्यापारिक व्यय, जो पूँजीगत या व्यक्तिगत न हो, और पूर्णतः तथा मूल रूप से व्यापारिक कार्यों के लिये किये जावे । इसमें व्यापार के अधिकांश खर्च आ जाते हैं । कोई व्यय विशेष पूर्णतया और मूलरूप से लाभ पैदा करने की दृष्टि से ही किया गया है या नहीं, यह बात प्रत्येक मामले में व्यापार के स्वरूप, व्यापारिक पद्धति, व्यय के स्वरूप तथा अन्य परिस्थितियों पर निर्भर रहती है । इसलिये इस खण्ड (clause) के अन्तर्गत क्या आता है और क्या नहीं आता, यह गिनाना बड़ा ही कठिन है । इस शीषक के अन्तर्गत घटाये जाने वाले खर्चों के निम्नलिखित उदाहरण हैं ।—

(१) माल तैयार करने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने और उसे बेचने में हुआ खर्चा ।

(२) विज्ञान व्यय, यदि वह साधारण रूप से माल बेचते हुये किया गया हो । किन्तु यदि व्यापार को बढ़ाने की दृष्टि से विशेष रूप से विज्ञापन किया गया हो, तो इसमें हुआ व्यय पूँजी व्यय के रूप में माना जायगा और घटाया नहीं जायगा ।

(३) व्यापार का हिसाब तैयार कराने और उसे ऑडिट कराने के लिए प्रतिवर्ष होने वाला व्यय, जिसमें कर-दाता का आय-कर दायित्व निश्चित कराने का व्यय भी शामिल है । किन्तु आय-कर की अपील से सम्बन्धित व्यय की छूट नहीं दी जा सकती ।

(४) माल बिकवाने के लिए या ऑर्डर प्राप्त करने के लिए दी हुई दलाली या कमीशन घटाया जाता है । किन्तु यदि कमीशन या दलाली ऋण लेने या पूँजी प्राप्त करने के लिए दी गई है, तो उस पर छूट नहीं मिलेगी ।

(५) खान के काम (mining), कॉपीराइट और पेटेंट के लिए दी गई रॉयल्टी ।

(६) कर्मचारियों की दुर्घटना के सम्बन्ध में चुकाए गए बीमों का प्रीमियम या व्यापार की हानि के विरुद्ध कराए हुये बीमों का प्रीमियम ।

(७) चोरी या रुपया गबन हो जाने से व्यापार को हुई हानियाँ, बशर्ते कि वे या तो व्यापार से सम्बन्धित (incidental) हो या व्यापारिक स्कन्ध की हानियाँ हो ।

(८) कर्मचारी को क्षति-पूर्ति के रूप में दी गई रकम, बशर्ते वह रकम उपहार (gift) के रूप में न दी गई हो ।

(९) दिवाली अथवा मुहूर्त या हिसाब चालू करने के वार्षिक दिन के उत्सव में पुरस्कार आदि तथा अन्य खर्चों की रकम । लेकिन यह रकम अधिक से अधिक २०० रु० तक हो सकती है ।

(१०) किसी व्यापारिक सस्था द्वारा दिये गये चन्दे यदि इन्हे देना अनिवार्य हो या जो व्यापारिक दूरदेशी के विचार से जरूरी और देने वाले को लाभप्रद हो ।

(११) कर्मचारियों को उनकी सेवायें बनाये रखने या कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिये पेंशन, ग्रेच्युटी तथा स्वेच्छा से दिये गए अन्य भुगतान ।

(१२) कानूनी व्यय जिन्हे करदाता व्यापारी की हैसियत से अर्थात् जब वह व्यवहार, जिसके सम्बन्ध में कानूनी कार्यवाहियाँ की गई हैं, करदाता के व्यापार व्यवसाय से सम्बन्धित (incidental) हो ।

स्पष्टतः अस्वीकृत व्यय (Expenditure expressly disallowed)

किसी व्यापार, व्यवसाय या पेशे से कर लगने योग्य लाभ मान्य करते समय, निम्नलिखित खर्चे स्पष्टतः अस्वीकृत कर दिये गए हैं —

(१) किसी परदेशी

इसमें से कर न काटा गया हो ।

(२) किसी फर्म द्वारा फर्म के साभोदार को दी हुई कोई ब्याज, वेतन, कमीशन या पुरस्कार । लेकिन साभोदारो को दी गई अन्य रकमों का निषेध नहीं है, जैसे किराया, जो फर्म के किसी साभोदार को, जो किसी भवन या स्थान का स्वामी है जिसमें कि फर्म का कारोबार होता है, चुकाया जाय तो वह काटा जा सकता है । 10(u) B

(३) प्राइवेट प्रांवीडेण्ट फण्ड या कर्मचारियों के हितार्थ रखे गये अन्य किसी फण्ड में दिया हुआ चन्दा भी नहीं घटाया जायगा जब तक कि ऐसी दी हुई रकमों पर कर न काट लिया गया हो ।

(४) कम्पनी द्वारा अपने किसी संचालक को या ऐसे व्यक्ति को, जो कि कम्पनी में समुचित (substantial) हित रखता हो, दिया गया अत्यधिक पुरस्कार, लाभ या सुविधा ।

(५) किसी कम्पनी की सम्पत्तियों के सम्बन्ध में, जो कि उपर्युक्त व्यक्तियों द्वारा पूर्णतः या अंशतः अपने निजी कार्यों के लिये प्रयोग की जाती हो, दिया गया अत्यधिक (Excessive) अलाउन्स ।

(६) मालिक या साभोदारो द्वारा निकाली गई रकमें (drawings) ।

(७) मालिको के निजी या व्यक्तिगत खर्चें ।

(८) सदिग्ध ऋण कोष या अन्य कोष ।

(९) दान-पुण्य के रूप में किये गये खर्चें ।

(१०) आय-कर, अतिरिक्त कर (Super tax) और आय पर लगे अन्य कर । किन्तु बिक्री कर की रकम घटायी जा सकेगी ।

(११) पूँजी प्रकृति के खर्चें । हाँ, जिस पूँजी व्यय को लाभ में से काटे जाने की स्वीकृति नहीं दी गई है, उसे ह्रास सम्बन्धी छूट पाने का अधिकार है ।

(१२) किसी मकान जायदाद का किराया (Rental value) जो व्यापार के स्वामित्व में हो और व्यापार के प्रयोग में आती हो ।

(१३) लाभ-हानि खाते में चार्ज की गई पिछली हानियाँ ।

(१४) स्वीकृत रकम से ह्रास का आधिक्य ।

(१५) अन्य खर्चें, जो पूर्णतः व्यापार के लिए नहीं किये गये, उदाहरणार्थ कर्मचारियों को, कर बचाने के लिये चुकाया गया अधिक पुरस्कार (Excessive remuneration) ।

लाभ-हानि खाते से आय छूट जाना (Omission of Income From P & L Account)

यदि कोई आय किसी व्यापार के हानि-लाभ खाते में दिखाई न गई हो (जैसे, मजदूरी की वे रकमें जो कर्मचारियों द्वारा नहीं ली गयी और जो सीधे कर्मचारियों के कल्याण कार्यों के फण्ड में जमा कर दी गयी हो अथवा कोई कमीशन कोष जो बिक्री खाते को नाम (Debit) करके बने) तो ऐसी आय व्यापार की कर लगने योग्य आय में शामिल की जानी चाहिये । दूसरी ओर, हानि लाभ खाने में जमा की गई ऐसी आय, जिस पर कर नहीं लगता है, कर लगने योग्य आय में से निकाल देनी चाहिये ।

लाभ-हानि खाते से व्यय छूट जाना

(Omission of Expenditure from Profit and Loss Account)

यदि लाभ-हानि खाते को कुछ स्वीकृत व्यापारिक व्ययों (admissible business expenditure) से नाम (Debit) करना छोड़ (omit) गये हैं, लेकिन किसी रिजर्व खाते से काट लिया है (जैसे, डूबा ऋण 'सदिग्ध ऋण कोष खाते' से या श्रम-कल्याण सम्बन्धी व्यय 'श्रम कल्याण फण्ड' से काट लिया गया हो), तो कर-योग्य व्यापारिक लाभों की गणना करते समय ऐसे व्यापारिक व्ययों को घटा देना चाहिये ।

कैश क्रेडिट्स (Cash Credits)

कुछ बेईमान करदाता लाभ को छिपाने की गरज से व्यक्तिगत खाते में झूठी जमाये दिखा देते हैं। किसी व्यक्तिगत खाते में दिखाई गई कोई ऐसी रकम (विशेषकर यदि वह किसी महिला रिश्तेदार की हो, जब तक कि करदाता भली प्रकार और सतोषजनक रूप से उसे समझा न दे, छिपायी हुई आय समझी जाती है और उसे कर-योग्य लाभ में सम्मिलित किया जायगा।

स्कन्ध का मूल्यांकन (Valuation of Stock)

व्यापार के लाभ निकालने में स्कन्ध के मूल्यांकन का प्रश्न भी उपस्थित होता है। यह शायद ही कभी हो कि साल भर में खरीदा हुआ माल कोई व्यापारी सारे का सारा बेच डाले। इसलिये वर्ष का हानि-लाभ निकालने के लिए न केवल बिक्री को अपितु स्कन्ध के रूप में बच रहने वाले माल, साल भर की खरीद की लागत, पिछले वर्ष के हिसाब से आगे लाये हुये माल का मूल्य भी विचार में लेना जरूरी है।

व्यापारिक स्कन्ध (Stock-in hand) का मूल्य किसी भी प्रकार स्थिर किया जा सकता है। व्यापारिक हिसाब-किताब की प्रचलित पद्धति के अनुसार स्कन्ध का मूल्य लागत के हिसाब से, बाजार मूल्य में या लागत का बाजार मूल्य—इनमें जो भी कम हो उसके हिसाब से स्थिर किया जाता है। आय कर सन्धियम में ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है जो स्कन्ध के मूल्यांकन का कोई विशेष ढंग निर्धारित करना हो। इसलिए यह आवश्यक है कि इस प्रकार के मूल्यांकन के लिए जिस पद्धति का एक बार अनुसरण किया जा चुका है, आने वाले वर्षों के लिए भी उसी का प्रयोग किया जाय। स्कन्ध के मूल्यांकन की पद्धति में यदि कोई परिवर्तन करना है, तो वह इनकम टैक्स आफिसर की स्वीकृति से ही किया जा सकता है।

चाय कम्पनियाँ

भारतवर्ष में पैदा और तैयार की गई चाय के बेचने से हुई आय भी व्यापार से हुई आय मानी गई है। किन्तु इस आय की केवल ४० प्रतिशत आय ही आय-कर लगने योग्य समझी जाती है। शेष ६० प्रतिशत आय को कृषि आय मानते हैं।

चीनी बनाने वाली मिल कम्पनियाँ

जो चीनी मिल कम्पनियाँ अपने कृषि फार्म रखती हैं और कारखानों में उपयोग के लिये गन्ना उपजाती हैं, वे व्यापार से कर-योग्य आय निकालते समय, किसी कृषि पैदावार (विशेषकर गन्ना) की कीमत को, जो वह पैदा करे और कच्चे माल के रूप में अपने कारखानों के लिए काम में लावें, बाजार भाव से लाभ-हानि खाते के नाम में

दिखा सकती है। किन्तु काश्त में किए गये अन्य खर्च इसमें नहीं दिखाये जा सकेंगे। इस प्रकार फार्म से प्राप्त हुई कृषि आय कर लगने योग्य आय में शामिल नहीं की जाती।

तेल कम्पनियों (Oil Companies) के लाभ

भारत सरकार ने एक तेल कम्पनी के साथ खनिज तेल निकालने के लिए सविदा किया है। इस सविदे के अनुसार सरकार ने कुछ विशेष छूटें दी हैं।

धारा १० (२ AA) के अनुसार ऐसी कम्पनियों के कर-देय आय निकालने के लिये इस सविदे में दी गई छूटें निकाली जायेंगी।

लेकिन ऐसी कम्पनी को धारा १५ C की छूटें नहीं मिलेंगी।

उदाहरण

(१) एक व्यापारी के (३१ दिसम्बर १९५८ को समाप्त हुए वर्ष के लिये) हानि लाभ के निम्न खाते से १९५९-६० के कर-निर्धारण वर्ष के कर लगने योग्य लाभ बताइये और साथ ही उसकी कुल आय भी निकालिए —

	₹०		₹०
कार्यालय सम्बन्धी केतन	४,८००	सकल लाभ (Gross Profit)	३५,५३२
सामान्य खर्च	२,५५०	कमीशन	१,२०५
हूबे ऋण की अपलिखित रकम	२,१००	छूटें (Discounts)	७५१
सदस्य ऋण कोष	३,०००	विविध प्राप्ति	५२
अग्नि बीमा प्रीमियम	४५०	हूबे ऋण की रकमें जो बाद में प्राप्त हो गई	१५०
विज्ञापन	२,५००	सरकारी प्रतिभूतियों पर —	
आय-कर	२,३७५	ब्याज (शुद्ध)	२,८००
पूँजी पर ब्याज	१,०००	विनियोगों की बिक्री पर लाभ —	२,८४०
बैंक ऋण पर ब्याज	१,५५०		
बिल्डिंग (अबीमित) में			
आग लगने से हानि	१,५००		
ह्रास	१,२००		
शुद्ध लाभ	२०,३०५		
	<u>४३,३३०</u>		<u>४३,३३०</u>

सामान्य खर्चों में एक स्वीकृत शिक्षण संस्था को मार्च १९५८ में दी हुई ५०० रु० दान की रकम भी शामिल है। बिल्डिंग और फर्नीचर के लिये स्वीकृत ह्रास की रकम १,००० रु० है। विज्ञापन व्यय में १,५०० रु० की वह रकम शामिल है जो दुकान पर स्थायी रूप से लगाए गये चिह्न का खर्चा है।

लाभ—हानि-लाभ खाते से
जोड़ो—खर्च जो स्वीकृत नहीं है —
स्वीकृत संस्था को दान

₹०
२०,३०५

सदिग्ध ऋण कोष	३,०००	
विज्ञापन व्यय जो पूँजीगत व्यय है	१,५००	
आयकर	२,३७५	
पूँजी पर ब्याज	१,०००	
बिल्डिंग की हानि, जो पूँजीगत हानि है	१,५००	
ह्रास का आधिक्य	२००	
		१०,०७५
		३०,३८०

घटाओ—प्रतिभूतियों पर ब्याज (अलग मानते हुए)	२,८००	
विनियोगों की बिक्री से लाभ (जो पूँजी लाभ मान लिया है)	२,८४०	५,६४०
कर लगने योग्य लाभ		२४,७४०

१ प्रातिभूतियों पर ब्याज (यह मानते हुए कि १,२०० रु० आयकर उद्गम स्थान पर ही काट लिया गया)	४,०००
२ व्यापार का लाभ	२४,७४०
कुल आय	२८,७४०

स्वीकृत सस्था को दी हुई ५०० रु० दान की रकम कुल आय में शामिल करनी पड़ेगी, लेकिन आय-कर और अतिरिक्त-कर की छूट (Rebate) कर की औसत दर से दी जायगी।

(२) नीचे एक लिमिटेड कम्पनी का ३१ दिसम्बर, १९५८ को समाप्त हुए वर्ष का हानि-लाभ खाता दिया जाता है—

	रु०		रु०
कॉटन खाता	५७,०८,९७५	सूत खाता	५४,०५,९७८
स्टोर्स खाता	९,१७,८२४	कपडा खाता	४८,१२,०५६
मजदूरी और वेतन	१९,१५,९९२	क्षय (waste) खाता	६०,७५४
सामान्य खर्च	१४,५०४	ट्रांसफर फीस	३,१०८
दान	५,०००	बगलो और चौलो (chawls) का किराया	२८,९५१
महसूल और बीमा	२०,१८८	सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज	१३,७००
दलाली	३,८६२	विविध प्राप्तियाँ	३,०००
कार्यालय व्यय	१,२०,३४७		
संचालको की फीस	४,५००		
अकेक्षण व्यय	२,५००		
अनुसंधान सम्बन्धी व्यय	६०,०००		
ब्याज	१,०५,९२५		
बिल्डिंग और मशीनरी की मरम्मत	६२,२७८		
कानूनी खर्च	२,८६५		

मजदूरो के कल्याणार्थ व्यय	२७,५६२
कर्मचारियों के प्रो० फण्ड	
(स्वीकृत) में चन्दे	३७,५००
मैनेजिंग एजेंट्स का कमीशन	१,००,८४५
लाभ (ह्रास कटेगा)	१२,१६,८५०

१,०३,२७,५४७

१,०३,२७,५४७

निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त कम्पनी के १९५८ के वर्ष के लिये कर लगने योग्य लाभ तथा इसकी कुल आय बताइए —

(अ) दलाली की रकम में से २,७०० रु० काटन तथा स्टोस खरीदने में दिये गये और शेष कम्पनी व्यापार के हेतु ऋण प्राप्त करने में दिया गया ।

✓(ब) महसूल के १,८०० रु०, बीमे के १,२५० रु० और बिल्डिंग की मरम्मत के २,८७२ रु० के खर्चे कर्मचारियों को किराये पर दिये हुए बगलो और चोलो के सम्बन्ध में किये गये थे ।

✓(स) ६५० रु० का कानूनी खर्चा अतिरिक्त भूमि की खरीद से सम्बन्धित कानूनी कार्यों के लिये किया गया था ।

✓(द) अनुसन्धान व्यय का दो-तिहाई पूँजी व्यय है ।

(य) ह्रास की छूट २,७५,८५० रु० निश्चित हुई है ।

रु०

रु०

लाभ—हानि-लाभ खाते से

१२,१६,८५०

जोड़ो—अस्वीकृत खर्चा

दान

५,०००

ऋणों की दलाली जो पूँजी व्यय है

१,१६२

बिल्डिंग का किराया और बीमा जो

व्यापार के काम में नहीं आती

३,०५०

बिल्डिंग की मरम्मत जो व्यापार के

काम में नहीं आती

२,८७२

कानूनी खर्चे, जो पूँजी व्यय है

६५०

अनुसन्धान सम्बन्धी पूँजी खर्चा

४०,०००

५३,०३४

१२,६६,८८४

कम करो—व्यापार के अन्तर्गत कर न लगने

योग्य आय

भवन का किराया

२८,६५१

प्रतिभूतियों पर व्याज

१३,७००

४२,६५१

१२,२७,२३३

कम करो—ह्रास की छूट

२,७५,८५०

अनुसन्धान सम्बन्धी पूँजीगत खर्चों का

५ वाँ हिस्सा

८,०००

२,८३,८५०

व्यापार से कर लगने योग्य लाभ

६,४३,३८३

किराये पर उठे बगले और चौल्स का किराया		२८,९५१
स्थानीय करो की कटौती जो वास्तविक रकम की आधी है		९००
जायदाद का वार्षिक मूल्य (annual value)		२८,०५१
कम करो—छठा हिस्सा मरम्मत के लिए	४,६७५	
बीमा	१,२५०	५,९२५
जायदाद से कर लगने योग्य आय		२२,१२६
१ जायदाद से आय		२२,१२६
२ प्रतिभूतियों का ब्याज (इसके लिये उद्गम स्थान पर ६,३०० रु० आय-कर काटा गया है)		२०,०००
३ व्यापार से लाभ		९,४३३
कुल आय		९,८५५

यदि ५,००० रु० का दान किसी स्वीकृत सस्था को दिया गया है, तो आय-कर की औसत दर से आय-कर की छूट (rebate) मिल जायगी। किन्तु इसके सम्बन्ध में कम्पनी अतिरिक्त कर की कोई छूट (rebate) पाने की हकदार नहीं है।

(३) अ महाशय चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट है। अपनी प्रैक्टिस के अलावा वे एक लेखाकर्म-शिक्षण विद्यालय (Accountancy Coaching Institute) भी चलाते हैं। वे अपना हिसाब-किताब रोकड़ी आधार (Cash Basis) पर रखते हैं। ३१ मार्च १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये उनका सक्षित रोकड़ खाता निम्न प्रकार है —

रु०	रु०
शेष नी/ला	९,५१४
अक्रेक्षण की फीस	१४,७७५
अन्य एकाउन्टेसी कार्यों से प्राप्त आय	५,४५०
इंस्टीट्यूट की फीस	२,१००
परीक्षक की फीस	६४५
विनियोगों की ब्याज	३,५००
जायदाद का किराया, जिस पर कोई स्थानीय कर नहीं लगता	४,८००
	४०,७८४
कार्यालय व्यय	४,१५०
इंस्टीट्यूट के खर्चे	९०२
निजी खर्चे	३,६००
सदस्यता और प्रमाण-पत्र शुल्क	५५
जीवन बीमा प्रीमियम	१,२५०
आय-कर	२,५००
मोटरकार की खरीद	३,४५०
कार के खर्चे	४२०
जायदाद का बीमा	३००
शेष आ/ले	२४,१५७
	४०,७८४

निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार करते हुए १९५८-५९ के गत वर्ष के लिये उनकी कुल आय निकालिए —

(क) कार्यालय व्यय में टैकनीकल पुस्तकों और कार्यालय के लिए फरनीचर की खरीद के क्रमशः १०८ रु० एवं ६५ रु० शामिल हैं।

(ख) मोटरकार के खर्चे का एक तिहाई भाग उनकी प्रैक्टिस के सिलसिले में है।

(ग) उनके सभी विनियोग (Investment) सरकारी प्रतिभूतियों में हैं।

(ङ) मोटरकार, पुस्तको और फरनीचर के ह्रास की छूट १४२ रु० है ।
व्यवसाय से सकल आय (Gross earning) —

	रु०	रु०
अकेक्षण की फीस	१४,७५०	
एकाउन्टैसी के काम से आय	५,४७५	
इ स्टीट्यूट की फीस से आय	२,१००	
परीक्षक की फीस	६४५	२२,९७०
घटाओ—स्वीकृत खर्च .—		
कार्यालय व्यय	३,९७७	
इ स्टीट्यूट के खर्च	९०२	
सदस्यता और प्रमाण-पत्र का शुल्क	५५	
मोटरकार खर्च (एक तिहाई)	१४०	
ह्रास की छूट	१४२	५,२१६
पेशे से कर लगने योग्य आय		१७,७५४
१ प्रतिभृतियों की ब्याज (ग्रास)		५०००
२. जायदाद से आय —		
वार्षिक मूल्य	४,८००	
घटाओ—मरम्मत के लिए छठा भाग ८००		
बीमा ३००	१,१००	३,७००
३ व्यवसाय की आय		१७,७५४
	कुल आय	२६,४५४

उसे ग्रासत दर पर जीवन बीमा प्रीमियम १२५० रु० पर आय-कर की छूट मिलेगी ।

(४) नीचे ३० जून १९५८ को समाप्त हुए वर्ष के लिए एक चीनी मिल कम्पनी का हानि-लाभ खाता दिया गया है .—

	रु०		रु०
चीनी आदि का प्रारम्भिक स्कन्ध	१,८२,३००	बिक्री	२६,५०,५००
ईख पिलाई की लागत	१२,५७,७००	विविध प्राप्तियाँ	७,७००
निर्माण व्यय	७,९८,५००	चीनी आदि का अन्तिम स्कन्ध	३,६६,०००
मजदूरी और वेतन	२,००,०००		
मरम्मत और नवकरण	४०,०००		
स्थापना व्यय	४१,७००		
बिक्री पर कमीशन	६२,५००		
सञ्चालको की फीस	२,६००		
सामान्य खर्च	१७,८००		
अकेक्षण की फीस	२,६००		
मैनेजिंग एजेंट का पारिश्रमिक	७८,६००		

ह्रास	१,३०,७००	
करो के लिए आयोजन	१,००,०००	
शेष नी/ले	१,०६,२००	
	<u>३०,२४,२००</u>	<u>३०,२४,२००</u>
सामान्य कोष •	१५,०००	शेष नी/ला
शेष स्थिति-विवरण को		<u>१,०६,२००</u>
स्थानान्तरित	६४,२००	
	<u>१,०६,२००</u>	<u>१,०६,२००</u>

निम्न सूचनाओं पर उचित विचार करते हुए १९५६-६० के कर-निर्धारण वर्ष (Assessment Year) के लिये कम्पनी की कुल आय बताइए —

(i) ईडु पिलाई के खर्चों में कम्पनी के फार्म पर पैदा किए गन्ने की लागत १,५४,००० रु० शामिल है, गन्ने का औसत बाजार भाव १,६६,००० रु० है ।

(ii) माल निर्माण कराने के खर्चों में (अ) उत्पादन-कर (Excise duty) के ४,२६,००० रु०, (ब) एक नयी वैज्ञानिक अनुसन्धान-प्रयोगशाला पर पूँजी खर्च के ६७,००० रु० और वर्ष-पर्यन्त उसके पोषण-व्यय (Maintenance Expenses) के ११,००० रु० शामिल हैं ।

(iii) स्थापना व्यय (Establishment Charges) में ३,२०० रु० की वह रकम भी शामिल है, जो एक कर्मचारी को, जिसे नौकरी में रखना उचित नहीं समझा गया, नौकरी से अलग किए जाने के हजाने स्वरूप दी गई थी ।

(iv) १,००० रु० कीमत की चीनी एक अनायालय को ख़ैरात में दी गई ।

(v) जून १९५७ में कारखाने की बिल्डिंग में वृद्धि (additions) के लिए १५,००० रु० का जो निर्माण कार्य हुआ था, वह मरम्मत और नवकरण (repairs and renewals) के अन्तर्गत शामिल कर लिया गया है ।

(iv) स्वीकृत ह्रास सम्बन्धी छूट की रकम ६८,२०० रु० है ।

लाभ—हानि-लाभ खाते से	रु०	रु०
घटाओं—उसमें शामिल कृषि आय		१,०६,२००
(१,६६,०००—१,५४,०००)		<u>४२,०००</u>
		६७,२००
जोड़ो—ख़ैरात में दी गई चीनी की कीमत,		
जो हानि-लाभ खाते में नहीं दिखाई		
गई है ।		<u>१,०००</u>
		६८,२००
जोड़ो—अस्वीकृत खर्च •		
अनुसन्धानशाला के पूँजी खर्च	६७,०००	
करो के लिए आयोजन	१,००,०००	
कारखाने की बिल्डिंग में वृद्धि	१५,०००	
ह्रास का आधिक्य	<u>३२,५००</u>	<u>२,१४,५००</u>

घटाओ—अनुसंधान पर प जी खर्च का
(पाँचवा हिस्सा)

	२,८२,७००
	१३,४००
कुल आय	<u>२,९६,१००</u>

कर्मचारी को (जिसे नौकरी में रखना उचित नहीं समझा गया) दिया हर्जाना—
आगम व्यय (revenue expenditure) है, क्योंकि कम्पनी की सेवा में उसे नौकरी
पर रखे रहना, कम्पनी के लाभ सहित संचालन दृष्टि से हानिप्रद होता ।

यह मान लिया गया है कि ६८,२०० रु० में फैक्टरी इमारतों की वृद्धि के
सम्बन्ध में मिलने वाली ह्रास की छूट भी शामिल है ।

(५) एक कम्पनी के हानि लाभ खाते (३१ दिसम्बर १९५८ को समाप्त होने वाले
वर्ष के लिये) में से निम्न रकम कम (debit) कर दी गयी हैं । १९५९-६० के कर
निर्धारण के लिये कम्पनी की कर लगने योग्य आय मालूम करने के हेतु क्या निम्न में
कटने योग्य है ? कारण सहित उत्तर दीजिये ।

(अ) अपूर्ण मशीनरी (imperfect machinery) को दुस्त कराने में हुआ
खर्च, १०,००० रु० ।

(ब) कम्पनी द्वारा व्यापार बाजार के दौरान में किसी ठेके को प्राप्त करने में दिया
गया कमीशन, १०,००० रु० ।

(स) ऋके ऋणा खाते में लिखे गये २०,००० रु० । कम्पनी को यह नुकसान अपने
ग्राहकों को दिये गये ऋणों के सम्बन्ध में सहना पड़ा था ।

(द) अप-लिखित अंश (shares written off) पर हुई हानि के ८०,०००
रु० इस कम्पनी ने दिल्ली में अपनी एजेंसी (Buying Agency) लेने के लिये एक
दूसरी कम्पनी खड़ी की थी और इसमें उसने एक-एक हजार रुपये के अंश ले लिये
थे । नई कम्पनी फेल हो जाने से अंशों के रूप में ८०,००० रु० की रकम मारी गई और
वह अप लिखित कर दी गई ।

उत्तर—

(अ) खरीदी हुई अपूर्ण मशीनरी को ठीक कराने में जो १०,००० रु० व्यय हुआ,
वह पूँजी व्यय है और इसीलिये उसे घटाया नहीं जा सकता । जब कोई अपूर्ण स्थायी
सम्पत्ति व्यापार के लिये खरीदी जाती है तो उसे काम योग्य (serviceable) बनाने
में जो खर्चा करना पड़े वह सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत (cost) का ही एक भाग
होता है ।

(ब) कम्पनी के व्यापार के सिलसिले में किसी ठेके को प्राप्त करने के लिये
कम्पनी को १०,००० रु० कमीशन देना पड़ा है, यह आगम व्यय है, और इसलिये कटने
योग्य (deductable) है । जब कभी किसी व्यापारी को व्यापार करते हुए किसी ठेके
या आर्डर के पाने के लिये कमाशन देना पड़े, तो वह व्यापारिक खर्च के रूप में घटाया
जा सकता है ।

(स) अप-लिखित ढ़्वा ऋण (Bad debts written off) उस दशा में कटने योग्य है जब कि ऋण व्यापार से सम्बन्धित (incidental) हो। जहाँ कोई कम्पनी अपने ग्राहकों को व्यापारिक नीतिज्ञता (Commercial expediency) के विचार से ऋण दे तो ऐसा ऋण कर-दाता के व्यापार से सम्बन्धित (incidental) नहीं कहा जा सकता। अतः ऐसे ऋण के सम्बन्ध में ढ़्वा ऋण के लिये कोई बटोती नहीं दी जायगी। इसी कारण कम्पनी द्वारा ढ़्वा ऋण खाते डाली गई २०,००० रु० की रकम कटने योग्य नहीं है।

(द) कम्पनी द्वारा अपलिखित अशो पर हुई ५०,००० रु० की हानि पूँजी हानि है, इसलिये वह कटौती के रूप में स्वीकृत नहीं की जा सकती। किसी सहायक (subsidiary) या सम्बद्ध (associated) कम्पनी के लिये हुये शेयर पूँजी सम्पत्ति (Capital Asset) के रूप में होते हैं और ऐसे अशो पर हुई हानि भी पूँजी हानि होती है।

(५) अन्य साधनों से आय (Income from other sources)

धारा १२ आय के पाँचवे शीषक से, जो अधिनियम के अन्तर्गत कर लगने योग्य हैं, सम्बन्धित है। इस धारा के अनुसार कर-दाता को उस प्रत्येक प्रकार की आय पर कर देना पडता है, जो उसे ऐसे साधन से प्राप्त हो जो दूसरे चार पदों में से किसी के अन्तर्गत नहीं आती। जिस आय का कोई साधन न हो, उसे आँधी के आम (windfall) के रूप में ही समझना चाहिये, और इसीलिये वह कर लगने योग्य नहीं है। अन्य साधनों से प्राप्त होने वाली आय के अन्तर्गत निम्न आय सम्मिलित की जाती है —

१—कम्पनियों से मिले लाभांश।

२—कोई ऐसी फीस या कमीशन जिसे किसी कर्मचारी ने अर्जित किया हो (किन्तु अपने स्वामी से अर्जित किया हुआ नहीं)।

३—किसी वसीयत के अन्तर्गत प्राप्त वार्षिक (Annuities)।

४—सभी प्रकार के ब्याज केवल प्रतिभृतियों से प्राप्त ब्याज का छोडते हुये।

५—उस जमीन की आय जो किसी बिल्डिंग से न लगी हो (वह कृषि-आय नहीं होनी चाहिये), जैसे बाहरो में खाली पडी हुई जमीनें जो माल जमा करने के लिये किराये पर उठा दी जाती हैं।

६—जमीन से प्राप्त किराया (ground rent)।

७—मकान-जायदाद (housing property) का कुछ भाग किराये पर उठा देने (sub-letting) से हुई आय।

८—बाजार लगवाने, घाट और मछली पकडने से हुई आय।

९—रॉयल्टी की आय, संचालको की फीस आदि।

१०—किसी विदेशी सरकार से प्राप्त हुआ वेतन या पेंशन।

११—निवासी पत्नी द्वारा परदेशी पति की विदेशी आय से प्राप्त रकम ।

१२—कृषि आय जो भारत से बाहर की जमीन से प्राप्त हो ।

कटौतियाँ (Deductions)

अन्य साधनों से कर लगने योग्य आय मालूम करने के लिए उन सभी खर्चों को घटा देना चाहिए जो इस आय को प्राप्त करने के उद्देश्य से किए गये हैं । किन्तु ये खर्चें पूँजी खर्च या निजी खर्च नहीं होने चाहिए । वे सभी खर्चें, जिन्हें किसी व्यापार, व्यवसाय अथवा पेशे की आय या लाभ मालूम करने में अस्वीकृत कर दिया गया है, अन्य साधनों की आय निकालने में भी अस्वीकृत होते हैं ।

लाभांश के रूप में प्राप्त आय की दशा में, किसी बेकर या अन्य व्यक्ति को कर दाता की ओर से सग्रह करने के बदले दिये गये पुरस्कार या कमीशन के लिये कटौती स्वीकृत की जायगी ।

धारा १८ (३ A) के अनुसार, जब किसी परदेशी (Non-residents) को ब्याज (प्रतिभूतियों के ब्याज के अलावा) अथवा कोई अन्य रकम, जो कर लगने योग्य है, दी जाती है, तो देने वाले व्यक्ति को भुगतान करते समय उस पर उच्चतम (maximum) दर से आयकर और अतिरिक्त कर काट लेना चाहिए, नहीं तो त्रुटि का दिशा में इस कर के चुकाने की जिम्मेदारी उस पर ही होगी । यदि जिस व्यक्ति को भुगतान दिया जा रहा है, वह निवासी (resident) है, तो ऐसी रकमों में से आय-कर काटने की आवश्यकता नहीं है ।

लाभांश (Dividends)

एक कम्पनी को अपने सदस्यों से पृथक्, वैधानिक अस्तित्व प्राप्त है । जब वह कर अदा करती है, तो वह अदायगी वह अपनी ओर से और अपने लाभ के सम्बन्ध में ही करती है । इसलिए जब इसका लाभ अशधारियों (Share-holders) को बाँटा जाता है, तब इन प्राप्त लाभांशों (dividends) पर उन अशधारियों को कर देना पड़ता है । किन्तु धारा ३९ B के अनुसार, कम्पनी द्वारा लाभांश पर चुकाये गये आयकर की सीमा तक आयकर अशधारियों द्वारा ही चुकाया माना जाता है । यही सिद्धान्त धारा १६ (२) और धारा १८ (५) में सन्निहित है, जिसके अनुसार कम्पनी को लाभांश पर जो आय-कर देना है वह अशधारियों की ओर से दिया हुआ ही माना जायगा और उनको अपने-अपने कर-निर्धारण (individual assessments) में इसके ऊपर क्रेडिट (credit) दी जाती है । धारा ४८ के अनुसार, यदि अशधारी के लाभांश पर अधिक आय-कर ले लिया गया है, तो उसे ऐसा आधिक्य वापस प्राप्त करने का अधिकार है, किन्तु कम्पनी द्वारा अदा किये अतिरिक्त कर (super Tax) के सम्बन्ध में अशधारी को यह छूट (relief) नहीं मिलेगी । अशधारी को अपने लाभांश पर अतिरिक्त-कर

दूसरी बार भी देना पड़ता है, क्योंकि कम्पनी द्वारा दिया गया अतिरिक्त कर तो समूह-कर (Corporation Tax) है।

अतिरिक्त-कर के उद्देश्य के लिए लाभांश (dividend) की परिभाषा का विशेष महत्व है, क्योंकि जहाँ तक आय कर का सम्बन्ध है, अशधारियों में वितरित करने से पूर्व कम्पनी द्वारा अपने लाभ पर अदा किया गया कर अशधारियों की ओर से दिया हुआ माना जाता है, और इस कर के लिए उन्हें (अशधारियों को) अपने-अपने कर-निर्धारण (Assessment) में क्रेडिट (Credit) मिल जाती है। लेकिन अतिरिक्त कर के मामले में ऐसा नहीं होता।

किसी कम्पनी द्वारा अपने अशधारियों को साधारण रूप में वर्ष के लाभ में से वितरित किया गया धन ही वह लाभांश है जिन पर अशधारियों के हाथों कर लगता है। लेकिन धारा २ (६ A) के अन्तर्गत लाभांश में निम्न विशेष (Specific) वितरण भी शामिल हैं —

(१) कम्पनी द्वारा अपने संचित लाभ (Accumulated Profits) का (जो चाहे पूँजीकृत (Capitalised) हो या न हो) वितरण, बशर्ते इस वितरण में कम्पनी को अपने अशधारियों को कुछ सम्पत्ति (Assets) देनी पड़ती हो। संचित लाभ (Accumulated Profits) का वितरण, निम्न में से किसी भी प्रकार किया जा सकता है .—

(अ) नकद या वस्तु रूप में (in cash or in kind)। ऐसी किसी अवस्था में वितरण स्पष्ट लाभांश है।

(ब) कम्पनी के अधिलाभांश अंशों (Bonus shares) के रूप में। जब अधिलाभांश अंश दिये जाते हैं, तो कम्पनी को इस वितरण पर अपनी सम्पत्ति (Asset) नहीं देनी पड़ती। इसलिए अधिलाभांश अंश को लाभांश (Dividend) के अन्तर्गत शामिल नहीं किया जा सकता और वह अशधारी के हाथों पर लगने योग्य नहीं है।

(स) किसी दूसरी कम्पनी में विनियोग के रूप में धारण किये हुये अंशों या ऋण-पत्रों (Debentures) में इस प्रकार जो वितरण किया जायगा, वह हिस्सेदारों के हाथों में लाभांश माना जायगा, क्योंकि इस रूप में कम्पनी की सम्पत्ति (Assets) का वितरण होता है।

(२) ऋण-पत्रों (Bonus Debentures) या निक्षेप प्रमाणपत्रों (Deposit Certificate) का किसी भी रूप में ब्याज सहित या बिना ब्याज वितरण, लाभांश में शामिल होगा यदि वे कम्पनी के संचित लाभों के आश्रित (Covered by) दिये गये हैं, भले ही वह संचित पूँजीकृत (Capitalised) हो या नहीं।

(३) एक समाप्ति होने वाली कम्पनी द्वारा अपने संचित लाभ में से अश-

धारियों को किया गया वितरण भी लाभांश में शामिल होता है। ऐसे लाभ निरन्तरक (Liquidator) द्वारा वितरित किए जाने पर कर लगने योग्य हो जावे है।

(४) संचित लाभ की सीमा तक, चाहे वह पूँजीकृत हो या नहीं, अपनी पूँजी घटाने पर कम्पनी द्वारा किया गया वितरण। यह वितरण लाभांश के अन्तर्गत इस लिये शामिल किया गया है कि कर बचाने के हेतु पूँजी में कमी करने के बहाने कहीं लाभ का वितरण न कर दिया जाय।

(५) एक कम्पनी द्वारा किसी शेयर होल्डर को ऋण या पेशगी के रूप में कम्पनी के संचित लाभों की सीमा तक किया गया भुगतान भी, जिसमें जनता का बड़ा हित नहीं है, (जैसे एक प्राइवेट कम्पनी) लाभांश में शामिल है।

यदि कोई कम्पनी अपने पूँजी लाभ (Capital profits) से लाभांश देती है, तो भुगतान अशुद्धि के हाथ में कर लगने योग्य होगा, चर्च इस रकम को लाभांश, बोनस या किसी अन्य नाम से पुकारें।

सकल लाभांश निकालना (Grossing up of Dividends)

धारा १६ (२) के अनुसार किसी अशुद्धि द्वारा प्राप्त हुआ लाभांश उसकी उस गत वर्ष की, आय मानी जाती है, जिसमें कि कम्पनी ने इसकी घोषणा की है। अतएव यदि लाभांश एक गत वर्ष में घोषित किया जाय और वह अगले वर्ष प्राप्त हो तो उसकी आय उस वर्ष में जब कि वह घोषित किया गया है, मानी जायगी। यह नियम, चाहे जो भी हिसाब की पद्धति अपनाई जाए, लागू होगा।

अशुद्धि की कुल आय निकालने के लिए वास्तव में प्राप्त लाभांश में (चाहे वह कर-मुक्त हो या कर घटा कर हो) उस लाभांश पर लगे आय कर को जोड़ कर ग्राँस करना होगा।

अशुद्धि के हाथ में सम्पूर्ण लाभांश कर लगने योग्य है, भले ही उसका कुछ भाग कम्पनी के कर मुक्त लाभ (जैसे कृषि आय, पूँजी लाभ आदि) से प्राप्त हुआ हो, क्योंकि एक भिन्न प्रकृति के लाभ की, जैसे ही वह किसी सामान्य लाभ राशि में एक बार मिला दिया जाता है, विशेषता (Identity) जाती रहती है। जब लाभांश का कुछ भाग कम्पनी के कर-मुक्त लाभ में से घोषित किया गया हो, तो अशुद्धि अधिक से अधिक यह माँग कर सकता है कि वस्तुतः प्राप्त लाभांश में जो कर जोड़ा जावे वह अनुपातिक हो।

लाभांशों के ग्राँस करने के नियम इस प्रकार हैं—

(१) शुद्ध लाभांश अर्थात् अशुद्धि द्वारा वस्तुतः प्राप्त लाभांश की रकम (कम्पनी द्वारा आय-कर काटने के बाद या बिना काटे) को, उसमें कम्पनी द्वारा भारत में उत्पन्न लाभांश के सम्बन्ध में शुकाया गया आय-कर जोड़कर ग्राँस किया जा सकता है।

कर योग्य आय की गणना (२)]

(२) जो अशुधारी कम्पनी को पुस्तकी में रजिस्टर्ड न हो, उसके द्वारा प्राप्त लाभार्जित ग्राँस नहीं किया जा सकता ।

(३) एक विदेशी कम्पनी से, जोकि भारत के बाहर कर चुकाती है, प्राप्त हुए लाभार्जित भी ग्राँस नहीं किये जाते ।

(४) एक ऐसी कम्पनी से जोकि भारत में और भारत के बाहर कर चुकाती है, प्राप्त हुये लाभार्जित को, उसमें कम्पनी द्वारा केवल भारत में चुकाया गया आय-कर ही जोड़कर ग्राँस करना चाहिये ।

(५) लाभार्जित को आय कर की उस दर के आधार पर ग्राँस करना चाहिये जोकि कम्पनी की कुल आय पर लागू होती है । ऐसी दर के सम्बन्ध में कम्पनी को दी गई छूट (Rebate) या कम्पनी से चार्ज किया गया अतिरिक्त कर (Super tax) शामिल नहीं किया जाता । आय-कर की जिस दर पर शुद्ध लाभार्जित ग्राँस किया जायगा वह उस वित्तीय वर्ष की कर दर होगी जिसमें कि लाभार्जित घोषित किया गया है ।

(६) जब कोई लाभार्जित ऐसे लाभों में से, जिन पर कम्पनी के हाथों कर नहीं लगता (उदाहरण के लिये, उनमें से कृषि से आय या कर न लगने योग्य पूँजी लाभ अथवा ह्रास सम्बन्धी छूट परिशोधित (set off) कर लेने के कारण), दिया जाये, तो लाभार्जित से जो वृद्धि की जाये वह, कम्पनी के कर-योग्य लाभों का उसके कुल लाभों से जो अनुपात है उसके आधार पर ही होनी चाहिये । इस प्रकार, यदि कोई कम्पनी अपने लाभों पर, जिसमें से लाभार्जित घोषित किया गया है, कर नहीं देती है (क्योंकि उसके लाभ ह्रास सम्बन्धी छूट परिशोधित (set off) करने में ही निबट गये) तो अशुधारी द्वारा प्राप्त हुये, लाभार्जित को ग्राँस नहीं करना चाहिये ।

(७) जहाँ एक कम्पनी अपने पूँजी लाभों में से लाभार्जित वितरित करती है, वह राशि जो एक अशुधारी प्राप्त करता है उसमें, पूँजी लाभों पर लागू होने वाला, आयकर, जोड़कर ग्राँस करना चाहिए ।

(८) जो कम्पनी भारत में कर देती है, उससे प्राप्त हुआ शुद्ध लाभार्जित अशुधारी के हाथ में निम्न प्रकार ग्राँस किया जाएगा —

(अ) १९५८-५९ तथा १९५९-६० कर निर्धारण वर्षों के लिए कम्पनी की लागू होने वाली आयकर की दर (सरचार्ज सम्मिलित करते हुए) ३१.५% है । जहाँ कि सम्पूर्ण लाभ कर योग्य हो तो शेष ६८.५% आयकर चुकाने के बाद वितरण के लिए बचता है । इसलिए नेट लाभार्जित ६८.५% के लिए सकल लाभार्जित १००% होगा । इस प्रकार यदि शुद्ध लाभार्जित ६८.५% प्राप्त हो तो सकल लाभार्जित १,०००% होगा ।

(ब) जहाँ केवल कम्पनी के लाभ का एक भाग ही कर-योग्य है, शुद्ध लाभांश को ग्राँस करने की निम्न पद्धति होगी — माना कि कम्पनी के लाभ का केवल ४०% ही कर-योग्य है। तब ४० पर आय-कर ३१ ५% से १२ ६ होगा। दूसरे शब्दों में कम्पनी अपनी आय पर १२ ६% आय-कर चुकाती है। ८७ ४ नेट लाभांश के लिए सकल लाभांश १०० होगा।

उदाहरण

३१ मार्च १९५६ को समाप्त हुए गत वर्ष में एक कर-दाता ने विभिन्न कम्पनियों द्वारा घोषित निम्न लाभांश प्राप्त किया —

(१) यूनाइटेड किंगडम में रजिस्टर्ड हुई कम्पनी से, जिस पर भारत में कर नहीं लगता, १,००० रु०।

(२) एक कम्पनी में जिसके लाभ पर ह्रास सम्बन्धी छूट के कारण कर नहीं लगा है, १,००० रु०।

(३) एक कम्पनी से जिसके अश कर-दाता के पास एक कोरे हस्तान्तर (Blank transfer) के अन्तर्गत है, १,००० रु०।

(४) एक कम्पनी से जिसने अपने कर लगे पिछले लाभों से लाभांश घोषित किया है, १,००० रु०।

(५) एक कम्पनी से जिसके ८०% लाभ पर कर लगता है, १५% कर-मुक्त हे तथा ५% कृषि आय है।

(६) एक कम्पनी से जिसने कुछ लाभों पर तथा कुछ पूँजी लाभों पर लाभांश घोषित किया है, १,००० रु०।

(७) एस कम्पनी से जिसने अपने ५०% लाभ पर आय-कर दिया है, १,००० रु०।

कर-दाता की १९५६-६० कर निर्धारण वर्ष के लिये कुल आय तथा लाभांश के लिये उद्गम स्थान पर की गई कटौती मालूम कीजिये।

जहाँ तक लाभांशों के ग्राँस करने का प्रश्न है, स्थिति इस प्रकार है—

(१) यह ग्राँस नहीं होगा, क्योंकि कम्पनी पर भारत में कर नहीं लगा।

(२) यह ग्राँस नहीं किया जाएगा, क्योंकि कम्पनी के लाभों पर ह्रास सम्बन्धी छूट के कारण कर नहीं लगा था।

(३) यह ग्राँस नहीं किया जाएगा, क्योंकि कर-दाता कम्पनी का रजिस्टर्ड अशधारी नहीं है।

(४) यह सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के प्रशासकीय हिदायतों के अनुसार ग्राँस नहीं किया जाएगा, क्योंकि लाभांश पिछले वर्ष के कर लगे लाभों से घोषित किया गया था।

(५) लाभांश ग्राँस करने पर १,३३६ ६ रु० होगा। उद्गम स्थान पर आय-कर ३३६ ६ रु० है।

(६) लाभान्नाई कर करने पर १४५६ न ६० होगा । उद्गम स्थान पर आय-कर ४५६ न ६० कटा है ।

(७) लाभान्नाई कर करने पर १,१८७ ६० होगा । उद्गम स्थान पर आय-कर १८७ ६० कटा है ।

१६५६-६० कर निर्धारण वर्ष के लिए कुल आय ७,६८३ ६० है तथा आय-कर जो उद्गम स्थान पर चुकाया ६८३ ७ ६० हुआ ।

परदेशी को किये गये भुगतानों पर कर का काटना

यह एक अगले अध्याय “उद्गम स्थान पर कर-कटौती” में समझाया गया है ।

किताबों के लेखकों की आय (Income of Authors of Book)

धारा १२ AA के अन्तर्गत, यदि वह माँगे (Claims), तो कर-निर्धारण के लिये पुस्तक के कॉपीराइट बिक्री पर प्राप्त एक मुश्त रकम कई वर्षों में बाँटी जा सकती है । यदि उस काय में वह १२ से अधिक व २४ माह से कम लगे हों तो लेखक की इच्छानुसार वह २ लगातार वर्षों में बाँटी व कर योग्य की जा सकती है । और यदि उस कार्य पर २४ माह से अधिक लगे हों तो वह ३ लगातार वर्षों में बाँटी व कर योग्य की जा सकती है ।

यदि लेखक यह नहीं मागता, जो तमाम भुगतान, जिस वर्ष में उसने यह रकम प्राप्त की है, उस वर्ष की आय मान कर उस पर निर्धारित होगा ।

हिसाब की पद्धतियाँ (Systems of Accounting)

यदि धारा १० और १२ को पढ़ा जाय तो यह स्पष्ट पता चलता है कि व्यापार और अन्य साधनों से कर लगने योग्य आय का हिसाब रखने के हेतु सभी कर-दाताओं के लिए किसी समान पद्धति की व्यवस्था नहीं की गई । इसीलिए प्रत्येक कर-दाता अपनी सुविधा के विचार से हिसाब की किसी पद्धति को व्यापार में ला सकता है । धारा १३ के अन्तर्गत इस दिशा में केवल निम्नलिखित प्रतिबन्ध है —

(अ) हिसाब की जो पद्धति व्यवहार में लायी जावे वह ऐसी हो कि गत वर्ष के लिये करदाता की आय का बिल्कुल स्पष्ट पता लग जाय ।

(ब) हिसाब की पद्धति ऐसी हो कि उसे करदाता अपने व्यापार का हिसाब रखने के लिये नियमित रूप से व्यवहार में लावे ।

यदि कर-दाता हिसाब रखने के लिये नियमित रूप से एक ऐसी पद्धति को व्यवहार में नहीं लाता, जो उसके गतवर्ष की आय को साफ-साफ प्रकट करे तो ऐसी दशा में उसकी आय ऐसे किसी ढग से निकाली जायगी जो इन्कम टैक्स ऑफीसर की राय में उसे स्पष्ट प्रकट करदे । इसलिए करदाता का यह कर्तव्य है कि वह अपने हिसाब ऐसे ढग में प्रस्तुत

करे जो उसकी सच्ची आय बताये और यदि वह ऐसा नहीं कर पाता, तो इनकम टैक्स ऑफीसर अपने सन्मुख सामग्री के आधार पर उस आय का यथासंभव उचित अनुमान निकालेगा और करदाता को वह अनुमान मानना पड़ेगा।

जब कोई करदाता अपना हिसाब रखने की पद्धति बदलने का इच्छुक हो और इसके लिए प्रार्थना-पत्र दे, तो इनकम टैक्स ऑफीसर को, यदि वह इस परिवर्तन के लिए सहमत है, यह देखना चाहिए कि इस परिवर्तन के कारण कोई आय या लाभ कर लगने से छूट न जाय।

हमारे देश में हिसाब की साधारणतया निम्न तीन पद्धतियाँ व्यवहार में लाई जाती हैं.—

(१) रोकड पद्धति (Cash System)

इस पद्धति के अनुसार वास्तविक प्राप्तियों और वास्तविक भुगतानों का एक लेखा रखा जाता है, बहियों में रकमें तभी चढ़ायी जाती हैं जबकि कोई रकम सचमुच में मिले या किसी को दी जावे। उन व्यापारिक फर्मों के लिए, जिनके यहाँ काफी उधार लेन-देन होता है, यह पद्धति बिल्कुल अपर्याप्त है। अतः सामान्यतः इस पद्धति के अनुसार व्यापारी अपना लाभ नहीं निकाला करता। फिर भी, यदि कोई छोटा व्यापारी रोकड पद्धति पर अपना हिसाब रखता है और इसके अनुसार अपना लाभ निकालना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा करते समय बिना बिके माल के प्रारम्भिक और अन्तिम स्क्रन्ध को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

डाक्टर, वकील, एकाउन्टेण्ट आदि व्यक्ति (जो कोई व्यवसाय करते हैं) अपना हिसाब रोकड-पद्धति के अनुसार सुविधा से चला सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ लेन-देन नकद होते हैं, और स्क्रन्ध का प्रश्न ही नहीं है।

(२) महाजनी-पद्धति (Mercantile System)

इस पद्धति के अनुसार नकद और उधार दोनों प्रकार के सभी व्यवहारों का लेखा रखा जाता है और वर्ष का सकल लाभ या हानि वर्ष से सम्बन्धित सभी आयों और व्ययों को (चाहे आय की रकम वास्तव में प्राप्त हुई है या नहीं, और चाहे व्यय की रकम वास्तव में दी गयी है या नहीं) शामिल करते हुए निकाला जाता है अर्थात् इस पद्धति से निकाला गया लाभ वह लाभ है जो वास्तव में अर्जित किया गया है, भले ही वह नकदी प्राप्त न किया गया हो तथा इस प्रकार निकाली गई हानि वह हानि है जो वास्तव में उठानी पड़ी है, यह आवश्यक नहीं कि वह नकदी में ही चुकाई गई हो।

(३) मिश्रित-पद्धति (Mixed Points)

रोकड-पद्धति और व्यापारिक-पद्धति के अतिरिक्त हिसाब की कई मिश्रितपद्धतियाँ भी हो सकती हैं। उदाहरणार्थ, कोई व्यवसायी व्यवहारों के एक वर्ग को रोकड-पद्धति

पर और दूसरे वर्ग के लिए महाजनी-पद्धति का उपयोग कर सकता है, इसी प्रकार माल की बिक्री और खरीद की वह महाजनी-पद्धति पर तथा आय और व्यय को रोकड़-पद्धति पर लिख सकता है।

वैधानिक रूप से किसी व्यक्ति के लिए (कम्पनियों को छोड़कर) हिसाब रखना जरूरी नहीं है। इनकम टैक्स ऑफीसर के सन्मुख आने वाली कठिनाइयों में एक प्रमुख कठिनाई आय-कर दाता की सही-सही आय निश्चित करना है। यदि कर-दाता नियमित रूप से और ठीक प्रकार से रखा हुआ (यदि सम्भव हो तो किसी शासन-प्राप्त लेखपाल से अक्रेषित कराया हुआ) हिसाब प्रस्तुत किया करे तो यह कठिनाई बहुत कुछ हल हो सकती है।

(६) पूँजी लाभ (Capital Gains)

फाइनेन्स (न० ३) एक्ट १९५६ पूँजी लाभ सम्बन्धी कर-योजना की, जो कि १ अप्रैल १९४६ से ३१ मार्च १९४८ तक विद्यमान थी, पुनः जीवन प्रदान करता है। धारा १२ बी के अनुसार, करदाता को 'पूँजी-लाभ' के शीर्षक के अन्तर्गत उस लाभ के सम्बन्ध में कर देना पड़ेगा, जो कि ३१ मार्च १९५६ के पश्चात् किये गये किसी पूँजी सम्पत्ति के विक्रय, विनिमय का हस्तांतर से उदत हो और ऐसा लाभ उस 'गत वर्ष' की आय माना जायेगा जिसमें कि विक्रय, विनिमय या हस्तांतर हुआ था।

'पूँजी-सम्पत्ति' (Capital assets) का आशय करदाता द्वारा रखी हुई (held) किसी भी प्रकार की सम्पत्ति से है चाहे वह व्यापार से सम्बन्धित हो या नहीं किन्तु इसमें निम्न शामिल नहीं है —

(अ) व्यापारिक स्कन्ध, उपभोग्य स्टोस या कच्चा माल जो कि व्यापारिक कार्यों के लिए हो।

(आ) वैयक्तिक सम्पत्तियाँ (जैसे जेवर, फर्नीचर आदि) और

(इ) भूमि, जिसकी आय 'कृषि-आय' हो।

एक सामेदार का किसी सामेदारी सस्था में हिस्सा 'सम्पत्ति' है और इसलिये वह पूँजी सम्पत्ति है। यदि करदाता ने कोई भूमि, जो किसी समय कृषि भूमि थी, इमारत बनाने के आशय से खरीदी और उस इमारत सहित भूमि को लाभ पर बेच दिया तो इस प्रकार अर्जित लाभ एक पूँजीगत लाभ है क्योंकि कर-दाता ने भूमि को कृषि के लिये नहीं खरीदा था, अतः भूमि को पूँजीगत सम्पत्तियों की परिभाषा में शामिल रखा जायेगा।

छूटे — निम्न पूँजी-लाभ स्पष्ट रूप से (Expressly) कर-मुक्त (Exempt) घोषित कर दिये गये हैं :—

(१) एक हिन्दू अविभाजित परिवार के पूर्ण या आंशिक विभाजन पर पूँजी सम्पत्तियों के वितरण से उदय होने वाला लाभ,

(२) वसीयत अथवा दान (Will, gift or bequest) द्वारा सम्पत्तियों के हस्तांतर से उदय होने वाला लाभ ,

(३) किसी पितृ-कम्पनी (Parent Company) द्वारा अपनी पूँजी सम्पत्तियाँ किसी पूर्णतः भारतीय स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी को हस्तांतर करने से उदय हुआ लाभ ।

(४) कर-दाता या उसके माता पिता द्वारा दो वर्ष से रहने वाले मकान को बेचने से उदय हुआ लाभ, यदि पूँजीगत लाभ की यह रकम पूर्णतः लाभ उदय होने के पहले या बाद में १ वर्ष के अन्दर किसी नये रहायसी मकान की खरीद में विनियोग कर दिया जाये । हाँ, यदि पूँजी-लाभ नई जायदाद की लागत से -अधिक बैठे, तो, आधिक्य पर कर लगेगा ।

मकान जायदाद के सम्बन्ध में एक और छूट भी है । यदि सब मकानों का, जिनका कि कर-दाता स्वामी है, उचित बाजार मूल्य (Fair market value) ५०,०००) से अधिक नहीं है, और यदि वह अपनी किसी एक जायदाद को ऐसे मूल्य में, जो कि २५,०००) से अधिक न हो, बेच देता है, तो ऐसे विक्रय से होने वाले पूँजी-लाभ पर कोई कर नहीं लगेगा ।

कटौतियाँ (Deductions) .—विक्रय, विनिमय या हस्तांतर के प्रतिफल के पूरे मूल्य में से निम्न कटौतियाँ करने के बाद ही पूँजी-लाभ की रकम निकाली जायेगी —

(१) केवल ऐसे विक्रय, विनिमय या हस्तांतर के सम्बन्ध में किये गये खर्च ,

(२) कर-दाता के लिये पूँजी सम्पत्ति की वास्तविक लागत, जिसमें किसी विस्तार या सुधार की लागत शामिल है लेकिन ऐसा व्यय शामिल नहीं है जोकि धारा ४, ६, १० और १२ के अन्तर्गत स्वीकार योग्य (admissible) है । हाँ, इस सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम हैं —

(अ) यदि कर-दाता से पूँजी सम्पत्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति उसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित है और इन्कम टैक्स आफीसर के पास इस विश्वास का पर्याप्त कारण है कि उक्त विनिमय, विक्रय या हस्तांतर कर बचाने के इरादे से किया गया था, तो उन पूँजी सम्पत्तियों या ऐसे विक्रय, विनिमय या हस्तांतर की तिथि पर जो उचित बाजार मूल्य था वही उक्त विक्रय विनिमय या हस्तांतर का सम्पूर्ण प्रतिफल (Full consideration) मान लिया जायेगा ।

(आ) यदि पूँजी सम्पत्ति वह है जिसके लिये कर दाता किसी वर्ष ह्रास सम्बन्धी छूट प्राप्त कर चुका है, तो कर-दाता के लिये सम्पत्ति की वास्तविक लागत उसका वह अपलिखित मूल्य (Written down value) होगी, जो कि धारा १० (२) (vii) के अन्तर्गत आवश्यक समायोजन करने के बाद निकले ।

(इ) कर-दाता को यह चुनने का अधिकार है कि वह पूँजी सम्पत्ति की वास्तविक लागत की बजाय १ जनवरी १९५४ के दिन उसका जो उचित बाजार मूल्य हो उसे स्वीकार कर ले। इसका यह अर्थ है कि १ जनवरी १९५४ तक जो पूँजी वृद्धि पूँजी सम्पत्ति के मूल्य में हो गई है, उस पर कर नहीं लगाया जायेगा।

(ई) यदि कर-दाता को किसी पूँजी सम्पत्ति का स्वामित्व उत्तराधिकार, सयुक्त हिन्दू परिवार के विघटन, फर्म के भग होने या कम्पनी के समापन पर प्राप्त हुआ है, तो उसकी वास्तविक लागत वह होगी जो कि पूर्व स्वामी के लिये वास्तविक लागत (ह्रास सम्बन्धी छूट घटा कर) है, और जब पूर्व स्वामी की वास्तविक लागत का पता न लग पाये, तो जिस दिन पूँजीगत सम्पत्ति पूर्व स्वामी की सम्पत्ति बनी थी उस दिन जो उचित बाजार मूल्य था वही इसकी वास्तविक लागत मान ली जावेगी।

हाँ, उक्त के सम्बन्ध में निम्न बातें स्मरणीय हैं—जब पूँजी सम्पत्ति किसी वसीयत सम्बन्धी इकरार (deed of gift) के अन्तर्गत या किसी हिन्दू अविभाजित परिवार के विघटन पर, १ अप्रैल १९५६ के पहले कर-दाता की सम्पत्ति हो गई थी, तो ऐसी वसीयत या विघटन की तिथि पर जो उचित बाजार मूल्य है वही उसे स्वीकार की जाने वाली लागत होगी बशर्ते ऐसा मूल्य पूर्व स्वामी की वास्तविक लागत से या इसके १ जनवरी १९५४ को उचित बाजार मूल्य से अधिक हो, और १ अप्रैल १९५६ को या बाद में, हिन्दू अविभक्त परिवार के विघटन पर, विघटन की तिथि को जो उचित बाजार मूल्य है वही उसे स्वीकार योग्य लागत होगी।

(उ) यदि पूँजी सम्पत्ति के लिये पहले कभी विक्रय हस्तांतर या परित्याग के लिये कोई वार्ता हुई थी और कर-दाता ने कोई द्रव्य या अन्य अधिकार प्राप्त कर लिया था, तो वास्तविक लागत निकालते समय ऐसी रकम को घटा दिया जायेगा।

उदाहरण

(१) ऐक्स एक निर्माण व्यापार में है। उसका हिसाबी वर्ष ३१ दिसम्बर को समाप्त होता है। १ नवम्बर १९५८ को उसने कुछ मशीन, जिसकी लागत ४०,००० रु० थी और जिस पर १५,००० रु० ह्रास के मिल चुके थे, ६०,००० रु० में बेच दी।

इस दशा में ३५,००० रु० का बिक्री पर लाभ है। इसलिये १९५९-६० कर निर्धारण वर्ष में ३५,००० रु० में से १५,००० रु० धारा १० (२) (vii) के अन्तर्गत आय के रूप में कर योग्य होंगे तथा २०,००० पूँजी लाभ के रूप में होंगे। पूँजी लाभ २०,००० रु० मालूम करने के लिए २५,००० रु० के अपलिखित मूल्य को धारा १० (२) (vii) के अन्तर्गत १५,००० रु० से समायोजित करके कर-दाता के लिए वास्तविक लागत आई।

(२) ऐक्स एक निर्माणी अपने हिसाब ३१ दिसम्बर को बनाता है। ३१ दिसम्बर १९५८ को उसने व्यापार बन्द कर दिया। माच १९५९ में उसने कुछ मशीनरी, जिसकी लागत ४०,००० रु० थी और जिस पर १५,००० रु० घिसाई के मिल चुके थे, ६०,००० रु० में बेच दी।

इस परिस्थिति में इस सम्पत्ति के विक्रय पर ३५,००० रु० का लाभ रहा। लेकिन यह बिक्री व्यापार बन्द होने के बाद हुई है अतः धारा १० (२) (vii) के अन्तर्गत किसी लाभ पर कर नहीं लग सकता। इसलिये सम्पूर्ण ३५,००० रु० १९६०-६१ कर निर्धारण वर्ष में पूँजी लाभ के रूप में कर योग्य होंगे।

(३) ऐक्स एक निर्माता रहा है जो अपना हिसाबी वर्ष ३१ दिसम्बर में बन्द करता है। १ नवम्बर १९५८ को उसने कुछ मशीन जिसकी लागत ४०,००० रु० थी और जिस पर १५,००० रु० ह्रास के कट चुके थे, २०,००० रु० में बेची।

इस परिस्थिति में इस सम्पत्ति की बिक्री पर ५,००० रु० की हानि रही जो सम्पूर्ण ही १९५९-६० कर निर्धारण वर्ष में अपशोधित ह्रास के रूप में मिल जायगा। २५,००० रु० का अपलिखित मूल्य इस शेष ह्रास से घट कर पूँजी लाभ मालूम करने के लिए २०,००० रु० हो गया है। इसलिए पूँजी लाभ बिलकुल नहीं है।

पूँजी लाभो पर कर की गणना

पूँजी-लाभो पर कर आय-कर का एक भाग है। अतः वह अन्य आय पर कर के साथ ही लगाया और वसूल किया जायगा। यह कर वस्तुतः प्राप्त (actually received) पूँजी लाभ पर लगाया जाता है न कि अर्जित (earned) पूँजी लाभ पर दूसरे शब्दों में, यदि किसी ने १९३२ में २०,००० रु० मूल्य की जायदाद खरीदी और इसका मूल्य आज ३५,००० रु० है, तो इन दोनों मूल्यों के अन्तर, अर्थात् १५,००० रु० पर कोई कर नहीं लगेगा जब तक कि सम्पत्ति वास्तव में बेची, विनिमय या हस्तांतरित न की जाये। पूँजी लाभ पर कर की गणना करने का ढंग धारा १७ (६) और १७ (७) में दिया गया है और इस प्रकार है —

कम्पनियाँ — एक कम्पनी को उस कम्पनी पर लागू दर से पूँजी-लाभ पर आय-कर देना होगा लेकिन कम्पनी को पूँजी-लाभ पर कोई सुपर-टैक्स नहीं देना होगा। सुपर-टैक्स केवल अन्य आय पर देना होगा।

अन्य कर-दाता (Other assesseees) — गैर कम्पनी कर-दाताओं की दशा में भी, पूँजी लाभो पर कोई सुपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, हाँ, पूँजी लाभों एवं अन्य आय पर दिये जाने वाले आय-कर की गणना इस प्रकार की जावेगी :—

(अ) पूँजी लाभो पर दिये जाने वाले आय-कर की दर कर-दाता की अन्य आय से सम्बन्धित है। एक-तिहाई पूँजी लाभ अन्य आय में जोड़ दिये जाते हैं और इस प्रकार जो योग आता है उस पर लागू होने वाली दर ही वह दर है जो सम्पूर्ण पूँजी पर लाभ

चार्ज की जावेगी। लेकिन किसी भी दशा में, पूँजी लाभ पर आय कर उस रकम के आधे से अधिक नहीं होगा, जो कि पूँजी लाभ के ५,००० रु० पर आधिक्य के बराबर है (shall not exceed one half of the amount by which the capital gains exceed Rs 5,000)। यह सीमावर्ती छूट है। यही नहीं, पूँजी लाभो पर कोई आय-कर नहीं लगता, यदि (अ) पूँजी लाभ ५,००० रु० से अधिक नहीं हो या (आ) कुल आय (पूँजी लाभ शामिल करते हुये) १०,००० रु० से अधिक नहीं हो।

पूँजी लाभ की पूर्ति और अग्र-नेशन — किसी वर्ष की पूँजी हानियो को जिन्हे उसी वर्ष के पूँजी लाभ में से अप-लिखित (write off) किया जा सके, आठ वर्षों तक भावी पूँजी लाभ से अप-लिखित करन के लिये आगे ले जा सकते हैं। ऐसे अग्र-नेशन (Carry forward) की अनुमति के लिये यह आवश्यक है कि किसी गत वर्ष में उठाई गई पूँजी हानि गैर-कम्पनी कर-दाताओं की दशा में ५,००० रु० से अधिक हो।

उदाहरण

एक व्यक्ति श्री X की आय का, ३१ मार्च १९५६ को समाप्त हुए वर्ष के लिये विवरण इस प्रकार है —

- (अ) वेतन २०,००० रु०
- (आ) ऋणो पर ब्याज १०,००० रु०
- (इ) अशो की बिक्री पर पूँजी लाभ १५,००० रु०
- (ई) एक मकान की बिक्री पर पूँजी लाभ ८,००० रु०

जिस मकान की बिक्री से ८,००० रु० का पूँजी लाभ हुआ है वह २४,००० रु० में बेचा गया था और X के पास २५,००० रु० मूल्य का एक और भी घर है। यह दिखाइये कि उनका कर दायित्व १९५६-६० के कर-निर्धारण वर्ष के लिये कैसे निश्चित होगा ?

मकान के विक्रय से उदय हुआ ८,००० रु० का पूँजी लाभ कर से मुक्त है, क्योंकि X की कुल मकान जायदाद का मूल्य ५०,००० रु० से अधिक नहीं है और मकान भी २५,००० रु० से कम में बिका है। अशो की बिक्री पर १५,००० रु० का पूँजी लाभ कर लगने योग्य है।

१९५६-६० के कर निर्धारण वर्ष के लिये कुल आय ४५,००० रु० है, जिसमें १५,००० रु० पूँजी लाभ है और ३०,००० रु०, अन्य आय है। उसके द्वारा दिया जाने वाला कर इस प्रकार निकलेगा —

१५,००० रु० के पूँजी लाभ पर आय कर उस दर से दिया जायेगा, जो कि ३५,००० रु० (अर्थात् ३०,००० रु० + ५,००० रु० जो कि पूँजी लाभ का एक तिहाई है) पर लागू होती है। लेकिन अन्य आय पर आय-कर और सुपर टैक्स ३०,००० रु० (अर्थात् कुल आय—पूँजी लाभ) पर लागू होने वाली दरों से दिया जायेगा।

ह्रास (Depreciation)

आय कर अधिनियम में 'ह्रास' शब्द की परिभाषा नहीं की गई है। यह लेखा-कर्म (Accountancy) का शब्द है। इसका अर्थ है किसी सम्पत्ति के मूल्य में मुख्यतः प्रयोग और टूट-फूट (wear and tear) के कारण कमी हो जाना। किसी व्यापार, व्यवसाय अथवा पेशे का कर लगने योग्य लाभ निकालने के लिये समस्त आगम व्यय (Revenue Expenses) सकल प्राप्तियों (Gross Receipts) में से घटा दिये जाते हैं, किन्तु पूँजी व्ययों को बिल्कुल अलग रखा (excluded) जाता है। इसलिये स्थायी सम्पत्तियों (Fixed Assets) के सम्बन्ध में, जो कि पूँजी व्यय का प्रतिनिधित्व करती हैं, ह्रास की छूट दी जाती है।

ह्रास की छूट केवल इमारतों, मशीनरी, सयन्त्र या फर्नीचर के सम्बन्ध में, जो कर-दाता की सम्पत्ति है और उसके व्यापार, व्यवसाय या पेशे के काम में आती है, दी जाती है। यदि कोई सम्पत्ति, जैसे मोटरकार, कुछ अंशों में मालिक के व्यापार के काम में और कुछ अंशों में उसके निजी प्रयोग में आती हो, तो इस सम्पत्ति के लिए ह्रास की छूट भी आंशिक अनुपातिक ही दी जायगी। इसी प्रकार, यदि कोई सम्पत्ति हिसाबी वर्ष (Accountancy year) में प्राप्त की गई है, तो जितने पूरे महीने उसे काम में लाते हुए बीते हैं उनके अनुपात से ह्रास की छूट दी जायगी।

प्रारम्भिक ह्रास (Initial Depreciation) पर समय के हिसाब से आंशिक प्रयोग (Partial use) का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह ह्रास को पूरा-पूरा पूरे साल के लिये दिया जाता है चाहे सम्पत्ति (asset) साल के बीच ही में प्राप्त की गई हो।

जिस साल में ऐसी सम्पत्ति बेची, हटाई या समाप्त की जाय उस गत वर्ष के लिए भवन, प्लान्ट, मशीन या फर्नीचर पर ह्रास की छूट नहीं मिलती, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में धारा १० [२] (VII) के अन्तर्गत छूट मिल जाती है।

'प्लान्ट' शब्द के अन्तर्गत गाड़ियाँ (vehicle), पुस्तकें, वैज्ञानिक यन्त्र और शल्यक्रिया-सम्बन्धी सामग्री (Surgical Equipment) शामिल हैं।

जो पूँजी सम्पत्ति व्यापार के काम में आती है उसके लिये ह्रास की छूट प्राप्त करने का अधिकार मालिक को ही है। किराया खरीद (Hire Purchase) के आधार पर ली हुई सम्पत्ति की दशा में, खरीदने वाला सम्पत्ति की सुपुर्दगी लेते ही उसका मालिक नहीं बन जाता, किन्तु सम्पत्ति के नकद मूल्य (Cash value of the assets) के आधार पर उसे विशेष रियायत के रूप में (as special case) ह्रास की छूट दी जाती है।

कर-दाता को ह्रास सम्बन्धी छूट प्राप्त करने के लिए निम्न दो शर्तों को पूरा करना चाहिए .—

(१) इन्कम टैक्स आफिसर के सन्मुख ह्रास के बारे में माँगा गया विवरण (आय-कर सम्बन्धी रिटर्न के फार्म के अनुसार) उपस्थित करना चाहिये।

(२) ह्रास सम्बन्धी छूट की कुल रकम (Aggregate amount) सम्पत्ति की वास्तविक लागत से (actual cost of an asset) अधिक नहीं बढ़नी चाहिए।

पुस्तको और फर्नीचर के लिये यदि कर-दाता चाहे तो वह ह्रास के बजाय प्रति-स्थापन व्यय (cost of replacement) की माँग कर सकता है किन्तु ऐसी प्रतिस्थापन सम्बन्धी लागत में किन्हीं सुधारों (improvements) की लागत शामिल नहीं होनी चाहिये।

विकास सम्बन्धी छूट (Development Rebate)

इस छूट के स्वीकृत करने का उद्देश्य औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है।

धारा १० (२) (vib) के अनुसार एक कर-दाता को ३१ मार्च १९५४ के बाद प्राप्त किए हुए जहाज (Ships) अथवा नई मशीन तथा प्लान्ट प्रतिस्थापित करने के लिये जो कि पूर्ण रूप से व्यापार के काम में लाई गई है (लेकिन व्यवसाय या पेशा में नहीं) निम्न दरों से विकास सम्बन्धी छूट पाने का अधिकार है —

(अ) जहाज जो ३१ दिसम्बर १९५७ के बाद प्राप्त किये—लागत का ४०%,

(ब) जहाज जो १ जनवरी १९५८ से पहले प्राप्त किये तथा मशीन एवं प्लान्ट की दशा में—लागत का २५%।

विकास सम्बन्धी छूट केवल नई मशीन और प्लान्ट के लिए ही जो कि पूर्णतः व्यापार के लिये प्रयोग में आती है मिलती है। अतः नई मोटरकार, मोटर साइकिल, साइकिल, टायपराइटर, हिसाब लगाने की मशीनें आदि के लिए विकास सम्बन्धी छूट नहीं माँगी जा सकती क्योंकि ऐसी सम्पत्तियाँ अन्य कार्यों में भी प्रयोग हो सकती हैं।

विकास सम्बन्धी छूट ह्रास-छूट का भाग नहीं है और यह कुल लागत के ह्रास-छूट के रूप में पूरा (Full recoupment) हो जाने के अतिरिक्त मिलती है।

विकास सम्बन्धी छूट निम्न शर्तें पूरी होने पर ही मिलती है —

(१) कर-दाता द्वारा जहाज या मशीन तथा प्लान्ट के सम्बन्ध में ह्रास सम्बन्धी छूट के लिए आवश्यक वितरण प्रस्तुत कर दिया है।

(२) गत वर्ष के खाते में प्राप्त होने वाली छूट का ७५% लाभ-हानि खाते के नाम तथा रिजर्व खाता में जमा दिखा दिया गया हो। यह शर्त, उन कर-दानाओं पर जो बिजली सप्लाई कम्पनियाँ हैं, तथा उन सम्पत्तियों पर जो १ जनवरी १९५८ से पहले खरीदी या प्रतिस्थापित की गई है, लागू नहीं होगी।

कर-दाता अपने व्यापार के लिए इस सचय को अगले १० वर्षों में काम में ला सकता है, लेकिन उस समय में भी (अ) लाभांश बाँटने के लिए, अथवा (ब) भारत से बाहर भेजने के लिए या भारत से बाहर कोई सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए यह सचय काम में नहीं लाया जा सकता।

(३) जिस वर्ष में यह प्राप्त की गई है उससे आगे दस वर्षों में यह किसी व्यक्ति सरकार को छोड़कर, को हस्तांतरित नहीं की जा सकती।

नोट—किसी भी उपर्युक्त दशाओं के दूट जाने से विकास सम्बन्धी छूट नहीं मिलेगी तथा जिस वर्ष में यह छूट मिल चुकी है उसका कर-निर्धारण तबदील (Revision) कर दिया जाएगा। ऐसा रिवीजन धारा ३५ के अन्तर्गत किया जायगा।

विकास सम्बन्धी छूट को आगे ले जाना—यदि किसी कर-दाता की कुल आय किसी गत वर्ष के लिए, विकास सम्बन्धी छूट घटाने से पूर्व, विकास सम्बन्धी छूट से कम पड़ती है तो विकास सम्बन्धी छूट उस वर्ष में कुल आय तक सीमित होगी। छूट का शेष अगले ८ वर्षों तक आगे ले जाकर माँगा (claim) जा सकता है।

ह्रास सम्बन्धी विभिन्न छूटें

(Various Depreciation Allowances)

(१) साधारण ह्रास (Normal Depreciation)—इमारत, मशीनरी, सयंत्र और फर्नीचर के सम्बन्ध में सम्पत्तियों के अपलिखित मूल्य (written down value) पर स्वीकृत दरों के अनुसार ह्रास की छूट दी जाती है। समुद्री जहाजों के लिए ह्रास की छूट उनके अप-लिखित मूल्य (written down value) पर देने के बजाय उनकी प्रारम्भिक लागत (original cost) पर दी जाती है। 'अप-लिखित मूल्य' शब्द की तथा ह्रास की कुछ प्रमुख स्वीकृत दरों की व्याख्या आगे चल कर की जायगी।

(२) अतिरिक्त पाली उपयोग की छूट (Extra Shift Allowances)—मशीनरी और सयंत्रों के लिये, उनको दुहरी और तिहरी पालियों में काम में लाने पर, अतिरिक्त पाली की छूट दी जाती है। अतिरिक्त पाली की यह छूट दुहरी पालियों के सम्बन्ध में साधारण ह्रास (Normal Depreciation) की ५० प्रतिशत होगी और

तिहरी पालियो के सम्बन्ध मे वह साधारण ह्रास की १०० प्रतिशत (बजाय ५०% के) तक हो सकती है ।

दुहरी और तिहरी पाली मे काम करने के लिए ह्रास की छूट का हिसाब अलूहदा निकालना होगा, और वह उन दिनों की सख्या के अनुपात मे होगी जितने दिन दो पालियाँ और जितने दिन तीन पालियाँ चली थी । इस उद्देश्य के लिए साल भर मे काम के दिन ३०० माने गये हैं । इस प्रकार, यदि कोई कारखाना १०० दिन दो पालियो मे और अन्य १०० दिन तीन पालियो मे चला है, तो दुहरी पाली का ह्रास पूरी साल के लिए साधारण ह्रास के ५० प्रतिशत का तिहाई होगा और तीसरी पाली का ह्रास पूरे वर्ष के लिए साधारण ह्रास के १०० प्रतिशत का एक तिहाई होगा ।

(३) अतिरिक्त ह्रास (Additional Depreciation)—धारा १० (२) (vi-a) के अन्तर्गत ३१ मार्च १९४८ के बाद प्राप्त की गई नई इमारतों और नई मशीनरी एवं प्लान्ट के सम्बन्ध मे उस वर्ष के बाद जिसमे सम्पत्तियाँ प्रयोग मे लाई जाती है, आगामी ५ कर-निर्धारण वर्षों तक (सन् १९४९-५० से सन् १९५८-५९ तक), साधारण ह्रास के बराबर (जिसमे अतिरिक्त पाली का ह्रास शामिल न होगा) ह्रास की अतिरिक्त छूट (Further Allowance) दी जायगी ।

‘अप-लिखित मूल्य’ निकालने के लिये अतिरिक्त ह्रास घटाया जाएगा ।

१९५९-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए अतिरिक्त-ह्रास नहीं मिलेगा ।

(४) प्रारम्भिक ह्रास (Initial Depreciation)—नई इमारत और नई मशीनरी व प्लान्ट पर उस वर्ष के लिए, जिस वर्ष मे वे प्राप्त (Acquired) की गयी हैं, निम्नलिखित प्रारम्भिक ह्रास स्वीकार किया जाता है ।

(अ) १ अप्रैल १९४६ और ३१ मार्च १९५६ के बीच के समय मे बनवाई गयी इमारतों पर लागत का १५ प्रतिशत ।

(ब) १ अप्रैल १९४५ और ३१ मार्च १९४६ के बीच के समय मे बनवाई हुई इमारतों के सम्बन्ध में लागत का १० प्रतिशत ।

(स) ३१ मार्च १९५४ के बाद लगाई गई मशीनरी और प्लान्ट, जिन पर विकास की छूट (Development Rebate) नहीं मिलती, लागत का २० प्रतिशत प्रारम्भिक ह्रास के रूप मे पाने के अधिकारी हैं ।

यह प्रारम्भिक ह्रास साधारण ह्रास की छूट (Normal depreciation Allowance) के अतिरिक्त होता है । भले ही सम्पत्ति (Asset) गतवर्ष में ही प्राप्त की गयी हो प्रारम्भिक ह्रास की पूरी छूट स्वीकार की जायगी ।

तत्पश्चात् साधारण ह्रास (Subsequent normal depreciation)

निकालने के उद्देश्य से अपलिखित मूल्य मालूम करने के लिए प्रारम्भिक ह्रास घटाया नहीं जायगा, लेकिन किसी सम्पत्ति को अलग कर देने या बेच देने पर हानि-लाभ निकालते समय अपलिखित मूल्य निश्चित करने के लिए इस पर (प्रारम्भिक ह्रास पर) अवश्य विचार करना पड़ेगा ।

प्रारम्भिक ह्रास की छूट नई इमारतों, प्लान्ट एवं मशीनों के सम्बन्ध में, जो कि ३१ मार्च १९५६ के बाद प्रयोग में लाई जावे देनी बन्द कर दी गई है ।

अशोधित ह्रास (Unabsorbed Depreciation)

यदि किसी वर्ष व्यापार में लाभ न होने या कम लाभ होने के कारण ह्रास की पूरी या उसके कुछ भाग की छूट न मिल सके, तो ह्रास की छूट का ऐसा भाग, जो प्राप्त नहीं किया जा सका है, अशोधित ह्रास (Unabsorbed Depreciation) कहलाता है । लेकिन अन्य किसी कारण (जैसे इन्कम टैक्स ऑफिसर के सम्मुख आवश्यक विवरण प्रस्तुत न करने से) प्राप्त न की जा सकी ह्रास सम्बन्धी छूट की रकम को अशोधित ह्रास के अन्तर्गत शामिल नहीं किया जायगा ।

यदि किसी कर-दाता के पास व्यापार के अतिरिक्त आय का कोई अन्य साधन (जैसे वेतन, जायदाद से आय आदि) भी है, तो अशोधित ह्रास की पूर्ति (set off) इन साधनों से हुई आय से की जा सकती है और जो रकम इस प्रकार पूर्ति होने से बचे (the amount not so set off) उसे ही अशोधित ह्रास के रूप में आगामी वर्ष को ले जाया (Carried forward) जा सकता है ।

अशोधित ह्रास आगामी वर्षों के हिसाब में अनिश्चित समय (indefinitely) तक आगे ले जाया जा सकता है और आने वाले कर-निर्धारण वर्षों में (in subsequent assessment years) उसकी माँग की जा सकती है । लेकिन शर्त यह है कि यदि कोई व्यापारिक नुकसान भी आगामी वर्षों के हिसाब में आगे लाया गया हो, तो अशोधित ह्रास की पूर्ति से पहले व्यापारिक हानि की ही पूर्ति (set off) की जायगी । किसी विशेष वर्ष का अशोधित ह्रास आगामी वर्ष की ह्रास सम्बन्धी छूट की रकम में जोड़ा जा सकता है और उस छूट का ही भाग माना जायेगा या, यदि उस वर्ष के लिये ह्रास सम्बन्धी कोई छूट न हो तो, उस अशोधित ह्रास की रकम उस वर्ष की छूट ही मानी जायेगी । यही प्रत्येक आगामी वर्ष में होता रहेगा ।

जब कोई व्यापार किसी वर्ष बन्द कर दिया जावे तो उसका अशोधित ह्रास आगे न ले जाया जा सकेगा और अन्य किसी हानि की भाँति ही उस अशोधित ह्रास को भी पूर्ण हानि माना जायगा ।

जब किसी रजिस्टर्ड फर्म के सामेदार के कर-निर्धारण में अशोधित ह्रास पूर्ण रूप से स्वीकृत कर दिया गया है, तो फर्म के मामले में उसे आगे न ले जाया जा सकेगा ।

अप-लिखित मूल्य (Written down value)

किसी सम्पत्ति के अप-लिखित मूल्य से निम्न अभिप्राय है—

(अ) गत वर्ष में प्राप्त की गई सम्पत्तियों की दशा में, कर दाता के लिये उनकी वास्तविक-लागत (actual cost) से ।

(अ) गत वर्ष के पहले प्राप्त की गई सम्पत्तियों की दशा में, वह रकम, जो कर-दाता को सम्पत्ति की वास्तविक लागत में से ह्रास की वस्तुतः प्राप्त हुई सभी छूटे घटाने के बाद बचे ।

किसी इमारत के सम्बन्ध में, जो पहले से ही कर-दाता के अधिकार में है और २८ फरवरी १९४६ के पश्चात् व्यापारिक कार्य में प्रयोग की गई है, अपलिखित मूल्य से आशय उस रकम का है, जो कर-दाता को उस सम्पत्ति की लागत में से ऐसा सब ह्रास जो स्वीकृत किया जा सकता था यदि वह सम्पत्ति प्राप्त होने की तारीख से व्यापार के काम में लगातार प्रयोग होती रहती, घटा देने के बाद निकले । इस बीच की अवधि के लिए ह्रास की दर वह दर होगी जो इमारत को व्यापार में लगाने के दिन प्रचलित थी ।

जहाँ कोई सम्पत्ति भेंट या उत्तराधिकार (gift or inheritance) से प्राप्त हुई है, उसकी वास्तविक लागत, सम्पत्ति या अप-लिखित मूल्य (जो गत मालिक के लिए निर्धारित किया गया है) या बाजार भाव दोनों में जो कम हो, मानी जावेगी ।

सम्पत्ति की वास्तविक लागत निश्चित करते समय उसकी लागत का वह भाग, जिसे सरकार या किसी सावजनिक या स्थानीय सत्ता नै दिया है, घटा देना चाहिये ।

साधारण ह्रास की छूट (Normal Depreciation Allowance) मालूम करने के उद्देश्य से अपलिखित मूल्य निकालने के लिए, नई इमारतों और नई मशीनरी व प्लाण्ट के सम्बन्ध में दी गई प्रारम्भिक ह्रास की छूट वास्तविक लागत (Original cost) में से नहीं घटानी है किन्तु किसी सम्पत्ति को बेचने या अलग (Discard) कर देने पर हानि-लाभ निश्चित करने के उद्देश्य से अपलिखित मूल्य मालूम करने में प्रारम्भिक ह्रास को अवश्य ध्यान में रखना होगा ।

‘वस्तुतः दी गई ह्रास की छूट’ (depreciation actually allowed) वाक्यांश में अवशोषित ह्रास (unabsorbed depreciation) शामिल नहीं है । इसके अर्थ यह हुये कि किसी सम्पत्ति का अपलिखित मूल्य निकालने के लिए अवशोषित ह्रास (unabsorbed depreciation) को विचार में लेना चाहिए ।

ह्रास की दरें

व्यापार, व्यवसाय या पेशे का लाभ मालूम करते समय ह्रास सम्बन्धी छूटें देने के लिए कुछ प्रमुख दरें (जो अपलिखित मूल्य के प्रतिशतों के रूप में हैं) निम्नलिखित हैं —

बिल्डिंग — प्रथम श्रेणी (२१%)

द्वितीय श्रेणी (५%)

तृतीय श्रेणी (७½%)

बिल्कुल अस्थायी निर्माण जैसे छप्पर इत्यादि के लिये कोई घिसाई नहीं दी जाती, केवल नवकरण (renewal) की छूट मिलती है।

फैक्टरी की इमारतों के लिए इन दरों का दुगुना ह्रास दिया जाता है।

फर्नीचर — सामान्य दर (६%)

होटलों में इस्तेमाल किये जाने वाला फर्नीचर (६%)

मशीनरी और प्लान्ट :— सामान्य दर (७%)

निम्न उद्योगों के प्रयोग में आने वाली मशीनरी और प्लान्ट की विशेष दरें हैं :—

आटा मिल, चावल मिल, चीनी मिल आदि के लिए ६%, कागज मिल, इंजीनियरिंग वर्क्स आदि के लिए १०% अन्य प्रकार की मशीनरी और प्लान्ट के लिए विशेष दरें निम्न प्रकार हैं —

बिजली की मशीनरी . बैटरीज २०%, अन्य मशीनरी १०%।

टैक्सटाइल मशीनरी . सूती १०%, जूट ६%, ऊनी १०%।

हिसाब की मशीनरी और टाइप राइटर पर १५% लेकिन अतिरिक्त पाली की छूट नहीं मिलेगी (No Extra Shift Allowance) मोटरकार और साइकिलों पर २०% लेकिन अतिरिक्त पाली की छूट नहीं मिलेगी। मोटर ठेले और लारियो आदि पर २५% लेकिन अतिरिक्त पाली की छूट नहीं मिलेगी।

उदाहरण

(१) एक फर्म ने, जिसका हिसाबी वर्ष ३१ दिसम्बर को समाप्त होता है, १५ जून १९५७ को एक नई मशीनरी २०,००० रु० में खरीदी। १९५७ में यह मशीन १०० दिन दो पालियों (Double Shift) में तथा १९५८ में २०० दिन तीन पालियों में चली। यदि ह्रास की स्वीकृत दर १०% हो, १९५८-५९ तथा १९५९-६० के निर्धारण वर्षों के लिए विकास सम्बन्धी छूट तथा ह्रास की क्या छूट दी जायगी?

कर-निर्धारण वर्ष १९५८-५९

विकास सम्बन्धी छूट

२५% नई मशीन की लागत (२०,००० रु०) पर

रु०

५,०००

ह्रास

साधारण ह्रास, २०,००० रु० पर १०%, ६ माह के लिए	१,०००
दुहरी पाली की छूट, जो एक वर्ष के लिए साधारण	
ह्रास २,००० रु० के तिहाई (१००/३००) की ५०%	३३३
अतिरिक्त छूट, साधारण ह्रास के बराबर	१,०००
	<u>२,३३३</u>

कर-निर्धारण वर्ष १९५९-६०

ह्रास

साधारण ह्रास, अपलिखित मूल्य, १७,६६७ रु० पर १०%	१,७६६
तिहरी पाली की छूट, जो १,७६६ रु० के दो—तिहाई	
(२००/३००) की १००%	१,१७७
	<u>२,९४३</u>

१९६०-६१ कर निर्धारण वर्ष के लिए अपलिखित मूल्य
१७,६६७ रु० - २,९४३ रु० = १४,७२४ रु० होगा ।

(२) ३१ दिसम्बर १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एक सूती मिल कम्पनी ने ह्रास सम्बन्धी आशय के लिए निम्न विवरण प्रस्तुत किये हैं :—

भवन

	रु०	दर
कारखाने की प्रथम श्रेणी, जो १९५० से पूर्व बनी,		
१-१-१९५८ को अपलिखित मूल्य	१,००,०००	५%
वृद्धियाँ १-१-१९५८ को	५०,०००	-
गैर कारखाने की प्रथम श्रेणी, जो १९५० से पूर्व		
बनी, १-१-१९५८ को अपलिखित मूल्य	५०,०००	२½%

प्लान्ट तथा मशीन .

१९५५ में स्थापित मशीन का १-१-१९५८ को		
अपलिखित मूल्य	१,५०,०००	१०%
वृद्धियाँ (नई) १-७-१९५८ को	१,००,०००	
वृद्धियाँ (पुरानी Second-hand) १-७-१९५८ को	१,००,०००	

फर्नीचर .

१-१-१९५८ को अपलिखित मूल्य	१०,०००	६%
१-७-१९५८ को वृद्धियाँ	५,०००	

१९५९-६० कर निर्धारण वर्ष के लिए विकास सम्बन्धी छूट तथा ह्रास की छूट, की रकम तथा १-१-१९५९ को अपलिखित मूल्य निकालिए ।

विकास सम्बन्धी छूट — १-७-१९५८ को लगाई गई नई मशीन की लागत १,००,००० रु० पर २५%

२५,००० रु०

ह्रास छूट

सम्पत्ति	साधारण	१-१-१९५६ को अपलिखित मूल्य
भवन .	₹०	₹०
१ ००,००० ₹० पर ५%	५,०००	६५,०००
५०,००० ₹० पर ५%, ६ माह के लिए	१,२५०	४८,७५०
५०,००० ₹० पर २½%	१,२५०	४८,७५०
प्लाण्ट तथा मशीन .		
१,५०,००० ₹० पर १०%	१५,०००	१,३५,०००
१,००,००० ₹० पर १०%, ६ माह के लिए	५,०००	६५,०००
(नई)		
१,००,००० ₹० पर १०%, ६ माह के लिए	५,०००	६५,०००
(पुरानी)		
फर्नीचर		
१०,००० ₹० पर ६%	६००	६,४००
५,००० ₹० पर ६%, ६ माह के लिए	१५०	४,८५०
	<u>३३,२५०</u>	<u>५,३१,७५०</u>

१९५६-६० कर-निर्धारण वर्ष से नए भवन तथा नई प्लाण्ट तथा मशीन पर अतिरिक्त ह्रास नहीं दिया जाएगा ।

(३) एक कागजी व्यापारी ने, जिसका हिसाबी वर्ष ३१ मार्च को समाप्त होता है, अपने व्यापार के लिए १ अक्टूबर १९५५ को २०,००० ₹० की लागत से एक भवन को बनवा कर समाप्त किया । १९५८-५९ के १,००० ₹० की ह्रास की छूट अशोषित (unabsorbed) रही ।

ह्रास दर ५% लेते हुए, १९५६-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए ह्रास की छूट की रकम निकालिए ।

कर-वर्ष	₹०	₹०
१९५६-५७ प्रारम्भिक ह्रास—२०,००० ₹० पर १५%	<u>३,०००</u>	
साधारण ह्रास—२०,००० ₹० पर ५%		
६ माह के लिए	५००	
अतिरिक्त ह्रास—साधारण के बराबर	<u>५००</u>	<u>१,०००</u>
१९५७-५८ साधारण ह्रास—अपलिखित मूल्य		
१९,००० ₹० पर ५%	९५०	
अतिरिक्त ह्रास—साधारण के बराबर	<u>९५०</u>	<u>१,९००</u>

१९५८-५९ साधारण ह्रास—अपलिखित मूल्य		
१७,१०० रु० पर ५%	८५५	
अतिरिक्त ह्रास—साधारण के बराबर	८५५	
	<hr/>	
घटाया—अशोधित ह्रास आ/ले	१,७१०	
	१,०००	७१०
	<hr/>	<hr/>
१९५९-६० साधारण ह्रास—अपलिखित मूल्य		
१६,३९० रु० पर ५%	८१९	
अशोधित ह्रास—१९५८-५९ से लाया गया	१,०००	१,८१९
	<hr/>	<hr/>

(४) ३१ जुलाई १९५८ को एक व्यक्ति एक नया व्यापार चालू करता है और इसके लिये वह एक अन्य व्यक्ति से, जिसने मई १९५५ में १०,००० रु० की लागत से अपने भवन में मशीन लगाई थी और जो अपना व्यापार बन्द कर रहा है, उससे २०,००० रु० में मशीन खरीदता है। मशीन तथा भवन पर प्रस्तावित ह्रास की दर ९% व २३% क्रमशः है। उसका हिसाबी वर्ष २१ मार्च को बन्द होता है।

यदि कर-दाता अपने प्रथम कर-निर्धारण वर्ष १९५९-६० में विकास सम्बन्धी छूट माँगे तथा भवन तथा मशीन पर ह्रास की छूट की मांग करे तो आप कहाँ तक देंगे ?

क्योंकि उसके द्वारा प्रतिस्थापित मशीन नई नहीं है वह मशीन के लिए किसी विकास सम्बन्धी छूट पाने का अधिकारी नहीं है।

१९५९-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए ह्रास की छूट निम्न प्रकार से होगी —

भवन .	रु०
साधारण ह्रास ८५८० रु० (नीचे हिसाब लगाने से लागत)	
पर २३% ८ मास के लिए	१४३
मशीन :	
साधारण ह्रास २०,००० रु० पर ९% ८ माह के लिये	१,२००
१९५९-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिये ह्रास की छूट	१,३४३
	<hr/>

किसी इमारत के सम्बन्ध में जो पहले से ही कर-दाता के अधिकार में है और २८ फरवरी १९४८ के बाद व्यापारिक कार्य में प्रयोग की गई है, अपलिखित मूल्य से आशय उस रकम का है, जो कर-दाता को उस सम्पत्ति लागत में से ऐसा सब ह्रास, जो स्वीकृत किया जा सकता था यदि वह सम्पत्ति प्राप्त होने की तारीख से व्यापार में लगातार प्रयोग होती रहती, घटा देने के बाद निकले। इस नियम के अनुसार भवन का अपलिखित मूल्य निम्न प्रकार से निकाला जायगा —

मई १९५५ में प्रारम्भिक मूल्य	रु०	रु०
	•	१०,०००

घटाया—स्वीकृत ह्रास

कर-निर्धारण वर्ष १९५६-५७ .

साधारण १०,००० रु० पर २३%

१० माह के लिए

२०८

अतिरिक्त, साधारण के बराबर

२०८

कर-निर्धारण वर्ष १९५७-५८

साधारण, अपलिखित मूल्य ६,५८५

पर २३%

२३६

अतिरिक्त, साधारण के बराबर

२३६

कर-निर्धारण वर्ष १९५८-५९ .

साधारण अपलिखित मूल्य ६,१०६ रु०

पर २३%

२२७

अतिरिक्त, साधारण के बराबर

२२७

कर-निर्धारण वर्ष १९५९-६०

साधारण, अपलिखित मूल्य ८,६५२ रु०

पर २३% ४ माह (अप्रैल से जुलाई

१९५८) का

७२

१,४२०

अपलिखित मूल्य

८,५८०

इस भवन के लिए कर निर्धारण वर्ष १९५६-५७ के लिए १५% प्रारम्भिक ह्रास मिलता है, लेकिन प्रारम्भिक ह्रास, साधारण ह्रास मालूम करने के लिए अपलिखितमूल्य पर आने के लिए नहीं घटता है ।

(५) एक इजीनियरिंग कम्पनी अपनी किताबें ३१ दिसम्बर को बन्द करती है । निम्न सूचनाओं से १९५९-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिये विकास सम्बन्धी छूट तथा ह्रास की छूट की गणना कीजिये .—

भवन	१९५१ से पूर्व बना लागत	४,००,०००
	१-१-१९५७ को वृद्धियाँ लागत	१,५०,०००
	१-७-१९५८ को वृद्धियाँ लागत	५,०००
	ह्रास जो वास्तव में १९५८-५९ तक और कर-निर्धारण वर्ष १९५८-५९ को मिलाते हुए स्वीकृत किया	८०,०००
	ह्रास की दर ५% ।	
मशीन	१९५१ से पूर्व लगी लागत	६,००,०००
	१-१-१९५७ को वृद्धियाँ लागत	१,००,०००
	१-७-१९५८ को वृद्धियाँ लागत	२,००,०००
	ह्रास जो वास्तव में १९५८-५९ तक और कर-निर्धारण वर्ष १९५८-५९ को मिलाते हुए स्वीकृत हुआ	१,६०,०००
	ह्रास की दर १०% ।	

१९५८ वर्ष में मशीन, जोकि १९५८ से पहले लगाई गई थी, में १०० दिन के लिए दोहरी पाली में और ३० दिन के लिए तिहरी पाली में काम किया।

विकास सम्बन्धी छूट •

नई मशीन की लागत २,००,००० रु० पर २५%

रु०

५०,०००

ह्रास :

भवन .

साधारण ह्रास ३,३५,००० (४,००,०००—
६५,०००) पर, जो कि १९५१ से पूर्व बनी

इमारत का अपलिखित मूल्य है, ५%

१६,७५०

साधारण ह्रास १,३५,००० रु० (१,५०,०००—
१५,०००) पर जो कि १-१-१९५७ की वृद्धियों

का अपलिखित मूल्य है, ५%

६,७५०

साधारण ह्रास ५०,००० रु० पर, जो कि

१-७-१९५८ को वृद्धियाँ हैं, ५% ६ माह के

लिए

१,२५०

२४,७५०

मशीन

साधारण ह्रास ४,६०,००० रु० पर (६,००,०००—
१,४०,०००) जो कि १९५१ से पूर्व लगी मशीन

का अपलिखित मूल्य है, १०%

४६,०००

साधारण ह्रास ८०,००० रु० पर (१,००,०००—
२०,०००), जो कि १-१-१९५७ को लगी

मशीन का अपलिखित मूल्य है, १०%

८,०००

साधारण ह्रास २,००,००० रु० पर जो कि

१-७-१९५८ को लगाई गई, १०% ६ माह के लिए

१०,०००

दुहरी पाली की छूट—साधारण ह्रास ५४,००० रु०

के तिहाई (१००/३००) का ५०%

६,०००

तीहरी पाली की छूट—साधारण ह्रास ५४,००० रु०

के दसवें भाग (३०/३००) का १००%

५,४००

७८,४००

१९५९-६० कर-निर्धारण के लिए ह्रास की छूट

१,०३,१५०

(५) सतुलनीय घिसाई (Balancing Depreciation).—यदि व्यापार के काम में आने वाली कोई मशीनरी, प्लांट या इमारत बेच दी जावे या अलग कर दी

जाय, अथवा गिरा दी जाय या नष्ट हो जाय तो उसके अप-लिखित मूल्य [अर्थात् लागत में से समस्त ह्रास, जिसके अन्दर प्रारम्भिक ह्रास भी (यदि कोई है) शामिल हो, घटाने के बाद जो रकम शेष रहे) में से बिक्री मूल्य (Sale Price) या अवशिष्ट मूल्य (Scrap value) (जैसी भी दशा हो)] घटाकर जो रकम आए, उसे सतुलन (Balancing Depreciation) के रूप में निम्न के अधीन स्वीकृत किया जाता है —

(अ) कर-दाता के बही-खातो में हानि की रकम सचमुच ही अपलिखित (Write off) कर दी गई हो ।

(ब) बिक्री मूल्य (Sale Price) का अपलिखित मूल्य (Written down value) पर आधिक्य पिछले वर्षों में वस्तुतः दी गई ह्रास सम्बन्धी कुल छूट की सीमा तक, कर लगने योग्य लाभ माना जायगा । लेकिन सम्पत्ति की लागत पर बिक्री मूल्य का कोई अन्य आधिक्य पूँजी लाभ (Capital surplus) होगा और उस पर कर नहीं लगेगा ।

(स) बीमा अथवा क्षति-पूर्ति के रूप में प्राप्त हुई रकम बिक्री के घन (Sale proceeds) या सम्पत्ति के अवशिष्ट मूल्य (Scrap value) का अंश ही मानी जायगी ।

(द) ऐसी सम्पत्ति के लिये, जिसे पूर्ण रूप से व्यापार के काम में नहीं लाया गया, सतुलनीय ह्रास की केवल आनुपातिक रकम की छूट में दी जायगी ।

जब सम्पत्ति को अलग (discard) कर देने के आधार पर संतुलनीय ह्रास की माँग की जावे, तब इसकी माँग उसी वर्ष में करनी चाहिये जिस वर्ष कि उससे काम लेना वास्तव में बन्द किया गया लेकिन यह बन्धन अलग की हुई सम्पत्ति को बाद में वास्तव में बेच देने से हुई हानि के लिये अधिक ह्रास (Further depreciation) माँगने पर लागू नहीं होगा ।

उदाहरण

(१) एक लिमिटेड कम्पनी के पास, जिसका हिसाबी वर्ष ३१ दिसम्बर को समाप्त होता है, ५०,००० रु० लागत की एक मशीनरी है । उसे सितम्बर १९५७ में अलग कर दिया गया । उस समय इसका अवशिष्ट मूल्य (Scrap value) १०,००० रु० आँका गया । इस मशीनरी पर १९५७-५८ के कर-निर्धारण वर्ष तक (और उस वर्ष के लिये भी मिलाते हुए) कुल २७,००० रु० ह्रास की माँग की गई । तत्पश्चात् मई, १९५८ में वह मशीनरी ८,००० रु० में बेच दी गयी ।

इस मशीनरी के लिए सतुलनीय ह्रास की रकम क्या होगी ? और यदि यह अलग की हुई मशीनरी १२,००० रु० में बेची गयी हो तो क्या स्थिति होगी ?

१०,००० रु० अवशिष्ट मूल्य के आधार पर १९५८-५९ के कर निर्धारण वर्ष में १३,००० रु० के सतुलनीय ह्रास की माँग की जा सकती है, और ८,००० रु० के वास्तविक बिक्री मूल्य पर १९५९-६० में सतुलन ह्रास के सम्बन्ध में २,००० रु० अधिक छूट (Further) माँगी जा सकती है।

यदि अलग की हुई मशीनरी वास्तव में १२,००० रु० में बेच दी गई है तो १९५९-६० के कर-निर्धारण वर्ष के लिये कर लगने योग्य लाभ २,००० रु० होगा, क्योंकि १०,००० रु० के अवशिष्ट मूल्य के आधार पर १९५८-५९ के कर निर्धारण वर्ष में १३,००० रु० की सतुलनीय ह्रास की माँग की गयी थी।

(२) मशीनरी की लागत १,००,००० रु० है। प्रारम्भिक ह्रास घटाने के बाद इसका अपलिखित मूल्य ४०,००० रु० है। यदि यह मशीनरी ३०,००० रु०, ४०,००० रु०; ७०,००० रु०, १००,००० रु०, या १,२०,००० रु० में बेची जाती तो ह्रास के सम्बन्ध में क्या स्थिति होगी।

(अ) जब मशीन ३०,००० रु० में बेची जावे तो सतुलनीय ह्रास १०,००० रु० होगा।

(आ) यदि मशीन ४०,००० रु० में बिकती है, तो सतुलनीय ह्रास कुछ भी नहीं होगा और न कर लगने योग्य लाभ ही कुछ होगा।

(इ) यदि वह ७०,००० रु० में बिकती है तो ३०,००० रु० का कर लगने योग्य लाभ होगा।

(ई) यदि वह १,००,००० रु० में बिके, तो कर लगने योग्य लाभ ६०,००० रु० होगा।

(उ) यदि मशीन १,२०,००० रु० में बेची जाय, तो ६०,००० रु० कर लगने योग्य लाभ होगा और २०,००० रु० पूँजीगत लाभ होगा।

(३) मशीनरी की लागत १,००,००० रु० है। प्रारम्भिक ह्रास घटा देने के पश्चात् इसका अपलिखित मूल्य ४०,००० रु० है। इसका बीमा भी हो चुका था। किन्तु वह नष्ट हो गयी और उसका अवशिष्ट मूल्य (Scrap value) १०,००० रु० आका गया। यदि प्राप्त बीमे की रकम २०,००० रु०, ३०,००० रु०, ६०,००० रु०, ९०,००० रु० या १,१०,००० रु० हो तो ह्रास की क्या स्थिति होगी ?

(अ) यदि बीमे से २०,००० रु० मिला है, तो सतुलनीय ह्रास १०,००० रु० है।

(आ) यदि बीमे से ३०,००० रु० मिला है, तो सतुलनीय ह्रास कुछ नहीं है और कर लगने योग्य लाभ भी कुछ नहीं होगा।

(इ) यदि बीमे से ६०,००० रु० मिलता है, तो कर लगने योग्य लाभ की रकम ३०,००० रु० होगी।

(ई) यदि बीमे से ६०,००० रु० मिला है, तो कर लगने योग्य लाभ ६०,००० रु० होगा ।

(उ) यदि बीमे से १,१०,००० रु० प्राप्त हुआ है, तो कर लगने योग्य लाभ ६०,००० रु० और पूँजीगत लाभ २०,००० रु० होगा ।

(४) एक कम्पनी ने ३,५०,००० रु० लागत की नई मशीन से १ जनवरी १९५५ को व्यापार आरम्भ किया । वह अपने हिसाब ३१ दिसम्बर को बन्द करती है । १ जनवरी १९५८ को काटखाने में आग लग गई और मशीन नष्ट हो गई । क्योंकि कम्पनी ने मशीन का बीमा कराया था, इसलिये उसे १,५०,००० रु० क्षति-पूर्ति स्वरूप प्राप्त हुये । ह्रास की दर १०% मानने हुए, १९५६-६० के कर-निर्धारण वर्ष में कर-योग्य लाभ या छोड़ी जाने वाली हाति आय-कर अधिनियम की धारा १० (२) (vii) के आदेशानुसार निकालिए ।

कर-वर्ष	रु०	रु०
१९५६-५७ मशीन की लागत		३,५०,०००
प्रारम्भिक ह्रास २०%	७०,०००	
साधारण ह्रास	३५,०००	
अतिरिक्त ह्रास	३५,०००	७०,०००
१९५७-५८ आपलिखित मूल्य		२,८०,०००
साधारण ह्रास	२८,०००	
अतिरिक्त ह्रास	२८,०००	५६,०००
१९५८-५९ अपलिखित मूल्य		२,२४,०००
साधारण ह्रास	२२,४००	
अतिरिक्त ह्रास	२२,४००	४४,८००
१९५९-६० वार्षिक ह्रास के लिए		
अपलिखित मूल्य		१,७६,२००
बटाओ प्रारम्भिक ह्रास		७०,०००
धारा १० (२) (viii) के अनुसार		
अपलिखित मूल्य		१,०६,२००
बीमे से प्राप्त रकम		१,५०,०००
धारा १० (२) (vii) के अन्तर्गत कर-योग्य लाभ		४०,८००

(५) एक काटन मिल कम्पनी का हिसाबी वर्ष ३१ दिसम्बर को समाप्त होता है और उसकी ह्रासित सम्पत्तियों का विवरण निम्न है —

सम्पत्तियाँ	१-१-१९५८ को अपलिखित मूल्य	१९५८ में वृद्धियाँ	ह्रास की दर
मिल भवन (प्रथम श्रेणी)	₹ १५,४७,३८०	—	५०%
गोदाम (द्वितीय श्रेणी)	₹ २,१५,७४०	—	५०%
मिल मशीन	₹ ३३,१७,६६५	₹ ४,४५,६७०	१००%
मोटर ट्रक	₹ ४५,७००	—	२५%
फर्नीचर	₹ २५,१७०	—	६%

एक गोदाम (जिसका १-१-१९५८ को अपलिखित मूल्य ₹ १,१५,६०० ₹ था) मई १९५८ में आग से पूरी तरह नष्ट हो गया है, तथा इसके लिए बीमा कम्पनी ने ₹ १,००,००० ₹ प्राप्त हुए।

यह मानते हुए कि अतिरिक्त मशीन ३० जून १९५८ को लगाई गई १९५६-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए विकास सम्बन्धी छूट तथा ह्रास की रकम निकालिए।

₹

१ विकास सम्बन्धी छूट १९५८ में लगाई गई नई मशीन की लागत ₹ ४,४५,६७० ₹ पर २५%	₹ १,११,४६२
२. ह्रास—जैसा कि नीचे गणना की गई है	₹ ४,६४,६७८
१९५६-६० के लिए छूट	₹ ५,७६,४७०
मिल भवन . साधारण ह्रास ₹ १५,४७,३८० ₹ पर ५%	₹ ७७,३६९
३१-१२-१९५८ को गोदाम . साधारण ह्रास—	
₹ १,००,१४० ₹ (₹ २,१५,७४० ₹ - ₹ १,१५,६०० ₹) पर ५%	₹ ५,००७
समाप्त हुआ गोदाम . सतुलनीय ह्रास (₹ १,१५,६०० ₹ - ₹ १,००,००० ₹)	₹ १५,६००
मिल मशीन	
साधारण ह्रास ₹ ३३,१७,६६५ ₹ पर १०%	₹ ३,३१,७६६
साधारण ह्रास ₹ ४,४५,६७० ₹ पर १०%, ६ माह के लिए	₹ २२,२६८
मोटर ट्रक : साधारण ह्रास ₹ ४५,७०० ₹ पर २५%	₹ ११,४२५
फर्नीचर . साधारण ह्रास ₹ २५,१७० ₹ पर ६%	₹ १,५१०
कुल ह्रास	₹ ४,६४,६७८

कुल आय और कुल विश्व आय (Total Income and Total World Income)

पिछले अध्याय में विभिन्न मदों के अन्तर्गत कर लगने योग्य आय मालूम करने की रीति समझाई गई थी, इस अध्याय में कर-दाता की कुल आय और कुल विश्व आय मालूम करने की विधि बतायी जायगी।

कुल आय (Total Income)

कर-दाता की कुल आय से आशय उसकी आय की कुल रकम से है, जिस पर उसके निवास स्थान के आधार पर कर लगता है और जो सन्नियम द्वारा निर्धारित तरीके से मालूम की गई है।

कुल विश्व आय (Total World Income)

कर-दाता की कुल विश्व आय से अभिप्राय उसकी समस्त आय से है, भले ही वह कहीं भी उत्पन्न हुई हो। निम्न अपवादों को छोड़कर, वे आय (incomes) जो कुल आय में शामिल नहीं की जाती कुल विश्व आय में भी शामिल नहीं करना चाहिये —

(1) किसी निवासी (resident) की न भेजी हुई विदेशी आय (Un-re-mitted foreign income) में से ४,५०० रु० की वैधानिक कटौती (Statutory Deduction)।

(11) किसी व्यक्ति द्वारा एक हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य होने के नाते परिवार की आय में से प्राप्त की हुई रकम।

ये दो प्रकार की आय कुल आय में शामिल नहीं की जाती, लेकिन उनको कुल विश्व आय में शामिल कर लेना चाहिए।

कुल विश्व आय मालूम करने के लिए सन्नियम के निम्नलिखित आदेश हैं:—

घाटे की पूर्ति (Set-off Losses) — आय-कर तो केवल एक ही कर है अर्थात् आय की जितनी मदें हैं उतने कर नहीं हैं। इसलिये यदि कर-दाता को किसी वर्ष की किसी मद में हानि हो जावे तो वह उस हानि की (जो पूर्ण हानि न हो) पूर्ति कर-निर्धारण वर्ष की किसी अन्य मद के अन्तर्गत प्राप्त हुई आय से कर

सकता है। धारा १०, जिसमें व्यापारिक आय की चर्चा है, स्वयं एक स्वतन्त्र मद है। भिन्न-भिन्न व्यापार आय के पृथक्-पृथक् मद नहीं हैं। सभी व्यापार, जहाँ कहीं भी वे किए जाते हों, आय के एक ही मद का निर्माण करते हैं। इसलिए व्यापार का कर-योग्य लाभ मालूम करने के लिए कर-दाता को अपने समस्त लाभ दिखाने और उन आयों में से उसी मद के अन्तर्गत हुई समस्त हानियों को काटने का अधिकार होता है।

यदि कर-दाता अनरजिस्टर्ड फर्म हो तो जो घाटा उसे आय की किसी एक मद में हुआ है उसकी पूर्ति उसी वर्ष के किसी अन्य मद के अन्तर्गत हुई आय से की जा सकती है। परन्तु किसी भी साभेदार को व्यक्तिगत रूप से फर्म के अपने भाग के घाटे की पूर्ति उसी वर्ष की अपनी आय में से करने का अधिकार नहीं है।

यदि कर-दाता एक रजिस्टर्ड फर्म है, तो जो घाटा उसे आय के किसी एक मद में हुआ है उसकी पूर्ति उसी वर्ष की अन्य मद से होने वाली आय से की जा सकती है। वह हानि, जिसकी इस प्रकार पूर्ति न की जा सकती हो, साभेदारों में विभाजित कर देनी चाहिए और प्रत्येक साभेदार फर्म की हानि के अपने भाग की पूर्ति उस वर्ष की अपनी आय के किसी अन्य मद से कर सकता है।

व्यापार, व्यवसाय और पेशे के लाभ मालूम करने के लिए, सट्टे की हानि (Speculation Losses) की पूर्ति केवल सट्टे के लाभों से ही की जा सकती है।

जहाँ हानि ऐसी हानि है जो कि पूँजी लाभ के शीर्षक में आती है तो वहाँ ऐसी हानि केवल उसी लाभ से अपलिखित की जा सकती है, जो कि इस शीर्षक के अन्तर्गत आता हो।

(२) व्यापारिक हानियों का आगे ले जाना (Carry forward of Business Losses)—यदि व्यापार में किसी वर्ष हानि हो और वह उस वर्ष की किसी अन्य आय से पूरी न हो सके, तो हानि की यह रकम आगे ले जाई जा सकती है और व्यापार के लाभों से अगले ८ वर्षों में पूरी की जा सकती है।

अब यह छूट और दी गई है कि आगे लाई गई व्यापारिक हानियाँ न केवल इसी व्यापार के लाभों से अपितु कर-दाता के अन्य व्यापार के लाभ से भी पूरी की जा सकती हैं, बशर्ते कि हानि उठाने वाला व्यापार अब भी चालू है।

जहाँ सट्टे की हानि उसी वर्ष सट्टे के लाभों से पूर्णतः काटी न जा सके तो उस दशा में ८ वर्ष तक उसे आगे ले जा सकते हैं और सट्टे के लाभ से पूरा कर सकते हैं।

यदि किसी वर्ष की पूँजी हानियाँ उसी वर्ष के पूँजी लाभों से पूर्णतः अपलिखित न की जा सकें तो उन्हें पूँजी लाभों से अपलिखित करने के लिए ८ वर्ष तक आगे ले जाया जा सकता है। ऐसे अग्र-नयन की अनुमति के लिए यह आवश्यक है कि गैर कम्पनी कर-दाताओं की दशा में किसी गत वर्ष के दौरान में उठाई हुई पूँजी हानि ५,००० रु० से अधिक हो।

रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड फर्मों की व्यापारिक हानियों को आगे ले जाने के सम्बन्ध में भी वे ही नियम लागू होते हैं जो हानियों की पूर्ति के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

व्यापारिक हानियों के आगे ले जाने में सन्निहित सिद्धान्त यह है कि हानियों को आगे ले जाने और उसकी पूर्ति का अधिकार केवल उस व्यक्ति को ही प्राप्त है जिसको हानि हुई है, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं। यदि किसी फर्म के सगठन में कोई परिवर्तन हुआ है अथवा व्यापार में कोई नया साझेदार आया है (उत्तराधिकार प्रथा के अतिरिक्त किसी अन्य ढंग से) तो केवल उस व्यक्ति को ही, जिसे वास्तव में हानि हुई है अपनी आय में से उस हानि की पूर्ति करने का अधिकार है। उदाहरण के लिए, यदि किसी फर्म के विधान में परिवर्तन हुआ है तो फर्म को साझेदारी से पृथक् हुए साझेदार (outgoing partner) की हानि का भाव आगे ले जाने और पूर्ति करने का अधिकार नहीं है और न कोई अन्य साझेदार ही, जो ऐसी हानि में भागी नहीं है, इस हानि के किसी भाग के लाभ पाने का अधिकारी हो सकता है।

हानि सूचित करने को आज्ञा (Order notifying losses)

कर-दाता की कुल आय का कर-निर्धारण के दौरान में जब यह साबित हो जाता है कि लाभ की हानि हुई है (There is a loss of profits), जिसे आगे लाने का कर-दाता को अधिकार है, तो आय कर अधिकारी को इस हानि की लिखित सूचना कर-दाता के पास भेज देनी चाहिए। इससे हानि की रकम के सम्बन्ध में भविष्य में कोई झगडा न उठेगा।

उदाहरण

(१) एक कर-दाता द्वारा दी गई निम्न सूचनाओं से १९५६-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए कर-योग्य लाभ या हानि आगे ले जाने के लिए रकम निकालिए, —

	रु०
(१) १९५२-५३ के लिए हानि आगे ले जाई गई	२,००,०००
(२) १९५३-५४ के लिए हानि आगे ले जाई गई	३०,०००
१९५३-५४ के लिए ह्रास छूट आगे ले जाई गई	१०,०००
(३) १९५४-५५ के लिए हानि आगे ले जाई गई	२०,०००
१९५४-५५ के लिए ह्रास छूट आगे ले जाई गई	१०,०००
(४) १९५५-५६ के लिए हानि आगे ले जाई गई	१०,०००
१९५५-५६ के लिए ह्रास छूट आगे ले जाई गई	५,०००
(५) १९५६-५७ के लिए हानि आगे ले जाई गई	१०,०००
१९५६-५७ के लिए ह्रास छूट आगे ले जाई गई	५,०००
(६) १९५७-५८ के लिए लाभ	३०,०००
१९५७-५८ के लिए वाजिब (due) ह्रास	१०,०००
(७) १९५८-५९ के लिए लाभ	१,००,०००
१९५८-५९ के लिए वाजिब ह्रास	२०,०००

(८) १९५६-६० के लिए लाभ		२,२०,०००
१९५६-६० के लिए वाजिब ह्रास		२०,०००
कर-निर्धारण वर्ष	हानि रु०	अशोधित ह्रास रु०
१९५२-५३ रकम आगे ले जाई गई	२,००,०००	—
१९५३-५४ " " " " "	३०,०००	१०,०००
१९५४-५५ " " " " "	२०,०००	१०,०००
१९५५-५६ " " " " "	१०,०००	५,०००
१९५६-५७ " " " " "	१०,०००	५,०००
१९५७-५८ लाभ	३०,०००	
घटाया वाजिब ह्रास	१०,०००	
	२०,०००	
१९५२-५३ की हानि काटी गई ।		
शेष १,८०,००० रु० तथा अन्य		
वर्षों की हानि आ/ले		
	२०,०००	
१९५८-५९ लाभ	१,००,०००	
घटाया वाजिब ह्रास	२०,०००	
	८०,०००	
१९५२-५३ की हानि काटी गई ।		
शेष १,००,००० रु० तथा अन्य		
वर्षों की हानि आ/ले		
	८०,०००	
१९५९-६० लाभ	२,२०,०००	
घटाया वाजिब ह्रास	२०,०००	
	२,००,०००	
हानियाँ १९५२-५३ से		
१९५६-५७ तक काटी गई		
	१,७०,०००	
	३०,०००	
अशोधित ह्रास १९५३-५४ से		
१९५६-५७ तक काटा गया		
	३०,०००	
	नहीं	

इस प्रकार १९५६-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए आय कुछ नहीं है, न ही कोई हानि या अशोधित ह्रास आगे ले जाने को है ।

(२) यदि अ, ब और स की फर्म का पुनर्संयोजन हो, जिसमें अ तो रिटायर हो जावे और द सामेदारी में शामिल हो, तो अ फर्म को छोड़ने से पुरानी फर्म द्वारा उठाई गई हानि में अपने भाग की हानि आगे ले जाने (Carry forward) के अधिकार से वंचित हो जाता है। हाँ उसे उसी वर्ष में इस हानि की पूर्ति अपने किसी अन्य लाभ से करने का अधिकार रहता है।

यही नहीं, ब, स और द इस हानि को प्राप्त (acquire) नहीं करते और वे भावी लाभों में अपने भाग के विरुद्ध A के भाग की हानि पूर्ति करने की माँग नहीं कर सकते।

(३) यदि अ का व्यापार ब के हाथ आ जाता है और अ को कोई हानि होती है, तो वह इस हानि को आगे ले जाने के अधिकार से वंचित हो जाता है और ब भी अपने लाभ में से अ द्वारा उठाई गई हानि को पूरी करने की माँग नहीं कर सकता।

(४) एक जूट मिल कम्पनी ने, जिसका हिसाबी वर्ष ३१ दिसम्बर को बन्द होता है, १ जनवरी १९५७ को एक नई मशीन ५०,००० रु० की खरीदी जिस पर स्वीकृत ह्रास की दर ६% है।

यह मशीन बराबर दोहरी पाली में प्रयोग की गई है। हाँ, १९५८ में केवल ६० दिन यह तिहरी पाली में प्रयोग हुई।

१९५८-५९ एव १९५९-६० के कर निर्धारण वर्षों के लिए यह मानते हुए ह्रास की छूट की रकम निकालो कि ७,००० रु० की सीमा तक ह्रास १९५८-५९ के कर-निर्धारण वर्ष में नहीं मोंगा जा सका था।

१९५८-५९ कर-निर्धारण वर्ष के लिए

विकास सम्बन्धी छूट—५०,००० रु० पर २५%	रु० १२,५००
--------------------------------------	---------------

साधारण ह्रास—५०,००० रु० पर ६%	४,५००
-------------------------------	-------

अतिरिक्त ह्रास—साधारण के बराबर	४,५००
--------------------------------	-------

दोहरी पाली की छूट—(साधारण से आधा)	२,२५०
-----------------------------------	-------

	११,२५०
--	--------

घटाया अशोधित ह्रास	७,०००
--------------------	-------

१९५८-५९ कर-निर्धारण वर्ष के लिए ह्रास की छूट	४,२५०
--	-------

१९५९-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए

साधारण ह्रास—४५,७५० रु० पर ६%	४,११७
-------------------------------	-------

दोहरी पाली की छूट— $\frac{१}{४}$ वर्ष (३०० दिन में से २४० दिन)	
--	--

के लिए साधारण ह्रास का आधा	१,६४६
----------------------------	-------

तिहरी पाली की छूट— $\frac{१}{४}$ वर्ष (३०० दिन में से ६० दिन)	
---	--

के लिए साधारण ह्रास के बराबर	८२३
------------------------------	-----

६,५८६

अशोधित ह्रास—१९५८-५९ कर-निर्धारण वर्ष से लाये गए
(अगर लाभ आजा दें)

७,००९

१९५९-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए ह्रास की छूट

१३,५८६

(३) कर-मुक्त आय (**Exempted Income**)—जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया है, कर-मुक्त आय दो प्रकार की है। प्रथम वह जो कर से मुक्त है और कुल आय में शामिल नहीं की जाती तथा दूसरी वह जो कर से मुक्त तो है लेकिन कुल आय में शामिल की जाती है। इसलिए दूसरे प्रकार के अन्तर्गत आने वाली आय को कर-दाता की कुल आय में शामिल करना चाहिए।

(४) फर्म की आय या हानि का हिस्सा (**Share of Firm's Income or Loss**)—यदि कर-दाता किसी फर्म में साझीदार है, तो उसकी कुल आय मालूम करने के लिए फर्म की हानि-लाभ में उसका हिस्सा वह होता है जो वेतन, व्याज, कमीशन अथवा फर्म द्वारा दिया जाने वाला कोई अन्य पारिश्रमिक फर्म के हानि-लाभ में उसका हिस्सा घटाने या जोड़ने के बाद निकलता है। फर्म के लाभ और नुकसान को साझीदारों में विभाजित (allocate) करने की विधि 'आय कर-दाता' से सम्बन्धित आगामी अध्याय में समझाई गई है।

(५) बन्दोबस्त या व्यवस्था (**Settlements**)—जब कोई सम्पत्ति या उससे होने वाली आय या दोनों ही पुरस्कार (Gift) के रूप में किसी को हस्तांतरित की जावे तो यह बन्दोबस्त (settlement) कहलाता है। कुल आय मालूम करने के सम्बन्ध में बन्दोबस्त के निम्न प्रभाव होते हैं—

(अ) यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का बन्दोबस्त किसी दूसरे व्यक्ति के पक्ष में करता है और वह सम्पत्ति, जिसकी आय इस प्रकार दी गई है, बन्दोबस्त करने वाले व्यक्ति के स्वामित्व में ही रहे, तो ऐसी आय बन्दोबस्त करने वाले की ही आय मानी जाती है और इसे उसकी कुल आय में शामिल करना चाहिए।

(आ) यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपनी सम्पत्ति की खण्डनीय हस्तांतरण (Revocable Transfer) करता है, तो इस सम्पत्ति की आय बन्दोबस्त करने वाले व्यक्ति की ही आय मानी जायगी और इसे उसकी कुल आय में शामिल करना चाहिए।

उपर्युक्त दोनों नियमों का एक अपवाद है। वह यह कि उस सम्पत्ति या आय के बन्दोबस्त (settlement) से होने वाली आय, जो ६ वर्ष से अधिक समय तक या इसे प्राप्त करने वाले (beneficiary) के जीवन पर्यन्त खण्डनीय नहीं है,

और उससे हस्तांतरण करने वाला कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ न उठाता हों, बन्दोबस्त करने वाले की आय नहीं मानी जायगी ।

(इ) यदि कोई व्यक्ति सम्पत्ति का अखण्डनीय हस्तांतरण (Irrevocable transfer) करता है तो ऐसी सम्पत्ति की आय प्राप्त करने वाले की आय ही मानी जायगी बशर्ते कि यह हस्तांतरण कर-दाता की स्त्री या नाबालिग बच्चे के प्रति न हो ।

(६) बेनामी लेन-देन (Benami Transactions).—‘बेनामी’ शब्द से मतलब बिना नाम से है । बेनामी लेन-देन वह है, जो वास्तविक व्यक्ति के नाम से न करके दूसरे के नाम से किया जाता हो । उदाहरण के लिए, कर बचाने के लिए कोई व्यक्ति नाम मात्र के लिए या दिखाने के लिए ही अपनी सम्पत्ति किसी दूसरे के नाम करदे या कोई सम्पत्ति खरीदते समय अपने नाम से उसे न खरीद कर किसी अन्य व्यक्ति के नाम से खरीद ले तो यह बेनामी लेन-देन ही होगा । कर-निर्धारण के लिए इनकम टैक्स अफसर को यह अधिकार है कि वह सम्पत्ति के असली म्वामी का पता लगाए और इस सम्पत्ति की आय को उसकी कुल आय में जोड़कर उसके ऊपर कर-निर्धारण करे ।

(७) लाभांश (Dividends).—किसी अशुधारी को प्राप्त हुआ लाभांश जिस वर्ष वह घोषित हो उस वर्ष अशुधारी की आय मानी जाती है, और अशुधारी की कुल आय मालूम करने के लिए लाभांश की रकम को जो उस कम्पनी से, जिस पर भारतीय आय-कर लागू होता है, वास्तव में प्राप्त की जावे, ग्राँस करके व्यक्ति की कुल आय में जोड़ देना चाहिए । ग्राँस करने की विधि पहले ही बतला दी गई है ।

(८) पत्नी की आय.—किसी व्यक्ति की पत्नी को निम्नलिखित साधनों से उत्पन्न होने वाली आय उसकी (पति की) कुल आय में जोड़ दी जाती है.—

(अ) उस फर्म की सदस्यता से, जिसमें उसका पति साझीदार है, अथवा

(आ) उस सम्पत्ति से जो उसके पति ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके (पत्नी के) पक्ष में हस्तांतरित कर दी है, उसे दशा में नहीं जबकि (अ) हस्तांतरण पर्याप्त प्रतिफल के लिए है और (ब) जहाँ यह हस्तान्तरण पृथक् रहने के विचार से हुआ है ।

(९) नाबालिग बच्चे की आय (Income of Minor Child) —किसी व्यक्ति के नाबालिग बच्चे की आय, जो निम्नलिखित साधनों से हुई है, उस व्यक्ति (माता या पिता) की कुल आय में शामिल की जायगी —

(अ) उस फर्म के लाभों में नाबालिग बच्चे के प्रवेश्य से, जिसमें वह व्यक्ति (बच्चे की माता या पिता) साझीदार है, अथवा

(आ) उस सम्पत्ति से जो नाबालिग बच्चे के हक में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः हस्तान्तरित कर दी गई है । हाँ, उस दशा में नहीं, जब कि (अ) हस्तान्तरण

पर्याप्त प्रतिफल के लिए हुआ है और (ब) जहाँ नाबालिग सन्तान कोई विवाहित पुत्री है ।

(१०) अन्य पक्षों की सम्पत्तियों का हस्तान्तरण (Transfer of Assets to Third Parties) —यदि कोई व्यक्ति अपने या नाबालिग बच्चे या दोनों ही के हितार्थ अपनी कोई सम्पत्ति किसी पर्याप्त प्रतिफल बिना किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी समूह को हस्तांतरित करदे, तो इस सम्पत्ति की आय उस व्यक्ति की ही आय समझी जायगी और उसे उसकी कुल आय में शामिल करना चाहिए ।

उदाहरण

(१) निम्नलिखित से विभिन्न कर-निर्धारण वर्षों के लिए कर-दाता की कुल आय निकालिए —

- (१) ३१ मार्च १९५४ को समाप्त हिसाबी वर्ष —मकान जायदाद से आय ७,००० रु०, तेल के व्यापार से हानि १४,००० रु०, अन्य साधन ६,००० रु० ।
- (२) ३१ मार्च १९५५ को समाप्त हिसाबी वर्ष —मकान जायदाद से आय १०,००० रु०, तेल के व्यापार से लाभ ५,००० रु० ।
- (३) ३१ मार्च १९५६ को समाप्त हिसाबी वर्ष —मकान जायदाद से आय १२,००० रु०, तेल के व्यापार से हानि २६,००० रु० ।
- (४) ३१ मार्च १९५७ को समाप्त हिसाबी वर्ष —मकान जायदाद से आय १२,००० रु०, तेल के व्यापार से हानि १०,००० रु० ।
- (५) ३१ मार्च १९५८ को समाप्त हिसाबी वर्ष —मकान जायदाद से आय १२,००० रु०, तेल के व्यापार से लाभ १०,००० रु० ।
- (६) ३१ मार्च १९५९ को समाप्त हिसाबी वर्ष —मकान जायदाद से आय १२,००० रु०, तेल के व्यापार से लाभ २०,००० रु० ।

कुल आय का विवरण

कर-वर्ष	रु०
१९५४-५५ मकान जायदाद से आय	७,०००
अन्य साधनों से आय	६,०००
	<hr/>
तेल के व्यापार से हानि	१३,०००
	१४,०००
	<hr/>
हानि जो १९५५-५६ कर-निर्धारण वर्ष को ले गये	१,०००
	<hr/>

१९५५-५६	मकान जायदाद से आय		१०,०००
	तेल के व्यापार से लाभ	५,०००	
	घटाओ १९५४-५५ की हानि	१,०००	४,०००

कुल आय १४,०००

१९५६-५७	मकान जायदाद से आय		१२,०००
	तेल व्यापार की हानि		२६,०००

• हानि जो कर-निर्धारण वर्ष १९५७-५८ को ले गये १४,०००

१९५७-५८	मकान जायदाद से आय		१२,०००
	तेल व्यापार की हानि		१०,०००

कुल आय २,०००

१९५८-५९	मकान जायदाद से आय		१२,०००
	तेल व्यापार का लाभ	१०,०००	
	घटाओ १९५६-५७ कर-निर्धारण वर्ष की आ/ला हानि	१०,०००	

कुल आय १२,०००

१९५९-६०	मकान जायदाद से आय		१२,०००
	तेल व्यापार का लाभ	२०,०००	
	घटाओ १९५६-५७ कर-निर्धारण वर्ष की हानि	४,०००	१६,०००

कुल आय २८,०००

(२) ३१ मार्च १९५९ को समाप्त होने वाले गतवर्ष के लिये किसी कर-दाता की आय का व्यौरा निम्न प्रकार है —

भारतीय आय

(अ) वेतन ७२५ रु० और मँहगाई भत्ता १०० रु० मासिक, और अधि-लाभाश (Bonus) १,६०० रु० ।

- (आ) कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज ५०० रु० और दूसरी प्रतिभूतियों से १,००० रु० (ग्राँस)
- (इ) मकान जायदाद (House property) से १,००० रु० का नुकसान निकाला गया है ।
- (ई) एक अनरजिस्टर्ड फर्म के लाभ में हिस्सा १५,००० रु० है ।
- (उ) लाभांश (ग्राँस) ६०० रु० , बैंक डिपॉजिट्स से ब्याज ४०० रु० ।
- (ऊ) एक सयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होने के नाते उसकी आय का हिस्सा ३,००० रु० है ।

विदेशी आय

(अ) अफ्रीका की आय जो भारत में लाई गई ५,००० रु० ।

(ब) ईरान में एक व्यापार से हुई (जो भारत से संचालित किया जाता है) आय १०,००० रु० और जायदाद से २,००० रु० ।

१९५१ में अफ्रीका में उत्पन्न हुई कर न लगी (Untaxed) आय में से १०,००० रु० वर्ष के बीच भारतवर्ष में लाया गया । १,००,००० रु० के अपने जीवन बीमा के लिए उसने प्रीमियम के ९,००० रु० दिये ।

उसकी कुल आय, कुल विश्व आय और कर-मुक्त आय मालूम कीजिये, यदि वह (अ) पक्का निवासी (Resident, ordinarily resident) है , (ब) कच्चा निवासी है और (स) परदेशी (Non-resident) है ।

	(अ) रु०	(ब) रु०	(स) रु०
भारतीय आय			
१ वेतन	११,५००	११,५००	११,५००
२ प्रतिभूतियों का ब्याज			
कर लगा	१,०००	१,०००	१,०००
कर मुक्त	५००	५००	५००
३ जायदाद (हात्ति)	-१,०००	-१,०००	-१,०००
४ फर्म से लाभ	१५,०००	१५,०००	१५,०००
५ अन्य साधन			
लाभांश (ग्राँस)	६००	६००	६००
बैंक की ब्याज	४००	४००	४००
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	२८,०००	२८,०००	२८,०००

विदेशी आय

१ अफ्रीका में बिना कर लगी पिछली आय जो वर्ष के बीच भारत में लायी गयी	१०,०००	१०,०००	—
२ अफ्रीका की आय जो भारत में लायी गयी	५,०००	५,०००	—

३ ईरान में पैदा हुई आय, भारत में न भेजी गई है	१२,०००	१०,०००	—
कुल आय	५५,०००	५३,०००	२८,०००
संयुक्त हिन्दू परिवार की आय का हिस्सा जो कुल आय में शामिल नहीं किया गया, लेकिन कुल विश्व आय में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए			३,००० १७,०००
कुल विश्व आय	५५,०००	५३,०००	४८,०००

कर-मुक्त आय

१ कर-मुक्त ब्याज	५००	५००	५००
२ जीवन बीमा प्रीमियम	८,०००	८,०००	७,०००
३ अनरजिस्टर्ड फर्म से आय	१५,०००	१५,०००	१५,०००
	२३,५००	२३,५००	२२,५००

जीवन बीमा प्रीमियम की कर-मुक्त रकम, कुल आय के चौथे पाँचवें भाग से अथवा ८,००० रु० से, जो भी इनमें कम हो, अधिक नहीं होनी चाहिये।

(३) १९५६-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए निम्न सूचना से एक व्यक्ति की कुल आय और कर-मुक्त आय मालूम कीजिये.—

(अ) वेतन १,५०० रु० प्रति माह।

(ब) उसका स्वीकृत प्राविडेंट फण्ड में चन्दा २,१६० रु०।

(स) मालिक का प्राविडेंट फण्ड में चन्दा २,१६० रु०।

(द) ब्याज ६% प्रति वर्ष से, जो कि उसके प्राविडेंट फण्ड पर जमा हुआ, १,२०० रु०।

(इ) लाभांश प्राप्त हुए ५,००० रु०। इन पर १,००० रु० आय कर के लागू होते हैं।

(फ) जीवन बीमा प्रीमियम चुकाया ५,००० रु०।

१. वेतन—	रु०	रु०
मालिक का प्राविडेंट फण्ड में १०% से अधिक का चन्दा	१८,०००	३६०

प्राविडेट फण्ड पर जमा ब्याज, ६% प्रतिवर्ष से अधिक	४००	१८,७६०
२ लाभाश (ग्रीस)		६,०००
कुल आय		<u>२४,७६०</u>

कर-मुक्त आय .

१ कर्मचारी का स्वीकृत प्राविडेट फण्ड में चन्दा	२,१६०
२ जीवन बीमा प्रीमियम (प्राविडेट फण्ड चन्दा तथा जीवन बीमा प्रीमियम २४,७६० रु० के चौथाई = ६,१९० रु० तक सीमित)	<u>४,०३०</u> <u>६,१९०</u>

(४) एक कर-दाता की, जो ३१ मार्च १९५६ को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए पक्का निवासी है, आय के सम्बन्ध में निम्न सूचनाएं प्राप्त हैं।

(अ) मासिक वेतन ३,००० रु०। ४ महीने के लिए वह भारत से बाहर छुट्टी पर था। छुट्टियों के दो महीनों का वेतन उसने भारत के बाहर ही प्राप्त किया और छुट्टियों के वेतन की शेष रकम उसने भारत वापस आने पर अगले वर्ष प्राप्त की।

(ब) वह एक मकान का मालिक है, जिसका एक चौथाई भाग वह अपने रहने के लिए इस्तमाल करता है और शेष भाग को उसने ०० रु० मासिक किराये पर उठा रखा है। किराये का छठा भाग उसका एजेंट बतौर कमीशन ले लेता है। मकान पर लगे म्यूनिसिपल कर की रकम १,६०० रु० थी।

(स) प्राप्त लाभाश ६,६६६ रु० (ग्रीस)।

(द) सट्टे के व्यापार से ५,००० रु० हानि हुई।

१९५६-६० के कर-निर्धारण वर्ष के लिए उसकी कुल आय निकालिए।

१ १२ महीने का वेतन	३६,०००
२ जायदाद से आय —	
भाडे पर उठाये गये मकान का किराया	४,८००
घटाओ—म्यूनिसिपल कर का आधा	<u>६००</u>
भाडे पर उठी जायदाद का वार्षिक मूल्य	४,२००
निजी निवास के हिस्से का भाडे पर उठे मकान की भाँति निर्धारित किया गया मूल्य	१,४००
घटाओ—प्राधा (वैधानिक छूट)	<u>७००</u>

कुल मकान का वार्षिक मूल्य		४,६००	
घटाओ—मरम्मत का १/६	८१६		
संग्रह व्यय ४,२०० रु०			
के ६% तक सीमित	२५२	१,०६८	३,८३२
१ लाभांश (ग्रीस)			६,६६६
कुल आय			<u>४६,४६८</u>

सट्टे के व्यापार की ५,००० रु० हानि उक्त आय से पूरी नहीं की जा सकती ।

(५) ऐक्स एक स्टक्चरल इंजीनियर है । ३१ मार्च १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष की निम्न सूचनाओं से १९५६-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए उसकी कुल आय निकालिए—

(अ) उसने हिन्द स्टक्चरल इंजीनियर्स लि० बम्बई से, जिनके यहाँ वह १ अप्रैल १९५८ से लगा, ३,५०० रु० प्रति माह वेतन तथा ७,२०० रु० मनोरजन भत्ते के प्राप्त किये । उसने वर्ष में ६,००० रु० मनोरजन पर व्यय किये ।

(ब) हिन्द स्टक्चरल इंजीनियर्स लि० से पहले वह पाइनियर बिल्डर्स लि० के यहाँ लगा था । उस कम्पनी के नौकरी के शर्तनामे के अनुसार उसकी सेवाएँ १ अक्टूबर १९५५ से तीन साल तक रहनी थी जिसमें उसे ३,००० रु० प्रति माह वेतन मिलता था लेकिन प्रबन्ध के साथ खटपट हो जाने से उसकी सेवाएँ ३१ मार्च १९५८ को समाप्त कर दी गईं, जो कि शर्तनामे से पहले रहा, तथा इसके लिए उसे ४ अप्रैल १९५८ को १८,००० रु० हर्जाने के प्राप्त हुए ।

(स) उसने ४८ महीने लगाकर एक स्टक्चरल इंजीनियरिंग पर एक पुस्तक लिखी । उसने उसका कॉपीराइट एक प्रकाशको की फर्म को बेच दिया । जिसके फलस्वरूप उसे १५ जून १९५८ को १५,००० रु० मिले । उसने चाहा है कि यह राशि ४ वर्षों में फैला दी जानी चाहिए ।

(द) उसका नागपुर में, जिसका वार्षिक मूल्य ३,६०० रु० है, एक मकान है । यह अपने रहने के लिए सुरक्षित रखा गया । गत पूर्ण वर्ष, जो ३१ मार्च १९५६ को समाप्त होता है, में यह खाली रहा क्योंकि उसे नौकरी के सिलसिले में बम्बई में दूसरी इमारत में रहना पड़ा ।

(इ) उसने अपने जीवन पर १५,००० रु० तथा अपनी पत्नी के जीवन पर १५,००० रु० जीवन प्रीमियम के चुकाये ।

रु०

१ वेतन जैसा कि है	४२,०००	
मनोरजन भत्ता (अ)	७,२००	
नौकरी के खो जाने पर हर्जाना (ब)	१८,०००	६७,२००

२. जायदाद से आय (स)

नहीं

३ अन्य साधनो से आय •

कॉपीराइट बिक्री के हजाने का
तिहाई (द)

१९५६-६० कर-निर्धारण के लिए कुल आय

५,०००
७२,२००

उमे औसत दर पर जीवन बीमा प्रीमियम के ८,००० रु० पर आय कर की छूट पाने का अधिकार है ।

उपयुक्त कुल आय की गणना के बारे में नोट

(अ) मनोरजन भत्ता वेतन की आय में जुड़ता है और तब यदि कर्मचारी अपने वर्तमान मालिक से लगातार १ अप्रैल १९५५ से मनोरजन भत्ता प्राप्त कर रहा है, तो कर्मचारी के वेतन (जिसमें विशेष भत्ता, लाभ या अन्य सम्मिलित नहीं है) के पाँचवें भाग या ७ ५०० रु० जो भी दोनों में से कम हो, कि उसमें से कटौती मिलती है । इस परिस्थिति में मनोरजन भत्ते की कोई कटौती नहीं मिलेगी ।

(ब) वेतन के बदले में प्राप्त लाभों में वर्तमान या पूर्व मालिक से नौकरी समाप्त किए जाने पर प्राप्त हजाना सम्मिलित है, चाहे यह केवल नौकरी खो जाने के बारे में हो या और किसी वजह से हो । इससे भी कोई अन्तर नहीं पड़ता कि यह हजाना अधिकार रूप में कर्मचारी द्वारा माँगा जा सकता था या मालिक ने अपने विकल्प से दे दिया है । यह हमेशा वेतन की तरह कर योग्य है ।

(ग) जब कि जायदाद, जो कि मालिक के पास है में केवल एक मकान है जो कि न तो वास्तव में मालिक द्वारा घिरा हो, न किराये पर उठाया गया हो, तथा न और ही कोई लाभ उठाया गया हो तब ऐसी जायदाद का वार्षिक मूल्य, यदि वह गत वर्ष में खाली रही है, शून्य लिया जाएगा ।

(द) यदि कोई पुस्तक १२ माह से अधिक और २४ माह से कम में तैयार की गई है और उसके बारे में प्राप्त एक मुस्त रकम, यदि लेखक चाहे, तो जिस वर्ष में प्राप्त हुई है उस वर्ष में तथा अगले वर्ष में ५० ५० बाँटी जाकर कर-निर्धारण होगा । यदि लेखक के पुस्तक ने २४ माह से अधिक लिए हैं तो एक-तिहाई जिस साल में प्राप्त हो तथा एक तिहाई अगले वर्ष में तथा शेष एक-तिहाई उससे अगले वर्ष में बाँट कर कर-निर्धारण किया जाएगा । क्योंकि यह नियम ऐक्स ने चाहा है । इसलिए गत वर्ष, जो ३१ मार्च १९५६ को समाप्त होता है, की कुल आय में एक-तिहाई ५,००० रु० ही सम्मिलित किया गया है ।

कर एकत्र करने की दो पद्धतियाँ हैं। एक सीधे कर-निर्धारण से तथा दूसरे उद्गम स्थान पर कर की कटौती से। उद्गम स्थान पर कर कटौती धारा १८ में दी गई है। धारा १८ के अतिरिक्त उद्गम स्थान पर कर-कटौती दो अन्य स्थितियों में दी गई है। एक तो स्वीकृत प्रॉविडेंट फण्ड में जुड़ा हुआ शेष जो कि कर्मचारी को दिया जाए जिसे इसके लिए धारा ५८ H के अन्तर्गत वेतन मान लिया गया है। दूसरे धारा ५८ S के अन्तर्गत कर्मचारी की अन्य आय (allied income) जिसमें स्वीकृत सुपरैन्नुएशन फण्ड (approved superannuation fund) का चन्दा सम्मिलित है। प्रॉविडेंट फण्ड तथा सुपरैन्नुएशन फण्ड के ट्रस्टियों का यह कर्तव्य है कि वे कर्मचारी को भुगतान करते समय, जहाँ कि उन्होंने एक निर्धारित न्यूनतम सेवा की अवधि पूरी नहीं की है, उसमें से कर की कटौती करें।

उद्गम स्थान पर कर-कटौती तथा उद्गम स्थान पर कर लगाने में अन्तर जान लेना चाहिए। बाद वाला (उद्गम स्थान पर करारोपण) अनरजिस्टर्ड फर्मों, व्यक्तियों के समूह तथा अविभाजित हिन्दू परिवारों के कर-निर्धारण में होता है। वहाँ पर बत्राय व्यक्ति (individual) पर कर लगाया जाए जब कि उसके हाथों में आय आ जाए उससे पहले ही इकाई के रूप में उस समूह पर ही कर-निर्धारण कर दिया जाता है।

धारा १८ के नियम (जैसे कि वे फाइनैस एक्ट १९५६ से संशोधित हो गए हैं) संक्षेप में निम्न हैं —

वेतन

‘वेतन’ शीर्षक के अन्तर्गत आने वाली आय में से आय कर तथा सुपर-टैक्स दोनों काटने होते हैं। निवासी कर्मचारियों (resident employees) की दशा में कर्मचारी, की ‘वेतन’ शीर्षक में अनुमानित आय पर लगने वाली दरों से (‘कुल आय’ पर लगने वाली दरों से नहीं) आय-कर तथा सुपर-टैक्स काटना होगा।

जहाँ कि वेतन परदेशी (non-resident) को (जो कि भारत का नागरिक तथा सरकारी नौकर भारत से बाहर सेवा करता हुआ न हो) चुकाया जाए वहाँ पर ‘वेतन’ शीर्षक में अनुमानित आय पर निर्धारित की गई दरों से आय-कर तथा सुपर-टैक्स काटना होगा।

वेतन से आय-कर तथा सुपर-टैक्स उस वर्ष की दरों में (जब कि वह चुकाया गया) काटा जाएगा ।

जब परदेशी कर्मचारी आय-कर अधिकारी से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है कि उसकी कुल आय या कुल विश्व आय कर योग्य न्यूनतम सीमा से कम है या उस पर कम दर लगनी है तो कर की कटौती या तो नहीं की जायेगी या नीची दर से की जायेगी ।

कर्मचारी के वेतन से कटौती की मासिक रकम निकालते समय निम्न मदों के लिए [बशर्ते कि वे उन शर्तों को (जो कि पिछले 'कर-मुक्त आय' के अध्याय में समझाई गई हैं) पूरी करें] कर्मचारी की कुल आय पर लागू होने वाली आय कर की दर से आय-कर से (लेकिन सुपर टैक्स से नहीं) छूट दी जाएगी —

(अ) सरकारी नौकर के वेतन में डेफर्ड एन्यूटी खरीदने या उसकी पत्नी या बच्चों के लिए किये गये आयोजन की राशि ।

(ब) ऐमे प्रॉविडेंट फण्ड जिसे प्रॉविडेंट फण्ड १९२५ लागू होता हो, या स्वीकृत प्रॉविडेंट फण्ड या अधिकृत सुपर एन्यूएशन फण्ड को कर्मचारी द्वारा दिया गया अशदान ।

(स) कर्मचारी द्वारा दिया गया जीवन-बीमा प्रीमियम यदि मालिक ऐसे प्रीमियम की राशि से सतुष्ट है ।

मालिक कटौती की राशि में घटोत्तरी या बढ़ोत्तरी कर सकता है यदि उसने पहले ज्यादा कर काट लिया है या नहीं काटा है ।

मालिक द्वारा काटा गया सम्पूर्ण कर मालिक को कर्मचारी के क्रेडिट में सरकार को चुकाना होगा । यदि मालिक कर नहीं काटता या कर काटने के बाद जमा नहीं करता तो वह उस कर के लिए डिफाल्ट में कर-दाता माना जाएगा ।

धारा ७ (1) के द्वितीय नियम के अनुसार, जहाँ कि कर धारा १८ के अन्तर्गत उद्गम स्थान पर काट लिया जाए, वहाँ कर-दाता से स्वयं कर देने को नहीं कहा जाएगा केवल उस स्थिति को छोड़ कर जहाँ कि उसने वेतन बिना ऐसा कर काटे प्राप्त किया है ।

धारा २१ के अन्तर्गत हर मालिक, सरकार सहित, का कर्तव्य है कि वह उन व्यक्तियों के नाम तथा पते देता हुआ जिन्होंने ३१ मार्च को समाप्त हुए वर्ष में वेतन की एक निर्धारित राशि तथा उसमें से काटा गया कर का रिटर्न आय-कर अधिकारी को ३१ मार्च के ३० दिन के अन्दर दाखिल करे ।

प्रतिभूतियों पर ब्याज

वह व्यक्ति जो कि 'प्रतिभूतियों पर ब्याज' शीर्षक के अन्तर्गत कोई आय देता है उसे भुगतान करते समय उस चुकाए जाने वाले ब्याज पर निर्धारित दरों से आय-कर तथा सुपर-टैक्स काटना होगा ।

जहाँ प्रतिभूतियों का मालिक (लेकिन कम्पनी नहीं) इन्कम टैक्स ऑफीसर से यह सर्टीफिकेट प्राप्त कर ले कि उसकी कुल आय कम से कम जितनी आय पर कर लगता हो उससे भा कम है अथवा नीची दर में कर लगने योग्य है तो प्रतिभूतियों पर ब्याज देने वाला व्यक्ति आय-कर काटे बिना ही ब्याज की राशि दे देगा या वह नीची दर से आय-कर काटेगा ।

प्रतिभूतियों पर ब्याज देने वाले व्यक्ति को यह आवश्यक है कि वह एम्पी कर-कटौती का विवरण निर्धारित फार्म में उस व्यक्ति को भेजे जिसके ब्याज से आय-कर काटा गया है । इन्कम टैक्स ऑफीसर को भी विवरण दिखाते हुए सूची भेजनी पड़ती है ।

लाभाश

एक कम्पनी के प्रधान अफसर को जो कि भारत में लाभाश बांटता है ऐसे लाभाश से निर्धारित दरो पर आय-कर तथा सुपर-टैक्स काटना होगा ।

जहाँ कम्पनी का प्रधान अफसर यह सोचता है कि लाभाश पाने वाले को धारा १५ C के नियमों के कारण लाभाश (पूर्ण या किसी भाग) पर कोई आय-कर व सुपर-टैक्स नहीं देना होगा तो वह लाभाश चुकाने से पहले आय-कर अधिकारी को एक प्रार्थना-पत्र दे सकता है कि वह कौन-सा भाग होगा जिस पर धारा १५ C के नियमों के अनुसार कर नहीं देना होगा तथा आय-कर अधिकारी के यह निश्चित कर देने के बाद उम भाग पर कोई आय-कर तथा सुपर-टैक्स नहीं काटा जाएगा ।

कम्पनी का प्रधान अफसर सरकार को (सरकार द्वारा रखे गए अगो पर) दिए गए किसी लाभाश से कोई भी कर नहीं काटेगा ।

जब एक कम्पनी का प्रधान अफसर लाभाश से कर काटता है तो उसे अशधारी को कटौती का सर्टीफिकेट देना होगा ताकि अशधारी वापसी या अपने कर-निर्धारण में कर-दायित्व के समय आवश्यक समायोजन करा सके ।

लाभाश से उद्गम स्थान पर कटौती के उपर्युक्त नियम सर्व प्रथम १९५६-६० कर-निर्धारण वर्ष से लागू हुए हैं, लेकिन ये केवल उन कम्पनियों के लाभ, जो कि १९६०-६१ कर-निर्धारण वर्ष में कर-देय होंगे, से बाटे गए लाभाशों पर ही लागू होंगे । किसी पूर्व वर्ष के लाभों (जो कि १९५६-६० कर-निर्धारण वर्ष में कर-देय हैं) में से बाटे गए लाभाशों से यह कटौती नहीं की जाएगी और उन पर पुराने नियम ही लागू होंगे ।

परदेशियों को अन्य भुगतान (Other Payments to Non-residents)

परदेशी व्यक्ति (कम्पनी को छोड़ कर) या एक कम्पनी, जो कि भारत में लाभाश नहीं बांटती, को चुकाए जाने वाली हर एक राशि से जिस पर आय-कर अधिनियम

लाभ होता है (प्रतिभूतियों पर ब्याज तथा लाभांश को छोड़ कर) निर्धारित दरों के अनुसार आय-कर तथा सुपर-टैक्स काटना होगा । ये भुगतान ब्याज, रायल्टी, कमीशन, किराया आदि हो सकते हैं ।

उस स्थिति को छोड़ कर जहाँ कि चुकाने वाला परदेशी के एजेंट के रूप में स्वयं कर चुकाएगा इन कटौतियों का उत्तरदायित्व भुगतान करने वाले व्यक्ति पर है ।

जहाँ कि परदेशी व्यक्ति आय-कर अधिकारी से 'कर-मुक्त' या 'कर-छूट' सर्टीफिकेट प्राप्त कर लेता है तो उस पर 'प्रतिभूतियों पर ब्याज' की तरह ही कटौती की जाएगी ।

सामान्य (General)

धारा १८ के अन्तर्गत उद्गम स्थान पर काटा गया कर प्राप्त करने वाले व्यक्ति की आय का भाग रहता है तथा उसकी कुल आय में जुड़ता है ।

उद्गम स्थान पर कर-कटौती उस व्यक्ति से, जिसकी आय से कर काटा गया है, कर एकत्र करने का केवल एक तरीका है । अतएव उद्गम स्थान पर काटा गया तथा सरकार को चुकाया गया कर कर-दाता की ओर से चुकाया गया माना जाता है और उसके लिए कर-दाता को उसके कर-निर्धारण में क्रेडिट दी जाती है ।

धारा १८ के अन्तर्गत काटा गया उद्गम स्थान पर कर सरकार को चुकाना होगा । इसमें सरकार की जोखिम नहीं है अतएव कर काटने वाले व्यक्ति को चोरी हो जाने या और किसी तरह से खो जाने के बावजूद भी यह राशि सरकार को देनी होगी ।

यदि भुगतान करने वाला व्यक्ति धारा १८ के अनुसार कर की कटौती नहीं करता या कटौती करने के बाद सरकार को चुकाने में चूक करता है तो वह डिफाल्ट में कर-दाता माना जाएगा तथा वह जान-बूझ कर भूल करने पर दण्ड का उत्तरदायी भी होगा ।

उस व्यक्ति के लिए जो कि अपने कटौती करने के दायित्व से बचना चाहता है अप्रीनेट असिस्टेंट कमिशनर के यहाँ अपील कर सकता है, लेकिन यह अपील का अधिकार धारा १८ के अन्तर्गत कर काटने तथा उसे चुकाने की शर्तों के सहित है ।

निर्धारित दरें (Prescribed Rates)

जैसा कि ऊपर कहा गया है कुछ स्थितियों में उद्गम स्थान पर कटौती निर्धारित दरों से करनी होती है । १९५९-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारित दरें निम्न हैं .—

(अ) कम्पनी को छोड़कर व्यक्ति की दशा में कुल आय पर आय-कर २५% तथा आय-कर पर सरचार्ज ५% ।

जहाँ व्यक्ति परदेशी है वहाँ कुल आय पर सुपर-टैक्स बिना किसी सरचार्ज के १९% या सुपर टैक्स जो कि उस आय पर निवासी को चुकाना

होता इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो उससे सुपर-टैक्स भी देना होगा ।
 १९५६-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए १६% की दर कुल आय ६१,७६० रु० तक लागू होगी ।

- (ब) कम्पनी की दशा में कुल आय (धारा ५६ A के अन्तर्गत किसी कम्पनी द्वारा चुकाए गए लाभांश को छोड़ कर) पर आय-कर, बिना किसी सरचार्ज के २०% तथा सुपर-टैक्स, बिना किसी सरचार्ज के १०% तथा भारतीय कम्पनी की दशा में कुल आय पर (भारतीय सब्सिडियरी से या ५६ A कम्पनी से प्राप्त लाभांश को छोड़कर) सुपर-टैक्स, बिना किसी सरचार्ज के, १५% तथा विदेशी कम्पनी की दशा में . कुल आय पर (भारतीय सब्सिडियरी से या ५६ A कम्पनी से प्राप्त लाभांश को छोड़ कर) सुपर-टैक्स, बिना किसी सरचार्ज के ३३% ।

कर-निर्धारण की कार्य विधि (Assessment Procedure)

इनकम टैक्स ऑफीसर कर-निर्धारण करने वाला अधिकारी है। कर-निर्धारण (Assessment) से अर्थ इस बात का निश्चय करना है कि कर-दाता की कुल आय कितनी है तथा उस पर उसे कितना कर देना पड़ेगा। कर-निर्धारण की कार्यविधि धारा २२-२६ में दी हुई है।

आय का नक्शा (Return of Income)

धारा २२ के अनुसार रिटर्न दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करना आय कर-निर्धारण की पहली कायवाही है। नोटिस दो प्रकार के होते हैं। प्रथम एक सामान्य (general) नोटिस होता है, जो धारा २२ (१) के अनुसार इनकम टैक्स ऑफीसर द्वारा १ अप्रैल और १ मई के बीच में प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को, जिसकी आय एक निश्चित आय से अधिक होती है, आज्ञा दी जाती है कि नोटिस की तारीख से ६० दिन के अन्दर वह अपनी आय का नक्शा दाखिल करे।

दूसरे प्रकार का नोटिस व्यक्तिगत नोटिस होता है। धारा २२ (२) के अनुसार इनकम टैक्स ऑफीसर को यह अधिकार है कि वह किसी विशेष कर-दाता के नाम यह नोटिस जारी करे और उसे नोटिस मिल जाने के ३० दिन के अन्दर स्वीकृत फार्म में आय का नक्शा दाखिल करने की आज्ञा दे।

सामान्य और व्यक्तिगत दोनों प्रकार के नोटिसों में नक्शा दाखिल करने की तारीख बढ़ाने का अधिकार इनकम टैक्स ऑफीसर को प्राप्त है।

जो व्यक्ति किसी विशेष कारण के बिना सामान्य नोटिस के अनुसार नक्शा दाखिल नहीं करता, उस पर कर की ड्यूटी रकम दण्ड स्वरूप और लग सकती है। लेकिन जिस कर-दाता की कुल आय ३,५०० में कम है, उस पर यह दण्ड नहीं लगता। व्यक्तिगत नोटिस के अनुसार यदि कर-दाता नक्शा दाखिल नहीं करता तो वह भी धारा २८ (१) के अन्तर्गत अर्थ-दण्ड (penalty) का भागी है। व्यक्तिगत नोटिस के अनुसार नक्शा

दाखिल न करना अपराध (offence) में भी शामिल है जिसके लिए धारा ५१ (C) के अन्तर्गत कर-दाता को जुर्माना भुगतना पड़ता है और धारा २३ (४) के अन्तर्गत उत्तम निर्णयानुसार (Best Judgment) उसका कर-निर्धारण किया जाता है। उत्तम निर्णय (Best Judgment) से क्या अभिप्राय है, यह आगामी पृष्ठों में समझाया गया है।

यदि कोई नकशा निश्चित अवधि के अन्दर दाखिल नहीं किया जाता, तो धारा २३ (३) के अन्तर्गत, कर-दाता इसे कर-निर्धारण से पूर्व किसी समय दाखिल कर सकता है। किन्तु किन्हीं उपयुक्त कारणों के बिना यदि नकशा निश्चित अवधि में दाखिल नहीं किया गया है तो धारा २८ (१) के अन्तर्गत कर-दाता जुर्माने का भागी हो सकता है चाहे नकशा बाद में दाखिल हो क्यों न कर दिया गया हो। यदि किसी व्यक्ति ने अपना नकशा दाखिल कर दिया हो और बाद में उसे ज्ञात हो कि उसके अन्दर कोई चूक अथवा त्रुटि रह गयी है ऐसी स्थिति में कर-निर्धारण से पूर्व किसी भी समय वह दूसरा ठीक किया हुआ नकशा दाखिल कर सकता है। किन्तु यदि कर-दाता जान-बूझ कर गलत और भ्रूषा नकशा दाखिल कर चुका है तो उसे इस रियायत का लाभ नहीं मिल सकता। जान-बूझ कर भ्रूषा नकशा दाखिल करने के अपराध को दूसरा ठीक किया हुआ नकशा दाखिल करके सुधारा नहीं जा सकता और धारा २८ के अन्तर्गत कर-दाता पर जुर्माना हो सकता है।

कुछ आय बताने वाले नकशों के स्वीकृत फार्म में यह सब दिया होता है कि विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत आय किस प्रकार भरी जाय। यह घोषित करते हुए, कि नकशों में जो इन्दराज हो रहे हैं वे जहाँ तक उसे (कर-दाता को) अच्छी तरह ज्ञात है, सही और पूरे हैं तथा एक वर्ष विशेष से सम्बन्धित हैं, कर-दाता नकशों के फार्म में अपने हस्ताक्षर कर देता है। साथ ही वह यह भी घोषित करता है कि यह उसकी आय का ही स्टेटमेंट है। इसी नकशों में कर-दाता अपने निवास की श्रेणी (Class of Resident) भी घोषित कर देता है।

हानि का नकशा (Return of Loss) — धारा २२ (२ A) के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति, जिसने किसी वर्ष कोई व्यापारिक हानि उठाई है, ऐसी हानि किसी बाद के कर-निर्धारण वर्ष को आगे ले जाना चाहता है तो यह आवश्यक है कि वह धारा २२ (१) के अन्तर्गत सामान्य सूचना में निर्दिष्ट किये हुये समय के भीतर या ऐसी बढ़ाई हुई अवधि के अन्दर, जिसके लिये इनकम टैक्स आफिसर ने आज्ञा दे दी है, हानि का एक नकशा वह सब विवरण दिखाते हुये जो आय के नकशों में दिया जाता है, दाखिल करे और हानि तय कराले। अधिनियम के आय के नकशों को लागू होने वाले आवेश हानि के नकशों पर भी लागू होते हैं।

कर का अग्रिम भुगतान (Advance Payment of Tax)

उस आय के सम्बन्ध में, जिसमें उद्गम स्थल पर कर नहीं काटा जाता, जैसे प्रतिभूतियों के व्याज और वेतन से अतिरिक्त आय, धारा १८ A में कुछ विशेष आदेश हैं जिनके अन्तर्गत इनकम टैक्स आफिसर को यह अधिकार है कि वह कर-निर्धारण वर्ष के पूर्व वित्तीय वर्ष में ही कर को किश्तों में, सग्रह के वर्ष को लागू होने वाली दरों से, सग्रह कर ले। यह आयोजन 'चुकाओ जैसे कमाओ' (Pay as you earn) योजना कहलाती है क्योंकि जैसे-जैसे आय कमाई जाती है कर सग्रह होता रहता है।

लेकिन यह अग्रिम कर तभी दिया जाता है जबकि कर-दाता की कुल आय, सबसे अन्त में (latest) पूर्ण हुये कर-निर्धारण के अनुसार, कर से मुक्त उच्चतम रकम से ₹५,००० से अधिक हो। जब तक अन्तिम पूर्ण हुये कर-निर्धारण के अनुसार कुल आय अविवाहित व्यक्तियों के लिये ₹५,५०० से अधिक न हो अग्रिम कर देने के लिए दायित्व उदय नहीं होता।

१९५६-६० में भारतीय कम्पनियाँ धारा १८ A में आय-कर २०, तथा सुपर-टैक्स २५% चुकायेगी जबकि विदेशी कम्पनियाँ आय-कर २०% तथा सुपर-टैक्स ४३% चुकायेगी।

यदि कुल आय, जो अन्तिम पूर्ण हुये कर-निर्धारण में दी हुई है, निर्धारित-सीमा से अधिक बैठती है तो इनकम टैक्स आफिसर उसको रकम को अग्रिम कर निश्चित करने के लिये कुल आय मान लेगा। ऐसी दशा में कर-दाता को कर के भुगतान के चालान सहित नोटिस भेजा जायगा। अग्रिम कर साधारणतः तिमाही किश्तों में सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की १५ जून, १५ सितम्बर, और १५ मार्च को चुकाया जाता है। किश्त चुकाने के लिये समय बढ़ाने की आज्ञा नहीं है। हाँ, कमीशन की आय के सम्बन्ध में आज्ञा मिल सकती है, क्योंकि कमीशन प्रायः समयान्तरा पर दिया जाता है और हो सकता है कि ऐसी किश्तों के लिये निर्धारित तिथियों को प्राप्त या समायोजित न हो सका हो। ऐसी दशा में, कमीशन के सम्बन्ध का कर तब तक स्थगित किया जा सकता है जब तक कि कमीशन प्राप्त या समायोजित न हो जाये, किन्तु कर-दाता को ऐसे कमीशन पर उसके प्राप्त होने या समायोजन करने के १५ दिन के अन्दर चुका देना चाहिये।

यदि कर-दाता यह समझता है कि उसकी कुल आय उस आय से कम होगी जो कि इनकम टैक्स आफिसर ने मानी है, तो वह अपने निजी अनुमान दाखिल कर उनके आधार पर ही कर चुका सकता है। कर-दाता द्वारा फाइल किये गये अनुमान के सम्बन्ध में २०% का मार्जिन त्रुटि के लिये रखा जाता है। यदि नियमित कर-निर्धारण के समय यह पाया गया कि अनुमान के अनुसार चुकाया गया कर, 'कर-निर्धारित-आय' (income assessed) पर देय वास्तविक कर (actual tax payable)

के ८०% से कम है, तो कर-दाता का इस कमी के धन पर वित्तीय वर्ष की, जिसमें कि कर चुकाया गया था, १ जनवरी से नियमित कर-निर्धारण की वास्तविक तिथि तक ४% वार्षिक ब्याज चुकाना पड़ेगा। यदि इनकम टैक्स आफीसर यह समझता है कि कर-दाता ने जान-बूझ कर देय कर कम बताया है, तो जितना कर कम दिया गया था उसके लब्धोदे तक 'अर्थ-दण्ड' कर-दाता पर लगा सकता है।

जिन व्यक्तियों पर पहले कर-निर्धारण हो चुका है उनके सम्बन्ध में इनकम टैक्स आफीसर ही कर के अग्रिम भुगतान के लिए आज्ञा देता है, लेकिन, यदि किसी व्यक्ति पर पहले कर-निर्धारण नहीं हुआ है, तो उसे चाहिये कि वह स्वयं ही गत कर-निर्धारण वर्ष की १५ मार्च के पहले (before 15th March preceding the assessment year) स्वेच्छापूर्वक कर का अग्रिम भुगतान करदे, यदि कर-निर्धारण वर्ष के लिये उसकी आय ऊपर बताई गई सीमा से अधिक होने की संभावना हो। यदि नया कर-दाता ऐसा नहीं करता है, तो ४% ब्याज लगाया जायगा और उस पर अर्थ-दण्ड भी लग सकता है।

सरकार द्वारा कर के अग्रिम भुगतान पर इस प्रकार ब्याज दिया जायेगा —

(अ) १९५३-५४, १९५४-५५ और १९५५-५६ के कर-निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में कर की पेशगी चुकाई गई अधिक रकम (अर्थात् नियमित कर-निर्धारण में निर्धारित की गई कर राशि पर चुकाई गई कुल किश्तों के आधिक्य) पर २% वार्षिक दर से।

(आ) १९५६-५७ और बाद के कर-निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में कर की पेशगी चुकाई गई अधिक रकम (अर्थात् नियमित कर निर्धारण में निर्धारित की गई कर-राशि पर चुकाई गई कुल किश्तों के आधिक्य) पर ४% वार्षिक दर से।

इस प्रकार ब्याज की जो रकम चुकाई जावेगी उसकी गणना वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से अगले वर्ष में नियमित कर-निर्धारण की तिथि तक करनी चाहिए। उदाहरण के लिये यदि १९५७-५८ के कर-निर्धारण वर्ष में कुल चुकाया गया कर १०,००० रु० है और १९५८-५९ के कर-निर्धारण वर्ष के लिए १५ जुलाई १९५८ को समाप्त हुये नियमित कर-निर्धारण में, कर की रकम ९,००० रु० निश्चित की गई है तो १,००० रु० पर १ अप्रैल १९५८ से १५ जुलाई १९५८ तक ४% वार्षिक दर से ब्याज दिया जावेगा।

उदाहरण

(१) (अ) एक कर-दाता से धारा १८ A के अन्तर्गत १२,००० रु० कर चुकाने के लिये कहा गया है। उसने अपने निजी अनुमान दाखिल किये और १९५८-५९ के

कर-निर्धारण वर्ष के दौरान में ४,००० रु० चुकाये। १९५६-६० के रिटर्न भरने पर दिया जाने वाला कर १ अक्टूबर १९५६ को ५,००० रु० निश्चित किया गया। वह दर बताइये जिस पर सरकार उसे ब्याज चुकायेगी और साथ ही यह भी सकेत कीजिये कि किस अवधि के लिये ब्याज देना पड़ेगा।

(ब) यह मानते हुये कि उपरोक्त मामले में नियमित कर-निर्धारण की समाप्ति पर निर्धारित किया गया कर १०,००० रु० था, बताइये कि क्या कर-दाता को दण्ड देना पड़ेगा ? यदि हाँ, तो उसकी कितनी रकम, क्या दर और कितनी अवधि होगी।

(स) किसी कर-दाता ने १ जुलाई १९५७ से बिजली के सामान की दूकान खोली। उसने अपने खाते ३१ मई १९५८ को बन्द कर दिये और इनकम टैक्स ऑफीसर को यह लिखा कि वह ३१ मई को समाप्त होने वाले वर्ष को ही अपना 'गत वर्ष' रखना चाहता है। यदि ३१ मई १९५८ को समाप्त हुई अवधि के लिये लाभ (अ) ५,४०० रु० और (ब) ६,६०० रु० हो तो क्या उसे धारा १८ A के अन्तर्गत कोई कर देना होगा ? यदि हाँ, तो वह अन्तिम तिथि बताइये जिस तक कि उसे कर चुका देना चाहिये और साथ ही आय की वह रकम भी बताइये, जिस पर उसे कर चुकाना होगा।

(अ) चूँकि धारा १८ A के अन्तर्गत चुकाया गया कर नियमित कर-निर्धारण में निर्धारित रकम से अधिक नहीं है इसलिये सरकार कर-दाता को कोई ब्याज नहीं देगी।

(ब) चूँकि कर-दाता द्वारा दी गई रकम (४,००० रु०) नियमित कर निर्धारण में निश्चित की गई कर राशि के ८०% (१०,००० रु० का ८०% ८,००० रु० होता है) से कम है, इसलिये कर-दाता को दण्ड स्वरूप १ जनवरी १९५६ से १ अक्टूबर १९५६ तक की अवधि के लिये ४००० रु० पर, (जो कि कर में कमी रह गई थी) ४% वार्षिक दर से ब्याज देना पड़ेगा।

(स) यदि उसकी आय ३१ मई १९५८ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये ५,४०० रु० है तो धारा १८ A के अन्तर्गत उसे कोई कर चुकाने की आवश्यकता नहीं है,। हाँ, यदि आय ६,६०० रु० है तो धारा १८ A के अन्तर्गत उस कुल रकम पर १५ मार्च १९५६ को या पहले ही कर चुकाना पड़ेगा, क्योंकि लाभो पर कर-निर्धारण १९५६-६० के कर-निर्धारण वर्ष में होगा जिसके लिये १८ A वर्ष १९५८-५९ होगा।

(२) एक कर-दाता को धारा १८ A के अन्तर्गत १९५८-५९ के वित्तीय वर्ष के भीतर तीन-तीन हजार रुपये की चार किश्ते देनी हैं। उसने भुगतान इस प्रकार किये — १५-६-१९५८ को ३,००० रु०, १५-६-१९५८ को ३,००० रु०, १५-१२-१९५८ को ३,००० रु० और १५-५-१९५९ को ३,००० रु०।

यदि १९५६-६० वर्ष के लिये कर-निर्धारण १५-५-१९६० को समाप्त हो जाये, और देय कर ८,००० रु० निश्चित हो, तो धारा १८ A (५) के अन्तर्गत आप कर-दाता को क्या ब्याज छोड़ेंगे ?

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अर्थात् १५-५-१९६० को दिया गया भुगतान विचार में नहीं लिया जावेगा। वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के भीतर दी गई किस्तों (९,००० रु०) के नियमित कर निर्धारण द्वारा निश्चित की गई कर राशि (अर्थात् ८,००० रु०) पर आधिक्य अर्थात् केवल १,००० रु० पर ही धारा १८ A के अन्तर्गत ब्याज दिया जायेगा।

अतः धारा १८ A (५) के अन्तर्गत चुकाया जाने वाला ब्याज १-४-१९५९ से १५-५-१९६० तक की अवधि के लिये १,००० रु० पर ४% वार्षिक से साधारण ब्याज होगा।

(३) १९५८-५९ के कर-निर्धारण वर्ष के लिये ३१ मार्च १९५९ को समाप्त हुये नियमित कर-निर्धारण में, कर-दाता पर निश्चित किया गया कर २००,००० रु० था। धारा १८ (१) के अन्तर्गत कर-दाता के लिये यह आवश्यक था कि वह १,२०,००० रु० अग्रिम कर चुकाये, लेकिन उसने धारा १८ A (२) के अन्तर्गत १,००,००० रु० बताने हुये अपना निजी अनुमान दाखिल किया और इसके ही अनुसार कर चुकाया। धारा १८ A (६) के अन्तर्गत कर-दाता में जो ब्याज वसूल किया जायेगा उसे निकालिये। १९५७-५८ और १९५८-५९ के लिये कर की दरें एक ही हैं।

यह मानते हुए कि कर-दाता या अनुमान जान बूझ कर कम रखा गया है इसलिए उस पर धारा १८ A (९) की पैनल्टी लागेगी अधिकतम पैनल्टी, जो उस पर लग सकती है, की गणना कीजिए।

यदि किसी कर-दाता का कर अनुमान नियमित कर-निर्धारण में निश्चित किये गये कर के ८०% से भी कम निकले तो उसे भुगतान से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष का पहली जनवरी से लेकर नियमित कर निर्धारण की तिथि तक कर में पड़ी कमी की रकम पर ४% वार्षिक (साधारण) ब्याज दण्ड स्वरूप चुकाना पड़ेगा।

चूँकि १९५७-५८ और १९५८-५९ के लिये कर की दरें एक ही हैं इसलिए धारा १८ A के अन्तर्गत लगने वाला ब्याज इस प्रकार निकाला जावेगा—

	रु०
नियमित कर निर्धारण में निश्चित किये गये कर ८०%	१,६०,०००
धारा १८ A के अन्तर्गत चुकाया गया कर	१,००,०००
कर की न्यूनता	<u>६०,०००</u>

अतः धारा १८ A (६) के अन्तर्गत ६०,००० रु० पर १ जनवरी १९५८ से ३१ मार्च १९५९ तक १५ महीनों के लिये ४% वार्षिक ब्याज लगाया जावेगा, जो कि ३,००० रु० आता है।

यदि धारा १८ A (२) के अन्तर्गत भेजे गये कर-अनुमान में कर-दाता ने जान-बूझ कर कमी बताई है तो धारा १८ A (९) (अ) के अन्तर्गत चुकाये गये कर की न्यूनता की छद्मदी राशि दण्ड स्वरूप अधिक से अधिक वसूल की जा सकती है। इस दशा में यह ६०,००० रु० का १½ गुना अर्थात् ९०,००० रु० होगी।

✓ अस्थायी कर-निर्धारण (Provisional Assessment)

जैसा कि ऊपर बतलाया गया है, धारा १८ A के अन्तर्गत पेशगी कर की रकम पिछले पूर्ण हुये कर-निर्धारण (Last completed assessment) के अनुसार मालूम की जाती है। इसलिए, यह सम्भव है कि जिस आय पर पेशगी कर दिया गया है, वह कर-दाता के नक्शे में, बाद को दिखाई गयी आय से, बहुत कम बैठे। ऐसी हालत में, जब तक कर-निर्धारण (Assessment) पूरे तौर से न हो जाय, कर की शेष रकम वसूल नहीं की जा सकती। कर-दाता कभी समय ढ़ढाने की अर्जों देकर, कभी सबूत साक्षी प्रस्तुत करने में देरी करके इनकम टैक्स ऑफीसर को छकाता रहता है, और काफी असें तक शेष कर की अदायगी से बचा रहता है।

इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए, इनकम टैक्स ऑफीसर को धारा २३ के अनुसार यह अधिकार दिया गया है कि वह कर-दाता के खुद बनाये नक्शे (रिटर्न) और इसके साथ दाखिल किये जाने वाले बहीखाते आदि हिसाब-पत्रों के आधार पर, याद कोई हो नियमित कर निर्धारण (Regular Assessment) से पूर्व अस्थायी कर-निर्धारण (Provisional Assessment) करले। एक अस्थायी कर-निर्धारण वस्तुतः एक सक्षिप्त कर निर्धारण (Summary assessment) है। यदि कर-दाता द्वारा अदा की गयी पेशगी कर की रकम नक्शे में दिखाई गई आय पर लगने वाली कर की रकम से अधिक होने का अनुमान हो, तो यह कोई जरूरी नहीं है कि इनकम टैक्स ऑफीसर अस्थायी कर-निर्धारण करे ही करे।

अस्थायी कर-निर्धारण के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती और इस कर-निर्धारण (assessment) में कर की जो रकम निश्चित कर दी गयी है उसे 'भाँग की सूचना' में आदेशित अवधि के अन्दर ही अवश्य जमा कर देना चाहिए नहीं तो कर दाता को कर की रकम के बराबर दण्ड (penalty) भुगतना पड़ सकता है।

धारा १८ के अन्तर्गत, उद्गम स्थान में काटा गया कर या धारा १८ A के अन्तर्गत जमा किया गया पेशगी कर, अस्थायी कर-निर्धारण के लिए ही दिया हुआ माना जाता है और इसके लिए अस्थायी कर-निर्धारण में कर-दाता को कटौती दी जाती है। इसी प्रकार, अस्थायी कर-निर्धारण के लिए दी गई कर की रकम नियमित कर-निर्धारण (Regular Assessment) के लिये दी गई रकम मानी जाती है और कर-दाता को नियमित कर-निर्धारण में उस रकम के लिये कटौती दी जायगी।

नियमित कर-निर्धारण (Regular Assessment)

धारा २३ के अनुसार निम्न तीन प्रकार के कर-निर्धारण किये जाते हैं —

(१) नकशे के आधार पर (**on the basis of return**)—कर-दाता से नकशा प्राप्त होने पर इनकम टैक्स आफीसर उसकी यह परीक्षा करता है कि वह आवश्यक विवरणों से पूर्ण है या नहीं तथा नकशे से सम्बन्धित आवश्यक हिसाब-पत्रक साथ में आए हैं या नहीं, और यदि उसे यह विश्वास हो जाता है कि सम्पूर्ण सामग्री सही और पूर्ण है तो धारा २३ (१) के अनुसार वह खुद ही कर-निर्धारण कर देता है, कर-दाता को दफ्तर में नहीं बुलाता।

(२) प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों के आधार पर (**on the basis of evidence produced**)—यदि इनकम टैक्स आफीसर कर-दाता के नकशे को पूर्ण और सही नहीं समझता अथवा साथ में आये हिसाब-पत्रक भी पूर्णतः समाधान प्रदान नहीं करते तो ऐसी दशा में धारा २३ (३) के अन्तर्गत आवश्यक जाँच-पड़ताल और पृच्छताछ के पश्चात् कर-निर्धारण कर दिया जाता है।

धारा २३ (२) के अनुसार, इनकम टैक्स आफीसर कर-दाता के नाम नोटिस जारी करता है कि उसमें निश्चित की हुई तारीख को उसके दफ्तर में स्वयं अथवा अपने किसी प्रतिनिधि द्वारा हाजिर होकर नकशे के समर्थन में सबूत प्रस्तुत करे। यदि इनकम टैक्स आफीसर कर-दाता की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक समझे तो वह धारा ३७ के अनुसार आज्ञा जारी करके उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकता है।

धारा २२ (४) के अन्तर्गत इनकम टैक्स आफीसर को यह अधिकार है कि वह कर-दाता से बही-खाते आदि हिसाब के कागजात तलब करे। किन्तु वह कर-दाता से, जिस गतवर्ष के लाभ पर कर-निर्धारण किया जाना है उससे तीन वर्ष से अधिक अवधि के पूर्व के बही-खातों की मांग नहीं कर सकता। यह प्रतिबन्ध केवल बही-खातों के लिए ही है, हिसाब-पत्रकों (documents) पर वह लागू नहीं होता। इनकम टैक्स आफीसर बही-खातों को अपने सम्मुख पेश करने के लिए तो कह सकता है लेकिन उन्हें अपने पास नहीं रख सकता।

हिसाबों, हिसाब-पत्रकों तथा कर-दाता द्वारा प्रस्तुत किसी अन्य साक्ष्य का निरीक्षण कर इनकम टैक्स आफीसर कर-निर्धारण सम्बन्धी आज्ञा दे सकता है।

(३) अति उत्तम निर्णाय के आधार पर (**Best judgment assessment**)—यदि कर-दाता धारा २२ (२) के अनुसार अपने नाम जारी किये गये व्यक्तिगत नोटिस के उत्तर में आय का नकशा दाखिल नहीं करता या धारा २३ (२) के अनुसार आवश्यक सबूत प्रस्तुत नहीं करता अथवा धारा २२ (४) के अन्तर्गत माँगे गये बही-खाते तथा हिसाब-पत्रकों को पेश नहीं करता तो इनकम टैक्स आफीसर यदि वह चाहे तो, उन्हें दाखिल करने के लिए उसे एक और अवसर दे सकता है। यदि तब भी कर-दाता कोई ध्यान न देकर चुप्पी साधे बैठा रहे, तो ऐसी दशा में इनकम टैक्स आफीसर को

अपने उत्तम निर्णय के अनुसार इकतरफा (ex-parte) कर-निर्धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा ।

यह स्वाभाविक है कि इकतरफा कर-निर्धारण किसी भी परिस्थिति में, उस कर-निर्धारण से तुलना नहीं कर सकता, जो कर-दाता की अमूल्य सहायता और सहयोग से किया जावेगा । आय-कर विभाग तो यही चाहता है कि कर-निर्धारण कर-दाता के सहयोग से ही किया जाय और राष्ट्र के हित में भी यही आवश्यक है कि लम्बे असें तक आय-कर सम्बन्धी झगड़े और विवादों को निबटाने में खर्च होने वाला समय, शक्ति और धन बचा लिया जाय और कर-दाता तथा इनकम टैक्स आफिसर के पारस्परिक सहयोग से किसी समझोते पर पहुँचा जाय ।

उत्तम निर्णयानुसार हुए कर-निर्धारण में कर-दाता को जितना कर देना है उसका ड्यौड़ा, दण्ड (penalty) स्वरूप और भी भुगतान पड़ सकता है ।

उत्तम निर्णयानुसार हुए कर-निर्धारण के विरुद्ध कर-दाता के पास दो उपाय हैं -
(१) धारा २७ के अन्तर्गत वह इनकम टैक्स आफिसर से कर-निर्धारण खारिज कर देने की प्रार्थना कर सकता है । (२) अपीलेंट असिस्टेंट कमिश्नर के यहाँ, धारा ३० के अन्तर्गत वह इस निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है । यदि इनकम टैक्स आफिसर का निर्णय न्याय सुगम नहीं है, तो उसे अपील में बदला जा सकता है ।

(M) 1914-15

कर की वसूली (Recovery of Tax)

जब इनकम टैक्स आफिसर कर-निर्धारण का काय समाप्त कर चुके तो वह कर-निर्धारण आदेश जारी करता है, जिसमें यह बताया जाता है कि उस पर कितना कर लगाया गया है और किस आधार पर लगाया गया है । इसके पश्चात् धारा २६ के अन्तर्गत वह कर-दाता के नाम कर की माँग करते हुए नोटिस जारी करता है कि अमुक तारीख तक अमुक ट्रैजरी या बैंक में कर की रकम जमा करदी जाय ।

धारा ४६ के अनुसार, यदि निश्चित तारीख तक कर जमा नहीं कराया जाता तो इनकम टैक्स आफिसर कर-दाता पर अथ-दण्ड (penalty) भी लगा सकता है और यदि फिर भी कर जमा न किया जावे तो वह दण्ड बढ़ा सकता है लेकिन दण्ड की कुल रकम बकाया कर (Arrears of tax) से अधिक नहीं होनी चाहिए । बकाया कर निम्न तरीकों में से किसी तरह वसूल किया जा सकता है —

(अ) इनकम टैक्स आफिसर कलक्टर के पास एक सार्टीफिकेट भेज सकता है, जिसमें वह रकम जो कर-दाता से लेनी रह गयी है, लिखी रहती है । इस सार्टीफिकेट के मिलने पर कलक्टर इस रकम को वसूल करने के लिए वैसी सी कार्यवाही करेगा, जैसी लगान (land revenue) वसूल करने के लिए की जाती है । यदि कर की

बसूली न हो सके तो कलक्टर को कर-दाता की कुर्की करवाने और उसकी सम्पत्ति बिकवाने का अधिकार है ।

(व) कलक्टर को कोई सर्टीफिकेट न भेजकर इनकम टैक्स ऑफिसर यह कर सकता है कि वह अन्य व्यक्तियों के ऊपर कर-दाता की जो रकम प्राप्य (moneys due) है उन्हें कुर्क (Attach) करले । इत आयोजन के अनुसार इनकम टैक्स ऑफिसर बैंक में जमा रकम कुर्क करा सकता है ।

कर चुकाने का प्रमाण पत्र (Tax Clearance Certificates)

यह विश्वास प्राप्त करने के लिये कोई व्यक्ति जो भारतीय आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत कर चुकाने का दायी है, बिना कर चुकाये भारतीय क्षेत्र छोड़कर न चला जाये, धारा ४६ A यह निर्देश करती है कि कोई भी व्यक्ति जल, धूल, वायु किसी भी मार्ग से भारत से बाहर नहीं जा सकेगा जब तक वह विदेश विभाग के किसी भी इनकम टैक्स ऑफिसर से, जो समय-समय पर नियुक्त किये जाये, कर चुकाने का प्रमाण-पत्र या कर-मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त न करले ।

भारतीय निवास (Indian domicile) के व्यक्तियों और अन्य दूसरे व्यक्तियों को, जिन पर पहले कर लग चुका है, यह चाहिये कि वे अपने क्षेत्र के या कर लगाने वाले इनकम टैक्स ऑफिसर को निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थना पत्र दे । यह इनकम टैक्स ऑफिसर एक अनुमति प्रपत्र देगा जिसे विदेश विभाग के इनकम टैक्स ऑफिसर से 'कर चुकाने के प्रमाण पत्र' से बदला जा सकता है । जो व्यक्ति भारतीय निवास के नहीं हैं और जिन पर पहले ही कर नहीं लगा है, उनको चाहिये कि वे सीधे विदेश विभाग के किसी भी इनकम टैक्स ऑफिसर को निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थना पत्र भेजें ।

कर चुकाने का प्रमाण पत्र या तो यह बताता है कि सम्बन्धित व्यक्ति पर कोई कर दायित्व नहीं है या यह बताता है कि उस व्यक्ति के द्वारा समस्त करो को चुकाने का सतोषजनक प्रबन्ध कर दिया गया है । यदि इनकम टैक्स ऑफिसर का यह सतोष हो जाय कि ऐसा व्यक्ति भारत लौटने का इरादा रखता है तो वह कर मुक्ति का प्रमाण-पत्र (Exemption Certificate) दे सकता है ।

स्टीमशिप एवं जहाज कंपनियों की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने को इससे सतुष्ट करले कि उनके मुसाफिरो के पास कर मुक्ति या कर चुका देने के प्रमाण-पत्र मौजूद है । यदि वह इसकी जाँच करने में त्रुटि करते हैं और ऐसे प्रमाण-पत्र बिना ही किसी व्यक्ति को यात्रा करने की आज्ञा दे देते हैं तो मुसाफिर का कर चुकाने की जिम्मेदारी उन पर आ जायगी ।

कुछ व्यक्तियों को उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के दायित्व से मुक्त रखा गया है ।

माग का अपलिखित करना (Write off of Demand)

जब कि कर-दाता के पास कोई सम्पत्ति न रहे और उस पर वाजिब कर प्राप्त होने योग्य न रहे तब इनकम टैक्स ऑफीसर की दरख्वास्त पर (जिसे इन्सपेक्टिंग एक्सीस्टेंट कमिश्नर, रिकमेंड करे) कमिश्नर को यह अधिकार है कि वह ऐसी रकम को अपलिखित कर दे।

केवल इस बात से कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी किताबों में ऐसा कर न प्राप्त होने वाला अपलिखित कर दिया है लेकिन यदि वह पाता है कि उसे उगाहना सम्भव हो जाना है तो डिपार्टमेंट के लिए उसे प्राप्त करने के लिए कोई रोक नहीं होगी।

कर-निर्धारण का विलोपन (Cancellation of Assessment)

धारा २७ के अनुसार, यदि कर-दाता मांग के नोटिस (Demand Notice) से एक महीने के अन्दर, निम्नलिखित किसी बात पर इनकम टैक्स ऑफीसर को सन्तुष्ट कर देता है, तो इनकम टैक्स ऑफीसर कर निर्धारण को खारिज कर सकता है और नया कर-निर्धारण कर सकता है —

(ग) किन्हीं उचित और उपयुक्त (sufficient) कारणों वश धारा २२ के अनुसार वह नकशा भेजने में असमर्थ हो गया था, अथवा

(ब) धारा २२ (४) अथवा धारा २३ (२) के अनुसार जारी किये गये नोटिस उसे प्राप्त नहीं हुए, या वह उपयुक्त कारणों वश नोटिसों की आज्ञा-पालन करने में असमर्थ हो गया था।

यदि धारा २७ के अनुसार कर-निर्धारण खारिज कर दिया जाता है, तो धारा २३ (३) के अनुसार नया कर-निर्धारण किया जायगा।

भूल सुधार Rectification of Mistakes)

धारा ३५ के अनुसार, कमिश्नर, अपीलेंट असिस्टेंट कमिश्नर या इनकम टैक्स ऑफीसर निम्न के समय यदि कोई भूल (जो उसके समक्ष प्रस्तुत किये गये तथ्यों या कागजातों से स्पष्ट प्रगट हो) रह गई हो तो उसे अपनी ओर से या कर-दाता की प्रार्थना पर सुधार सकते हैं। निम्न की तारीख से ४ वर्ष की अवधि तक कर के निर्धारण में हुई भूल का सुधार हो सकता है।

आकस्मिक कर-निर्धारण (Emergency Assessment)

धारा २४ A आकस्मिक कर-निर्धारण की धारा है। यह उन लोगों पर लागू होती है जिनके भारत छोड़कर विदेश जाने की सभावना है और जो लौट कर भारत में आने का इरादा नहीं रखते। ऐसे लोगों के कर-निर्धारण में सामान्य कायदा ही के अनुसार नहीं चला जाता। यदि कोई व्यक्ति चालू वित्तीय वर्ष में भारत छोड़कर जाने का इरादा रखता है, तो इनकम टैक्स ऑफीसर उसे केवल ७ दिन का ही नोटिस देकर नकशा

दाखिल करने को बाध्य कर सकता है। गत वर्ष की आय के साथ साथ कर-दाता की चालू वर्ष की आय पर भी कर निर्धारण किया जा सकता है यदि उम पर साधारण प्रगति में गत वर्ष की आय के लिए पहले से ही कर नहीं लगा है। जाने की तिथि तक, पिछले वर्षों की अन्तिम तिथि से, इनकम टैक्स ऑफिसर को उसकी कुल आय का अन्दाज लगा लेना चाहिए और उस पर उस वर्ष, जिसमें कर-निर्धारण हो रहा है, की दरों से कर लगाना चाहिए। यह वारा हम सामान्य नियम का अपवाद है कि कर-निर्धारण गत वर्ष की आय पर ही किया जाता है।

मरणा के स्वामित्व में हेर-फेर (Succession of Business)

धारा २६ (२) के अनुसार, जब किसी व्यापार, व्यवसाय या पेशे के स्वामित्व (Proprietorship) में कोई परिवर्तन हो गया है, तो जिन लोगों को लाभ पाने का अधिकार है उन्हीं व्यक्तियों से कर वसूल किया जा सकता है। यह भी आयोजन किया गया है कि यदि पूर्व स्वामी या साझीदार का पता न चल सके या वह कर न दे सकता हो, तो उसके उत्तराधिकारी से ही उसके कर की रकम वसूल की जायगी। लेकिन उस व्यक्ति को, जिसे किसी दूसरे की ओर से कर चुकाना पड़ा है, उस दूसरे व्यक्ति से इस प्रकार चुकाया गया कर वसूल पाने का अधिकार दिया गया है।

बन्द किये हुये व्यापार का कर-निर्धारण

(Assessment of Discontinued Business)

किसी व्यापार, व्यवसाय या पेशे को बन्द करने का मतलब उसे बिलकुल समाप्त कर देना है। बन्द हुए व्यापार पर कर के सम्बन्ध में, उन व्यापारों में अन्तर रखा जाता है जिन पर सन् १९१८ के आय-कर अधिनियम के अनुसार किसी भी समय कर लगाया जा चुका है और जिन पर इस प्रकार कर नहीं लगाया गया था।

यदि १९१८ के अधिनियम के अनुसार कर लगा हो

धारा २५ (३) का सम्बन्ध बन्द हुए उस व्यापार के कर-निर्धारण (Assessment) से है, जिस पर सन् १९१८ के आय-कर अधिनियम के अनुसार किसी भी समय कर लग चुका है। १९१८ के अधिनियम के अनुसार तो चालू वर्ष के लाभ पर कर लगाया जाता था, लेकिन १९२२ के अधिनियम के अनुसार गत वर्ष के लाभ पर कर लगाया जाता था। १९२२ में जब ऐसा परिवर्तन हुआ था, तब १९२१-२२ और १९२२-२३ के कर-निर्धारण उसी हिसाबी अवधि के लिए किये गये थे। इसका अर्थ यह हुआ कि इस हिसाबी अवधि के लाभ पर दो बार कर लगा। इमीलिए जिस वर्ष में इस प्रकार का व्यापार बन्द होता है उसमें निम्नलिखित रियायतें देने के लिए धारा २५ (३) की व्यवस्था की गई है।—

(अ) जिस वर्ष में व्यापार समाप्त किया जाता है उस वर्ष के या व्यापार बन्द होने वाले वर्ष के या उसके भाग के लाभ पर कर-निधारण नहीं किया जाता ।

(आ) कर-दाता को यह माँग करने का अधिकार होगा कि व्यापार बन्द होने वाले वर्ष के या उसके एक भाग के लाभ को, व्यापार बन्द होने से पूर्व की पूर्ण हिसाबी अवधि (Full accounting period) की आय के स्थान में स्वीकार कर लिया जाय ।

उदाहरण

हिसाबी वर्ष ३१ दिसम्बर को समाप्त होता है । १९५८ का लाभ २,००,००० रु० है । ३१ मार्च १९५९ को व्यापार बन्द हो गया । इस तारीख तक ३ महीने का लाभ ४०,००० रु० है । कर-दाता को निम्न रियायते (Concessions) प्राप्त होगी —

(अ) १९५९ के ३ महीनों की आय पर कर-निधारण नहीं होना चाहिए, और

(आ) १९५८ के लिये २,००,००० रु० के लाभ पर, यदि इस पर पहले ही कर-निधारण हो चुका है, यह मानते हुये कि वह रुकम ४०,००० रु० ही है, पुनः कर-निधारण होना चाहिए और यदि कर अधिक वसूल हो गया है तो वह आधिक्य कर-दाता को वापस मिलना चाहिए ।

यदि बन्द हुए व्यापार पर १९१८ के अधिनियम के अनुसार कर नहीं लगा है ।

यदि कोई व्यापार, व्यवसाय या पेशा (जिसकी आय पर १९१८ के अधिनियम के अनुसार कभी कर नहीं लगा है) किसी वर्ष में बन्द हो जाता है, तो धारा २५ (१) के अनुसार उस वर्ष में, गत वर्ष की समाप्ति और व्यापार बन्द होने की तारीख के बीच की अवधि की आय के आधार पर कर लगाया जाना चाहिए । ऐसा कर निर्धारण करने में कर की जो दरे लागू होंगे वे उस वित्तीय वर्ष की चालू दरे होंगी जिसमें कि व्यापार बन्द हुआ है ।

धारा २५ (२) के अनुसार व्यापार, व्यवसाय या पेशे को बन्द करने का नोटिस इनकम टैक्स अफसर को १५ दिन के भीतर ही दे देना चाहिए, नहीं तो व्यापार बन्द करने वाले व्यक्ति दण्ड (Penalty) के भागी बन सकते हैं ।

अतिरिक्त कर निर्धारण (Additional Assessment)

यदि इनकम टैक्स अफसर को यह विश्वास करने के कारण है कि कोई आय कर लगने से रह गई है, तो वह धारा ३४ के अनुसार, उस पर कायवाही प्रारम्भ कर सकता है । यदि उसने घाटे की या घिसाई की अधिक छूटें दे दी हैं तो यह धारा उसे उनके ऊपर पुनर्विचार करने का अधिकार प्रदान करती है । इस धारा के अनुसार कर-निधारण या पुनः कर-निधारण निम्न परिस्थितियों में जरूरी हो सकता है —

(अ) जबकि धारा २२ के अनुसार कर-दाता ने आय का नकशा दाखिल नहीं

किया है अथवा कर-निर्धारण के लिये आवश्यक तथ्यों को उनमें पूरा तरह और सच्चाई के साथ प्रकट नहीं किया है, और

(ब) जब कि उन सूचनाओं के आधार पर जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर के पास हो वह समझता है कि कोई आय कर लगने से रह गई है अथवा अधिक छूटे द दी गयी है।

धारा ३४ के अन्तर्गत कार्यवाही

जब कोई इनकम टैक्स ऑफीसर इस धारा के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ करना चाहता है, तो उसे चाहिये कि कर-दाता को नोटिस दे। यदि धारा ३४ के अन्तर्गत दिये जाने वाले नोटिस में धारा २२ (२) का कोई आदेश भी समाविष्ट किया गया हो, तो उस आदेश को पूरा करने के लिये कर-दाता को कम से कम ३० दिन की अवधि मिलनी चाहिये।

यदि कर-दाता की ओर से कोई त्रुटि नहीं है लेकिन इनकम टैक्स ऑफीसर को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई आय पूर्णतः या अंशतः कर निर्धारण से बच गई है, तो इस धारा के अन्तर्गत नोटिस देने के समय की सीमा सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष के अन्त में ४ वर्ष होगी। इस समय सीमा में अतिरिक्त कर-निर्धारण के पूरा करने के लिये एक साल की वृद्धि की जा सकती है।

जब कर-दाता की ओर से कोई त्रुटि हो, तो कर-निर्धारण पुनः खोलने (re-opening) के लिये कोई समय-सीमा (Time Limit) नहीं होगी, हा इस सम्बन्ध में निम्न प्रतिबन्ध हैं। —

(१) १९४०-४१ के पहले किसी वर्ष के लिये कर-निर्धारण फिर से नहीं खोला जा सकता।

(२) किसी कर-निर्धारण या पुनः कर-निर्धारण को पूरा करने के लिये कोई समय-सीमा नहीं है।

(३) इन दशाओं में, जो कि ८ वर्ष से अधिक पुराने नहीं हैं, इनकम टैक्स ऑफीसर इस धारा के अन्तर्गत तब ही नोटिस जारी कर सकता है (अ) जबकि एक या अधिक वर्ष के लिये कर से बची हुई आय की रकम ₹१,००,००० रु० से कम न हो, और (ब) जबकि उसने ऐसी कायवाही के लिये 'कारण' दे दिया हो और सेण्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली हो।

युद्ध-काल में कर की चोरी के मामलों के सम्बन्ध में निपटारे की व्यवस्था जारी रहेगी। यदि कोई कर-दाता अपना मामला निपटवाना चाहता है, तो वह धारा ३४ के अन्तर्गत मिले हुए नोटिस के ६ माह के अन्दर सेण्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू को, जिसे उक्त

निपटारा करने का अधिकार प्राप्त है, प्राथना-पत्र भेज सकता है। इस प्रकार जो निपटारा होगा वह 'अन्तिम' (Final) रहेगा।

किसी वर्ष के लिये, उस वर्ष से २ वर्ष की समाप्ति के बाद, कोई नोटिस जारी नहीं किया जा सकेगा यदि वह व्यक्ति, जिस पर कर-निर्धारण या पुनः कर-निर्धारण करना है, किसी परदेशी का प्रतिनिधि माना गया हो।

कर उस दर से चार्ज किया जायगा, जिस पर तब चार्ज किया जाता जबकि आय कर-निर्धारण से न बचा होती। जान बूझकर छिपाई हुई आय की दशा में बचाये हुए कर की ड्यूटी रकम दण्ड स्वरूप लगाई जा सकती है।

अपील और पुनर्निर्णय (Appeals and Revision)

इनकम टैक्स ऑफीसर भी मनुष्य ही है। अन्य सभी आदमियों की भाँति उमसे भी गलतियाँ (तथ्यों की और कानून की) हो सकती हैं। कभी-कभी वह ईमानदारी से (किन्तु भ्रमपूर्वक) यह विश्वास किये रहता है कि उसके विचार कानून सम्मत हैं। इसी प्रकार कर-दाता और इनकम टैक्स ऑफीसर के बीच में भी कानून और तथ्य के प्रश्न पर ईमानदारी के मतभेद हो सकते हैं। जब कर-दाता का इनकम टैक्स ऑफीसर से मतभेद हो, तो वह उसकी आज्ञा के विरुद्ध अपील कर सकता है अथवा उसकी निगरानी के लिये मांग कर सकता है।

कर-दाता के अपील सम्बन्धी अधिकार

कर-दाता को अपील सम्बन्धी निम्नलिखित अधिकार दिये गये हैं —

(१) अपीलेट असिस्टेण्ट कमिशनर

प्रथम तो कर-दाता इनकम टैक्स ऑफीसर के फैसलों के विरुद्ध अपीलेट असिस्टेण्ट कमिशनर के यहाँ अपील कर सकता है। माँग की सूचना प्राप्ति के या फैसले की प्राप्ति के तीस दिन के अन्दर-अन्दर अपील फाइल कर देनी चाहिये। अपील पाने पर अपीलेट असिस्टेण्ट कमिशनर एक विशेष दिन और स्थान नियत कर देगा जब कि अपील सुनी जायेगी। सुनवाई की तिथि और स्थान सूचित करते हुए कर-दाता को बुलाने का नोटिस दिया जायेगा जो या तो खुद अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित हो सकता है। उसकी और इनकम टैक्स ऑफीसर की बातें सुनकर अ० अ० क० आदेश जारी करेगा जिसकी एक नकल कर-दाता को दी जायेगी। इस आदेश द्वारा कर-निर्धारण की पुष्टि की जा सकती है या उसे खारिज किया जा सकता है अथवा कर घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

(२) अपीलेट ट्रिब्यूनल

अपीलेट असिस्टेण्ट कमिशनर के आदेशों के विरुद्ध अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपील की जा सकती है। अपील का अधिकार कर-दाता को और आय-कर विभाग दोनों को

ही दिया गया है। कमिश्नर इनकम टैक्स ऑफीसर को अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपील करने का निर्देश कर सकता है यदि उसे अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर के आदेश में कोई विरोध हो। कर-दाता को अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करने के पहले १०० रु० जमा करने पड़ते हैं परन्तु अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करने के लिये विभाग द्वारा ऐसी क्नेई रकम जमा करना आवश्यक नहीं है।

ट्रिब्यूनल को अपील आरोपित आदेश की प्राप्ति के ६० दिन के अन्दर ही कर देनी चाहिये।

यह अपील एक निर्धारित प्रपत्र में भर कर भेजनी चाहिये। तथ्यों का जहाँ तक प्रश्न है ट्रिब्यूनल अपील की अन्तिम अदालत है परन्तु सन्नियम के प्रश्न पर मामला हाईकोर्ट को विवाराय भेजा जा सकता है।

(३) हाईकोर्ट

यदि कोई कानूनी प्रश्न पैदा हो तो कर-दाता या कमिश्नर इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल से मामला हाईकोर्ट को विचारार्थ भेजने की प्रार्थना कर सकता है। इस प्रकार की प्रार्थना-पत्र ट्रिब्यूनल को देने के लिये ट्रिब्यूनल के कर-दाता या कमिश्नर को आदेश जारी करने की तिथि से ६० दिन की अवधि सीमा रखी गई है। यह प्रार्थना-पत्र निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिये और कर-दाता द्वारा प्रार्थना पत्र देने की दशा में उसके साथ १०० रु० की फीस भी आनी चाहिये।

ट्रिब्यूनल से मामले का क्विरण प्राप्त होने पर, हाईकोर्ट मामले को सुनेगा और पैदा हुये कानूनी प्रश्न पर निर्णय देगा।

(४) सुप्रीम कोर्ट

हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध कानूनी प्रश्न पर अन्तिम अपील भारत के सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है।

अपील तब ही की जा सकती है जब हाईकोर्ट यह प्रमाणित करे कि वह मामला ऐसा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को अपील करना उचित है।

कमिश्नर द्वारा पुनर्विचार (Revision by Commissioner)

अपनी मर्जी से या कर-दाता की प्रार्थना पर कमिश्नर धारा ३३ A तथा ३३ B के अन्तर्गत पुनर्विचार करने के अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है।—

(१) यदि कमिश्नर स्वयं करता है तो वह किसी मामले का विवरण, जिसमें इनकम टैक्स ऑफीसर या अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर ने आदेश जारी किया, मँगा सकता है और ऐसी सब जाँच करने के उद्देश्य से जो वह आवश्यक समझे, वह उस पर निर्णय दे सकता है बशर्ते वह कर-दाता के लिये अहितकर न हो। हाँ, वह आदेश निम्न द्वाआ में सशोधित न कर सकेगा।—

(अ) जबकि अ० अ० क० या अ० टि० को उस आदेश के सम्बन्ध में अपील की जा सकती है और अपील का समय अभी नहीं निकला है, या

(आ) जब वह मामला अ० अ० क० के या अ० टि० के सम्मुख चल रहा हो,

(इ) जब आदेश दिये हुये एक साल से अधिक समय बीत चुका है ।

(२) यदि कर दाता इनकम टैक्स ऑफीसर अथवा अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर के आदेश के विरुद्ध पुनर्विचार के लिये कमिश्नर को प्रार्थना-पत्र देना चाहता है तो उसे आदेश की प्राप्ति के एक वर्ष के अन्दर प्रार्थना-पत्र दे देना चाहिये । साथ में २५ रु० फीस भी जानी चाहिये ।

ऐसे किसी मामले में कमिश्नर का पुनर्विचार सम्बन्धी अधिकार निम्न शर्तों के अधीन है :—

(अ) यदि आदेश के विरुद्ध अ० अ० क० या अ० टि० को अपील की जा सकती है, तो कमिश्नर तभी पुनर्विचार कर सकता है जबकि अपील का समय गुजर जाय । अ० टि० को अपील की दशा में यदि कर दाता अपना अपील सम्बन्धी अधिकार छोड़ देता है तो समय गुजरने के पहले भी कमिश्नर आदेश पर पुनर्विचार कर सकता है ।

(आ) यदि अ० अ० क० को अपील की गई है, तो अपील चलने के दौरान में कमिश्नर अपना पुनर्विचार सम्बन्धी अधिकार प्रयोग नहीं कर सकता । हाँ, जब अपील पर निर्णय हो जाय तब वह पुनर्विचार कर सकता है ।

(इ) यदि अपील अ० टि० को की गई है तो फिर कमिश्नर को पुनर्विचार का अधिकार नहीं रहता ।

प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति पर वह सम्बन्धित मामले की कार्यवाहियों का विवरण मँगा सकता है और विवरण आने पर ऐसी जाँच कर सकता है और ऐसा आदेश जारी कर सकता है जो वह ठीक समझे । उसका निर्णय कर-दाता के विरुद्ध पक्षपातमय (Prejudicial) न होना चाहिये ।

(३) उल्लेख से यह मालूम होगा कि धारा ३३ A के अन्तर्गत कमिश्नर किसी आदेश को इस प्रकार सशोधित नहीं कर सकता कि उससे कर-दाता को हानि पहुँचे । अतः धारा ३३ B यह आयोजन करती है कि कमिश्नर किसी भी कार्यवाही का रिकार्ड भगा कर जाँच सकता है और यदि वह यह समझता है कि इनकम टैक्स ऑफीसर (अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर नहीं) द्वारा जारी किया आदेश अनुचित है क्योंकि उससे रेवेन्यू को नुकसान पहुँचता है, तो वह कर दाता को सुनवाई का उचित अवसर देकर

आवश्यक जाँच करके ऐसा आदेश जारी कर सकता है जो वह उस परिस्थिति में ठीक समझे। इस आदेश द्वारा कर-निर्धारण बढ़ाया भी जा सकता है। किन्तु इस धारा के अन्तर्गत कोई आदेश धारा ३४ के अन्तर्गत जारी किये गये पुनः कर निर्धारण के आदेश पर पुनर्विचार करने के लिये पास किया जा सकता है। ऐसा आदेश प्राप्ति की तिथि से दो वर्ष गुजरने के बाद भी नहीं किया जा सकता।

धारा ३३ B कमिश्नर को अपीलेंट असिस्टेंट कमिश्नर या अपीलेंट ट्रिब्यूनल के आदेशों पर पुनर्विचार करने का अधिकार नहीं देती। न ही वह कमिश्नर को इनकम टैक्स ऑफीसर के निर्णय पर, जबकि कर-दाता ने उस निर्णय के विरुद्ध अपील कर रखी हो, पुनर्विचार का अधिकार देती है।

कमिश्नर के सशोधित आदेश से जिस कर-दाता को हानि पहुँची हो वह प्रदेश सूचना की तिथि के ६० दिनों के भीतर ट्रिब्यूनल से अपील कर सकता है।

कर की वापसी (Refund)

कर की वापसी 'उद्गम स्थान पर लगने' की दशा में, जैसे लाभशो की दशा में, तथा 'उद्गम स्थान पर कटौती करने' के कारण, जैसे वेतन और प्रतिभूतियों के ब्याज की दशा में, आवश्यक हो जाती है। इसका कारण यह है कि इन दोनों ही दशाओं में कर-दाता की कुल आय पर लागू होने वाली औसत कर की दर का पता कर लगाते या काटते समय नहीं होता।

निम्नलिखित दशाओं में एकूण कर-दाता कर वापसी की माँग कर सकता है :—

- (१) जब वेतन या प्रतिभूतियों के ब्याज से उद्गम स्थल पर, कर-दाता की कुल आय को लागू होने वाली दर से ऊँची दर पर कर काटा गया हो।
- (२) जब कोई कर-दाता लाभशो से आय प्राप्त करता है और उसकी कुल आय को लागू होने वाली उचित दर लाभशो पर लगे कर की उच्चतम दर से कम है।
- (३) जब दोहरे आय-कर भुगतान के सम्बन्ध में छूट चाहिये।
- (४) जब परदेशियों को किये गये भुगतानों से उच्चतम दर पर आय कर काटा गया हो, जबकि उन पर वास्तव में कम दर से लगना था।
- (५) जब कर-निर्धारण में धारा ३५ के अन्तर्गत कोई गलती सुधारी गई हो, जिसके प्रभाव स्वरूप दिया गया कर कम हो जाता है।
- (६) जब कर-निर्धारण के खिलाफ किसी अपील के परिणाम स्वरूप कर (जो पहले ही चुकाया जा चुका है) कम हो जाता है।

धारा ४८ के अनुसार, जब चुकाया गया कर उचित रूप से लगने वाले कर की रकम से अधिक हो तब कर-दाता को ऐसे आधिक्य की वापसी का हक है। कर की

वापसी की माँग करने वाले व्यक्ति को इनकम टैक्स ऑफीसर के यहाँ नियमित फार्म पर प्रार्थना पत्र देना चाहिए। इस प्रार्थना-पत्र के साथ कुल आय का नकशा और दावे को सिद्ध करने के लिए आवश्यक अन्य साक्ष्य भी, जैसे आय-कर कटौती का प्रमाणपत्र तथा लाभांश सम्बन्धी सूचनाये (Dividend warrants) आदि अन्य आवश्यक कागजात भेजने चाहिये।

कर की वापसी के लिये प्रार्थना-पत्र कर-निर्धारण वर्ष के अन्त से, जिसमें कोई आय (जिस पर कर अधिक चुका दिया गया है) कर लगने को थी, चार वर्ष के भीतर-भीतर दिया जा सकता है। उदाहरण के लिये १९५८-५९ में पैदा होने वाली आय पर, जिसमें से उद्गम स्थान पर कर काटा गया है, १९५९-६० के कर-निर्धारण वर्ष में कर लगाया जायगा, और उद्गम स्थान पर की गयी कटौतियों के सम्बन्ध में वापसी की माँग १९६३-६४ की समाप्ति (अर्थात् ३१ मार्च १९६४ तक) की जा सकती है।

वापसी की माँग को सिद्ध करने का भार प्रार्थना-पत्र भेजने वाले कर-दाता पर होता है। उसे यह साबित करना पड़ेगा कि उसने या उसकी ओर से जो कर की रकम अदा की गयी है वह उस कर की रकम से अधिक थी जो कि उससे नियमानुसार ली जा सकती है।

साधारणतया कर वापसी की अर्जी पर अर्जी देने के तीन महीनों के अन्दर कार्य-वाही हो जाती है। यदि इस काम में देर हो जाय तो इनकम टैक्स ऑफीसर या इन्स्पेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर से कहना चाहिए। कर वापसी की रकम कर-दाता को लौटाने के बजाय उस कर के विरुद्ध रख ली जा सकती है जो उससे अभी लेना रह गया हो।

यदि इनकम टैक्स ऑफीसर से इस आशय का सर्टीफिकेट ले लिया जाय कि कुल आय या कुल विश्व आय कर लगने योग्य नहीं है अथवा वह उच्चतम से कम दर पर ही कर लगने योग्य है तो प्रतिभूतियों के ब्याज पर तथा परदेशियों को दिये गये वेतनों एवं दूसरी रकमों पर काटे गये कर की वापसी के लिये माँग करने की आवश्यकता बहुत से मामलों में नहीं रह जाती। सर्टीफिकेट प्राप्त करने के लिए कुल आय के नक्शे के साथ इनकम टैक्स ऑफीसर के यहाँ अर्जी देनी चाहिए।

यदि कर की वापसी या कर में कर्मा करने का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया जाय तो उसकी अपील पहले अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर के यहाँ और यदि वहाँ से कर-दाता की सतुष्टि न हो तो बाद में अपीलेट ट्रिब्यूनल से करनी चाहिए। यदि कर वापसी की माँग करने वाला कर-दाता अपील न करना चाहे तो वह कमिश्नर के यहाँ निगरानी के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकता है। जिस आज्ञा के विरुद्ध यह अर्जी दी जा रही है उसके जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक निगरानी (Revision) के लिये प्रार्थना-पत्र दिया जा सकता है।

जैसा कि एक पिछले अध्याय में बताया जा चुका है, कर-दाताओं में व्यक्ति सयुक्त हिन्दू परिवार, फर्म तथा अन्य जन-मण्डल, कम्पनियो और स्थानीय सत्ताएँ शामिल हैं। इस अध्याय तथा आगामी अध्यायों में यह बताया जायगा कि इन कर-दाताओं में से प्रत्येक पर कर किस प्रकार लगाया जाता है।

(१) व्यक्ति (Individuals)

‘व्यक्ति’ शब्द में आमतौर पर मानव मात्र (human being) का ही बोध होता है। इसके अन्तर्गत एक स्त्री, एक पुरुष, एक नाबालिग या अपरिपक्व मस्तिष्क का व्यक्ति शामिल है।

व्यक्ति पर आय-कर और अतिरिक्त कर उसकी कुल आय की रकम के अनुसार विभागीय दरों (graded scale of rates) से लगता है। व्यक्ति पर पृथक् रूप से कर लगाया जाता है, चाहे वह कर के अर्धीन अन्य इकाइयों (units) में से किसी में आता हो। इन परिस्थितियों में एक व्यक्ति पर कर-दायित्व इस प्रकार है—

(१) सयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य होने के नाते परिवार की आय में से किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाली रकम उसके हाथों में कर मुक्त है, चाहे परिवार ने अपनी आय पर कर अदा न किया हो, लेकिन यदि सयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य की आय में उसकी निज की कमाई हुई आय (personal earnings) शामिल हो तो ऐसी आय पर उसके हाथों में एक व्यक्ति की भाँति कर लगेगा। किसी हिन्दू पुत्र को पिता के अपने प्रयत्न से प्राप्त जायदाद (self-acquired property) में जन्म लेने से ही कोई हक प्राप्त नहीं हो जाता। ऐसी जायदाद की आय के लिए पिता के ऊपर ही व्यक्ति के रूप में कर लगता है।

(२) अनरजिस्टर्ड फर्म के सामीदार को फर्म के लाभ में अपने हिस्से पर, यदि फर्म के ऊपर कर लगाया जा चुका है, कर नहीं देना पड़ता है। किन्तु दर निकालने के उद्देश्य से हिस्से की यह रकम उस सामीदार की कुल आय में अवश्य जोड़ी जानी चाहिए। यदि फर्म की कुल आय पर उसके कर-योग्य सीमा (taxable

limit) से कम होने के कारण कर नहीं लगा है, तो प्रत्येक साझीदार को अपने-अपने लाभ के हिस्से पर कर देना पड़ेगा ।

(३) एक रजिस्टर्ड फर्म को, यदि कुल आय ४०,००० रु० से अधिक है, स्वयं अपनी कुल आय पर आय-कर चुकाना पड़ता है, फिर भी ऐसी फर्म के साझीदार पर फर्म की आय में उसके भाग के लिये अन्य आय के साथ कर गणना की जावेगी । हाँ, उसे निम्न छूटें (rebates) पाने का अधिकार होगा—(अ) फर्म द्वारा चुकाये गये आय-कर में उसके भाग की रकम पर आय-कर की छूट और (आ) व्यापार के अतिरिक्त अन्य साधनों से अर्जित आय पर फर्म द्वारा चुकाये गये अनुपातिक आय-कर में उसके भाग की रकम पर सुपर टैक्स की छूट ।

(४) कर-दायित्व की दृष्टि से किसी जन-मण्डल के सदस्य की भी वही स्थिति है जो अनरजिस्टर्ड फर्म के सदस्य की होती है ।

(५) कम्पनी को, एक पृथक् कर लगने योग्य इकाई के रूप में अपने लाभ पर कर देना पड़ता है । वह अपने निजी दायित्व के सम्बन्ध में ही कर अदा करती है अशधारियों के बदले में नहीं । फिर भी, जब कोई लाभांश कम्पनी द्वारा किसी अशधारी को कर लगी आय में से वितरित किया जाता है तो इस लाभांश पर आय कर (अतिरिक्त कर नहीं) अशधारियों की ओर से ही कम्पनी द्वारा अदा किया हुआ माना जाता है ।

अशधारी द्वारा वास्तव में प्राप्त किये गये लाभांश (Net dividend) में आय-कर की रकम, जो उसकी ओर से अदा की हुई मानी गयी है, जोड़कर सकल लाभांश (Gross dividend) मालूम कर लेना चाहिए । लाभांश की यह ग्राँस रकम ही अशधारी की कुल आय में शामिल की जाती है ।

कमायी हुई आय की छूट

एक व्यक्ति को अपनी कुल आय में शामिल हुई समस्त कमायी हुई आय पर कमायी हुई आय की छूट दी जाती है ।

एक रजिस्टर्ड फर्म की दशा में फर्म को स्वयं अपनी ओर से कर नहीं देना पड़ता । इसलिए कमायी हुई आय की छूट साझीदारों को (यदि वे फर्म के व्यावसायिक कार्य में सक्रिय रूप से सहयोग देते हों) दी जाती है, और ये ही लोग फर्म में अपने-अपने लाभ के हिस्सों पर आय-कर देते हैं ।

एक अनरजिस्टर्ड फर्म को अपनी कुल आय में शामिल कमायी हुई आय पर कमाई हुई आय की छूट पाने का अधिकार है । किन्तु यदि अनरजिस्टर्ड फर्म अपनी कुल आय कर-योग्य सीमा (Taxable limit) से कम होने के कारण कर योग्य न हो तो ऐसी दशा में फर्म के लाभ में साझीदार के हिस्से पर कमायी हुई आय की छूट दी जाती है, बशर्ते कि यह साझीदार इस फर्म के व्यावसायिक कार्य में सक्रिय रूप से सहयोग देता हो ।

धारा १६ के आदेश

कर से बचने की रोक-थाम के लिए धारा १६ के अन्तर्गत निम्न व्यवस्था की गयी है :—

(१) कर से बचने की दृष्टि से यदि कोई व्यक्ति अपनी आय किसी और के नाम बन्दोबस्त (Settle) करदे, लेकिन सम्पत्ति और जायदाद (जिनकी आय इस प्रकार हस्तातरित की गयी है) पर उसी का अधिकार बना रहे, तो ऐसी दशा से यह हस्तातरित की हुई आय उसकी ही मानी जायगी और उसे उसकी कुल आय में शामिल किया जायगा ।

(२) यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के नाम सम्पत्ति का कोई खण्डनीय हस्तातरण (Revocable transfer) करे, तो ऐसी सम्पत्ति की आय उस व्यक्ति (हस्तातरित करने वाले) की ही समझी जायगी और उसे उसकी कुल आय में शामिल किया जायगा ।

इन दो उपयुक्त नियमों के साथ यह अपवाद है कि किसी आय और सम्पत्ति के बन्दोबस्त से, जो ६ वर्ष से अधिक समय के पहले या हिताधिकारी (beneficiary) के जीवन काल में खण्डनीय नहीं है और जिससे बन्दोबस्त करने वाले को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई लाभ नहीं होता, होने वाली आय बन्दोबस्त करने वाले की आय नहीं मानी जाती ।

(३) यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को सम्पत्ति का खण्डनीय हस्तान्तर (Revocable transfer) करता है, तो ऐसी सम्पत्ति की आय उस व्यक्ति की ही आय समझी जायगी, जिसे वह हस्तातरित की गई है, हाँ, उस दशा में नहीं, जब कि वह हस्तातरण करने वाले ने अपनी पत्नी या अपने नाबालिग बच्चे के हक में किया हो ।

(४) एक व्यक्ति की पत्नी की निम्न साधनों वाली आय उसकी (पति की) कुल आय में शामिल की जायगी—

(अ) किसी फर्म की सदस्यता से, जिसमें उसका पति साझीदार है, या

(ब) उस सम्पत्ति से, जो पति ने उसके लिए प्रत्यक्षत या अप्रत्यक्षत हस्तातरित कर दी है । किन्तु यदि (1) यह हस्तातरण किसी पर्याप्त प्रतिफल के लिये (For adequate consideration) या (2) अलग-अलग रहने के राजीनामे (Agreement) के सम्बन्ध में किया गया है तो ऐसी दशा में हस्तातरित सम्पत्ति की आय पति की कुल आय में शामिल नहीं की जायगी ।

(५) किसी व्यक्ति (माता अथवा पिता) के नाबालिग बच्चे (निम्न की) के साधनों द्वारा होने वाली आय उस व्यक्ति की कुल आय में शामिल की जायगी—

(अ) उस फर्म के लाभ में नाबालिग बच्चे के प्रवेश से, जिसमें उसका पिता या माता साझीदार हैं, या

(ब) उस सम्पत्ति से, जो माता या पिता ने उसके लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः हस्तांतरित कर दी है। किन्तु यदि यह हस्तांतरण पर्याप्त प्रतिफल के लिये है और जहाँ नाबालिग सतान विवाहिता पुत्री हो तो ऐसी दशा में हस्तांतरित सम्पत्ति की आय व्यक्ति (माता या पिता) की कुल आय में शामिल नहीं की जायगी।

(६) यदि कोई व्यक्ति, पर्याप्त प्रतिफल के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से किसी अन्य व्यक्ति या जन-मण्डल को, अपनी पत्नी या नाबालिग बच्चे अथवा दोनों ही के हितार्थ सम्पत्ति, का हस्तांतरण करता है तो इस सम्पत्ति की आय हस्तांतरण करने वाले व्यक्ति की आय ही समझी जायगी और इसे उसकी कुल आय में शामिल किया जायगा।

मृत्यु होने पर कर-निर्धारण

यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उस पर कर उसके कानूनी उत्तराधिकारी या प्रबन्धक (Executor or Administrator) द्वारा (Through) लगाया जाता है। मृत व्यक्ति की आय का कर-निर्धारण करते समय केवल उसकी मृत्यु की तारीख तक हुई आय पर ही विचार करना चाहिये। मृत्यु के उपरान्त होने वाली आय पर कर-निर्धारण मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारियों पर किया जाता है।

उदाहरण

(१) ३१ मार्च १९५६ को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए एक कर-दाता की आय के बारे में निम्न सूचना प्राप्त हुई है —

(अ) एक रजिस्टर्ड फर्म जिसमें वह साझीदार है, से वेतन ६,००० रु०।

(आ) उपयुक्त फर्म से लगाई गई पूँजी पर ब्याज १५०० रु०।

(इ) इस फर्म से बिक्री पर १% कमीशन ७५०० रु०।

(ई) इस फर्म के व्यापार के हेतु विभिन्न स्थानों पर जाने के लिए सवारी भत्ता ३,६०० रु०।

(उ) इस फर्म की हानि का भाग, वेतन, ब्याज, कमीशन और सवारी भत्ता जो भागीदारों को चुकाया गया, को छोड़ते हुए, ६,००० रु०।

(ऊ) जायदाद की आय (६,००० रु० रिहायशी मकान का सम्मिलित करते हुए) १७,५०० रु०।

(ए) कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज १,५०० रु०।

(ऐ) प्रतिभूतियों पर ब्याज (ग्रॉस) २,००० रु० जिसमें से उचित दर पर कर उद्गम स्थान पर काट लिया गया।

(अ) एक चाय कम्पनी (जिसकी ४०% आय पर कर लगता है) से प्राप्त लाभांश ८७४ रु० ।

(अ) एक कम्पनी (जिसने अपने पूर्व कर लगे लाभ में से लाभांश बाँटा) से प्राप्त लाभांश २,००० रु० । जिस साल में कम्पनी ने यह लाभांश बाँटा उस वर्ष कम्पनी की आय शेष (Minus) में थी क्योंकि व्यापारिक लाभ से वाजिब ह्रास अधिक था ।

कर-दाता ने अपने तथा अपनी पत्नी के जीवन बीमा पर ६,००० रु० तथा ३,००० रु० प्रीमियम दिया ।

कर-दाता की १९५६-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए कुल आय तथा कर-मुक्त आय निकालिए ।

		रु०	
(१) प्रतिभूतियों पर ब्याज	कर योग्य (Taxed)	२,०००	
	कर मुक्त (Tax-free)	१,५००	३,५००
(२) जायदाद से आय		११,५००	
किराये पर दी गई जायदाद रिहायशी जायदाद			
(कुल आय ३०,००० रु० के १/१० तक सीमित)		३,०००	१४,५००
(३) व्यापारिक आय रजिस्टर्ड फर्म से भाग			
वेतन		६,०००	
पूँजी पर ब्याज		१,५००	
कमीशन		७,५००	
		१४,०००	
घटायी फर्म में हानि		६,०००	८,०००
(४) चाय कम्पनी से लाभांश (उद्गम स्थान पर आय-कर कटौती १२८ रु०)		१,०००	
न कर लगे लाभों से लाभांश (ग्रॉस नहीं किये जाएँगे)		२,०००	३,०००
	कुल आय		३०,०००

सवारी भत्ता धारा ४ (३) (vi) के अन्तर्गत कर-मुक्त है । कर-दाता को जीवन बीमा प्रीमियम ७,५०० रु० (कुल आय के चौथाई) पर आय-कर की छूट पाने का अधिकार है ।

(२) ३१ मार्च १९५६ को समाप्त हुए वर्ष में एक व्यक्ति की आय का विवरण निम्न प्रकार है—

(अ) उसका वेतन ७५० रु० मासिक था और वर्ष के लिये उसका यात्रा-भत्ता

पम्बन्धी बिल १,६६० रु० बैठा । किन्तु यात्रा मे उसका वास्तविक खर्च केवल १,१४० रु० हुआ ।

(ब) वेतन का ८% उसने १९२५ के प्रोवीडेण्ट ऐक्ट के अधीन एक प्रोवीडेण्ट फण्ड मे चन्दा दिया । उसका मालिक भी फण्ड मे उतना ही चन्दा जमा करता था । उसीके प्रोवीडेण्ट फण्ड के हिसाब पर साल भर मे ब्याज के ५८० रु० हुए ।

(स) वह दो मकानो का मालिक है, जिनमे से एक १४० रु० मासिक किराये पर उठा हुआ है और दूसरा मकान, जिसका वार्षिक मूल्य ८५० रु० है, वह अपने स्वयं के रहने के लिए इस्तेमाल करता है । पहले वाले के लिए वह जमीन किराये और बीमा के हिसाब मे १५० रु० देता है और दूसरे मकान के लिए २१० रु० देता है । इन दोनो मकानो पर क्रमशः ४०० रु० और १५० रु० स्थानीय कर देना पड़ता है ।

(द) विनियोगो से उसे साल मे इस प्रकार आय हुई—

२५० रु० कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियो से और ४८० रु० (ग्राँस) लाभाश के रूप मे ।

उसका बीमा हो चुका है । वह अपनी २५,००० रु० की जीवन-बीमा पालिसियो पर २,३५० रु० वार्षिक प्रीमियम देता है ।

१९५६-६० के कर-निर्धारण वर्ष के लिये उसकी कुल आय और कर-मुक्त आय मालूम करिये ।

	रु०	रु०	
(१) वेतन		६,०००	
(२) कर-मुक्त प्रतिभूतियो का ब्याज		२५०	
(३) जायदाद से आय—			
किराये पर उठाये गये मकान का भाडा	१,६८०		
घटाओ—स्थानीय करो का आधा	२००		
	१,४८०		
निजी निवास के मकान का मूल्य	८५०		
घटाओ—स्थानीय करो का आधा	७५		
	७७५		
घटाओ इसका आधा	३८७	३८८	
दोनों मकानों का वार्षिक मूल्य		१,८६८	
घटाओ—मरम्मत का १/६	३११		
जमीन किराया और बीमा	३६०	६७१	१,१९७

(४) अन्य श्रोतो से आय—
लाभाश (ग्राँस)

४८०

अतिरिक्त यात्रा भत्ता

(Excess Travelling Allowance)

५२०

१,०००

कुल आय

११,४४७

कर-मुक्त आय —

(१) प्रोवीडेंट फण्ड के चन्दे

७२०

(२) जीवन बीमा प्रीमियम (प्रोवीडेंट फण्ड का चन्दा व बीमा प्रीमियम दोनों मिला कर कुल आय के १/४ या ८,००० रु० से अधिक नहीं होना चाहिये)

२,१४१

(२) कर-मुक्त प्रतिभूतियों का ब्याज

२५०

३,१११

(३) ३१ मार्च १९५६ को समाप्त हुए वर्ष में एक व्यक्ति की (जो पक्का निवासी है) आय का विवरण नीचे दिया जाता है। १९५६-६० के कर-निर्धारण वर्ष के लिये इस व्यक्ति की कुल आय और कर-मुक्त आय मालूम करिये —

(क) वर्ष के पहले ६ महीनों के लिए वेतन ३०० रु० मासिक था, जिसमें से १०% उसने एक अस्वीकृत प्रोवीडेंट फण्ड में चन्दा दिया, जिसकी व्यवस्था उसका मालिक करता था।

(ख) १ अक्टूबर १९५८ में वह छुट्टनी में नौकरी से पृथक् कर दिया गया और उस तारीख को प्रोवीडेंट फण्ड में से उसे ६,५०० रु० मिले (जिसमें फण्ड में उसके चन्दे और इस पर ब्याज के ६,५०० रु० शामिल हैं)। इसके अतिरिक्त, उसे नौकरी से पृथक् होने पर क्षति-पूर्ति के ५,००० रु० प्राप्त हुए।

(ग) १ दिसम्बर १९५८ से उसे एक दूसरी नौकरी २५० रु० मासिक पर मिल गयी।

(घ) साल भर में उसे यह आय और हुई —

(1) जीवन-बीमा पॉलिसी (endowment) से ६,००० रु०, (11) बम्बई की एक काँटन मिल कम्पनी से लाभांश (ग्राँस) के १,६२० रु०, (111) अपने पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक एकाउण्ट से ब्याज के १०० रु०, (1V) ५०० रु० डायरेक्टर का पारिश्रमिक (fees), (V) संयुक्त हिन्दू परिवार की आय में उसके हिस्से के २,००० रु०, (VI) आगरा जिले में अपनी कृषि भूमि से लगान के ३५० रु० और नेपाल की जमीन से लगान के १,००० रु० मिले।

(ड) एक अनरजिस्टर्ड फर्म के लाभ में तिहाई हिस्से के ५,४०० रु०।

(च) स्टॉलिंग प्रतिभूतियों के ब्याज के ३७५ पौंड जिसमें से आधी रकम बम्बई में प्राप्त की गयी और शेष को लन्दन में ही पुन विनियोग कर दिया गया।

इस व्यक्ति ने अपनी जीवन बीमा पॉलिसी पर प्रीमियम के ५,००० रु० दिये।

रु०

१. वेतन जिसमे ३,००० रु० प्रो० फण्ड के और ५,००० रु० क्षतिपूर्ति के शामिल है)		१०,८००
२ अनरजिस्टर्ड फर्म से लाभ		५,४००
३ अन्य साधनों से आय		
लाभाश (ग्रास)	१,६००	
डाइरेक्टर का पारिश्रमिक	५००	
प्राप्त स्टर्लिंग आय	२,५००	
नेपाल की भारत भेजी आय	१,०००	
अनरैमिटेड स्टर्लिंग आय	२,५००	८,४२०
	<u>कुल आय</u>	<u>२४,६२०</u>

कर मुक्त आय

१ अनरजिस्टर्ड फर्म से लाभ	५,४००
२ जीवन बीमा प्रीमियम कुल आय के १/४ तक सीमित	५,०००
	<u>१०,४०० *</u>

नेपाल मे जो कृषि भूमि है, उसका लगान कृषि-आय के अन्तर्गत नहीं माना जा सकता क्योंकि वह भारत मे मालयुजारी नहीं देती ।

(४) एक अमरीकन कैमिस्ट बम्बई मे पहली बार १ जनवरी १९५६ को एक कैमीकल वर्क्स मे चीफ कैमिस्ट के पद पर नियुक्त होकर आया । कैमीकल वर्क्स के साथ पञ्चवर्षीय एग्रीमेन्ट के अनुसार उसे ६,००० रु० मासिक वेतन महीने की प्रत्येक आखिरी तारीख को मिलना तय हुआ । ३१ मार्च १९५६ को समाप्त हुए वर्ष के लिये उसकी अन्य आय का विवरण निम्न प्रकार है ।—

(अ) ३% भारतीय सरकार की प्रतिभूतियों पर ६ महीने का ब्याज २,५०० रु० ।

(ब) भारतीय कम्पनियों से प्राप्त लाभाश ६,८५० रु० (ग्रास) ।

(स) बम्बई की एक कम्पनी से डाइरेक्टर का पारिश्रमिक २५० रु० ।

(द) अमरीका की कृषि आय के ५०,००० रु०, जिसमे से आधी रकम मार्च सन् १९५६ मे उसके पास बम्बई भेज दी गयी ।

एक अमरीकन बीमा कम्पनी मे उसका ५,००० डालरों का जीवन बीमा है, जिसके प्रीमियम मे उसने ५०० डालर न्यूयार्क मे अदा किये ।

१९५६-६० के कर-निर्धारण वर्ष के लिए इस व्यक्ति की कुल आय बताइए ।

रु०

१ वेतन	१८,०००
२ प्रतिभूतियों पर ब्याज	३७५

३ लाभाश (ग्राँस)	६,८५०
डाइरैक्टर का पारिश्रमिक	२५०
विदेशी आय जो प्राप्त हुई	२५,०००
कुल आय	<u>५०,४७५</u>

“गतवर्ष १९५८-५९” के लिये कर-दाता भारत में कच्चा निवासी (Resident not ordinary resident) है ।

(५) ३१ मार्च १९५९ को समाप्त हुए वर्ष के लिये मि० जमशेदजी का हानि-लाभ खाता इस प्रकार है —

	रु०		रु०
वेतन	४०,०००	ग्राँस लाभ	५,००,०००
मृत कर्मचारियों की		मशीनरी की बिक्री पर	
विधवाओं को भत्ता	३,०००	लाभ	५०,०००
पोस्टेज स्टेशनरी	१,०००		
शुत कमीशन	१०,०००		
बम्बई यूनीवर्सिटी को दान	१०,०००		
किराया	६,०००		
स्टाफ प्रो० फण्ड को चन्दा			
(मान्यता प्राप्त)	५,०००		
विनियोगों के बेचने पर हानि	१,००,०००		
पूँजी पर व्याज	५,०००		
शुद्ध लाभ	<u>३,७०,०००</u>		
	<u>५,५०,०००</u>		<u>५,५०,०००</u>

(अ) बेची हुई मशीनरी का वास्तविक मूल्य (Original cost) १,००,००० रु० था और ३१ मार्च १९५८ को इसका अपलिखित मूल्य ७०,००० रु० था ।

(ब) मिस्टर और मिसेज जमशेदजी का सामोदारी में एक व्यापार भी चलता है, जिसका रजिस्टर्ड फर्म के रूप में १९५९-६० के लिये कर-निर्धारण योग्य लाभ ६०,००० रु० निश्चित हुआ है । फर्म की सम्पूर्ण पूँजी मि० जमशेदजी द्वारा लगाई गई है और इसका लाभ भी दोनों सामोदारों में बराबर बँट जाता है ।

(स) मि० जमशेदजी ने एक खण्डनीय हस्तान्तरण किया है, जिसकी लाभांशों से होने वाली आय १९५९-६० के कर-निर्धारण वर्ष के लिए १०,००० रु० है । इस हस्तान्तरण के अनुसार यह आय मिसेज जमशेदजी को जीवन पर्यन्त प्राप्त होती रहेगी ।

(द) मिसेज जमशेदजी ने भी एक खण्डनीय हस्तान्तरण किया है, जिसकी लाभांशों से होने वाली आय १९५९-६० के कर-निर्धारण के वर्ष के लिए १५,००० रु० है । इस हस्तान्तरण के अनुसार वह आय उनके तीनों बच्चों, जो नाबालिग हैं, भोगेंगे ।

मिस्टर और मिसेज जमशेदजी तथा नाबालिग बच्चों के ट्रस्टियों का कर-दायित्व १९५६-६० के कर-निर्धारण वर्ष के लिए क्या होगा ? बताइये ।

	रु०	रु०
हानि-लाभ खाते के अनुसार लाभ		३,७०,०००
जौड़ो—अस्वीकृत खर्चे		
युक्त कमीशन	१०,०००	
विनियोगों की बिक्री पर हानि, जो पूँजी हानि है	१,००,०००	
पूँजी पर ब्याज	५,०००	
बम्बई यूनीवर्सिटी को दान	१०,०००	१,२५,०००
		<hr/>
		४,६५,०००
घटाओ—मशीनरी की बिक्री पर पूँजी लाभ, जो लागत-मूल्य से बिक्री मूल्य का आधिक्य है		२०,०००
		<hr/>
	कर-योग्य लाभ	४,७५,०००

बेची हुई मशीनरी का अपलिखित मूल्य ७०,००० रु० है, ५०,००० रु० के मुनाफे पर बेचने के लिये इसे १,२०,००० रु० में बेचा गया होगा । इसलिये ५०,००० रु० में से २०,००० रु० पूँजीगत लाभ है ।

१९५६-६० के लिये मिस्टर जमशेदजी का कर-निर्धारण

	रु०	रु०
१ व्यापार में लाभ अपना व्यापार रजिस्टर्ड फर्म से	४,७५,०००	
	३०,०००	५,०५,०००
		<hr/>
२ अन्य साधनों से फर्म की आय में पत्नी का हिस्सा दोनों हस्तांतरणों (settlements) से आय		३०,०००
		२५,०००
३ पूँजी लाभ		२०,०००
		<hr/>
	कुल आय	५,५०,०००

मिस्टर जमशेदजी को (१) पूँजी लाभ २०,००० रु० पर ५,६६,६६६ रु० (अर्थात् अन्य आय जमा (+) पूँजी लाभ का एक-तिहाई) पर लाभ होने वाली दरों से आय-कर, तथा (२) अन्य आय ५,६०,००० रु० पर लाभ होने वाली दरों से आय-कर चुकाना होगा ।

उन्हे अतिरिक्त-कर ५,६०,००० रु० पर चुकाना होगा क्योंकि पूँजी लाभ पर अतिरिक्त-कर चुकाना नहीं होता ।

उन्हे कुल आय पर लागू होने वाली औसत दरो पर आय-कर और अतिरिक्त कर दोनों की १०,००० रु० (दान) पर छूट पाने का अधिकार है।

उन्हे रजिस्टर्ड फर्म द्वारा चुकाये गये आय कर की छूट पाने का अधिकार है क्योंकि रजिस्टर्ड फर्म की आय ४०,००० रु० से अधिक है तथा उसकी कुल आय में रजिस्टर्ड फर्म की सम्पूर्ण आय सम्मिलित है।

मिसेज जमशेद जी और नाबालिग बच्चों के ट्रस्टियों पर कोई कर नहीं लगेगा।

(६) ३१ मार्च १९५६ को समाप्त हुए वर्ष में डॉक्टर अ को निम्न साधनों से आय हुई. —

	रु०
(अ) डॉक्टरी पेशे से आय	५०,०००
(ब) जमीन के किराये से आय	१०,०००
(स) लाभांश (ग्रीस) से आय	१५,०००
(द) जायदाद से आय, जो आय-कर अधिनियम की धारा ६ के आदेशानुसार निर्धारित की गई है	३०,०००

डॉक्टर अ ने १ अप्रैल १९५८ को ५,००,००० रु० का अखण्डनीय हस्तातरण ट्रस्ट (irrevocable deed of trust settlement) के लिये किया है। इसके प्रत्यास सलेख (trust deed) में निम्न व्यवस्था है—

ट्रस्ट की सम्पूर्ण आय भोगने की हकदार जीवन पर्यन्त डाक्टर अ की पत्नी होगी। उनकी मृत्यु के उपरान्त यदि डॉक्टर अ जीवित रहे तो सम्पूर्ण आय को भोगने का हक उन्हें होगा।

ट्रस्ट की सारी पूँजी जॉइन्ट स्टॉक कम्पनियों के शेयरों के रूप में है, ३१ मार्च १९५६ को समाप्त हुए वर्ष में ३०,००० रु० के लाभांश (ग्रीस) प्राप्त हुए थे। यह रकम डाक्टर महोदय की पत्नी को दे दी गयी।

३० मार्च १९५६ को ट्रस्टियों ने अपने अधिकार से, जो उन्हें इस सम्बन्ध में प्राप्त था, ट्रस्ट के उपयुक्त अंशों को बेच दिया। अंशों की बिक्री से ६,००,००० रु० प्राप्त हुए।

१९५६-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिये डा० अ की कुल आय निकालिये।

१९५६-६० के लिये डाक्टर अ का कर निर्धारण

	रु०
१ जायदाद से आय	३०,०००
२, पेशे से आय	५०,०००
३ अन्य साधनों से आय.	
जमीन से किराया	१०,०००
ग्रीस लाभांश	१५,०००
पत्नी के हक में ट्रस्ट की आय	३०,०००
	५५,०००

४ पूँजी लाभ—ट्रस्ट विनियोगो के बेचने पर हुआ

	१,००,०००
कुल आय	२,३५,०००

ट्रस्ट के अन्तर्गत एक सम्पत्ति (अर्थात् शेयस) ट्रस्टियों को हस्तातरित कर दी गई है, जिसकी सम्पूर्णा आय केवल डाक्टर महोदय की पत्नी को ही जीवन पर्यन्त मिलेगी। इसलिए यह ट्रस्ट खण्डनीय (revocable) ट्रस्ट नहीं है और धारा १६ (१) सी के अनुसार ट्रस्ट की आय डाक्टर महोदय की आय नहीं मानी जायगी। लेकिन ट्रस्ट के अन्तर्गत एक सम्पत्ति का पर्याप्त प्रतिफल के बिना (without adequate consideration), ट्रस्टियों को पत्नी के हितों में हस्तातरण हुआ है। इसलिये धारा १६ (३) बी के अनुसार ट्रस्ट की आय हस्तातरण करने वाले व्यक्ति की ही आय मानी जायगी। इसीलिए, लाभश की आय ३०,००० रु० जो ट्रस्ट विनियोगो पर हुई तथा ऐसे विनियोगो की बिक्री पर हुआ पूँजी लाभ १,००,००० रु० दोनों ही डाक्टर अ की आय माने जाएँगे।

(७) कई वर्षों से अ कपडे का व्यापार कर रहा है जिसके खाते ३१ मार्च तक प्रतिवर्ष बनते हैं। १ अगस्त १९५८ को उसने परचूनिया का नया व्यापार भी आरम्भ किया। १९५९-६० के कर-निर्धारण के समय तक उसने परचूनी व्यापार के खाते नहीं बनाये थे।

(अ) यदि उसका कर-निर्धारण जून १९५९ में किया जाये और वह यह प्रार्थना करे कि वह अपने परचूनी व्यापार के प्रथम वर्ष के खाते ३१ जुलाई १९५९ को बन्द करेगा, तो क्या आप उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे ? यदि हाँ, तो क्यों ?

(ब) यदि उसका कर-निर्धारण सितम्बर १९५९ में किया जाय और वह यह प्रार्थना करे कि वह ३१ जुलाई को समाप्त होने वाले वर्ष को 'गत वर्ष' मानना चाहता है, तो क्या आप उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे ? यदि हाँ, तो क्यों ?

(अ) आय के प्रत्येक श्रोत के लिये कर-दाता एक पृथक् 'गतवर्ष' रखने का अधिकारी है। इस दशा में, करदाता के विद्यमान कपडा व्यापार का हिस्साबी वर्ष ही उसका गत वर्ष है जबकि उसका परचूनी व्यापार १ अगस्त १९५८ को आरम्भ हुआ था। परचूनी व्यापार के लिये वह किसी भी अवधि को, व्यापार आरम्भ करने की तिथि से १२ महीने समाप्त होने तक किसी भी अवधि को, 'गत वर्ष' मान सकता है क्योंकि करदाता परचूनी व्यापार के लिये ३१ जुलाई १९५९ को खाते बन्द करना चाहता है (अर्थात् व्यापार आरम्भ करने के ठीक १२ महीने की अवधि के बाद), इसलिये वह ३१ जुलाई को समाप्त होने वाले वर्ष को अपना 'गत वर्ष' रख सकता है। उसकी प्रार्थना इस सम्बन्ध में स्वीकार कर ली जायेगी और ऐसी दशा में १९५९-६० के कर-निर्धारण वर्ष के लिये परचूनी व्यापार का कोई गत वर्ष न होगा ?

(ब) यदि सितम्बर १९५९ में कर-निर्धारण रखा जावे, तो करदाता ३१ जुलाई १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष का अपने परचूनी व्यापार का गत वर्ष तब रख सकता है जब उस दिन को ही उसने उस व्यापार के खाते बन्द किये हों। लेकिन खाते कर-

निर्धारण की तिथि तक नहीं बनाये गये हैं। चूँकि खाते बन्द नहीं किये गये हैं इसलिये कर-दाता को, ३१ मार्च १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष के अलावा कोई अन्य गत वर्ष रखने का विकल्प नहीं रहता। १-८-१९५८ से ३१-३-१९५६ तक अवधि के लिये परचूनी व्यापार की आय पर १९५६-६० के कर-निर्धारण वर्ष के लिये कर निर्धारण होगा।

(२) हिन्दू अविभाजित परिवार (Hindu Undivided Families)

आय-कर के उद्देश्य के लिए, हिन्दू लॉ (Hindu Law) के अनुसार एक संयुक्त हिन्दू-परिवार (Joint Hindu Family) और एक अविभाजित हिन्दू-परिवार (Hindu Undivided Family) में अन्तर है। हिन्दू लॉ में एक संयुक्त हिन्दू परिवार में सब व्यक्ति शामिल किये जाते हैं जो एक ही पूर्वज के वंशज हैं (Lineally descended) और उनकी पत्नियों और अविवाहित पुत्रियों को भी इसके अन्दर शामिल किया जाता है। लेकिन, आय-कर की दृष्टि से अविभाजित हिन्दू परिवार वह है, जो निम्न दो शर्तों को पूरा करता हो—

(१) परिवार की शामिली जायदाद (Common property) हो।
शामिली जायदाद में निम्न जायदाद शामिल होती है—

- (१) पितृक जायदाद (Ancestral property)।
- (ब) पितृक जायदाद की सहायता से प्राप्त सम्पत्ति।
- (स) परिवार के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से पितृक सम्पत्ति की सहायता के बिना प्राप्त की हुई सम्पत्ति, जिसे वे लोग (परिवार के सदस्य) परिवार की सम्पत्ति मानते हो।

(२) परिवार में हिन्दू सहभागिता (Coparcenary) हो। अविभाजित हिन्दू परिवार के सदस्यों में निम्न व्यक्ति शामिल होते हैं।

- (अ) सहभागी (Coparceners) यानी वे व्यक्ति जिन्हें बेटवारे पर हक माँगने का अधिकार प्राप्त है, और
- (ब) अन्य लोग जो हिन्दू लॉ के अनुसार केवल गुजर-बशर (Maintenance) के हकदार हैं।

हिन्दू लॉ में संयुक्त परिवार केवल पुरुष सदस्य के साथ ही बन सकता है अथवा केवल स्त्री सदस्यों से ही उसका निर्माण हो सकता है। आय-कर के उद्देश्य के लिए यदि सम्पत्ति में कोई सहभागी या समाधी (Coparceners) नहीं हैं, तो परिवार अविभाजित हिन्दू परिवार नहीं हो सकता। जैसा कि आगे बताया गया है, अविभाजित हिन्दू परिवार, हिन्दू लॉ के दो सम्प्रदायों (Schools) द्वारा नियन्त्रित है—(१) दाय भाग और (२) मिताक्षरा। दाय भाग बंगाल में और मिताक्षरा भारत के शेष हिस्सों में प्रचलित है।

निम्न दशाओं में आय को अविभाजित हिन्दू परिवार की आय नहीं माना जाता और न उस पर इस रूप में कर-निर्धारण ही किया जा सकता है —

(अ) जब किसी अविभाजित हिन्दू परिवार के सदस्य की आय उसकी निज की कमायी हुई आय हो, तो उस आय के लिए उसके हाथों (व्यक्ति रूप में) कर लगेगा ।

(आ) किसी हिन्दू के पुत्र को जन्म लेने से ही अपने पिता के निजी प्रयत्नों से पैदा की गयी सम्पत्ति में हक प्राप्त नहीं हो जाता । ऐसी सम्पत्ति की आय के लिए पिता के ऊपर व्यक्ति के रूप में ही कर-निर्धारण किया जाता है ।

(इ) दाय भाग कानून के अनुसार, जन्म से ही पुत्र पैतृक सम्पत्ति में हकदार नहीं हो जाता । पिता के मरने के पश्चात् ही पहली बार उसे यह हक प्राप्त होता है । इसलिए पिता के जीवन-काल में पैतृक सम्पत्ति की आय पर व्यक्ति की आय के रूप में ही कर-निर्धारण होगा, बशर्ते कि पिता स्वयं अपने भाई के साथ उस पैतृक सम्पत्ति का सहभागी (Coparcener) न हो । अर्थात् पिता ने उस पैतृक जायदाद को किसी भाई के साथ प्राप्त (inherit) न किया हो ।

(ई) मिताक्षरा कानून के अधीन किसी अविभाजित हिन्दू परिवार के एक-मात्र जीवित पुरुष सदस्य की आय पर, यदि उसके कोई पुत्र न हो, उसकी व्यक्तिगत आय के रूप में ही कर-निर्धारण होता है । इस व्यक्ति की पत्नी और पुत्री जीवित होने से इस स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि पैतृक सम्पत्ति में पत्नी और पुत्री का कोई हक नहीं है ।

(उ) यदि संयुक्त परिवार (Joint family) का कोई सदस्य अपने हानि-लाभ पर कोई स्वतन्त्र व्यवसाय करता है, तो इस व्यवसाय की आय उस सदस्य की अपनी निजी आय होगी, परिवार की नहीं, चाहे उसने व्यवसाय के लिए परिवार के कोष में से ही रुपया उधार लिया हो । व्यवसाय से होने वाली उसकी निजी आय पर एक व्यक्ति के रूप में आय-कर लगेगा ।

(ऊ) यदि संयुक्त परिवार (Joint family) के सदस्य साझीदारी में अपने-अपने लाभ के लिये कोई व्यापार-व्यवसाय करते हो, तो उसके लाभ साझीदारी की आय होगी, परिवार की नहीं, और साझीदारों के लाभों पर अनरजिस्टर्ड फर्म के रूप में कर लगेगा ।

अविभाजित हिन्दू परिवारों का कर-निर्धारण

(Assessment of Hindu Undivided Families)

एक अविभाजित हिन्दू परिवार पर उसकी कुल आय के अनुसार, किसी व्यक्ति की भाँति ही एक पृथक् इकाई के रूप में (कर्त्ता या प्रबन्धक के द्वारा) कर-निर्धारण

किया जाता है और परिवार के सदस्यों की पृथक् आय पर कर-निर्धारण करते समय इस बात का विचार नहीं किया जाता कि परिवार की आय परिवार के सदस्यों में किस प्रकार वितरित की जाती है। यह बात उन मामलों में भी होती है जिनमें परिवार की आय कर लगने योग्य सीमा में कम हो और इसलिये इस पर कर न लगता हो। यही बात अतिरिक्त-कर के लिए लागू होती है।

एक अविभाजित हिन्दू परिवार पर व्यक्ति की भाँति कर-निर्धारण किया जाय यह सचमुच ही बड़ी कठोरता है। लेकिन यह कठोरता निम्न व्यवस्थाओं द्वारा कुछ असो में कम हो जाती है —

- (अ) कर-मुक्त आय की सीमा उच्चतर (higher) है,
- (ब) सरचार्ज की सीमा भी उच्चतर है,
- (स) जीवन-बीमा प्रीमियम के सम्बन्ध में अपेक्षाकृत बड़ी रकमों के लिए छूट दी जाती है।

एक अविभाजित हिन्दू परिवार को उसकी कुल आय में शामिल कमाई हुई आय के लिये कमाई हुई आय की छूट दी जाती है।

किसी अविभाजित हिन्दू परिवार द्वारा अपने किसी पुरुष सदस्य या उसकी पत्नी के जीवन-बीमा के लिए दी गई रकमे, परिवार की कुल आय के चौथे भाग तक या १६,००० रु० तक, जो भी इनमें कम हो, आय कर से मुक्त है।

एक हिन्दू अविभाजित परिवार को अधिकतम कर अयोग्य आय तथा सरचार्ज सीमा कितनी होगी यह 'कर-गणना' से सम्बन्धित अध्याय में बताया गया है।

बँटवारे के पश्चात् कर-निर्धारण

(Assessment after partition)

यदि एक बार परिवार पर अविभाजित रूप में कर-निर्धारण हो चुका है तो बँटवारा होने के बाद भी उस पर अविभाजित परिवार के रूप में ही कर-निर्धारण होता रहेगा, जब तक कि इनकम टैक्स ऑफीसर उस बँटवारे को स्वीकार न कर ले।

धारा २५ A अविभाजित हिन्दू परिवार के बँटवारे के पश्चात् के कर-निर्धारण से सम्बन्ध रखती है। यह धारा तभी लागू होती है जब अविभाजित हिन्दू परिवार का कोई सदस्य कर-निर्धारण के समय या उससे पूर्व यह कहता है कि परिवार में बँटवारा हो गया है, और यदि पुछ-ताछ करने के पश्चात् इनकम टैक्स ऑफीसर को भी यह इत्मीनान हो जाय कि संयुक्त परिवार की सम्पत्ति का बँटवारा परिवार के सदस्यों के बीच निश्चित भागों में हो गया है, तो वह इस बँटवारे की स्वीकृति प्रदान करते हुए आज्ञा (Order) जारी कर सकता है।

इसके पश्चात् इनकम टैक्स ऑफीसर परिवार का कर-निर्धारण करेगा,

मानो कि उसका बँटवारा ही न हुआ हो। इसका अर्थ यह है कि उसे यह मालू करना है कि परिवार की कुल आय कितनी है और उस पर दिये जाने वाले कर की रकम इस प्रकार निकालना है, कि मानो वह एक इकाई द्वारा देना था। इस प्रकार कर-निर्धारण कर लेने के पश्चात् परिवार के ऊपर लगी कर की रकम को वह परिवार के सदस्यों में, बँटवारे में मिले हिस्सों के अनुसार, बाँट देता है। ये सदस्य, सयुक्त रूप में और व्यक्तिगत रूप में भी सयुक्त परिवार की कुल आय पर लगे कर के लिए दायी होते हैं।

आंशिक बँटवारा (Partial Partition)

कुछ परिस्थितियों में एक अविभाजित हिन्दू परिवार का कुछ अंशों में ही बँटवारा होता है। 'आंशिक बँटवारे' (Partial Partition) से उन स्थितियों का संकेत होता है जबकि (1) परिवार से एक या कुछ सदस्य अलग हो जाते हैं, और (11) जबकि परिवार की सम्पत्ति के केवल कुछ अंश का ही विभाजन होता है। पहली स्थिति में तो पृथक् होने वाले सदस्यों से आय-कर के उद्देश्य से अलहदा रूप में व्यवहार किया जायेगा और शेष सदस्यों को एक अविभाजित परिवार के रूप में ही समझा जाता है। दूसरी स्थिति में सयुक्त परिवार पर ही, उसकी अविभाजित सम्पत्ति की आय के सम्बन्ध में, कर लगेगा।

उदाहरण

(१) ३१ मार्च १९५६ को समाप्त हुए गतवर्ष के लिये किसी अविभाजित हिन्दू परिवार ने एक नक्शा दाखिल किया जिसमें आय निम्न प्रकार दिखायी गई है —

रु०

जग्यदाद का किराया (मरम्मत के लिए १/६ घटाने के बाद)

२०,०००

कपड़े के व्यवसाय से आय

६०,०००

सट्टे से लाभ

२०,०००

पूछगछ करने के पश्चात् आपको निम्न तथ्य ज्ञात होते हैं —

(अ) ३१ मार्च १९५८ को कपड़े के व्यवसाय का, परिवार के विभिन्न सदस्यों में, उनमें से प्रत्येक का पूँजी खाता (Capital account) खोल देने पर, बँटवारा हो गया। इसके बाद इस व्यापार को चलाने के लिये, परिवार के सदस्यों में साझेदारी हो गयी।

(ब) इस बिल्डिंग के म्यूनिसिपल टैक्स के रूप में परिवार ने ३,००० रु० अदा किये।

१९५६-६० के कर-निर्धारण वर्ष के लिए इस परिवार का कर-दायित्व निश्चित करिये।

	रु०	रु०
१ जायदाद का ग्राँस किराया, मरम्मत का १/६ बिना कटे घटाओ—स्थानीय करो के लिये कटौती	२४,००० १,५००	
जायदाद का वार्षिक मूल्य घटाओ—१/६ भाग मरम्मत के लिये	२२,५०० ३,७५०	१८,७५०
२ सट्टे का लाभ		२०,०००
कुल आय		३८,७५०

परिवार को आय-कर अतिरिक्त कर ३८,७५० रु० पर १९५६-६० की दरों से देना पड़ेगा।

कपडे का व्यवसाय (जिसका बँटवारा हो चुका है) की आय पर परिवार को आय के रूप में कर-निर्धारण नहीं होगा, बल्कि इसके ऊपर अनरजिस्टर्ड फर्म की आय के रूप में कर लगाया जायगा।

(२) एक हिन्दू अविभाजित परिवार सोना, चाँदी, महाजनी, दलाली और शेयरो का व्यापार करता है। उसने ३१ मार्च १९५६ को समाप्त हुए गत वर्ष के लिये दाखिल किये आय के नक्शे में निम्नलिखित विवरण दिखाया :—

	रु०		रु०
चाँदी में हानि	१,००,०००	सोने में लाभ	१,५०,०००
प्रतिभूतियों की बिक्री पर हानि	२०,०००	गिन्नी में लाभ	२५,०००
शेयर व्यापार में हानि	५०,०००	दलाली ब्याज और कमी-	
कानूनी व्यय	३०,०००	शन से लाभ	१,५०,०००
डूबा ऋण	५०,०००	प्रतिभूतियों और लाभानो	
एस्टेब्लिशमेण्ट एव		का ब्याज	५०,०००
कन्टिनजैन्सीज	२०,०००		
शुद्ध लाभ	१,०५,०००		
	३,७५,०००		३,७५,०००

पुस्तकों की परीक्षा से निम्न तथ्य प्रकाश में आये :—

(अ) चाँदी खाने को हैजिंग अनुबन्ध (Hedging contract) में हुई हानि के १,००,००० रु० और चाँदी के सट्टे में हुई हानि के ५०,००० रु० से नाम किया गया है।

(आ) कानूनी व्यय में, चोरी से लाये स्वर्ण की कथित खरीद (alleged purchase) से सम्बन्धित क्रिमिनल कार्यवाही में खर्च हुये १०,००० रु० शामिल हैं।

(इ) डूबे ऋणों में व्यापार भवन की तिजोरी चोरी गये रुपये की १०,००० रु० हानि और कर्त्ता के साले को, जिसका व्यापार असफल हो गया, बिना ब्याज दिये अखण्डनीय ऋण के २०,००० रु० शामिल है।

(ई) सस्थापन व्यय (Establishment expenses) में निम्न शामिल है — कर्त्ता के पुत्र को दिये गये वेतन के ३,००० रु० और उसके (कर्त्ता के पुत्र के) दफ्तर आने जाने के लिये मोटर साइकिल की खरीद (सितम्बर १९५८ में) के १,००० रु०।

हानियों और व्ययों की मदों को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के कारण देते हुए परिवार की कुल आय निकालिये।

		रु०
उक्त विवरण के अनुसार शुद्ध लाभ		१,०५,०००
घटाओ—प्रतिभूतियों और लाभांश का ब्याज (अलग-अलग विचारते हुये)		५०,०००
		<hr/> ५५,०००
जोड़ो—चाँदी के सट्टे की हानि	५०,०००	
क्रिमिनल कार्यवाही	१०,०००	
तिजोरी से चुराया गया रुपया	१०,०००	
अखण्डनीय ऋण जो महाजनी व्यापार की साधारण प्रगति में नहीं है।	२०,०००	
मोटर साइकिल की लागत	१,०००	६१,०००
	<hr/>	<hr/>
घटाया—मोटर साइकिल का ह्रास साधारण २०% से ६ माह के लिए		१,४६,०००
		<hr/> १००
		<hr/>
कर-योग्य व्यापार लाभ		१,४५,६००
ब्याज तथा लाभांश-ग्रॉस मान लिए गए		५०,०००
		<hr/> १,९५,६००
	कुल आय	

उपरोक्त गणना निम्न टिप्पणियों के अधीन है —

(१) चाँदी के सट्टे में हानि के ५०,००० रु० स्वीकार नहीं किये जायेंगे, क्योंकि उस वर्ष सट्टे का कोई लाभ नहीं है,

(२) क्रिमिनल कार्यवाही में खर्च हुए १०,००० रु० कानूनी व्यय स्वीकार योग्य कटौती नहीं है।

(३) व्यापार भवन से नगदी की चोरी भी व्यापार से सम्बन्धित नहीं कही जा सकती और वह स्वीकार योग्य नहीं है। यदि यह साबित किया जा सके कि रोकड़ व्यापारिक स्कन्ध का भाग है और हानि किसी कमचारी के गबन के कारण हुई तो मामला दूसरा हो जायगा। परन्तु साधारणतः इस प्रकार की हानि कर-दाता की

लापरवाही से ही होती है और ऐसी हानि को स्वीकार करने के लिये अधिनियम में कोई व्यवस्था नहीं है ।

(४) कर्त्ता के साले को २०,००० रु० ऋण, बिना ब्याज देना, व्यापारिक ऋण नहीं । अतः डूबे ऋण की माँग अस्वीकृत की जाती है ।

(५) कर्त्ता के पुत्र को वेतन स्वरूप दिये गये ३,००० रु० स्वीकार है यह मानते हुए कि उसने व्यापार में सचमुच काम किया था ।

(६) मॉटर साइकिल की लागत (१,००० रु०) अस्वीकृत कर दी गई है क्योंकि यह पूँजी व्यय है । परन्तु १,००० रु० पर ह्रास स्वीकृत किया जायेगा क्योंकि हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्त्ता का पुत्र एक कमचारी है ।

(३) फर्म (Firms)

‘फर्म’, ‘साझेदार’ और ‘साझीदारी’ शब्दों का अर्थ आय-कर के उद्देश्य के लिए भी वही है, जो १९३२ के भारतीय साझेदारी अधिनियम (Indian Partnership Act of 1932) में दिया गया है, केवल ‘साझीदार’ शब्द के अन्तर्गत उस किसी व्यक्ति को भी शामिल कर लिया गया है, जो नाबालिग होने पर भी साझेदारी के लाभ में हिस्सेदार है।

साझेदारी का नाता अनुबन्ध से उत्पन्न होता है स्थिति (Status) से नहीं। इसलिए अविभाजित हिन्दू परिवार के सदस्य, जो पारिवारिक व्यापार करते हैं, इस व्यापार के साझीदार नहीं माने जा सकते। लेकिन एक अविभाजित हिन्दू परिवार के सदस्यों को यह विकल्प है कि वे चाहे तो पारिवारिक व्यवसाय का विभाजन कराले और तत्पश्चात् परिवार की अन्य सम्पत्ति (assets) का विभाजन कराए बिना साझीदार के रूप में उस व्यवसाय को चलावे।

आय कर के उद्देश्य के लिए फर्म रजिस्टर्ड होती है या अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड फर्म उसे कहते हैं जो धारा २६ ए की व्यवस्थानुसार रजिस्टर्ड हुई हो, और अनरजिस्टर्ड फर्म वह है जो इस प्रकार रजिस्टर्ड नहीं है।

रजिस्ट्रेशन—फर्म की रजिस्ट्री निम्न शर्तों के पूरा करने पर हो सकती है—

- (१) फर्म का सगठन साझेदारी प्रलेख के अन्तर्गत किया जाय,
- (२) साझेदारों के व्यक्तिगत शेयर उस प्रलेख में स्पष्ट निर्धारित कर दिये जायें,

और

(३) वर्ष का लाभ व हानि इस निर्धारित अनुपात में ही साझेदारों में विभाजित किया जाय।

यह रजिस्ट्रेशन उस रजिस्ट्रेशन से भिन्न है जो भारतीय साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत किया जाता है। यह फर्म की रजिस्ट्री कहलाती है परन्तु वास्तव में वह साझेदारी प्रलेख (Partnership deed) की रजिस्ट्री है।

रजिस्ट्री कराने के लिये सम्बन्धित क्षेत्र के इनकम टैक्स ऑफीसर को एक प्रार्थना पत्र देना चाहिये। इसके लिये एक विशेष निर्धारित फार्म भरना पड़ता है।

यदि प्रारम्भिक रजिस्ट्री करानी है तो प्रार्थना-पत्र फर्म के हिसाबी वर्ष की समाप्ति के पहले या फर्म बनने के छ. महीने के भीतर, जो भी तिथि पहले हो, प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर देना चाहिए। उस फर्म को जिसकी फर्मों के रजिस्ट्रार से रजिस्ट्री हो चुकी है या जिसका साभेदारी प्रलेख सब-रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड हो चुका है, यह अनुमति है कि वह हिसाबी वर्ष की समाप्ति के पहले कभी भी प्रार्थना-पत्र दे दे। यदि फर्म इस बात से सतुष्ट करदे कि प्रार्थना-पत्र में देरी किसी पर्याप्त कारण वश हो गई थी, तो इन्कम टैक्स ऑफीसर समय को बढ़ा सकता है।

यदि फर्म की एक बार इन्कमटैक्स ऑफीसर से रजिस्ट्री हो चुकी है तो फर्म के साभेदारों की प्रार्थना पर उसे प्रतिवर्ष नया किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन के नवकरण के लिये प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष में ३० जून के पहले प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर देना चाहिये।

यदि प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति पर इन्कमटैक्स ऑफीसर को यह विश्वास हो जाता है कि साभेदारी प्रलेख में दी गई सूचनाओं के अनुकूल ही कोई फर्म वास्तव में विद्यमान है तो वह उस प्रलेख पर फर्म के रजिस्टर्ड हो जाने की सूचना अंकित कर देगा। इस प्रकार दिया गया रजिस्ट्री का प्रमाणपत्र केवल उस वर्ष के कर निर्धारण के लिये ही प्रभावशील होगा जो उसमें उल्लिखित है।

फर्मों का कर निर्धारण (Assessment of Firms)

किसी फर्म की कर-योग्य आय निर्धारित करने के लिये फर्म को उसके सदस्यों से शृङ्ख एक इकाई के रूप में माना जाता है। किन्तु धारा १० (१४) बी के अनुसार वेतन, ब्याज, कमीशन या पारिश्रमिक के रूप में साभेदार को जो रकम दी गई है, वह घटाई नहीं जा सकता।

धारा १६ (१) बी के अन्दर वह विधि बताई गई है, जिसके अनुसार फर्म की कर देय आय (assessable income) उसके साभेदारों में बाँटी जानी चाहिये। इस धारा के अनुसार, फर्म की देय आय में प्रत्येक साभेदार का हिस्सा फर्म से प्राप्त की गई वास्तविक आय नहीं होता, बल्कि वह निम्न रूप में निकाली गई आय होता है—

(अ) पहले तो फर्म का धारा १० में वर्णित नियमों के अनुसार हानि-लाभ निकाला जाता है।

(ब) फर्म की आय इस प्रकार निकालने के पश्चात् साभेदारों को वेतन, ब्याज, कमीशन अथवा अन्य पारिश्रमिक के रूप में दी गई रकमें घटा दी जाती हैं, और

(स) फर्म की शेष कर-देय आय (Balance of assessable income) को साभेदारों के बीच में उनके लाभ के हिस्सों के अनुपात में बाँट दिया जाता है।

(द) अन्त मे, यदि फर्म की कुल आय मे कोई स्वीकृत धार्मिक दान शामिल है तो कटौती (Rebate) के मतलब के लिये ऐसे दान को साभेदारो मे उनके लाभ-विभाजन के अनुपात मे बाँट देना चाहिये ।

यदि फर्म द्वारा किया जाने वाला व्यापार बन्द कर दिया जाय तो फर्म की कुल आय पर, इनकम टैक्स आफिसर उसी तरह जैसे कि व्यापार बन्द नही हुआ हो मानकर, कर-निर्धारण करेगा तथा यदि फर्म कोई आज्ञा भंग (default) करती है तो उस पर दण्ड (penalty) लगाई जा सकती है ।

प्रत्येक व्यक्ति जो बन्द किए जाने वाले समय पर साभेदार था फर्म द्वारा दिए जाने वाले कर तथा दण्ड को देने के लिए, संयुक्त तथा पृथक् दोनों रूप से, दायी होगा ।

धारा २६ (१) के द्वितीय आयोजन के अन्तगत जबकि एक साभेदार पर निर्धारित किया गया कर उससे वसूल न किया जा सकता हो तो वह कर फर्म से ही वसूल किया जा सकता है ।

उदाहरण

अ, ब और स एक फर्म मे साभेदार है । फर्म के हानि-लाभ मे इनका हिस्सा क्रमश ३, ३ और १ है । ३१ दिसम्बर १९५८ को समाप्त हुए वर्ष के लिये लाभ-हानि-खाता निम्न प्रकार है —

	रु०		रु०
व्यापारिक खर्च	५०,०००	ग्रॉस लाभ	१,४५,०००
पूँजी पर व्याज	३,०००	प्रतिभूतियों पर व्याज	
अ	२,०००	(ग्रॉस)	५,०००
ब	१,०००		
स	६,०००		
ब को वेतन	३,०००		
स को कमीशन	८५,०००		
शुद्ध लाभ	१,५०,०००		१,५०,०००

फर्म की कर-देय आय (assessable income) बताइये और उसे तीनों साभेदारो मे बाँटिए ।

रु०

रु०

फर्म की कुल आय

- व्यापारिक लाभ
- हानि-लाभ खाते के अनुसार
- शुद्ध लाभ

८५,०००

जोड़ो—खर्च जो स्वीकृत नहीं है •

पूँजी पर व्याज	६,०००		
साम्प्रदायिक का वेतन	६,०००		
साम्प्रदायिक का कमीशन	३,०००	१५,०००	
		<hr/>	
		१,००,०००	
घटाओ—लाभांश जो व्यापारिक लाभ के रूप में नहीं है		५,०००	९५,०००
		<hr/>	
२ लाभान्वित (ग्राहक)			५,०००
			<hr/>
	फर्म की कुल आय		१,००,०००
			<hr/>

फर्म को कुल आय साम्प्रदायिकों में निम्न प्रकार बाँटी गई—

	(अ)	(ब)	(स)
	रु०	रु०	रु०
पूँजी पर व्याज	३,०००	२,०००	१,०००
वेतन	—	६,०००	—
कमीशन	—	—	३,०००
कुल आय का वितरण			
(२, २ और १)	३४,०००	३४,०००	१७,०००
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	३७,०००	४२,०००	२१,०००

(अ) रजिस्टर्ड फर्म (Registered Firms)

आयकर—१९५६-५७ कर-निर्धारण वर्ष से पूर्व एक रजिस्टर्ड फर्म को कर नहीं देना पड़ता था परन्तु साम्प्रदायिकों पर उनके लाभ-भागों पर उनकी वैयक्तिक कर दरों से सीधे कर लगाया जाता था। लेकिन १९५६ के फाइनेंस एक्ट ने यह स्थिति बदल दी है।

१९५६-५७ और बाद के कर-निर्धारण वर्षों के लिए एक रजिस्टर्ड फर्म को जिसकी आय ४०,००० रु० से अधिक हो, फाइनेंस एक्ट में निर्दिष्ट की गई दरों से आय-कर चुकाना होगा। १९५६-५७ एवं १९५७-५८ कर-निर्धारण वर्षों के लिये ये दरें निम्न हैं—

(१) कुल आय के प्रथम ४०,००० रु० पर	कुछ नहीं
(२) कुल आय के अगले ३५,००० रु० पर	५%
(३) कुल आय के अगले ७५,००० रु० पर	६%
(४) कुल आय के शेष भाग पर	९%

जहाँ तक साभेदारो का सम्बन्ध है, उन पर पहले की तरह ही उनके लाभ-भागों पर सीधे कर लगेगा लेकिन उन्हें फर्म द्वारा नये आयोजनों के अन्तर्गत चुकाए गए कर में अपने-अपने भाग की रकम पर वैयक्तिक दरो के अनुसार आय-कर की छूट मिलेगी। फर्म द्वारा चुकाए आय-कर से साभेदारो का भाग उनके आपस के लाभ-विभाजन के अनुसार निश्चित किया जाएगा।

सुपर टैक्स — एक रजिस्टर्ड फर्म पर सुपर-टैक्स नहीं लगता। फर्म की आय में प्रत्येक साभेदार का भाग उसकी कुल आय में जोड़ दिया जाता है और फिर उस पर वैयक्तिक रूप से सुपर-टैक्स लगता है।

यदि रजिस्टर्ड फर्म की कुल आय 'व्यापार' से प्राप्त हुई है तो साभेदारो को उनके व्यक्तिगत कर-निर्धारण में सुपर-टैक्स के लिये फर्म द्वारा चुकाए गए आय कर के किसी भाग की छूट नहीं दी जाएगी, लेकिन यदि फर्म की आय में 'व्यापार' के मद के अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से भी आय है तो उस अन्य भाग पर लगने वाले आय-कर की छूट साभेदारो के व्यक्तिगत कर-निर्धारण सुपर-टैक्स के लिए दी जाएगी।

जहाँ कि एक रजिस्टर्ड फर्म का कोई साभेदार परदेशी है या आय-कर अधिकारी यह समझता है कि रजिस्टर्ड फर्म का कोई साभेदार पाकिस्तान में रहता है तो ऐसे साभेदार का फर्म की आय में भाग का फर्म पर कर-निर्धारण किया जाएगा तथा चुकाने वाले कर की रकम, उस पर वैयक्तिक रूप में यदि कर-निर्धारण किया जाए, यह मानते हुए, निकाली जायगी। इस तरह निश्चित की हुई राशि फर्म को चुकानी होगी।

घाटे की पूर्ति और उमका आगे ले जाना (Set-off and carry forward)—यह पहले ही एक अध्याय में समझाया जा चुका है।

कमाई हुई आय की छूट (Earned Income Relief)—रजिस्टर्ड फर्म तथा उस अनरजिस्टर्ड फर्म, जोकि रजिस्टर्ड फर्म की तरह मानी जाय, की दशा में साभेदारो को जो कि कर-दाता हैं, यदि उन्होंने फर्म के व्यापार में सक्रिय भाग लिया है, कमाई हुई आय की छूट दी जाएगी। इस हेतु फर्म की आय में से प्रत्येक साभेदार का भाग कमाई हुई आय तथा 'न कमाई हुई आय' के भाग में बाँटा जायगा।

लाभ का गलत विभाजन (Wrong Distribution of Profits)—यदि रजिस्टर्ड फर्म का लाभ साभेदारी सलेख के अनुसार नहीं बाँटा जाए और फर्म का कोई साभेदार अपनी वास्तविक आय से कम आय का नकशा दाखिल करे तो इन्कम-टैक्स ऑफीसर उस साभेदार पर दण्ड लगा सकता है और इसके लिए अन्य साभेदार दण्ड स्वरूप दी गई रकम को वापिस करने की भाग नहीं कर सकता।

उदाहरण

नोट • उदाहरण (२) 'कर-गणना' अध्याय को पूर्ण अध्ययन कर लेने के बाद करना चाहिए ।

(१) कर-निर्धारण वर्ष १९५६-६० । हिसाबी वर्ष समाप्त हुआ ३० जून १९५८ को । एक रजिस्टर्ड फर्म में अ, ब, तथा स तीन साझेदार हैं जो २४.१० के अनुसार लाभ बाँटते हैं । फर्म की कुल आय 'व्यापार' से १,००,०००, नीचे की बातों को ध्यान रखते हुए, मानी गई —

	रु०
अ को चुकाया गया वेतन	१५,०००
ब को चुकाया गया ब्याज	६,०००
स को चुकाया गया कमीशन	६,०००

(अ) फर्म के द्वारा चुकाये जाने वाले कर की (ब) हर साझेदार को लाभ जो कि उसकी कुल आय में जुड़ना है, तथा (स) हर साझेदार के आय-कर तथा सुपर-टैक्स के कर-निर्धारण में यदि कोई क्रेडिट, रिबेट या कटौती मिलनी हो तो उसकी गणना कीजिए ।

(अ) फर्म द्वारा चुकाया जाने वाला कर :

	रु०
प्रथम ४०,००० रु० पर	कुछ नहीं
अगले ३५,००० रु० पर ५%	१,७५०
अगले २५,००० रु० पर ६%	१,५००
रजिस्टर्ड फर्म द्वारा चुकाया जाने वाला कर	<u>३,२५०</u>

(ब) हर साझेदार का आय-का भाग (Share income of each partner)

	अ रु०	ब रु०	स रु०
वेतन	१५,०००	—	—
ब्याज	—	६,०००	—
कमीशन	—	—	६,०००
आय का शेष (२४.१०)	<u>८,७५०</u>	<u>१७,५००</u>	<u>४३,७५०</u>
	<u>२३,७५०</u>	<u>२३,५००</u>	<u>५२,७५०</u>

(स) साझेदारों को फर्म द्वारा चुकाए गए आय-कर के लिए निम्न छूट मिलेगी ।

	रु०
अ—३,२५० रु० का २/१६	४०६
ब—३,२५० रु० का ४/१६	८१३
स—३,२५० रु० का १०/१६	२,०३१
	<u>३,२५०</u>

नोट क्योंकि रजिस्टर्ड फर्म की कुल आय 'व्यापार' से प्राप्त की गई है अतएव फर्म द्वारा चुकाए गए आय-कर के लिए साभेदारों को सुपर-टैक्स में कोई रिबेट नहीं मिलेगी।

साभेदारों के आय-कर चुकाने के लिए कुल आय में रजिस्टर्ड फर्म से आय का भाग 'कमाई हुई आय' मानी जाएगी यदि सब साभेदारों ने उस फर्म के व्यापार में सक्रिय सहयोग दिया है।

(२) एक रजिस्टर्ड फर्म में अ और ब दो साभेदार हैं जो कि १२ के अनुपात में लाभ और हानि बाँटते हैं। १९५९-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए उसकी कुल आय नीचे की तरह निकाली गई।

	रु०	रु०
जायदाद		५०,०००
व्यापार	१,००,०००	
ए को वेतन	१२,०००	
ब को व्याज	<u>१८,०००</u>	<u>३०,०००</u>
		१,३०,०००
		<u>१,८०,०००</u>

(अ) फर्म द्वारा चुकाये जाने वाला कर, साभेदारों के भाग, तथा उनके आय-कर तथा सुपर-टैक्स में कर के भाग की रिबेट की गणना कीजिए।

(ब) अ द्वारा चुकाये जाने वाला कर, यह मानते हुए कि उसे अन्य कोई आय नहीं है, निकालिए।

	रु०
कुल आय के प्रथम ४०,००० रु० पर	कुछ नहीं
कुल आय के अगले ३५,००० रु० पर ५%	१,७५०
कुल आय के अगले ७५,००० रु० पर ६%	४,५००
शेष ३०,००० रु० पर ९%	<u>२,७००</u>
रजिस्टर्ड फर्म द्वारा चुकाये जाने वाला आय-कर	<u>८,९५०</u>

हर साभेदार का आय का भाग निम्न होगा।

	अ	ब
	रु०	रु०
वेतन	१२,०००	—
व्याज	—	१८,०००
आय का शेष (१.२)	<u>५०,०००</u>	<u>१,००,०००</u>
	<u>६२,०००</u>	<u>१,१८,०००</u>

व्यापार के मद को छोड़ कर अन्य मदों से फर्म का आय पर आय-कर निम्न होगा.—

$$\frac{८,९५० \times ५०,०००}{१,८०,०००} = २,४८६ रु०।$$

इसलिए उनके वैयक्तिक कर-निर्धारण में निम्न रिबेट मिलेगी —

	आय-कर की रिबेट रु०	सुपर-टैक्स की रिबेट रु०
अ (एक-तिहाई)	२,६८३	८२६
ब (दो-तिहाई)	५,६६७	१,६५७
	<u>८,३५०</u>	<u>२,४८३</u>

१६५६-६० के लिए अ का कर-निर्धारण

१	जायदाद से आय का भाग ५०,००० रु० का एक-तिहाई (न कमाई हुई)	रु० १६,६६७
२	१२,००० रु० वेतन सहित व्यापार आय से भाग (कमाई हुई आय यह मानते हुए कि अ ने सक्रिय भाग लिया है)	४५,३३३ <u>६२,०००</u>
	कुल आय	

४५,३३३ रु० की कमाई हुई आय पर आय-कर	रु० ८,३५३-२५
१६,६६७ रु० की न कमाई हुई आय पर आय-कर	४,१६६-७५

सामान्य सरचार्ज १२,५२० रु० पर ५%	६२६	१२,५२०-००
विशेष सरचार्ज . ४,१६६ ७५ रु० पर १५%	६२५	१,२५१-००

घटाया—२६८३ रु० के आय-कर पर रिबेट	१३,७७१-००
$\frac{२,६८३ \times १३,७७१}{६२,०००} =$	६६२-५६
चुकाये जाने वाला आय-कर	<u>१३,१०८-४४ (अ)</u>

४५,३३३ रु० की कमाई हुई आय पर सुपर-टैक्स	४,६००-००
१६,६६७ रु० की न कमाई हुई आय पर सुपर-टैक्स	५,७००-००

सामान्य सरचार्ज . १०,३०० रु० पर ५%	५१५	१०,३००-००
विशेष सरचार्ज : ५,७०० रु० पर १५%	८५५	१,३७०-००
		<u>११,६७०-००</u>

घटाया—८२६ रु० के सुपर-टैक्स पर रिबेट .

$$\frac{८२६ \times ११,६७०}{६२,०००} = \frac{१५६-००}{११,५१४-००} \text{ (ब)}$$

अतएव कुल चुकाये जाने वाला कर (अ) + (ब) = २४,६२२-४४ रु० ।

(ब) अन-रजिस्टर्ड फर्म (Unregistered Firms) —

अनरजिस्टर्ड फर्म के कर-देय लाभ साभेदारों में उसी प्रकार बाटे जाते हैं, जिस प्रकार की रजिस्टर्ड फर्म के लाभ । अनरजिस्टर्ड फर्म और उसके साभेदारों का कर-निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है —

आय कर .—अनरजिस्टर्ड फर्म पर एक व्यक्ति की भाँति ही उसकी कुल आय की रकम के अनुसार कर लगाया जाता है । यदि उसकी कुल आय कर-योग्य सीमा से कम है तो उस पर कोई आय-कर नहीं लगता ।

धारा १४ (२) (a) के अन्तर्गत, फर्म के लाभ के उस भाग पर जिस पर फर्म ने आय-कर दे दिया है साभेदार को आय-कर नहीं देना होगा, लेकिन यह लाभ का भाग अन्य आय पर कर देने के लिए आय-कर की दर निकालने के लिए जोड़ा जाएगा ।

यदि फर्म की कुल आय न्यूनतम कर-सीमा से कम है अथवा फर्म अपने आय-कर को चुकाने में असमर्थ है तो फर्म के लाभ का भाग साभेदार के हाथ में कर-मुक्त नहीं होगा ।

सुपर-टैक्स :—एक व्यक्ति की तरह ही एक अनरजिस्टर्ड फर्म पर भी सुपर-टैक्स लगता है । धारा ५५ के नियम द्वितीय के अनुसार यदि फर्म पर सुपर-टैक्स लगा है तो फर्म के लाभ के भाग पर साभेदार को सुपर-टैक्स नहीं देना होगा तथा यह भाग कुल आय में भी नहीं जोड़ा जाएगा । जरूरी यह है कि फर्म पर सुपर-टैक्स लगा है या नहीं ।

धारा २३ (५) (b) .—जब कि व्यक्तिगत साभेदारों की कुल आय किसी अनरजिस्टर्ड फर्म की कुल आय से बहुत अधिक हो तो फर्म के लिए अनरजिस्टर्ड रहना ही लाभदायक है । इस प्रकार से कर की बचत को रोकने के लिए धारा २३ (५) (b) का यह आदेश है कि अनरजिस्टर्ड फर्म की दशा में इनकम टैक्स ऑफीसर फर्म द्वारा दिए जाने वाले कर का निर्धारण करने के बजाय प्रत्येक साभेदार की कुल आय पता लगाए और इस कुल आय में उसकी फर्म की आय को भी सम्मिलित करते हुए प्रत्येक साभेदार द्वारा दिया जाने वाला कर निश्चित करे । हाँ, यह शर्त है कि अतिरिक्त कर सहित उस कर की कुल रकम जो ऐसी विधि के अन्तर्गत साभेदारों द्वारा चुकाई जावे वह उस कुल रकम से अधिक होनी चाहिए जो कि फर्म और साभेदार, व्यक्तिगत रूप से साभेदार पृथक-पृथक कर-निर्धारण होने की दशा में चुकाते ।

जहाँ कि आय-कर अधिकारी धारा २३ (५) (b) के अन्तर्गत अनरजिस्टर्ड फर्म पर कर लगाए वहाँ यह कहना उचित नहीं है कि उस पर रजिस्टर्ड फर्म की तरह कर लगाया गया है। कारण यह है कि रजिस्टर्ड फर्म में साझेदारों के ऊपर आय-कर और अतिरिक्त-कर के अतिरिक्त फर्म पर भी टैक्स लगता है। धारा २३ (५) (b) के अन्तर्गत साझेदारों पर कर लगाने के अतिरिक्त अनरजिस्टर्ड फर्म पर कर लगाने का उसे कोई अधिकार नहीं है।

जिस दशा में कर-निर्धारण की उक्त विधि अपनाई गई हो और जब किसी अनरजिस्टर्ड फर्म का कोई साझेदार परदेशी हो या पाकिस्तान में रहता हो तो ऐसे साझेदार के फर्म में आय-भाग के लिए फर्म पर कर-निर्धारण किया जाएगा और देय कर की रकम उस दर से निकाली जाएगी जो कि तब लागू होती जब कि उसी आय के लिए उस पर व्यक्तिगत रूप से कर-निर्धारण होता। इस प्रकार निकाली गई कर की रकम फर्म द्वारा चुकाई जावेगी।

घाटे की पूर्ति और अग्र-नेशन (Set-off and carry forward of losses)—अनरजिस्टर्ड फर्म प्रथम तो अपने घाटे की पूर्ति उसी वर्ष की अपनी अन्य आय में से कर सकती है और शेष घाटे को धारा (२४) (२) के अनुसार व्यापारिक हानि के रूप में आगे ले जा सकती है। किन्तु किसी अनरजिस्टर्ड फर्म का कोई साझेदार फर्म की हानि में अपने हिस्से की पूर्ति अपनी अन्य आय से नहीं कर सकता।

कमाई हुई आय की छूट (Earned income relief)—जब कि अनरजिस्टर्ड फर्म खुद ही आय-कर के लिये दायी बनाई जावे तो उसकी कुल आय में शामिल समस्त कमाई हुई आय पर कमाई हुई आय की छूट दी जाती है। ऐसी परिस्थितियों में अनरजिस्टर्ड फर्म के साझेदार को फर्म के लाभ में अपने उस हिस्से के लिये, जो आय-कर की दर निकालने के लिए उसकी कुल आय में शामिल किया जाता है लेकिन जिसपर कर नहीं लगता, कमाई हुई आय की छूट नहीं दी जाती है।

यदि रजिस्टर्ड फर्म की कुल आय पर कर योग्य सीमा से कम होने के कारण कर नहीं लगता तो फर्म के साझेदार को फर्म के लाभ में उसके हिस्से पर कमाई हुई आय को उचित छूट दी जाती है बशर्ते कि वह साझेदारी के व्यावसायिक कार्य में सक्रिय सहयोग दे रहा हो।

उदाहरण

(१) एक फर्म क अ, ब और स तीन साझेदार हैं, जिनके हिस्से क्रमशः ४, ३ और १ है। १९५८ के फर्म के हानि-लाभ खाते से ज्ञात होता है कि फर्म को, निम्न मदे काटने (charge) के बाद १६,००० रु० की शुद्ध हानि हुई। पूँजी पर ब्याज • अ ३,००० रु०, ब २,००० रु०, स १,००० रु० और स का वेतन २,००० रु०।

अ की अन्य साधनों से कर लगने योग्य आय ५,००० रु० है, लेकिन ब और स की ऐसी कोई आय नहीं है।

यदि फर्म (१) रजिस्टर्ड हो और (११) अनरजिस्टर्ड हो तो उसका कर निर्धारण किस प्रकार किया जायगा ?

पूँजी पर व्याज और साझीदार के वेतन के लिए सुधार (adjustment) करने के बाद, फर्म का नुकसान ८,००० रु० रहेगा, और तीनों साझीदारों के क्रमशः हिस्से निम्न प्रकार होंगे—

	अ रु०	ब रु०	स रु०
पूँजी पर व्याज	३,०००	२,०००	१,०००
वेतन			२,०००
फर्म की हानि में हिस्सा	-८,०००	-६,०००	-२,०००
	<u>-५,०००</u>	<u>-४,०००</u>	<u>१,०००</u>

(अ) जब फर्म रजिस्टर्ड है—

अ फर्म के घाटे में अपने हिस्से (५,००० रु०) को ५,००० रु० की अपनी अन्य आय में से पूर्ण (set-off) कर सकता है और इस प्रकार उस पर कोई कर नहीं लगेगा।

ब बर्फ की हानि में अपने हिस्से ४,००० रु० की पूर्ति ८ वर्षों तक इसी फर्म के आगामी लाभ में अपने हिस्से से कर सकता है।

स की कुल आय १,००० रु० ही है, इसलिए उस पर कर नहीं लगेगा।

(ब) यदि फर्म रजिस्टर्ड नहीं है—

अनरजिस्टर्ड फर्म अपने ८,००० रु० की घाटे की पूर्ति आगामी कर-निर्धारण में अपनी भावी आय से स्वयं कर सकती है।

अ अपने हिस्से के घाटे की पूर्ति अपनी अन्य आय में से नहीं कर सकता। उसे पूरे ५,००० रु० पर कर अदा करना पड़ेगा।

ब भी आगामी वर्षों की आय में से घाटे की पूर्ति नहीं कर सकेगा और स पर कर लगेगा ही नहीं।

(२) एक रजिस्टर्ड फर्म में अ और ब बराबर के साझीदार हैं। ३१ दिसम्बर १९५८ को समाप्त हुए वर्ष के लिए फर्म का हानि-लाभ खाता निम्न प्रकार है।

	रु०		रु०
वेतन और बोनस	४,०००	सकल लाभ (Gross Profit)	३४,६००
सामान्य व्यय	६,०००		
बिक्री-कर	३,०००	बैक व्याज	१,०००

किराया और महसूल	१,३००	विनियोगो की बिक्री	
ह्रास कोष	१,२००	पर से लाभ	३,०००
	३००		
डूबते खाते कोष	८००		
विज्ञापन	२,०००		
चन्दे और दान-पुण्य	१,०००		
मोटरकार बेचने पर नुकसान	२,०००		
पूँजी और ब्याज अ	१,५००		
ब	१,५००		
साम्भीदारो का वेतन अ	१,२००		
ब	१,८००		
कमीशन ब को	१,०००		
शुद्ध लाभ (Net Profit)	१०,०००		
	<u>३८,६००</u>		<u>३८,६००</u>

(क) सामान्य खर्चों में २०० रु० एक नया साम्भीदारी सलेख (partnership deed) लिखाने के लिये चुकाये गये कानूनी खर्चों के २०० रु० शामिल हैं।

(ख) विज्ञापन-व्यय के अन्दर स्थायी चिह्न (permanent signs) का खर्च ७०० रु० और अखबारों में विज्ञापन देने का व्यय १,३०० रु० शामिल हैं।

(ग) चन्दे और दान के व्यय में निम्नलिखित व्यय शामिल हैं — व्यापार समिति को दिये चन्दे के २०० रु०, शरणार्थियों के लिये छप्पर बनवाने में खर्च हुए ५०० रु० और एक स्कूल को दान दिया गया ३०० रु०।

(घ) मोटरकार साम्भीदारो के बिल्कुल निजी इस्तमाल में आती थी।

(ङ) ह्रास की स्वीकृत रकम केवल ५०० रु० है।

साम्भीदारो की अन्य आय निम्न प्रकार है —

अ—प्रतिभूतियों की ब्याज (ग्राँस) ५,००० रु०, लाभांश (ग्राँस) ३,००० रु०; और ब्याज से विदेशी आय जो भारत में नहीं भेजी गई ३,००० रु०।

ब—प्रतिभूतियों की ब्याज (ग्राँस) ७,००० रु०, लाभांश (ग्राँस) ४,००० रु०, जायदाद की कर लगने योग्य आय ५,००० रु०, ब्याज से विदेशी आय, जो भारत में नहीं भेजी गयी १,००० रु०।

यह मानते हुए कि अ और ब दोनों पक्के निवासी हैं, इनका कर-दायित्व बताइये।

हानि-लाभ खाते के अनुसार लाभ

जोड़ो—अस्वीकृत व्यय —

ह्रास कोष	१,२००
डूबत खाता कोष	८००
पूँजी पर ब्याज	३,०००

रु०

रु०

१०,०००

सामीदारो का वेतन	३,०००	
सामीदारो का कमीशन	१,०००	
कातूनी खर्चा	२००	
विज्ञापन व्यय जो पूँजी व्यय है	७००	
चन्दे और दान	८००	
मोटरकार की बिक्री पर घाटा	२,०००	१२,७००
		<hr/>
		२२,७००
घटाओ—विनियोगो के बेचने पर लाभ, जो पूँजी लाभ है	३,०००	
ह्रास की छूट	५००	३,५००
		<hr/>
फर्म की कर देय आय (assessable income)		१९,२००
		<hr/>

३,००० रु० के पूँजी लाभ पर कर नहीं लगेगा, क्योंकि वह ५,००० रु० से कम है।

फर्म की कुल आय सामीदारो में निम्न प्रकार वितरित हुई —

	अ रु०	ब रु०
पूँजी पर ब्याज	१,५००	१,५००
वेतन	१,२००	१,८००
कमीशन	—	१,०००
आय का शेषांश	६,१००	६,१००
	<hr/>	<hr/>
	८,८००	१०,४००

१९५६-६० के लिये अ और ब का कर-निर्धारण—

	अ रु०	ब रु०
१ प्रतिभूतियों पर ब्याज (ग़ौस)	५,०००	७,०००
२ जायदाद की आय	—	५,०००
३ व्यापारिक लाभ	८,८००	१०,४००
४ लाभांश ग़ौस	३,०००	४,०००
विदेशी आय	३,०००	१,०००
	<hr/>	<hr/>
कुल आय	१९,८००	२७,४००

रजिस्टर्ड फर्म पर कर नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी कुल आय ४८,००० रु० से अधिक नहीं है। अ १९,८०० रु० पर आय कर देगा (८,००० रु० पर १९५८-५९ की दरों से और शेष आय पर १९५६-६० की दरों से), ब २७,४०० रु० पर आय कर देगा (११,००० रु० पर १९५८-५९ की दरों से और शेष आय पर १९५६-६० की दरों से)।

से)। प्रतिभूतियों के व्याज और लाभांशों पर उद्गम स्थानों में जो कर संग्रह हुआ या काटा गया है उसके लिए उन्हें क्रेडिट (Credit) मिलेगी।

(३) क दो पृथक् व्यापारों (अ और ब) का मालिक है। अ व्यापार से उसे ५०,००० रु० का शुद्ध लाभ हुआ और ब व्यापार से उसे ८०,००० रु० का नुकसान हुआ। उसे ६०,००० रु० एक अनरजिस्टर्ड फर्म के लाभ में अपने हिस्से के मिले। क का कर-दायित्व क्या है ?

कुल आय का लेखा

	रु०
१ प्रोप्राइटी बिजनैस से हानि (५०,००० रु० - ८०,००० रु०)	-३०,०००
२ अनरजिस्टर्ड फर्म के लाभ (जिस पर कर लग चुका है) में हिस्सा	६०,०००
कुल आय	<u>३०,०००</u>

क्योंकि अनरजिस्टर्ड फर्म की आय पर आय-कर और अतिरिक्त कर लगाया जा चुका है, क को कर देने की आवश्यकता नहीं है। ३०,००० रु० के घाटे पर उसे ३०,००० रु० पर लागू होने वाली दरों से आय-कर और अतिरिक्त-कर देना पड़ेगा। चूँकि रकम एक हानि है इसलिये यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कर की दर क्या हो। कर शून्य है। दर धनात्मक (+ या Positive) है और वह रकम जिससे इसका गुणन किया गया है शेषात्मक (- या Negative) है। इसलिये देने वाला कर भी शून्य है।

(४) एक फर्म को, जिसके अ और ब दो बराबर के साझीदार हैं, ३१ मार्च १९५६ को समाप्त हुए व्यापारिक वर्ष में ३०,००० रु० का निम्न प्रकार घाटा हुआ —

	रु०
साझीदार अ को पूँजी का १०,००० रु० व्याज देने के बाद व्यापार का लाभ	५०,०००
एक पट्टे की जायदाद से हानि	८०,०००
शुद्ध हानि	<u>३०,०००</u>

साझीदार अ को इस वर्ष में २५,००० रु० मकान की जायदाद से आय हुई। साझीदार ब ने, जिसे इस वर्ष कोई आय नहीं हुई, ३१ मार्च १९५८ को बन्द हुये कपड़े के अपने व्यक्तिगत व्यवसाय की, पिछले वर्ष से आगे साई हुई १०,००० रु० हानि पूरी करने की माँग की।

फर्म को (1) रजिस्टर्ड, और (11) बिना रजिस्टर्ड या रजिस्टर्ड फर्म पर लागू होने वाले तरीके से २३ (५) बी के अन्तर्गत कर अयोग्य मानते हुए प्रत्येक साझीदार की कुल आय मालूम करिये।

हानि-लाभ खाते के अनुसार फर्म का लाभ	₹ ५०,०००
जोड़ो—सांभोदार अ को ब्याज	₹ १०,०००
	₹ ६०,०००
घटाओ—पट्टे की जायदाद से हानि	₹ ८०,०००
शुद्ध हानि	₹ २०,०००

सांभोदार अ और ब में फर्म की हानि का बटवारा—

	अ	ब
	₹	₹
पूँजी पर ब्याज	₹ १०,०००	—
व्यापार की आय का शेषांश	₹ २५,०००	₹ २५,०००
	₹ ३५,०००	₹ २५,०००
घटाओ—पट्टे की जायदाद से हानि	₹ ४०,०००	₹ ४०,०००
हानि	₹ ५,०००	₹ १५,०००

(अ) यदि फर्म रजिस्टर्ड है तो सांभोदार अ फर्म की हानि में अपने हिस्से (अर्थात् ₹ ५,००० ₹) की पूर्ति ८ वर्ष तक अपनी ₹ २५,००० ₹ की जायदाद की आय में से कर सकता है और उसकी कुल आय केवल ₹ २०,००० ₹ होगी। सांभोदार ब फर्म की हानि में अपने हिस्से (अर्थात् ₹ १५,००० ₹ की पूर्ति आगामी वर्षों में फर्म की आय में से कर सकता है। सांभोदार ब का कपड़े का निजी व्यवसाय बन्द हो गया, इसलिए इस व्यवसाय की घाटे की पूर्ति करने का अधिकार भी इस व्यवसाय के साथ समाप्त होगा। उसे यह घाटा आगे लाने का अधिकार नहीं है।

(ब) यदि फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो फर्म की ₹ २०,००० ₹ की हानि की पूर्ति आगामी वर्षों में इसी फर्म की भावी आय से ८ वर्ष तक की जा सकती है और किसी भी सांभोदार को फर्म की हानि में अपने हिस्से की पूर्ति अपनी अन्य आय में से (यदि कोई है) करने का अधिकार नहीं है। इसलिए अ की कुल आय ₹ २५,००० ₹ होगी और ब की कुल आय कुछ भी नहीं होगी।

(५) एक अनरजिस्टर्ड फर्म ने, जिसके अ और ब सांभोदार हैं, १९५८ साल की आय का नकशा निम्न प्रकार दाखिल किया है।

(अ) अ की पूँजी पर ₹ ५,००० ₹	₹
और ब की पूँजी पर ₹ ३,००० ₹	
ब्याज के घटाकर ब्याज से हुई आय	₹ २०,०००
(आ) एक चीनी मिल कम्पनी से वस्तुतः प्राप्त मैनेजिंग एजेंसी कमीशन	₹ २०,०००

घटाओ—पर्याप्त प्रतिफल के लिये किये गये
एक ठहराव के अनुसार एक
तीसरी पार्टी को दी गई रकम

२०,०००

कुछ नहीं

(इ) ब को दिया गया ६,००० रु० कमीशन घटाने के बाद सट्टे का नुकसान २०,०००

कुल आय

कुछ नहीं

हिसाब-किताब जाँचने के दौरान मे निम्न तथ्यो का पता चलता है—

(अ) वर्ष का मैनेजिंग एजेंसी कमीशन ६०,००० रु० बैठा, किन्तु कर दाता ने अपनी हिसाब-पद्धति को महाजनी पद्धति से रोकड़ पद्धति में बदल दिया, और ४०,००० रु० का शेषांश, जो १९५६ में प्राप्त किया गया, उस वर्ष (१९५६) की आय माना गया ।

(आ) साक्षीदारो के बैंक के निजी खातो मे विभिन्न रकमे जमा हैं जिनमे से प्रत्येक का कुल योग १५,००० रु० है। पूछने पर यह बताया गया कि ये रकमे घर के जेबरात बेचने से प्राप्त हुई हैं लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं दिया गया ।

फर्म की कुल आय मालूम करिये ।

	रु०	रु०
१ व्याज की आय, पूँजी पर व्याज जोड़ने के बाद		२८,०००
२ मैनेजिंग एजेंसी कमीशन घटाओ—एक तीसरी पार्टी को दी गई रकम	६०,०००	
	२०,०००	४०,०००
३ छिपी आय (जो अनुमानत. सट्टे से है) घटाओ-सट्टे की हानि, ब का ६,००० रु० का (कमीशन अस्वीकृत करने के बाद)	३०,०००	
	१४,०००	१६,०००
कुल आय		८४,०००

यह मान लिया गया है कि धारा १२-ए के अनुसार मैनेजिंग एजेंसी कमीशन के सम्बन्ध का माँगा गया घोषणा-पत्र (declaration) इनकम टैक्स ऑफीसर के यहाँ दाखिल कर दिया गया है ।

इनकम टैक्स ऑफीसर की स्पष्ट आज्ञा के बिना कर-दाता को अपनी हिसाब-पद्धति बदलने का अधिकार नहीं है ।

किन्हीं सतोषजनक प्रमाणो के अभाव में, साक्षीदारो के निजी बैंक खातो मे जमा रकमो को छिपी आय माना जा सकता है ।

(६) १९५९-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए एक अनरजिस्टर्ड फर्म की कुल आय १०,००० रु० निम्नलिखित की गई। इसमें दो समान साझीदार हैं अ और ब। अपने हिस्से की आय के साथ ही हर साझीदार को १,५०,००० रु० की कर-योग्य आय है। फर्म पर कर कैसे लगेगा ?

अनरजिस्टर्ड फर्म की दशा में, धारा २३ (५) (B) के अनुसार एक अनरजिस्टर्ड फर्म को रजिस्टर्ड फर्म माना जा सकता है, यदि ऐसा करने पर पहली स्थिति से अधिक कर बनता है।

इस स्थिति में, यदि अनरजिस्टर्ड फर्म का, धारा २३ (५) (B) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड फर्म की तरह कर-निर्धारण हो, तो क्योंकि हर साझीदार की अन्य कर-योग्य आय १,५०,००० रु० की है अतएव फर्म की कुल आय १०,००० रु० पर १०,००० रु० पर लागू होने वाली दरों से बहुत ऊँची दरों पर कर लगेगा। इसलिए इस अनरजिस्टर्ड फर्म में धारा २३ (५) (B) का लगाना अनिवार्य है।

फर्म के सगठन में परिवर्तन

(Change in Constitution of Firm)

फर्म के सगठन में परिवर्तन या तो किसी साझीदार की मृत्यु हो जाने से अथवा उसमें किसी नये साझीदार के प्रवेश से होता है। “नव निर्मित फर्म” (a firm newly constituted) से अभिप्राय यह है कि वर्तमान फर्म नये सगठन के अन्तर्गत नये संचालक साझीदारों के नेतृत्व में चल रही है। इससे यह मतलब नहीं निकाला जाता कि एक बिल्कुल ही नवीन फर्म की स्थापना हुई है।

यदि किसी फर्म के सगठन में कोई परिवर्तन हुआ है अथवा कोई फर्म पुनर्गठित हुई है तो धारा २६ (१) के अन्तर्गत कर-निर्धारण के समय फर्म जिस रूप में सगठित है उसी रूप में फर्म पर कर-निर्धारण किया जायगा किन्तु फर्म का लाभ, गत वर्ष में फर्म के जो मालिक या साझीदार रहे थे उन्हीं में बाँटा जायगा न कि उन लोगों में जो कर-निर्धारण के समय लाभ में भाग पाने के हकदार हों। इस प्रकार साझीदार के ऊपर कर केवल उसी लाभ पर लगता है जिसको प्राप्त करने का वह गत वर्ष में वास्तविक रूप से हकदार था। यहाँ सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक साझीदार (वर्तमान या भूतपूर्व) गत वर्ष में फर्म के लाभ में आने की हिस्से पर कर देगा।

यदि किसी साझीदार के ऊपर लगाये हुये कर की वसूली उससे न हो सके तो वह फर्म से कर-निर्धारण के समय जिस प्रकार भी वह सगठित हो उसी रूप में वसूल किया जा सकता है।

धारा (२४) (२) ई के अन्तर्गत, यदि फर्म के किसी अवसर प्राप्त (retired) अथवा स्वर्गवासी साझीदार के हिस्से में फर्म के नुकसान के हिस्से की रकम आती है तो फर्म इस घाटे की पूर्ति बाद के किसी वर्ष के अपने लाभ में से नहीं कर सकती, केवल वह

अवसर-प्राप्त अथवा मृत साभेदार हो उस वर्ष ही की अपनी अन्य आय में से इसकी पूर्ति कर सकता है ।

उदाहरण

(१) अ, ब और स जो कि साभेदार हैं, क्रमशः १/२, १/४ और १/४ के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं । स १ अक्टूबर १९५८ से साभेदार नहीं रहा और अन्य साभेदारों ने अपना लाभ-विभाजन अनुपात बदले बिना व्यापार चालू रखा ।

३१ मार्च १९५९ को समाप्त हुये वर्ष के लिये फर्म का शुद्ध लाभ, अ का ₹,६०० रु०, ब का ₹,००० रु० और स का ₹,५०० रु०, वेतन तथा पूँजी पर अ का ₹,४०० रु०, ब का ₹,००० रु० और स का ₹,५०० रु० काटने के पश्चात्, ₹४,००० रु० हुआ ।

यदि फर्म रजिस्टर्ड है तो साभेदारों की कुल आय की गणना करिये । साभेदारों की प्राइवेट आय इस प्रकार है—

अ ₹०,००० रु०, ब ₹०,००० रु० और स ₹५००० रु० ।

फर्म की कुल आय

साभेदारों को विभाजित वर्ष का शुद्ध लाभ—

	रु०	रु०
अ (१/२ का १ + १/४ का १)	१४,०००	
ब (१/४ का १ + १/४ का १)	७,०००	
स (१/४ का १)	<u>३,०००</u>	२४,०००
जोड़ो साभेदारों को दिया गया वेतन • अ	३,६००	
ब	३,०००	
स	१,५००	८,१००
जोड़ो साभेदारों को दिया गया ब्याज • अ	१,४००	
ब	१,०००	
स	<u>५००</u>	२,९००
	<u>कुल आय</u>	<u>३५,०००</u>

साभेदारों में वितरण

	लाभ रु०	वेतन रु०	ब्याज रु०	कुल रु०
अ	१४,०००	३,६००	१,४००	१९,०००
ब	७,०००	३,०००	१,०००	११,०००

स	३,०००	१,५००	५००	५,०००
	<u>२४,०००</u>	<u>८,१००</u>	<u>२,६००</u>	<u>३५,०००</u>

साम्भेदारो की कुल आय

	अ	ब	क
	₹०	₹०	₹०
फर्म से आय का भाग	१६,०००	११,०००	५,०००
प्राइवेट आय	२०,०००	१०,०००	५,०००
	<u>३६,०००</u>	<u>२१,०००</u>	<u>१०,०००</u>

(२) अ, ब और क किसी फर्म में साम्भेदार थे। उनमें हानि-लाभ क्रमशः १/२, १/४ और १/४ के अनुपात में बँटता था। आठ माह के बाद स फर्म से अलग हो गया और क उसके स्थान में आ गया। लाभ-हानि का अनुपात इस प्रकार रखा गया —

अ ६/१६, ब ५/१६ और क ५/१६

३० जून १९५८ को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिये हिसाब की पुस्तकें ४३,००० ₹० का लाभ प्रगट करती हैं।

पुस्तक लाभ निम्न को नाम (Debit) करने के बाद निकाला गया —

(अ) अ को दिये गये ब्याज का ४,००० ₹०, (आ) ब को चुकाया गया वेतन ६,००० ₹०, (इ) स को दिया गया दुकान किराया ३,००० ₹०, (ई) क को दिये गये कमीशन के १,५०० ₹० और (उ) पुण्यार्थ सस्थाओं को दान २,००० ₹०।

फर्म को नई मशीन पर, जिसकी प्रारम्भिक लागत १,००,००० ₹० है और जो गत वर्ष के मध्य में लगवाई गई थी विकास सम्बन्धी छूट तथा ह्रास की कटौती १०% दर से देनी है।

फर्म की कुल आय निकालिये और साम्भेदारों में उसका विभाजन करिये।

	₹०
पुस्तक के अनुसार निकलने वाला लाभ	४३,०००
जोड़ो—अ को दिया गया ब्याज	४,०००
ब को दिया गया वेतन	६,०००
क को दिया गया कमीशन	१,५००
पुण्यार्थ दान	२,०००
	<u>५६,५००</u>

घटाओ—विकास सम्बन्धी छूट व ह्रास	२५,०००	
साधारण ६ माह के लिए	५,०००	३०,०००
	<u>कुल आय</u>	<u>२६,५००</u>

साम्झीदारो मे विभाजन—

	अ	ब	स	क
	रु०	रु०	रु०	रु०
ध्याज	४,०००	—	—	—
वतन	—	६,०००	—	—
कमीशन	—	—	—	१,५००

शेष—

८ माह के लिए (१०,००० रु०)	५,०००	२,५००	२,५००	—
४ माह के लिए (५,००० रु०)	१,८७५	१,५६३	—	१,५६२
	<u>१०,८७५</u>	<u>१०,०६३</u>	<u>२५००</u>	<u>३,०६२</u>

दान जो कर-मुक्त है

८ माह के लिए (१,३३३ रु०)	६६७	३३३	३३३	—
४ माह के लिए (६६७ रु०)	२५०	२०८	—	२०६
	<u>९१७</u>	<u>५४१</u>	<u>३३३</u>	<u>२०६</u>

(३) एक अनरजिस्टर्ड फर्म को, जिसके अ, ब और स बराबर के साम्झीदार हैं ३१ मार्च १९५८ को समाप्त हुये वर्ष में १२,००० रु० की हानि हुई। १ अप्रैल १९५८ को स की मृत्यु हो गई और मूल साम्झीदारी सलेख के अन्तर्गत, अ और ब ने उसके पुत्र द को साम्झीदार बना लिया। तत्पश्चात् अ, ब और द बराबर साम्झीदारो के रूप में व्यापार चलाते रहे।

यदि १९५८-५९ के हिसाबी वर्ष के लिये नई फर्म की आय १५,००० रु० थी, तो आप १९५९-६० के कर निर्धारण वर्ष के लिये अ, ब और द की नई फर्म का किस आय पर कर निर्धारण करेंगे और उक्त कर-निर्धारण वर्ष के लिये अ, ब और द प्रत्येक साम्झीदार के आय-भाग की किस प्रकार गणना करियेगा ?

१९५७-५८ कर-निर्धारण वर्ष के लिये पुरानी फर्म की हानि में स का अनुपातिक भाग जो ४,००० रु० है उसकी १९५८-५९ के कर-निर्धारण वर्ष के लिये नई फर्म के लाभो में से पूर्ति नहीं की जा सकती। केवल फर्म की हानि के शेष ८,००० रु० की इस प्रकार पूर्ति की जा सकेगी तदनुसार अ, ब और द की फर्म की १९५८-५९ के हिसाबी

वर्ष की आय कर-निर्धारण वर्ष १९५६-६० के लिये ७,००० रु० (१५,०००-८,०००) निश्चित की जावेगी ।

अ, ब और द का आय भाग इस प्रकार होगा ।

अ—५,००० रु० - ४,००० रु० = १,००० रु०

ब—५,००० रु० - ४,००० रु० = १,००० रु० और

द—५,००० रु०

फर्म का बन्द या भग होना

(Discontinuance of Dissolution)

धारा ४४ के अन्तर्गत, यदि फर्म या अन्य जन-मंडली द्वारा किये जाने वाला व्यापार बन्द हो जाये या फर्म या जन-मंडली भग हो जाये तब इन्कम टैक्स ऑफीसर यह मान कर कि कोई बन्द या भग नहीं हुआ है फर्म या जन-मंडली की कुल-आय पर कर-निर्धारण करेगा । यदि इस ओर फर्म या अन्य जन-मंडली द्वारा कोई आज्ञा भग (default) की जाती है तो इस पर दण्ड (penalty) लगाई जा सकती है ।

हर वह व्यक्ति, जो कि बन्द या भग होने के समय फर्म का सांभेदार या मण्डली का सदस्य था, कर तथा दण्ड चुकाने के लिये पृथक् तथा संयुक्त (Joint and several) दोनों रूप से उत्तरदायी होगा ।

यदि कभी फर्म के ऊपर सन् १९१८ के आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत कर लग चुका है तो, कारोबार के बन्द होने पर धारा (३) के अनुसार, और फर्म के प्रबन्ध में परिवर्तन होने पर धारा २५ (४) के अनुसार, फर्म को छूट प्राप्त करने का अधिकार है ।

उदाहरण

(१) एक रजिस्टर्ड फर्म में, जिसकी आय ३० जून १९५७ को समाप्त हुए वर्ष के लिये ३६,००० रु० है, अ, ब और स बराबर के सांभेदार हैं । १ जनवरी १९५८ को अ सांभेदारी से रिटायर हो गया और उसकी जगह द सांभेदार बन गया । ३० जून १९५८ को समाप्त हुए वर्ष की फर्म की कुल आय ४८,००० रु० है ।

यह मानते हुए कि सांभेदारों की कोई अन्य आय नहीं है, १९५८-५९ और १९५९-६० के कर-निर्धारण वर्षों के लिए फर्म का और उसके सांभेदारों का कर-निर्धारण किस प्रकार किया जायगा, यह दिखलाइये ।

(क) १९५८-५९ के लिए कर-निर्धारण सांभेदार ब, स और द की फर्म के रूप में (क्योंकि कर निर्धारण के समय फर्म का सांभेदारी संगठन इसी प्रकार है) होगा, किन्तु ३० जून १९५७ को समाप्त हुए गत वर्ष के लिये फर्म की आय निश्चित और निर्धारित हो जाने पर इसे कर-निर्धारण के लिये अ, ब और स से बाँट दिया जायगा (ब, स और द में नहीं), क्योंकि ये ही व्यक्ति तो सांभेदार फर्म की आय के हकदार थे ।

अ, ब और स प्रत्येक पर १२,००० रु० पर कर लगाया जायगा, किन्तु द कोई कर नहीं देगा, क्योंकि ३० जून १९५७ को समाप्त हुए वर्ष की आय में से उसे कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ ।

(ख) यह मानते हुए कि ३० जून १९५८ को समाप्त हुए वर्ष की आय साल भर एक सी होती रही है, ३१ दिसम्बर १९५७ तक के छह महीनों की आय २४,००० रु० हुई । १९५६-६० के कर-निर्धारण के निमित्त ब, स और द में साझीदारी फर्म की कुल आय निम्न प्रकार बाँटी जायगी —

	अ	ब	स	द
३१ दिसम्बर १९५७ तक छ महीनों का लाभ	रु० ८,०००	रु० ८,०००	रु० ८,०००	रु० —
३० जून १९५८ तक छह महीनों का लाभ	—	रु० ८,०००	रु० ८,०००	रु० ८,०००
	<u>८,०००</u>	<u>१६,०००</u>	<u>१६,०००</u>	<u>८,०००</u>

प्रत्येक साझीदार फर्म के लाभ के अपने भाग पर स्वयं कर देगा ।

(२) एक रजिस्टर्ड फर्म के तीन साझीदार हैं । अ, ब और स । हानि-लाभ में इनका क्रमशः २, २ और १ का हिस्सा है । ३० सितम्बर १९५८ को अ फर्म से रिटायर हो गया और इसी तारीख को उसकी जगह द, जो इसी फर्म में ३०० रु० मासिक वेतन पर सहायक के रूप में कार्य करता था, साझीदार बन गया । ब, स और द के हिस्से क्रमशः ४, ३ और ३ थे । इन साझीदारों ने यह भी तय कर लिया कि चालू खाते पर कोई ब्याज नहीं लगाई जायगी ।

३१ मार्च १९५६ को समाप्त हुए वर्ष के लिये फर्म का हानि-लाभ खाता निम्न प्रकार है —

	रु०		रु०
१ अप्रैल १९५८ को स्कन्ध खरीद	२०,०००	बिक्री	१,५०,०००
वेतन	८०,०००	३१ मार्च ५६ को स्कन्ध	१५,०००
किराया	१२,०००	स के चालू खाते पर ब्याज	३२०
सामान्य व्यय	६,०००		
चन्दे . व्यापारिक दान पुण्यार्थ	१,७००		
	६०		
	८०		
चालू खाते पर ब्याज .			
अ	५६०		
ब	४४०		
शेष	४४,४८०		
	<u>१,६५,३२०</u>		<u>१,६५,३२०</u>

साझीदारो की अन्य कर लगने योग्य आय निम्न प्रकार हैं—

- अ—लाभाश (ग्रीस) ५,७६० रु०
 ब—बैंक डिपॉजिट पर ब्याज ५०० रु०
 स—कुछ नहीं
 द—फर्म में कर्मचारी के रूप में वेतन

यदि फर्म कर लगने योग्य लाभ साल के दोनो अर्द्ध भागो में बराबर होता है, तो बताइये १९५६-६० के लिए कर-निर्धारण किस प्रकार होगा ?

हानि लाभ खाते के अनुसार लाभ	रु०	
जोड़ो—मदे जो अस्वीकृत हैं .	४४,४८०	
दान पुण्य के चन्दे	८०	
चालू खाते पर ब्याज	१,०००	१,०८०
		४५,५६०
बटाओ—चालू खाते का ब्याज		३२०
		४५,२४०
फर्म की कुल आय		४५,२४०

साझीदारो के मध्य फर्म की कुल आय का वितरण—

	अ	ब	स	द
	रु०	रु०	रु०	रु०
चालू खाते का ब्याज	५६०	६४०	—३२०	—
पहले छह महीनो का शेषांश (२, २ और १)	८,७७६	८,७७६	४,३८८	—
दूसरे छह महीनो का शेषांश (४, ३, ३)	—	६,०४८	६,७८६	६,७८६
	६,३३६	१८,२६४	१०,८५४	६,७८६

साझीदारो को कुल आय का विवरण

	अ	ब	स	द
	रु०	रु०	रु०	रु०
१ वेतन	—	—	—	१,८००
२ फर्म से लाभ	६,३३६	१८,२६४	१०,८५४	६,७८६
३ लाभांश (ग्रीस)	५,७६०	—	—	—
४ बैंक ब्याज	—	५००	—	—
कुल आय	१२,०९६	१८,७६४	१०,८५४	८,५८६

ब, स और द की फर्म पर ४५,२४० रु० की कुल आय पर कर-निर्धारण किया जायगा, अ, ब, स और द प्रत्येक अपनी-अपनी कर-देय आय पर कर देगे। लेकिन उन्हें फर्म द्वारा चुकाये गये आय-कर से अपने भाग के बराबर आय-कर की छूट (Rebate of income tax) मिलेगी।

यदि अ, ब और स की फर्म पर १९१८ के आय-कर अधिनियम के अनुसार किसी समय कर लग चुका है तो धारा २५ (४) की व्यवस्थानुसार अ को छूट प्राप्त करने का अधिकार होगा।

अन्य जन-मण्डल या सस्थाएँ

(Other Association of Persons)

‘जन-मण्डल’ या सस्था (Association) शब्द का कोई टैक्नीकल अर्थ नहीं है। इससे केवल समुदाय या ग्रुप का ही अर्थ प्रकट होता है। कोई जन-मण्डल (जो एक कम्पनी, फर्म, संयुक्त हिन्दू परिवार या स्थानीय सस्था के रूप में नहीं है) व्यक्तियों, व्यावसायिक फर्मों या कम्पनियों की अथवा अविभाजित हिन्दू परिवारों की सस्था हो सकती है। जन-मण्डल या सस्था में नाबालिग भी शामिल हो सकते हैं।

किसी सम्पत्ति को, जिसे आय कमाने के उद्देश्य से प्रबन्धित किया जायगा, प्राप्त करने के उद्देश्य से दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर बनी कोई सस्था या समिति ‘अन्य जन-मण्डल’ (Other association of persons) के अन्तर्गत आती है। सह-उत्तराधिकारों (Co-heirs या Co-legatees) को भी, जो किसी सामान्य उद्देश्य (Common intention) से मिल कर काम करे, एक जन-मण्डल कहा जा सकता है। अतः यदि किसी मृत मुसलमान के लड़के अपने बाप की सम्पत्ति का मिलकर या संयुक्त रूप से प्रबन्ध करते हैं, संयुक्त रूप में ही किराये की रकमों को वसूल करते हैं और अपने खातों में संयुक्त रूप से ही उन्हें जमा करते हैं, तो उनका इस प्रकार कार्य करना एक जन-मण्डल (Association of persons) का ही काम माना जायगा।

धारा ६ (३) के आदेशानुसार यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप में किसी मकान-जायदाद (House property) के निश्चित और निर्धारित हिस्सों में मालिक हैं, तो ऐसी जायदाद की आय के लिए उन्हें जन-मण्डल नहीं माना जा सकता। यह धारा केवल मकान-जायदाद (House property) की आय के सम्बन्ध में ही लागू होती है, आय के अन्य साधनों के लिए नहीं। साथ ही, यदि मकान-जायदाद पर व्यक्तियों का संयुक्त अधिकार तो है किन्तु इसमें इनके हिस्से निश्चित और निर्धारित नहीं हैं, तो ऐसी दशा में भी यह धारा इन लोगों पर लागू नहीं होगी। इसलिए जब विनियोग अथवा आय के अन्य साधनों पर सम्मिलित रूप से दो या दो से अधिक व्यक्तियों का अधिकार हो अथवा जायदाद के ऊपर भी जब सम्मिलित रूप से अनिर्धारित हिस्सों में अधिकार हो तो जायदाद के सह-स्वामियों (co-owners) पर जन-मण्डल की भाँति आय-कर लगेगा।

जन-मण्डल पर आय-कर और अतिरिक्त-कर ठीक व्यक्ति की भाँति ही लगता है । जन-मण्डल की आय में प्रत्येक सदस्य के हिस्से को इस प्रकार माना जाता है कि मानो वह अनरजिस्टर्ड फर्म के लाभ का हिस्सा हो ।

अनरजिस्टर्ड फर्म की भाँति ही जन मण्डल को भी कमाई हुई आय की छूट दी जाती है ।

(४) कम्पनियाँ (Companies)

आय-कर अधिनियम में दी हुई 'कम्पनी' शब्द की परिभाषा कम्पनियों के अधिनियम की परिभाषा से अधिक विस्तृत है । आय-कर अधिनियम की धारा २ (५ A) के अनुसार कम्पनी से मतलब है,—

(अ) किसी भी भारतीय कम्पनी से, अथवा

(आ) किसी सस्था या जन-मण्डल से है (जो चाहे समामेलित (incorporated) हो या न हो और चाहे भारतीय हो या विदेशी), जिस पर १९४७-४८ के कर-निर्धारण वर्ष में कम्पनी के रूप में कर-निर्धारण हुआ है (या होता) अथवा जिसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ रैवेन्यू ने आय-कर के लिए कम्पनी घोषित कर दिया है ।

'भारतीय कम्पनी' शब्द से अभिप्राय उस कम्पनी से है जिसकी व्याख्या १९५६ के कम्पनियों के अधिनियम में की गई है अथवा जो कम्पनी पूर्व ख भाग के राज्यों (Former Part B States) में या इन राज्यों में विलय हुए (merged) राज्यों में लागू होने वाले कानून के अन्तर्गत बनी है और रजिस्टर्ड हुई है तथा जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस भारत में है ।

कम्पनी का निवास स्थान (Residence of a Company)

धारा ४ A के अनुसार एक कम्पनी भारत में किसी वर्ष के लिये निवासी है (अ) यदि यह भारतीय कम्पनी है, अथवा (ब) यदि उसका प्रबन्ध तथा नियन्त्रण (Control and management) पूर्ण रूप से उस वर्ष में भारत में स्थित है ।

एक कम्पनी यदि निवासी है तो वह भारत में पक्का निवासी होगी ।

कर निर्धारण (Assessment)

दूसरे कर-दाताओं की भाँति एक कम्पनी की कर-निर्धारण कार्यवाहियाँ भी कम्पनी के प्रमुख अधिकारी द्वारा कुल आय का नक्शा दाखिल करने से प्रारम्भ होती हैं । कम्पनी के प्रमुख अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह कम्पनी के निम्तारण में होते हुये भी कुल आय का एक नक्शा दाखिल करे ।

कम्पनी के करारोपण की अनोखी विशेषताये (Special Features)

कम्पनियों के कर-निर्धारण की निम्नलिखित अनोखी विशेषताये हैं—

(१) एक कम्पनी को आय-कर और अतिरिक्त-कर दोनों ही देना पड़ता है,

भले ही उसकी कुल आय कितनी भी हो। उसे आय-कर और अतिरिक्त-कर दोनों ही अपनी सम्पूर्ण कुल आय पर प्रदिष्ट दरों (Prescribed flat rates) से देना पड़ेगा।

(२) कम्पनी, जिस पर कर लगता है, जो लाभार्थ अश्वधारी को चुकाती है उस पर आय-कर (अतिरिक्त-कर नहीं) जिससे लाभार्थ बढ़ा दिया गया है अश्वधारी के लिए चुकाया गया माना जाता है।

(३) १९५७-५८ कर-निर्धारण वर्ष से विनियोग कर्ता अथवा मालिक कम्पनी (investing or principal company) को अपनी भारतीय सबसिडियरी कम्पनी से प्राप्त लाभार्थ के हेतु १०% कॉर्पोरेशन टैक्स देना होगा, जबकि उसे अपनी अन्य कुल आय तथा जैसा कि वह भारत में या बाहर लाभार्थ बाँटती है, के अनुसार अतिरिक्त कर २०% या ३०% चुकावा होगा।

(४) यदि आय-कर अधिकारी यह सोचे कि एक कम्पनी के, जिसमें पब्लिक का कोई विशेष हित नहीं है, संचालकों का अधिकांश अंश रखने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार, लाभ या सुविधाओं के रूप में किया गया व्यय, कम्पनी की उचित व्यापारिक आवश्यकताओं और इनसे प्राप्त हुए लाभ का ध्यान रखते हुए अत्यधिक या अनुचित है तो उसे यह अधिकार है कि ऐसे व्यय को अस्वीकृत कर दे। इनकम टैक्स ऑफीसर का विवेकाधिकार (discretionary power) उक्त व्यक्ति द्वारा प्रयोग की जाने वाली सम्पत्तियों के सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा ह्रास सम्बन्धी छूट की मांग पर भी लागू होता है।

(५) अश्वधारी द्वारा सुपरटैक्स बचाने की रोकथाम के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं —

(अ) 'लाभार्थ' शब्द की परिभाषा इतनी विस्तृत कर दी गई है कि कम्पनी द्वारा अश्वधारियों को किये गये सभी प्रकार के वितरण इसमें शामिल हो गये हैं।

(ब) भारत में कर लगने वाले लाभों से भारत के बाहर दिया गया लाभार्थ भारत में ही उदय मान लिया गया है, और इसलिये, उस पर अतिरिक्त-कर लगेगा भले ही अश्वधारी निवासी है या नहीं।

(स) एक कम्पनी 'लाभार्थ' की परिभाषा के प्रभाव से बचने की यह युक्ति कर सकती है कि वह किसी प्रकार का वितरण न करे, लेकिन इस पर धारा २३ (अ) ने अक्रुश लगा दिया है। यह धारा उन कम्पनियों पर लागू होती है जिनमें पब्लिक का विशेष हित (substantial interest) नहीं है। यदि कोई कम्पनी एक निर्दिष्ट प्रतिशत सीमा तक वितरण नहीं करती, तो ब्रुटि की सीमा पर उसे एक निश्चित दंड सहित अतिरिक्त-कर देना पड़ेगा।

(६) एक कम्पनी द्वारा जारी किये गये बोनस शेयरों पर और दत्त पूँजी के ६% से अधिक लाभांश के वितरण पर विशेष अतिरिक्त-कर लगता है ।

(७) गैर कम्पनी कर-दाताओं की दशा में, यदि पूँजी लाभ की रकम ५,००० रु० से अधिक नहीं है, तो पूँजी लाभों पर आय-कर नहीं लगेगा । किन्तु कम्पनी की दशा में आय कर लगेगा (अतिरिक्त-कर नहीं) चाहे उनकी रकम कितनी भी हो ।

(८) साधारणतः कम्पनी को अपनी कुल आय पर, जिसमें अन्य कम्पनियों से प्राप्त लाभांश शामिल है, आय-कर और अतिरिक्त-कर दोनों ही देना पड़ता है । लेकिन अन्य भारतीय कम्पनियों में अपना आधिक्य विनियोग करने को उत्साहित करने के लिये धारा ५६ (अ) ने किसी भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभांश की अतिरिक्त कर से मुक्त कर दिया है बशर्ते उस धारा की शर्तें पूरी हो गई हों ।

हानियों का निराकरण (Set-off of losses)

यदि कोई कम्पनी दो या अधिक पृथक् व्यापार चलाती है, तो यह एक व्यापार हानि उसी वर्ष में दूसरे व्यापारों के लाभ से पूरा कर सकती है । यह आवश्यक नहीं है कि ये व्यापार एक ही स्थान पर चलाए जायें । जब कम्पनी भारत में निवासी है, तो वह अपने विदेशी व्यापार की हानियाँ अपने भारतीय व्यापार से पूरी कर सकती है । सन्निध के अन्तर्गत विभिन्न व्यापार आय के अलग-अलग श्रोत नहीं माने जाते । सभी व्यापार भले हों वे कहीं भी चलाए जावे, धारा १० के अन्तर्गत कर योग्य लाभ निकालने के लिए एक ही 'मद' माने जाते हैं ।

कर-गणना — कम्पनी द्वारा चुकाए जाने वाले आय-कर और अतिरिक्त-कर निकालने की विधि 'कर-गणना' सम्बन्धी अध्याय में बताई गई है ।

उदाहरण

(१) ३१ दिसम्बर १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एक कोल कम्पनी का हानि-लाभ खाता इस प्रकार है .—

	रु०		रु०
प्रारम्भिक स्कन्ध	४,००,०००	कोयले की बिक्री	२०,००,०००
निकाला गया कोयला	८,००,०००	अन्तिम स्कन्ध	५,००,०००
वेतन एवं मजदूरी	८०,०००		
उत्पादन पर रॉयल्टी	२,००,०००		
साधारण खर्चें	५०,०००		
कानूनी व्यय	१०,०००		
दलाली	११,०००		
अकेक्षक की फीस	१,०००		

रवाना किये गये			
कोयले पर वाटर बोर्ड का कर	५००		
लाभ पर आधारित सडक-कर	३००		
कर्मचारियों की क्षति-पूर्ति			
सम्बन्धी बीमे का प्रीमियम	२००		
शेष जो आ/ले	६,४७,०००		
	<hr/> २५,००,०००		<hr/> २५,००,०००
प्रबन्ध अभिकर्ता का कमीशन	४७,३५०	शेष नी/ला	६,४७,०००
संचालको की फीस	१६,०००	प्रतिभूतियों का	
		ब्याज (ग्रास)	६,५००
विनियोगो की बिक्री पर हानि	१४,३५०	ट्रांसफर फीस	६००
हैदराबाद की खान से हुई हानि	४६,०००		
ह्रास	१,००,०००		
करारोपण कोष (provision)	२,६०,०००		
लाभांश कोष	२,००,०००		
शेष चिट्ठे को	२,३७,७००		
	<hr/> ६,५४,४००		<hr/> ६,५४,४००

निम्न सूचनाओं को ध्यान में रखते हुये १९५६-६० के कर-निर्धारण वर्ष के लिये कम्पनी की कुल आय निकालिये —

(अ) कम्पनी की प्रथा के अनुसार प्रारम्भिक स्कन्ध और अन्तिम स्कन्ध दोनों ही लागत से २०% कम मूल्यांकित किये गये हैं।

(आ) साधारण खर्चों में निम्न मदे शामिल हैं — (क) २५,००० रु० जो बाढ़ से रक्षा के लिए पक्की रोक बनवाने की लागत है और (ख) १,००० रु० जो पत्थर के कोयले (Coke) की किस्म सुधारने के लिये वैज्ञानिक अनुसन्धानों का व्यय है।

(इ) कानूनी व्यय एक ऐसे मुकद्दमे का खर्चा है, जो कुछ खानों के प्रति कम्पनी के स्वत्वाधिकारों की रक्षा के लिये लड़ा गया था।

(ई) वेतन एव मजदूरी में निम्न मदे शामिल हैं (क) एक स्वीकृत सुपरएनुएशन फण्ड में चन्दा १,००० रु० और (ख) उक्त फण्ड से एक रिटायर्ड मैनेजर को दी गई पेंशन के ३,००० रु०।

(उ) दलाली में कम्पनी के अग्रे को बिकवाने के ५,००० रु० हैं।

(ऊ) संचालको की फीस में १८,००० रु० की वह रकम शामिल है, जो एक संचालक को आधुनिक कार्य प्रणालियों (Mining methods) का अमेरिका जाकर अध्ययन करने के लिये दी गई थी।

(ए) डूबे ऋण में से, जिसके लिये १९५६-५७ के कर-निर्धारण वर्ष में छूट दी जा चुकी थी, प्राप्त हुये ४०,००० रु० अंशिक कल्याण कोष में स्थानान्तरित कर दिये गये थे।

(ऐ) सभी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में, जून १९५८ में की गई मशीनरी की वृद्धि को छोड़कर, ह्रास की छूट ७५,००० रु० है। नई वृद्धि के लिये ह्रास की दर १०% है।

	रु०	रु०
लाभ—हानि-लाभ खाते से		२,३७,७००
जोड़ो—अस्वीकृत व्यय		
रोक की लागत, जो पूँजी व्यय है	२५,०००	
सुपरएनुएशन फण्ड से दी गई पेंशन	३,०००	
दलाली, जो पूँजी व्यय है	५,०००	
लाभ पर आधारित सड़क-कर	३००	
विनियोगो की बिक्री पर हानि जो पूँजी व्यय है	१४,३५०	
लगाया गया ह्रास	१,००,०००	
करारोपण कोष (Taxation Provision)	२,६०,०००	
लाभांश कोष	२,००,०००	६,३७,६५०
		८,७५,३५०
घटाओ—स्वीकृत ह्रास		
पुरानी सम्पत्तियों के लिये	७५,०००	
नई मशीनरी के लिए विकास सम्बन्धी छूट	५०,०००	
साधारण ह्रास के नई मशीनरी पर ६ महीनो के लिये	१०,०००	१,३५,०००
		७,४०,३५०
जोड़ो—प्राप्त हो गये डूबे ऋण जिन्हें लाभ-हानि खाते में नहीं दिखाया गया		४०,०००
		७,८०,३५०
घटाओ—प्रतिभूतियों का ब्याज जिस पर अलग विचार किया गया है		२,५००
	कर योग्य लाभ	७,७७,८५०
१ प्रतिभूतियों का ब्याज (ग्राँम)		६,५००
२ व्यापारिक लाभ		७,७३,८५०
	कुल आय	७,८०,३५०

टिप्पणियाँ —(अ) धारा १३ के अनुसार यह आवश्यक है कि स्कन्ध सदा आधार पर मूल्यांकित करें भले ही वह आधार कुछ भी हो।

(आ) कम्पनी के खदान सम्बन्धी अधिकारों की रक्षा करने में जो कानूनी व्यय उठाने पड़े, वे आगम व्यय हैं, क्योंकि उन्हें कम्पनी की पूँजी सम्पत्तियों (Capital assets) के पोषणार्थ (Maintenance) व्यय किया गया है।

(इ) आधुनिक कार्य-प्रणालियों के अध्ययन हेतु इङ्ग्लैंड की यात्रा के लिये संचालक को चुकाया गया १८,००० रु० पूर्णरूपेण व्यापार के काम के लिये किया गया खर्चा है, क्योंकि यात्रा से कम्पनी की निर्माण क्रियायें काफी सुधर जायेगी और लाभ बढ़ जायगा।

(२) एक कम्पनी से सम्बन्धित निम्न सूचनाओं की सहायता से १९५६-६० के कर-निर्धारण वर्ष के लिये उसकी कुल आय मालूम करिये —

३० जून १९५८ को समाप्त हुये वर्ष का लाभ-हानि खाता

	रु०		रु०
चीनी का प्रारम्भिक स्कन्ध	५२,४००	चीनी और चुकन्दर की	
गन्ने की खरीद	४,६६,२००	बिक्री	१०,५८,४००
निर्माण सम्बन्धी व्यय	२,५६,३००	चीनी का अन्तिम स्कन्ध	७६,१००
वेतन एवं मजदूरी	२५,२००		
उपयोग में आया स्टोर्स	४६,६००		
साधारण खर्च	८,५००		
कमीशन एवं दलाली	३६,४००		
ऋण पर ब्याज	६,०००		
संचालकों की फीस	५,५००		
अभिकर्तों की फीस	७००		
बिक्री-कर	४,३००		
हूबे ऋण और सदस्य ऋण कोष	२६,६००		
ह्रास	६४,८००		
शेष आ/लि	१,२६,०००		
	<u>११,३४,५००</u>		<u>११,३४,५००</u>
प्रबन्ध अभिकर्ता का		पिछले वर्ष का शेष	
कमीशन	१२,६००	नी/ला	८,२००
साधारण कोष	७५,०००	शेष नी/ला	१,२६,०००
लाभांश का आयोजन	३०,०००		
अग्रनेयन (carry forward)	१६,६००		
	<u>१,३४,२००</u>		<u>१,३४,२००</u>

(अ) एक ऋण-दाता द्वारा छोड़ी हुई ऋण-राशि १०,००० रु० जो उसके प्रति कमीशन के रूप में कम्पनी द्वारा देय थी, और जिसे कम्पनी ने पिछले वर्ष के आगम खाते (revenue a/c) में नाम डाल दिया था, और स्टेट से लाभ के ३,००,००० रु०

एक विशेष कोष (special reserve) को ले जाये गये है। यह कहा गया है कि सट्टा कम्पनी का नियमित-व्यापार नहीं है।

(आ) वेतन और मजदूरी में एक प्रॉवीडेंट फण्ड का, जो मान्यता प्राप्त नहीं है, कम्पनी द्वारा दिया गया २,००० रु० चन्दा शामिल है।

(इ) साधारण खर्चों में निम्न मदें शामिल है—(क) एक अस्पताल को दान के ५०० रु० जहाँ कम्पनी के कर्मचारियों का मुफ्त इलाज किया जाता है, और (ख) कम्पनी के लिये दीर्घ-कालीन ऋण का प्रबन्ध करने के हेतु एक दलाल को दिया गया कमीशन १,६०० रु०।

(ई) कमीशन और दलाली में प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा चुकाया गया मुफ्त कमीशन १०,००० रु० शामिल है। कम्पनी आय-कर अधिकारियों को हर तरह से सतोष दिलाने के लिये तैयार है किन्तु केवल ऐसा कमीशन पाने वालों के नाम नहीं बतलाना चाहती, क्योंकि ऐसा करने से उसके व्यापार को हानि पहुँचेगी।

(उ) सदिव्य ऋण-कोष की रकम १५,००० रु० है।

(ऊ) ऋण पर ब्याज नैपाल के किसी बैंकर को चुकाये गये है। कम्पनी ने इस पर कोई कर नहीं काटा है, क्योंकि नैपाल में हुए इकरारनाम की शर्तों के अनुसार ऋण-दाता ब्याज की पूरी रकम (कोई कर घटाये बिना) पाने का अधिकारी है।

(ए) ह्रास की स्वीकृत छूट ५५,८०० रु० है।

	रु०	रु०
लाभ—लाभ हानि खाते से		१,२६,०००
जोड़ो—अस्वीकृत खर्चें		
प्रॉवीडेंट फण्ड (जिसे मान्यता प्राप्त नहीं है) का चन्दा	२,०००	
ऋण पर दलाली, जो पूँजी व्यय है	१,६००	
मुक्त कमीशन	१०,०००	
सदिव्य ऋण-कोष (Provision)	१५,०००	
भारत से बाहर दिया गया ब्याज	६,०००	
ह्रास का अधिव्य (Excess)	६,०००	४६,६००
		१,७२,६००
घटाओ—प्रबन्ध अभिकर्ता का कमीशन		१२,६००
		१,६०,०००
जोड़ो—लाभ-हानि खाते में न दिखाई गई मदें—एक ऋणी द्वारा छोड़ा गया धन		१०,०००
सट्टे का लाभ		३०,०००
	कुल आय	२,००,०००

टिप्पणियाँ—(क) ऋण-दाता द्वारा जो १०,००० रु० छोड़े गये हैं उसे आय नहीं माना जा सकता।

(ख) यह मान लिया गया है कि प्रॉवीडेण्ट फण्ड एक अखण्डनीय प्रत्यास (Irrevocable Trust) के रूप में संगठित नहीं हुआ है। अतएव ऐसे फण्ड का चन्दा घटाने योग्य नहीं है।

(ग) जहाँ ब्याज कर लगने वाले क्षेत्र से बाहर चुकाया गया हो और अधिनियम के अन्तर्गत उधार देने वाले के हाथों कर लगने योग्य हो (उदाहरण के लिये, धारा ४२(१) के अन्तर्गत) तो उसे घटाने की स्वीकृति तब ही मिल सकती है जबकि ऐसे ब्याज में से धारा १८ के अन्तर्गत कर काट लिया जावे या कर लगने वाले क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति हो, जिस पर ऐसे ब्याज के सम्बन्ध में धारा ४३ के अन्तर्गत प्रतिनिधि रूप में कर लग सकता हो।

चूँकि ऋण का इकरारनामा नैपाल में किया गया था और ब्याज भी नैपाल में देय (Payable) है, इसलिये ऐसे ब्याज से आय नैपाल में ही उदय होती है, किन्तु धारा ४२ (१) के अन्तर्गत वह भारत में उदय हुई मानी गई है। अतः ऐसे ब्याज पर भारतीय कर लगेगा।

(घ) कम्पनी का यह दावा कि सट्टे का लाभ उसकी आकस्मिक आय है स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह सट्टे का व्यवहार व्यापार के रूप में एक साहसिक प्रयत्न (Adventure in the nature of trade) है।

(३) ३१-मार्च १९५६ को समाप्त हुए वर्ष के लिये, होजियरी के निर्माण में सलग्न एक कम्पनी का हानि-लाभ खाता नीचे दिया गया है—

	रु०		रु०
प्रारम्भिक स्कन्ध	५०,०००	बिक्री	२,८०,०००
उपयोगों में आया सूत (लागत पर)	७४,०००	अन्तिम स्कन्ध	३६,०००
निर्माण सम्बन्धी व्यय	१,१६,०००	ब्याज	२,५००
मरम्मत	१६,०००		
एस्टेब्लिशमेंट	३,५००		
विज्ञापन	४,५००		
यात्रा व्यय	३,०००		
अकेक्षण की फीस	५००		
विविध खर्चें	१,५००		
आय-कर	२,०००		
बिजली का मोटर बेचने पर हुई हानि	१,०००		
साख, जिसे अपलिखित कर दिया गया है	१२,५००		
ब्लॉक सुधार को	१०,०००		
शुद्ध लाभ	२४,०००		
	<hr/>		<hr/>
	३,१८,५००		३,१८,५००
	<hr/>		<hr/>

नीचे दी गई सूचना को विचार में लेते हुए १९५६-६० के कर-निर्धारण वर्ष के लिये कम्पनी की कुल आय निकालिये—

(अ) कम्पनी अपने स्कन्ध का सदैव लागत पर ही मूल्यांकन करती रही है। ३६,००० रु० का अन्तिम स्कन्ध लागत पर ही मूल्यांकित किया गया है। यदि ५०,००० रु० प्रारम्भिक स्कन्ध लागत पर ही मूल्यांकित किया जाता, तो वह ३०,००० रु० बैठता, और सचै तो यह है कि ३१ मार्च १९५८ को बनाये गये चिट्टे (Balance sheet) में प्रारम्भिक स्कन्ध ३०,००० रु० दिखाया गया था, जो कर-निर्धारण के लिये स्वीकार कर लिया गया था।

(आ) मरम्मत में १२,००० रु० की एक वह रकम शामिल है, जो अप्रैल-जुलाई १९५८ में इमारतों में विस्तार (Additions to buildings) करने की लागत है। इस प्रकार बने अतिरिक्त भवनों से कार्यालय और गोदाम का काम लिया जाता है।

(इ) विज्ञान में ३,००० रु० की वह रकम शामिल है जो कारखाने की इमारत के ऊपरी कोने पर एक स्थायी प्रबन्ध करने पर खर्च हुई जिसके द्वारा कारखाने में उपयोग होने वाली विभिन्न निर्माण क्रियाओं (Manufacturing processes) की फिल्म स्लाइडें प्रदर्शित की जा सकें।

(ई) विविध खर्चों में इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल के सम्मुख की गई अपील के सम्बन्ध में नियुक्त किए गये वकील की फीस के १,००० रु० शामिल हैं।

(उ) बिजली का पुराना मोटर, जिसका लागत मूल्य १६,००० रु० और अप-लिखित मूल्य १०,००० रु० था, वर्ष के दौरान में ६,००० रु० में बेचा गया और एक नया मोटर दिसम्बर १९५८ में २०,००० रु० में खरीदा गया।

(ऊ) पहली अप्रैल १९५८ को जो सम्पत्तियाँ विद्यमान थी उनके सम्बन्ध में ह्रास की छूट १६,७४० रु० है।

	रु०	रु०
लाभ—लाभ-हानि खाते से		२४,०००
जोड़ो—अस्वीकृत खर्चें .—		
प्रारम्भिक स्कन्ध की अधिक दिखाई		
गई रकम	२०,०००	
नई इमारत की लागत	१२,०००	
विज्ञापन, जो पूँजी व्यय है	३,०००	
वकील की फीस	१,०००	
आय-कर	२,०००	
अपलिखित साख	१२,५००	
ब्लॉक सुधार कोष	१०,०००	६०,५००
		८४,५००

घटाओ—ह्रास की छूट
पुरानी सम्पत्तियाँ

१६,७४०

नई इमारतें		
साधारण ह्रास ८ महीने के लिये		
२३% की दर से	२००	
नया मोटर .		
विकास सम्बन्धी छूट २५%	५,०००	
साधारण ह्रास ३ महीने के लिये		
१०% से	५००	
नये फिक्चर्स (Fixtures)		
साधारण ह्रास ६% से ६ महीने के लिये ३,००० रु० पर	६०	२५,५३०
लाभ जो कुल आय है		५८,६७०

टिप्पणियाँ — (अ) यह मान लिया गया है कि बिजली के पुराने मोटर का १०,००० रु० अपलिखित मूल्य निकालने के लिये, प्रारम्भिक ह्रास (यदि कोई हो) विचार में ले लिया गया है। इस मोटर की बिक्री पर १,००० रु० की हानि सतुलनीय ह्रास के रूप में स्वीकृत की जा सकती है और इसे १६,४७० रु० शामिल मान लिया गया है।

(आ) इनकम टैक्स की अपील के सम्बन्ध में चुकाये गये कानूनी खर्च और लेख-पाल की फीस व्यापारिक खर्च के रूप में घटाये न जा सकेंगे।

(४) किसी टैक्सटाइल कम्पनी से सम्बन्धित निम्न सूचनाओं से १९५६-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिये उसकी कुल आय निकालिये —

नाम (Dr)	रु०	जमा (Cr)	रु०
प्रारम्भिक स्कन्ध	६,००,०००	कपडा, सूत	
कच्चा माल और स्टोर्स	१५,६०,०००	और क्षेप्य (waste)	
मजदूरी एवं वेतन	६,००,०००	की बिक्री	४० ००,०००
सकल लाभ	२१,४०,०००	बिक्री कमीशन का कोष	२,००,०००
		अन्तिम स्कन्ध	३८,००,०००
			१४,००,०००
	५२,००,०००		५२,००,०००
एस्टेब्लिशमेंट	५०,०००	सकल लाभ	२१,४०,०००
किराये, कर आदि	२३,०००	एक पुरानी मशीन का	
ऋणपत्रों का व्याज	२,५०,०००	बिक्री घन (लागत	
साधारण खर्चें	१२,०००	मूल्य ५,००० रु० और इस	
कानूनी व्यय	१३,०००	पर पिछले वर्षों में ह्रास पूर्ण	
विज्ञापन	१०,०००	रूप से काटा जा चुका है)	१०,०००

छपाई एव स्टेशनरी	२,०००	अपलिखित डूबा ऋण,	
कपडे का स्कन्ध, जो जल गया	३०,०००	जिसके लिये पिछले कर-	
शुद्ध लाभ	१७,८०,०००	निर्धारण मे छूट दे दी	
		गई थी	१०,०००
		आय कर की वापसी	५,०००
		ट्रान्सफर फीस	५,०००
	<hr/> २१,७०,००० <hr/>		<hr/> २१,७०,००० <hr/>
मैनेजिंग एजेंट का कमीशन	१,०७,०००	गत वर्ष का शेष	५०,०००
करारोपण कोष	५,६०,०००	इस वर्ष का लाभ	१७,८०,०००
लाभाश	४,००,०००		
ह्रास (स्वीकृत रकम के बराबर)	४,००,०००		
ऋण-पत्र शोधन कोष मे चन्दा	१,००,०००		
दान	१,००,०००		
शेष बैलेन्स शीट को	१,३३,०००		
	<hr/> १८,३०,००० <hr/>		<hr/> १८,३०,००० <hr/>

(अ) बिक्री कमीशन कोष खाता (Selling Commission Provision A/c) यह बताता है कि (क) वर्ष के दौरान मे वास्तव मे चुकाये गये बिक्री कमीशन की रकम, जो नाम डाली गई (Debited) है, ५०,००० रु० है, और (ख) भूतकाल मे आयोजित किये गये कमीशन के लिये, जो इस वर्ष के दौरान मे किसी एक प्रतिनिधि द्वारा छोड़ दिया गया, १०,००० रु० जमा है।

(आ) ऋण-शोधन कोष के विनियोग के रूप मे कम्पनी ने ५% ब्याज वाले ६,००,००० रु० अंकित मूल्य के अपने ही ऋण-पत्र खरीद लिये। उन पर ब्याज सीधा कोष को जमा किया किन्तु अधिनियम की धारा १८ के अन्तर्गत उसमे से कोई कर नहीं काटा गया।

(इ) विज्ञापन व्यय मे वह व्यय शामिल है जो एक सिनेमा कम्पनी को दिवाली १९६३ को समाप्त होने वाले पाँच वर्षों के लिये स्लाइडें दिखाने के हेतु दिया गया।

(ई) आग से जला हुआ कपड़ा प्रारम्भिक स्कन्ध मे तो शामिल था किन्तु अन्तिम स्कन्ध मे नहीं। लाभ-हानि खाते मे नाम (Debit) की गई मद के साथ को दूसरी द्विप्रविष्टि रिजर्व खाते के जमा (Credit) मे की गई थी।

(उ) कानूनी व्यय मे एक अशुधारी को, जिसने यह धमकी दी थी वह मैनेजिंग एजेंट के विरुद्ध इस बात का दावा करेगा कि उन्होंने कम्पनी के लाभो का एक बड़ा भाग कमीशन के रूप मे हजम कर लिया है, समझौता करने के प्रतिफल स्वरूप दिये गये १०,००० रु० शामिल हैं।

(ऊ) दान की रकम वह है जो एक स्वीकृत सस्था को चन्दा दी गई थी।

अपनी गणना में आप जो समायोजन (adjustments) करें, उनके लिये कारण लिखिये ।

	₹०	₹० १७,८०,०००
शुद्ध लाभ—हानि-लाभ खाते से		
जोड़ो (अ) बिक्री कमीशन का कोष (PROVISION) (वस्तुतः चुकाई गई रकम की छूट ही स्वीकृत की जायगी)		२,००,०००
(आ) कपड़े का स्कन्ध (यह मानते हुए कि उसका बीमा नहीं हुआ है) जो अग्नि से जल गया, क्योंकि इसे सचित कोष के बजाय प्रारम्भिक स्कन्ध को जमा करना चाहिये था ।		३०,०००
(इ) ऋण-मित्र शोधन कोष के विनियोगों के रूप में लिये हुये ऋण-पत्रों का ब्याज, जिसे हानि-लाभ खाते में जमा (credit) नहीं किया गया ।		३०,०००
(ई) आगामी वर्षों के लिये चुकाया गया विज्ञापन व्यय		८,०००
(उ) कानूनी खर्च, जो व्यापार से सम्बन्धित कार्यों के लिये नहीं हैं ।		१०,०००
		<hr/> २०,५८,०००
घटाओ (अ) मशीन की बिक्री पर पूँजी लाभ, जो लागत मूल्य पर बिक्री घन का आधिक्य है	५,०००	
(आ) मैनेजिंग एजेंट का कमीशन, जो १७,८०,००० ₹० का उक्त लाभ निकालने से पहले, काटा नहीं गया था ।	१,०७,०००	
(इ) आय-कर की वापसी, जो अग्रिम नहीं है ।	५,०००	

(ई) ह्रास की छूट	४,००,०००	
(उ) वस्तुतः दिया गया बिक्री कमीशन	५०,०००	५,६७,०००
		<hr/>
		१४,६१,०००
जोड़ो—कमीशन जो एजेंट ने छोड़ दिया परन्तु जिसे हानि-लाभ खाते में जमा नहीं किया		<hr/>
		१०,०००
		<hr/>
व्यापारिक लाभ		१५,०१,०००
पूँजी लाभ		५,०००
		<hr/>
कुल आय		१५,०६,०००

टिप्पणियाँ — एक स्वीकृत सस्था को चन्दे के दिये गये ७५,३०० रु० (जो कुल आय का $\frac{1}{2}$ है) पर उसकी कुल आय पर लगने वाले आय-कर की औसत दर से आय-कर की छूट (rebate) कम्पनी को मिलेगी किन्तु अतिरिक्त-कर की छूट नहीं ।

भूतकाल में आयोजित किये गये (provided for) कमीशन की मद में १०,००० रु० जिन्हे इस वर्ष के दौरान में एक ऋण-दाता द्वारा छोड़ दिया गया, आय नहीं है ।

अबीमित स्कन्ध को आग से हुई हानि, यदि वह हानि-लाभ खाते से काटने योग्य है, तो प्रारम्भिक स्कन्ध या खरीद में से भी काट देनी चाहिये । इस दशा में, चूँकि खरीद कपडे की है इसलिये, हानि की रकम प्रारम्भिक स्कन्ध में से ही काटनी चाहिए ।

(५) एक चीनी मिल कम्पनी का, ३१ अगस्त १९५८ को समाप्त हुये वर्ष के लिये, हानि-लाभ खाता इस प्रकार है —

	रु०		रु०
निर्माण सम्बन्धी व्यय	१३,७०,५६०	चीनी एवं चुकन्दर की आय	२३,२२,६००
उत्पादन-कर	२,१५,०००	कृषि भूमियों से किराया	१,६००
भेदन एवं मजदूरी	२,४०,६६०	स्टाफ क्वार्टर्स से किराया	५,४००
एस्टेब्लिशमेंट चार्जेंज	१,००,३००	मच्छी क्षेत्रों की आय	१,०००
साधारण खर्चें	२७,५००	फैरी की आय	१,०००
संचालकों की फीस	३,५००	गन्ने एवं दूसरी फसलों की बिक्री राशि	१२,१५,३४०
ऋण-पत्रों का ब्याज	५०,०००	ट्रान्सफर फीस	६००
मैनेजिंग एजेंट का पुरस्कार	८२,०००	मोटर ट्रक की बिक्री से लाभ	१,२३०
ह्रास	१,३८,०००		
खेती के व्यय	६,१५,०००		
करारोपण आयोजन	५०,०००		
शुद्ध लाभ	३,५६,१६०		
	<hr/>		<hr/>
	३५,४६,०७०		३५,४६,०७०

१९५६-६० के कर-निर्धारण वर्ष के लिये निम्न सूचना को विचार में लेने के बाद कम्पनी की कुल आय मालूम करिये —

(अ) गन्ने और दूसरी फसलों की बिक्री राशि में, कारखाने के उपयोग में आये गन्ने को उपजाने और निर्माणा व्यय के नाम डाले हुये व्यय के १०,२४,००० रु० शामिल है। ऐसे गन्ने का औसत बाजार मूल्य ११,५०,००० रु० है।

(आ) वर्ष के दौरान में ३,२३० रु० में जो मोटर ट्रक बेची गई थी, उसे भूतकाल में १७,००० रु० में खरीदा गया था, इसके सम्बन्ध में ह्रास के लिये गत कर-निर्धारणों में १५,००० रु० की माँग की गई थी, जिसमें प्रारम्भिक ह्रास शामिल है।

(इ) साधारण व्ययों में निम्न शामिल हैं—(क) १,५०० रु० कानूनी व्यय, जो किन्हीं कृषि-क्षेत्रों के प्रति कम्पनी के स्वत्वाधिकार सम्बन्धी किसी मुकद्दमे को लड़ने में खर्च हुये, और (ख) निर्माण सम्बन्धी नये ढंगों का जापान जाकर अध्ययन करने के लिए एक सचालक को चुकाया गया यात्रा व्यय ६,००० रु०।

(ई) वर्ष के दौरान में कम्पनी ने एक वैज्ञानिक अनुसन्धान-शाला निर्मित चीनी की किस्म सुधारने के लिये स्थापित की और अनुसन्धान शाला की सजा एव उसके पोषण (Maintenance) पर क्रमशः २५,००० रु० और १२,००० रु० व्यय किये। पहली रकम एस्टेब्लिशमेंट चार्जेंज में और दूसरी साधारण खर्चों में नाम डाली हुई (Debited) है।

(उ) अनुसन्धानशाला को छोड़ते हुये शेष सभी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में ह्रास के लिये ७५,००० रु० की छूट स्वीकार कर ली गई है।

(ऊ) डूबते खाते डाली गई रकम (जिसकी छूट पिछले कर-निर्धारण वर्षों में दी जा चुकी है) में से १५,००० रु० वसूल हो गये, जिन्हें श्रमिक कल्याण कोष को स्थानांतरित कर दिया था।

व्यापार से कम्पनी के कर लगने योग्य लाभ दिखाते हुये, कम्पनी का समायोजित (Adjusted) हानि-लाभ खाता निम्न प्रकार है—

	रु०		रु०
निर्माण सम्बन्धी व्यय	१४,६६,५६०	चीनी एव चुकन्दर	
उत्पादन कर	२,१५,०००	की आगम	२३,२२,६००
वेतन एव मजदूरी	२,४०,६६०	वसूल हुई डूबते खाते	
एस्टेब्लिशमेंट चार्जेंज	७५,३००	की रकम	१५,०००
साधारण व्यय	२६,०००	ट्रान्सफर फीस	६००
सचालकों की फीस	३,५००	मोटर ट्रक की बिक्री	
ऋण-पत्रों का ब्याज	५०,०००	से लाभ	१,२३०
प्रबन्ध-अभिकर्त्ताओं का कमीशन	८२,०००		
ह्रास	७५,०००		
अनुसन्धान पर हुये पूँजी व्यय			
का १/५	५,०००		
कर लगने योग्य लाभ	७०,०५०		
	<u>२३,३६,४३०</u>		<u>२३,३६,४३०</u>

	र०	र०
१ जायदाद से आय किराये, जो वार्षिक मूल्य है घटाओ मरम्मत के लिये १/६	५,४०० <u>६००</u>	४,८००
२ व्यापार के लाभ		७०,०५०
३ दूसरे साधनों से—मच्छी क्षेत्रों से आय फैरी की आय	१,००० <u>१,०००</u>	<u>२,०००</u>
कुल आय		<u>७६,८५०</u>

टिप्पणियाँ— (अ) चीनी के प्रारम्भिक एवं अन्तिम स्कन्धों को (Sugar and Molasses Revenue) की मद में समायोजित (adjust) कर लिया गया होगा। कुछ कम्पनियाँ इस ढंग को पसंद करती हैं, क्योंकि वे अपने स्कन्धों को हानि-नाभ खाते में नहीं दिखाना चाहती।

(आ) वैज्ञानिक अनुसन्धान पर १२,००० र० का आगम व्यय स्वीकृत है।

(इ) जापान की यात्रा के लिये एक सचालक को दिये गये ६,००० र० कटने योग्य व्यय है, क्योंकि वह व्यापार के उद्देश्यों के लिये है।

(ई) यह मान लिया गया है कि कम्पनी के कर्मचारियों के क्वाटर्स पर कोई स्थानीय कर नहीं लगता, इसलिये जायदाद का वार्षिक मूल्य निकालने के लिये प्राप्त किराये की रकम से स्थानीय करों के लिये कोई कटौती नहीं की गई है।

(उ) कम्पनी के किन्हीं कृषि-भूमियों पर स्वत्वाधिकार (Title) की रक्षा के लिये किये गये कानूनी व्यय १,५०० र० आगम व्यय है, किन्तु व्यापार से कर लगने योग्य लाभ निकालने के लिये उनकी कटौती स्वीकार न होगी, क्योंकि वे कर अयोग्य कृषि-आय के सम्बन्ध में किये गये थे।

(५) परदेशी (Non-residents)

परदेशी पर सभी आय के लिये (अ) जो भारत में प्राप्त हो या प्राप्त हुई मानी जाये, भले ही वह कहीं भी उदय हो, और (ब) जो भारत में उदय हुई हो या उदय हुई मानी जाये भले ही वह कहीं भी प्राप्त हो, कर लगाया जाता (Chargeable) है।

परदेशियों को अपनी विदेशी आय पर कर नहीं देना पड़ता भले ही वह भारत में लाई या भेजी जाये। किसी परदेशी की विदेशी आय तब ही कर योग्य होती है जबकि वह भारत में प्राप्त की जाये। किन्तु यदि वह भारत में लाई गई है तो कर योग्य न होगी। 'प्राप्त करने' और 'लाई जाने में' अन्तर है। 'प्राप्त करने' का अर्थ 'प्रथम प्राप्ति' से है। जो आय एक बार प्राप्त हो गई है वही फिर प्राप्त नहीं की जा सकती। अतः जब आय भारत के

बाहर प्राप्त (received) हो चुकी है तो उसे भारत भेजना 'लाया जाना' (bringing in) होगा।

वह धारा, जिसके अन्तर्गत आय भारत में उदय या अर्जित (accrue or arise) हुई मानी जाती है और जिसका परदेशियो से अधिक सम्बन्ध है ४२ वी धारा है। धारा ४२ (१) का बड़ा व्यापक प्रभाव है। इसकी शब्द रचना इस प्रकार रखी गई है कि जहाँ तक सम्भव हो वहाँ तक भारत में व्यापार करने से परदेशी को हुआ सभी लाभ कर-क्षेत्र में आ जाये। इस प्रकार आय के निम्न चार वर्ग रखे गये हैं—

(१) भारत में किसी व्यापारिक सम्बन्ध में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्ष रूप से उदय होने वाली आय,

(२) भारत में किसी जायदाद (Property) से उदय होने वाली आय,

(३) भारत में किसी सम्पत्ति (asset) या आय के श्रोत से आय, और

(४) वह आय जो ब्याज पर उधार दिये गये धन से उदय हो भारत में नगद या वस्तु रूप में (in cash or in kind) में लाई जाय।

यह सम्भव है कि आय की उक्त मदों के सम्बन्ध में अनुबन्ध भारत के बाहर किया जाये और उसकी शर्तों के अनुसार द्रव्य भारत के बाहर देय (Payable) रखा जाये। ऐसी दशाओं में, आय भारत के बाहर उदय या अर्जित होती है, किन्तु धारा ४२ (१) के अन्तर्गत ऐसी आय भारत में उदय अथवा अर्जित मानी जायगी।

परदेशी फर्मों के भारतीय प्रतिनिधि जो कि टैक्नीकल दृष्टि से न तो उनकी शाखाएँ हैं, और न सहायक फर्म, अपने स्वामियों की ओर से उस कर को चुकाने के लिये दायी होंगे जो कि उनके स्वामियों पर भारतीय लाभों के सम्बन्ध में निर्धारित किया जाये। किसी परदेशी का कर-निर्धारण या तो स्वयं उसके नाम से या उसके प्रतिनिधि के नाम से किया जा सकता है और अन्तिम दशा में ऐसे कर के सम्बन्ध में ऐसा प्रतिनिधि ही कर-दाता मान लिया जायेगा।

कर-गणना

धारा १७ (१) में वह आधार बतलाया गया है जिसके अनुसार परदेशियों की कुल आय पर कर की गणना की जानी चाहिये।

एक परदेशी द्वारा दिये जाने वाले आय-कर और सुपर टैक्स की गणना विधि कर-गणना सम्बन्धी अध्याय में समझाई गई है।

आय-कर अधिनियम आय-कर और अतिरिक्त-कर दोनों से ही सम्बन्धित है। उसमें कर-निर्धारण के आधार, विधि और व्यवस्था (machinery) का वर्णन किया गया है। इसके अन्दर दरो की तालिका (Schedule of Rates), जिनके हिसाब से कि कर लगाया जायगा, नहीं दी जाती। करो की दरे पार्लियामेंट द्वारा मार्च में प्रति वर्ष पास किये जाने वाले फाइनेन्स ऐक्ट (Annual Finance Act) द्वारा निश्चित और निर्धारित की जाती है।

आय-कर अधिनियम कोड के रूप में एक स्थायी विधान (enactment) है। इसके आदेशों को सम्बन्धित वर्ष के फाइनेन्स ऐक्ट द्वारा निर्धारित दरो के अनुसार, यदि वह वर्ष के प्रारम्भ के पूर्व ही पास कर दिया जाय, कार्यान्वित किया जाता है। किन्तु यदि किसी कारण से फाइनेन्स ऐक्ट के पास होने में देरी होती हो तो, धारा ६७ बी के अन्तर्गत पिछले वर्ष फाइनेन्स ऐक्ट द्वारा निर्धारित दरो के अनुसार अथवा पार्लियामेंट के सम्मुख प्रस्तुत उस वर्ष के फाइनेन्स बिल में प्रस्तावित दरो के अनुसार, दोनों में जो भी कर-दाताओं के हित में हो कर लगाया जायगा।

कर लगने वाली आय पर आय-कर की गणना (Computing) दो पद्धतियों से की जा सकती है—आय अनुसार (Step System) और विभागानुसार (Slab System)। आय अनुसार पद्धति में कुल आय की पूरी रकम पर एक ही दर के अनुसार जो कुल आय पर लागू होती हो, आय-कर चुकाना पड़ता है और कुल आय की विभिन्न रकमों के लिए आय-कर की भिन्न-भिन्न दरे निर्धारित हैं। यदि आय ऊँची है, तो इसके लिए दर भी ऊँची है। यह पद्धति १ अप्रैल १९३६ को समाप्त कर दी गयी, किन्तु इस तिथि से पूर्व इसी पद्धति के अनुसार कर लगाया जाता था। इस पद्धति के अनुसार उन कर-दाताओं के साथ, जिनकी कुल आय उस सीमा से, जहाँ पर दरें बदलती है, कुछ ही अधिक बैठती थी, कठोरता और अन्याय होता था। इस कठोरता को दूर करने के लिए कुछ सीमान्त छूट (Marginal relief) दी जाती है।

आय के अनुसार कर-निर्धारण से जो कठोरता, अन्याय और असमान फल होते हैं, उन्हें समाप्त करने के लिये १९३६ के फाइनेन्स ऐक्ट ने करारोपण की एक नई और न्यायोचित पद्धति, जिसे विभागानुसार करारोपण कहते हैं, प्रचलित की। इसके अनुसार आय को विभागों में बाँटा जाता है। पहले विभाग पर कोई कर नहीं लगता। इसके बाद प्रत्येक अगले विभाग (Successive slab) के लिये बढ़ती हुई दर से आय-कर लगाया जाता है।

आय-कर की दरें

१९५६ के फाइनेन्स ऐक्ट द्वारा १९५६-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए निम्न-लिखित दरें निर्धारित की गई हैं। ये दरें वही हैं जो कर-निर्धारण वर्ष १९५८-५९ के लिए लागू थी।

(१) प्रत्येक व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार तथा अनरजिस्टर्ड फर्म के लिए —

कुल आय के भाग पर

	(अ) रु०	(ब) रु०	(स) रु०	दर
(१) प्रथम	३,०००	३,३००	३,६००	कुछ नहीं
(२) अगले	२,०००	१,७००	१,४००	३%
(३) अगले	२,५००	२,५००	२,५००	६%
(४) अगले	२,५००	२,५००	२,५००	६%
(५) अगले	२,५००	२,५००	२,५००	११%
(६) अगले	२,५००	२,५००	२,५००	१४%
(७) अगले	५,०००	५,०००	५,०००	१८%
(८) शेष पर				२५%

कालम (अ) जब कि व्यक्ति का कोई बच्चा उस पर निर्भर न हो अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार में नाबालिग साझी न हो।

(ब) जब कि व्यक्ति का एक बच्चा उस पर निर्भर हो अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार में एक नाबालिग साझी हो।

(स) जब कि व्यक्ति का एक से अधिक बच्चे उस पर निर्भर हो अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार में एक के अधिक नाबालिग साझी हो।

प्रत्येक अविवाहित व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार जिस कुल आय २०,००० रु० से अधिक है, तथा अनरजिस्टर्ड फर्म या अन्य जन-मण्डल के लिए :-

(१) कुल आय के प्रथम १,००० रु० पर	दर कुछ नहीं
(२) कुल आय के अगले ४,००० रु० पर	३%
(३) कुल आय के अगले २,५०० रु० पर	६%
(४) कुल आय के अगले २,५०० रु० पर	६%
(५) कुल आय के अगले २,५०० रु० पर	११%
(६) कुल आय के अगले २,५०० रु० पर	१४%
(७) कुल आय के अगले ५,००० रु० पर	१८%
(८) कुल आय के शेष पर	२५%

‘विवाहित व्यक्ति’ वाक्यांश में विधवायें और विधुर भी शामिल हैं। कोई व्यक्ति विवाहित है या नहीं इसका निर्णय गत वर्ष के अन्तिम दिन की स्थिति के आधार पर लगाना चाहिए।

उपयुक्त दरों के अनुसार १,००० रु० की वैयक्तिक छूट, २,००० रु० की विवाह की छूट तथा ३०० प्रति बच्चा दो बच्चों के लिए बच्चों की छूट है। विवाह तथा बच्चों की छूट केवल उन व्यक्तियों के लिए, जिनको कुल आय २०,००० रु० से बढ़ती नहीं है।

कर-मुक्ति की सीमा (Exemption Limit)—यदि कुल आय निम्न निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक नहीं है तो कुल आय पर कोई आय-कर नहीं दिया जायेगा। साथ ही सीमावर्ती छूट का भी निम्न आयोजन है—

(अ) आय कर उस राशि के जो कि कुल आय कर मुक्ति की सीमा से बढ़ रही है के आधे से अधिक नहीं होगा। इस अध्याय में उदाहरण (२) देखिये।

(ब) विवाहित व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार, जिसकी कुल आय २०,००० रु० से अधिक है, द्वारा चुकाया जाने वाला आय कर (१) २०,००० रु० पर चुकाये जाने वाले आय-कर तथा (२) उस राशि के जो कि कुल आय २०,००० रु० से बढ़ती है के आधे से जोड़ से नहीं बढ़ेगा। इस अध्याय में उदाहरण (४) देखिए।

ऊपर वर्णित कर-मुक्ति की सीमा निम्न है—

(अ) ६,००० रु० उस स्थिति में जब कि हिन्दू अविभाजित परिवार में कम से कम दो वयस्क साझे (adult coparceners) हैं, तथा

(ब) ३,००० रु० अन्य किसी दशा में।

आय-कर पर सरचार्ज—आय कर पर सरचार्ज दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

(अ) सामान्य सरचार्ज यूनियन के हेतु जो कुल आय पर लगे आय-कर का ५% है तथा अतिरिक्त सरचार्ज १,००,००० रु० से अधिक कमाई हुई आय (earned income) पर लगे आय-कर का ५% तथा,

(ब) न कमाई हुई आय (unearned income) पर लगे आय-कर पर विशेष सरचार्ज १५% जिसको कि राज्यों (states) में बँट जाना है।

विशेष सरचाज की गणना के लिए न कमाई हुई आय को उस भाग में, जहाँ कि कमाई हुई आय समाप्त होती है, माना जाता है या ऊँचे विभाग में यदि आवश्यकता हो तो। इस अध्याय में उदाहरण (५) देखिए।

यदि व्यक्ति की कुल आय ७,५०० रु० से तथा हिन्दू अविभाजित परिवार की कुल आय १५,००० से न बड़े तो कोई सरचार्ज नहीं लिया जाता है। इन सीमाओं के ऊपर १,५०० रु० तक इक्विटी अशो (equity shares) पर लाभांश पर भी सरचार्ज की छूट है।

सरचार्ज के लिए भी सीमावर्ती छूट का आयोजन है। सरचार्ज के हेतु, जैसा कि ऊपर कहा गया है, कर-मुक्ति सीमा और कुल आय के अन्तर से सामान्य सरचार्ज या विशेष सरचार्ज या दोनों एक साथ लेकर आधे से नहीं बढ़ना चाहिये। सामान्य सरचार्ज ५% तथा विशेष सरचार्ज १५% निकालने के लिए उन दोनों के लिए सीमावर्ती छूट अलग-अलग लेनी चाहिये। इन दोनों सरचाज का योग, हर एक पर सीमावर्ती छूट लगाने के बाद, ७,५०० रु० से कुल आय का जो आधिक्य है उसके आधे तक सीमित कर दिया है। इस अध्याय में उदाहरण (६) और (७) देखिये।

(२) कम्पनियों तथा स्थानीय सत्ताओं के लिए

उसकी कुल आय पर आय-कर की दर ३०% है (साथ में सरचार्ज ५% है। भले ही कुल आय की रकम कुछ भी हो।

(३) रजिस्टर्ड फर्मों के लिए

	दर
(१) कुल आय के प्रथम ४०,००० रु० पर	कुछ नहीं
(२) कुल आय के अगले ३५,००० रु० पर	५%
(३) कुल आय के अगले ७५,००० रु० पर	६%
(४) कुल आय के शेष पर	६%

(४) उच्चतम दर (Maximum Rate)

परदेशी की दशा में जिन्होंने अपनी कुल विश्व आय पर दर जो लगनी है उस पर कर-निर्धारण की घोषणा नहीं की हो तथा ट्रस्टी, मैनेजर अथवा रिसीवर्स (Receivers) जहाँ कि आय स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति के पक्ष में प्राप्त नहीं की जाय

अथवा जहाँ कि वैयक्तिक भाग बाँटने वालों का (beneficiaries) ज्ञात नहीं हो तो ऐसी दशा में आय-कर उच्चतम दरों से चार्ज किया जाता है। ऐसी दशाओं में आय-कर की उच्चतम दर २५% (उस पर सरचार्ज २०% सहित) कुल आय पर लगेगी।

(५) परदेशी (Non residents)—एक परदेशी व्यक्ति को (एक कम्पनी को छोड़कर) आय कर और सुपरटैक्स निम्नलिखित ढंग से देना पड़ेगा.—

(अ) कुल आय पर (भले ही इसकी रकम कुछ भी हो) आय-कर अधिकतम दर से, और

(ब) कुल आय पर (भले ही इसकी रकम कितनी भी हो) सुपर-टैक्स १६% से (बिना सरचार्ज) या उतना सुपर टैक्स जो वह अपने निवासी होने की दशा में कुल आय पर चुकाता, दोनों में जो भी अधिक हो। कर-निर्धारण वर्ष १९५६-६० के लिए यह दर १६% की कुल आय ६१,७६० रु० तक ही लागू होगी।

हाँ, एक परदेशी को सदैव के लिये केवल एक ही बार यह निर्णय करने का विकल्प दिया जाता है कि वह उक्त आधार पर कर देगा या अपनी कुल विश्व आय को लागू होने वाली दरों से कुल आय पर आय-कर और सुपर टैक्स चुकावेगा। इस विकल्प का प्रयोग करने के लिये उस कर-निर्धारण वर्ष की, जबकि परदेशी पहले-पहल कर-निर्धारण का उत्तरदायी बना था, ३० जून के पूर्व ही इनकम टैक्स ऑफिसर को लिखित घोषणा पत्र दे देना चाहिये। जो भी आधार एक बार चुन लिया जायेगा वही बाद के सब वर्षों को भी लागू होगा।

आय जिस पर उद्गम स्थान पर कटौती होगी—वेतन, प्रतिभूतियों पर ब्याज तथा भारतीय आय-कर देने वाली कम्पनियों के लाभांश की दशा में उद्गम स्थान पर आय-कर काटने या एकत्र करने की व्यवस्था है। इसलिए १९५६-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए कर-निर्धारण करने के लिए ऐसी आय पर, जो कि एक कर दाता (कम्पनी को छोड़ कर) की कुल आय में शामिल है, १९५५-५६ कर-निर्धारण वर्ष की लागू होने वाली दरें लगेगी। जबकि कुल आय के शेष पर १९५६-६० कर-निर्धारण वर्ष का दरें लागू होगी।

क्योंकि १९५५-५६ तथा १९५६-६० की दरें एक ही हैं यह नियम १९५६-६० कर-निर्धारण वर्ष में लागू नहीं हो रहा है।

कर मुक्त आय—जब किसी करदाता की कुल आय में कोई ऐसी आय शामिल है जोकि आय-कर और या सुपर टैक्स से मुक्त है, तो गायकर और सुपर टैक्स पहले तो कुल आय पर निकाला जावेगा और फिर आय-कर व सुपर टैक्स की ओसत दरों से आय कर और/या सुपर टैक्स की छूट (rebate) काट दी जावेगी।

पूँजी लाभ—एक कम्पनी को अपनी कुल आय को लागू होने वाली दर से पूँजी लाभ पर आय-कर चुकाना पड़ता है, लेकिन पूँजी लाभो पर सुपर टैक्स नहीं देना पड़ता। पूँजी लाभो पर और अन्य आय पर दिया जाने वाला आय कर इस प्रकार निकाला जाता है।

(अ) पूँजी लाभ पर दिये जाने वाले आय कर की दर करदाता की अन्य आय से सम्बन्धित है। पूँजी लाभ का $\frac{1}{3}$ अन्य आय में जोड़ दिया जाये और इस प्रकार निकले योग की रकम को लागू होने वाली आय-कर की दर ही वह दर है जिसके आधार पर सम्पूर्ण पूँजी लाभ पर आय-कर लगेगा। लेकिन किसी भी दशा में पूँजी लाभ पर आय-कर ५,००० रु० पर पूँजी लाभ के आधिक्य की आधी रकम से अधिक न हो सकेगा। यही सीमावर्ती छूट है।

यही नहीं, पूँजी लाभ पर कोई आय-कर नहीं लगता यदि (अ) पूँजी लाभ ५,००० रु० से अधिक नहीं है, या (ब) कुल आय (जिसमें पूँजी लाभ शामिल है) १०,००० रु० से अधिक नहीं है।

(ब) अन्य आय पर दिये जाने वाले आय-कर और सुपर-टैक्स की गणना पूँजी लाभ घटा कर निकली कुल आय पर की जावेगी।

अतिरिक्त कर (Super Tax)

धारा ५५ के अनुसार, अतिरिक्त कर (Super tax) आय-कर का ही एक अतिरिक्त (Additional) प्रभार (Duty) है जो गत वर्ष की कुल आय के सम्बन्ध में लगाया और चुकाया जाता है। यह कर व्यक्ति विशेष, संयुक्त हिन्दू परिवार, कम्पनी, स्थानीय सत्ता, अनरजिस्टर्ड फर्म तथा अन्य जन-मण्डलों से वसूल किया जाता है।

एक रजिस्टर्ड फर्म पर अतिरिक्त-कर नहीं लगाया जाता, लेकिन फर्म के साझेदारों पर उनकी अन्य आय के साथ में साझेदारी के मुनाफो पर, अतिरिक्त कर लगाया जाता है। एक अनरजिस्टर्ड फर्म, के जिसे धारा २३ (५) वी के अनुसार रजिस्टर्ड फर्म के रूप में माना जाता है, अतिरिक्त-कर के उद्देश्य से भी रजिस्टर्ड फर्म ही माना जाता है।

सामान्यत एक कम्पनी को अपनी सम्पूर्ण आय पर, जिसमें अन्य कम्पनियों से प्राप्त लाभांश भी सम्मिलित हैं आय-कर और सुपर टैक्स दोनों ही चुकाना होता है। लेकिन कम्पनियों को इस बात का प्रोत्साहन देने के लिए कि वे अपने आधिक्य को भारत में कुछ मुख्य (Basic) उद्योगों में लगाएँ, धारा ५६ A ऐसी कम्पनियों को (चाहे भारतीय हो या विदेशी हो) भारतीय कम्पनी से जो कि ३१ जनवरी १९५२ को प्रारम्भ हुई है, प्राप्त लाभांश पर सुपर-टैक्स की छूट का आयोजन करती है, बशर्ते कि

ऐसी लाभांश देने वाली भारतीय कम्पनी सम्पूर्णतया या मुख्यतः निश्चित प्रदिष्ट उद्योगों (certain specified industries) में कार्यरत है ।

२८ फरवरी १९५३ के बाद विद्यमान कम्पनियों द्वारा उत्पादन बढ़ाने या निर्दिष्ट मदों के उत्पादन में प्रलग इकाइयों प्रारम्भ करने के लिए जनता से चन्दा लेकर संग्रह की गई नई पूँजी के सम्बन्ध में दिये गये लाभांशों के लिए भी यह नियम लागू होता है ।

सामान्य नियम के रूप में जो कुल आय आय-कर के लिये निर्धारित की जावे उस पर ही अतिरिक्त कर लगाया जाता है । लेकिन निम्न दशाओं में अतिरिक्त कर की कुल आय आय-कर की कुल आय से भिन्न होती है —

(१) जब कोई अनरजिस्टर्ड फर्म या अन्य जन-मण्डल (कम्पनी नहीं) स्वयं ही अतिरिक्त-कर के लिये दायी हो, तो ऐसी फर्म या जन-मण्डल में सदस्य के लाभ का हिस्सा अतिरिक्त कर ही कुल आय में शामिल नहीं किया जाता ।

(२) किसी व्यापार के बन्द होने या प्रबन्ध बदले जाने की दशा में, जो कि १९१८ के कानून के अन्तर्गत कर-योग्य हुआ है, व्यापार बन्द होने या प्रबन्ध बदले जाने वाले वर्ष के लाभ आय-कर से कर-मुक्त हो सकते हैं लेकिन, जैसा कि एक पूर्व गध्याय में समझाया गया है, उन पर सुपर टैक्स देना होगा ।

(३) जब कुल आय में कुछ पूँजी लाभ शामिल हो, तो सुपरटैक्स कुल आय—पूँजी लाभ पर लगाया जायगा क्योंकि पूँजी लाभों पर सुपरटैक्स नहीं लगता ।

पुण्यार्थ दान (Charitable Donations)

सभी कर-दाताओं (कम्पनी की छोड़कर) द्वारा किसी स्वीकृत संस्था या काय में दिया गया दान आय-कर और अतिरिक्त-कर दोनों से मुक्त है । कम्पनियों द्वारा दान में दी गई रकम आय-कर से मुक्त है अतिरिक्त-कर से नहीं । लेकिन दान में दी गई ये रकमें कुल आय में अवश्य शामिल की जाती है, हाँ, औसत दर से आय-कर और अतिरिक्त कर की छूट (Rebate) काट दी जाती है ।

अतिरिक्त कर की दरें

१९५६-६० के कर निर्धारण वर्ष के लिए १९५६ के फाइनेन्स एक्ट द्वारा अतिरिक्त कर की निम्नलिखित दरें निर्धारित की गई हैं ।

(१) प्रत्येक व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार तथा अनरजिस्टर्ड फर्म की दशा में —

कुल आय के विभाग (slabs)	दर
१ प्रथम २०,००० रु० पर	कुछ नहीं
२ अगले ५,००० रु० ,,	५%
३ अगले ५,००० रु० ,,	१५%
४ अगले १०,००० रु० ,,	२०%
५ अगले १०,००० रु० ,,	३०%
६ अगले १०,००० रु० ,,	३५%
७ अगले १०,००० रु० ,,	४०%
८ शेषांश पर	४५%

.सुपर टैक्स पर सरचार्ज—सुपर टैक्स पर सरचार्ज (आय-कर पर सरचार्ज की तरह) निम्न है —

(अ) कुल आय के सुपर टैक्स पर सामान्य सरचाज ५% और १,००,००० रु० से अधिक कमाई हुई आय के सुपरटैक्स पर अतिरिक्त सरचार्ज ५%, तथा

(ब) न कमाई हुई आय के सुपर टैक्स पर विशेष सरचार्ज १५% जब एक करदाता की कुल आय में दोनों कमाई हुई तथा न कमाई हुई आय शामिल हो तो न कमाई हुई आय जिस विभाग में कमाई हुई आय समाप्त होती है उससे सम्बन्धित या आवश्यकता पड़ने पर ऊँचे विभाग में मानी जाती है।

(२) स्थानीय सत्ताओं के लिए

सुपर टैक्स की दर सम्पूर्ण कुल आय पर १६% है। साथ में इस सुपर टैक्स पर १२½% सरचाज भी लगेगा।

(३) सहकारी समितियों के लिए

सुपर टैक्स की दरें इस प्रकार हैं कुल आय के प्रथम २५,००० रु० पर कुछ नहीं, कुल आय के शेष पर १६%। ऐसे सुपर टैक्स पर १२½% का सरचाज भी है।

(४) कम्पनियों के लिए

कम्पनियों पर लगाये गये सुपर टैक्स को 'कॉरपोरेशन टैक्स' कहते हैं। प्रत्येक कम्पनी (चाहे भारतीय हो या विदेशी हो) के लिए सुपर टैक्स की बेसिक दर ५% बिना किसी सरचार्ज के है। यह दर कुछ परिस्थितियों में बदली हुई प्रतिशत पर निश्चित छूट से घटा दी गई है।

वेतन (Salaries)—जब कि एक कर-दाता (कम्पनी नहीं) की कुल आय में वेतन जिस पर सुपर टैक्स काट लिया गया है (उदाहरणार्थ, जब कि वेतन की आय २०,००० रु० से बढ़ती है) तब १९५६-६० कर-निर्धारण वर्ष का कर-निर्धारण करते

हुए कर-दाता को ऐसे वेतन पर सुपर टैक्स १९५८-१९५९ की दरों से देना होगा तथा उसे कुल आय के शेष पर १९५९-६० की दरों से सुपर टैक्स देना होगा ।

कर-निर्धारण की गणना

(Computation of Assessment)

कर-दाता का कर-निर्धारण (Assessment) तैयार करने के लिए क्रमशः निम्न कदम उठाने आवश्यक हैं —

(१) पहले बता दी गई विधि के अनुसार कुल आय मालूम करिये । उद्गम स्थान पर कर की जो रकमे काटी गयी हैं या अदा हो चुकी हैं, उन्हें जोड़ लीजिये । कर-दाता के परदेशी (Non-resident) होने की दशा में, यह जरूरत हो तो उसकी कुल विश्व आय भी निकालिये ।

(२) कुल आय पर आय-कर तथा सरचार्ज की रकम निकालिये और आय-कर की औसत दर मालूम कीजिये । सुपर टैक्स तथा उस पर सरचाज की रकम मालूम कीजिये और यदि आवश्यक हो, तो सुपर टैक्स की औसत दर भी निकालिये । सुपर टैक्स की औसत दर तब निकालना आवश्यक होगा जबकि कर-दाता की कुल आय में पुण्यार्थ दान की रकम शामिल हो ।

(३) कुल आय में शामिल आय की वह रकम निश्चित करिये, जो आय कर और । या अतिरिक्त-कर से मुक्त है तथा उस पर छूट की रकम निकालिये ।

(४) उपर्युक्त विधि से निकाली हुई आय-कर और अतिरिक्त कर को ग्राँस रकम (Gross amount) में से निम्नलिखित रकमे (Amount) घटाइए —

(अ) कर-मुक्त आय पर छूट (Rebate) की रकम ।

(ब) कर की वह रकम जो उद्गम स्थान पर दी जा चुकी है ।

(स) धारा १८ ए के अनुसार कर की पेशगी दी हुई रकम और उस पर ब्याज ।

(द) विदेशी आय पर दुहरे कर सम्बन्धी छूट (Double taxation relief) की रकम यदि कोई हो ।

इस प्रकार, उपर्युक्त रकमे घटाकर जो रकम शेष बचे, वह अदा किये जाने वाले या वापस (Refund) किए जाने वाले कर की नेट रकम होगी । यदि कर-दाता पर दण्ड (Penalty) की कोई रकम है तो उसे भी इसमें जोड़ दीजिये । इस प्रकार जो रकम आये वह अदा किये जाने वाले या वापस किये जाने वाले कर की कुल रकम होगी ।

उदाहरण

(१) निम्न दशाओं में १९५९-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए देय कर की राशि निकालिये .—

(अ) अविवाहित व्यक्ति । जायदाद की आय ४,५०० रु० ।

(आ) विवाहित व्यक्ति जिसके दो बच्चे हैं । जायदाद की आय ४,५०० रु० ।

(इ) एक विधवा जिसके एक बच्चा है । व्यापार लाभ ४,८०० रु० तथा जायदाद की आय ३,६०० रु० ।

(ई) हिन्दू अविभाजित परिवार जिसमें तीन नाबालिग साझे (minor coparceners) हैं । व्यापार लाभ १,२०,००० रु० तथा जायदाद की आय १२,००० रु० । जीवन बीमा प्रीमियम २०,००० रु० चुकाया ।

(उ) एक विधुर (Widower) जिसके कोई बच्चा नहीं है । वेतन ६,००० रु० जायदाद की आय ८०० रु०, साधारण अशो पर लाभांश ८२२ रु० (नेट) ।

(ऊ) विवाहित व्यक्ति । वेतन ८०,००० रु० । वैधानिक प्रॉवीडेण्ट फण्ड में वन्दा ६,००० रु० । जीवन बीमा प्रीमियम १०,००० रु० ।

(ए) अनरजिस्टर्ड फर्म । व्यापार लाभ २५,००० रु० तथा प्रतिभूतियों पर ब्याज (नेट) २४,५०० रु० ।

(अ) न कमाई हुई आय पर आय-कर

प्रथम १,००० रु० पर

अगले ३,५०० रु० पर ३%

रु०

कुछ नहीं
१०५

चुकाया जाने वाला आय-कर

१०५

इस पर कोई सरचार्ज नहीं होगा क्योंकि कुल आय ७,५०० रु० से अधिक नहीं है ।

(आ) न कमाई हुई आय पर आय-कर

प्रथम ३,६०० रु० पर

अगले ६०० रु० पर ३%

रु०

कुछ नहीं
२७

चुकाया जाने वाला आय-कर

२७

इस पर कोई सरचार्ज नहीं होगा क्योंकि कुल आय ७,५०० रु० से अधिक नहीं है ।

(इ) कमाई हुई आय पर आय-कर

प्रथम ३३०० रु० पर

अगले १,५०० रु० पर ३%

रु०

रु०
कुछ नहीं
४५

न कमाई हुई आय पर आय-कर

२०० रु० पर ३%

६

२,५०० रु० पर ६%
६०० रु० पर ६%

१५०
८१

२३७ ००

आय-कर धर सामान्य सरचार्ज २८२ रु० पर ५%
आय-कर पर विशेष सरचार्ज २३७ रु० पर १५%

२८२ ००
१४ १०
३५ ३५

बुकाया जाने वाला आय-कर

३३१ ६५

(ई) कमाई हुई आय १,२०,००० रु० पर आय कर .

रु०

रु०

१,००,००० रु० पर
२०,००० रु० पर २५%

२२,०२० ००
५,००० ००

२७,०२० ००

27 020 00

३,००० ००

न कमाई हुई आय पर आय-कर

१२,००० रु० पर २५%

३०,०२० ००

सामान्य सरचार्ज . ३०,०२० रु० पर ५%
५,००० रु० पर ५%

१५०१ ००
२५०० ००

विशेष सरचार्ज ३००० रु० पर १५%

४५० ००

२,२०१ ००

३२ २२१ ००

घटाया—जीवन बीमा प्रीमियम पर आय-कर की

छूट (१६,००० रु० तक सीमित)

१६,००० × ३२२२१ ✓ =

१,३२,०००

३,६०५ ५६

बुकाया जाने वाला आय-कर

२८,३१५ ४४

कमाई हुई आय १,२०,००० रु० पर सुपर-टैक्स .

१,००,००० रु० पर

२७००० ००

२०,००० रु० पर ४५% १

६,००० ००

३६,००० ००

न कमाई हुई आय पर सुपर-टैक्स .

१२,००० रु० पर ४५%

५,४०० ००

४१,४०० ००

सामान्य सरचार्ज . ४१,४०० रु० पर ५% ✓

२,०६० ००

६,००० रु० पर ५% ✓

४५० ००

विशेष सरचार्ज . ५,४०० रु० पर १५% ✓

८१० ००

३,३३० ००

चुकाया जाने वाला सुपर-टैक्स	४४,७३० ००
चुकाया जाने वाला आय-कर	२८,३१५ ४४
चुकाया जाने वाला सुपर-टैक्स	४४,७३० ००
चुकाया जाने वाला कुल-कर	७३,०४५ ४४
(उ) १ वेतन (१२० रु० आय-कर उद्गम स्थान पर काटा गया)	६० ६,०००
२ जायदाद की आय	८००
३ साधारण अशो पर ग्राँस लाभांश (आय-कर ३७८ रु० लागू हुआ)	१,२००
कुल आय	८,०००

कमाई हुई आय पर आय-कर (६,००० रु०)	१२०
न कमाई हुई आय पर आय-कर (२,००० रु०)	१३५
	२५५

उद्गम स्थान पर आय-कर चुकाया	
वेतन	१२०
लाभांश	३७८
	४९८
वापिसी (Refund) की रकम	२४३

कुल आय साधारण अशो पर लाभांश को छोड़कर ७,५०० रु० से तथा कुल आय साधारण अशो पर लाभांश को शामिल करके ९,००० रु० से अधिक नहीं है। इसलिये आय-कर पर सरचार्ज नहीं लगेगा।

(ऊ) ८०,००० रु० पर आय-कर	६० १७,०२०
सामान्य सरचार्ज १७,०२० रु० पर ५%	८५१
	१७,८७१

घटाय—प्रॉविडेंट फण्ड चन्दे तथा जीवन बीमा प्रीमियम की छूट ८,००० रु० तक सीमित :

८०००×१७.८७१	१,७८७
८००००	१६,०८४

सुपर टैक्स * ८०,००० रु० पर	१८,०००	
सामान्य सरचार्ज * १८,००० रु० ५%	९००	१८,९००
		<hr/>
चुकाया जाने वाला कुल कर		३४,९८४
		<hr/>
(ए) १ प्रतिभूतियों पर ब्याज (उद्गम स्थान पर आय-कर १०,५०० रु० कटा)	३५,०००	
२. व्यापार लाभ	२५,०००	
	<hr/>	
कुल आय	६०,०००	
	<hr/>	
कमाई हुई आय पर आय-कर २५,००० रु० पर		३,२७० ००
न कमाई हुई आय पर आय-कर ३५,००० रु० पर		८,७५० ००
		<hr/>
		१२,०२० ००
सामान्य सरचार्ज १२,०२० रु० पर ५%		६०१ ००
विशेष सरचार्ज ८,७५० पर १५%		१,३१२ ५०
		<hr/>
		१३,९३३ ५०
कमाई हुई आय पर सुपर टैक्स * २५,००० रु० पर	२५० ००	
न कमाई हुई आय पर सुपर टैक्स * ३५,००० रु० पर	९,२५० ००	
	<hr/>	
	९,५०० ००	
सामान्य सरचार्ज ९,५०० रु० पर ५%	४७५ ००	
विशेष सरचार्ज ९,२५० रु० पर १५%	१,३८७ ५०	११,३६२ ५०
	<hr/>	
चुकाया जाने वाला कुल कर		२५,२९६ ००
		<hr/>

(२) एक अविवाहित व्यक्ति का ३१ दिसम्बर १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष का व्यापार से लाभ ३,१०० रु० है तथा उसने जीवन बीमा प्रीमियम के ६०० रु० चुकाये। १९५९-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिये चुकाये जाने वाले कर की रकम निकालिये।

इस दशा में, निम्न में से कम रकम, चुकाये जाने वाला आय-कर होगा :—

(अ) विभागीय दरों से गणना पर कर।

(ब) ३००० रु० से ३१०० रु० के आय-व्यय का आधा।

विभागीय दरों (Slab rates) से ३,१०० रु० पर आय-कर ६३ रु० होगा जब कि ३,००० रु० के ऊपर ३,१०० रु० के आय-व्यय का आधा ५० रु० है। क्योंकि कुल आय ७ ५०० रु० से कम है अतएव आय-कर पर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा।

	₹०
कुल आय पर आय-कर	₹०.००
घटाया—जीवन बीमा प्रीमियम (कुल आय के चौथाई तक सीमित)	
७७५ ₹० पर औसत दर छूट	₹२.५०
	<hr/>
बुकाया जाने वाला आय-कर	₹७.५०
	<hr/>

अविवाहित व्यक्ति की दशा में सीमावर्ती (marginal relief) कुल आय ₹,१२७ ₹० तक लागू होगी।

(३) एक विवाहित (बिना किसी बच्चे के) कमचारी की ३१ मार्च १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में ₹,००० ₹० मासिक कर-मुक्त वेतन (Tax-free salary) मिला। १९५६-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए उसका ग्राँस वेतन क्या होगा ?

वास्तविक प्राप्त हुए वेतन के साथ ही उसपर लागू कर को साथ लेते हुए कर-मुक्त वेतन ग्राँस करने की विधि को “कर के ऊपर कर” पद्धति कहा जाता है।

	₹०	₹०
१—₹२,००० ₹० पर आय-कर .		
₹,००० ₹० पर	नही	
२,००० ₹० पर ३%	₹०.००	
२,५०० ₹० पर ६%	₹५०.००	
२,५०० ₹० पर ६%	₹२२.५०	
२,००० ₹० पर ११%	₹२०.००	
	<hr/>	
	₹५५.००	
सरचार्ज ५% से	₹२.७५	₹६७.७५
	<hr/>	

२—₹६७ ₹० ७५ नये पैसे पर आय-कर .

₹०० ₹० पर ११%	₹५.००	
₹६७ ७५ ₹० पर १४%	₹९.२६	
	<hr/>	
	₹१४.२६	
सरचार्ज ५% से	₹०.६	₹१४.८६
	<hr/>	

३—₹५ ₹० ३५ नये पैसे पर आय-कर :

₹५ ३५ ₹० पर १४%	₹११.६३	
सरचार्ज ५% से	₹०.६०	₹१२.२३
	<hr/>	

४—१२ रु० ५३ नये पैसे पर आय-कर .

१२ ५३ रु० पर १४%

१ ७५

सरचाज ५% से

० ०६

१ ८४

५—१ रु० ८४ नये पैसे पर आय-कर .

१ ८४ रु० पर १४%

० २६

सरचार्ज ५% से

० ०१

० २७

मालिक द्वारा दिया गया कुल कर

७८७ ७४

चुकाया गया कर-मुक्त वेतन

१२,००० ००

ग्रॉस वेतन की राशि

१२,७८७ ७४

या (कहिए)

१२,७८८ ००

(४) ३१ दिसम्बर १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एक विवाहित व्यक्ति (जिसके कोई बच्चा नहीं है) को व्यापार से लाभ २०,२०० रु० है । १९५९-६० कर निर्धारण वर्ष के लिए चुकाये जाने वाले कर की राशि निकालिये ।

विवाह तथा बच्चों की छूट कुल आय २०,००० रु० तक ही स्वीकृत की जाती है । इस दशा में चुकाया जाने वाला आय-कर सीमावर्ती छूट के आधीन है । इसलिये चुकाया जाने वाला आय-कर इनके योग से नहीं बढ़ेगा ,—

रु०

(अ) आय-कर जो कुल आय २०,००० रु० होने पर चुकाना होता

१,९६० ००

(ब) २०,००० रु० के ऊपर २०,२०० रु० के अधिक्य का आधा

१०० ००

चुकाया जाने वाला आय-कर

२,०६० ००

सामान्य सरचार्ज आय-कर पर २०६० रु० ५%

१०३ ००

सुपर-टैक्स २०,२०० रु० पर

१० ००

सामान्य सरचार्ज सुपर-टैक्स पर १० रु० पर ५%

५०

चुकाया जाने वाला कुल कर

२,१७३ ५०

क्योंकि न कमाई हुई आय नहीं है इसलिये विशेष सरचार्ज नहीं लगेगा ।

इस जैसी दशा में २०,२४० रु० कुल आय तक सीमावर्ती छूट स्वीकृत की जाती है । यदि व्यक्ति के एक बच्चा है, समावर्ती छूट २०,२७६ रु० तक और यदि व्यक्ति के दो बच्चे हैं तो यह छूट कुल आय २०,३१२ रु० तक मिलती है ।

(५) ३१ मार्च १९५६ को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए एक विवाहित व्यक्ति की कुल आय २,१५,००० रु० है जिसमें से १,३०,००० रु० कमाई हुई तथा ८५,००० रु० न कमाई हुई आय के हैं। १९५६-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए उसके द्वारा चुकाये जाने वाले कर की गणना कीजिये।

	रु०	रु०
कमाई हुई आय पर आय-कर . १,००,००० रु० पर	२२,०२०	
३०,००० रु० पर	७,५००	२९,५२०
न कमाई हुई आय पर आय-कर ८५,००० रु० पर		२१,२५०
		५०,७७०
आय-कर पर सामान्य सरचार्ज (५०,७७० रु० पर ५ ^० / _{१०})	२,५३६	
(७,५०० रु० पर ५%)	३७५	
आय-कर पर विशेष सरचार्ज (२१,२५० रु० पर १५%)	३,१८८	६,१०२
आय-कर तथा सरचार्ज		५६,८७२ (अ)
कमाई हुई आय पर सुपर-टैक्स १,००,००० रु० पर	२७,०००	
३०,००० रु० पर	१३,५००	४०,५००
न कमाई हुई आय पर सुपर-टैक्स ८५,००० रु० पर		३८,२५०
		७८,७५०
सुपर-टैक्स पर सामान्य सरचार्ज (७८,७५० रु० पर ५ ^० / _{१०})	३,९३७	
(१३,५०० रु० पर ५%)	६७५	
सुपर-टैक्स पर विशेष सरचार्ज (३८,२५० रु० पर १५%)	५,७३७	१०,३४९
सुपर-टैक्स तथा सरचार्ज		८९,०९९ (ब)

चुकाये जाने वाला कुल कर (अ)+(ब)=१,४५,९७१ रु०।

(६) एक विवाहित व्यक्ति ने (जिसके कोई बच्चा नहीं है) गत वर्ष, जो कि ३१ मार्च १९५६ को समाप्त होता है, में ७,५२० रु० का वेतन कमाया तथा ७५२ रु० वैधानिक प्रॉविडेंट फण्ड में अशदान दिये तथा जीवन बीमा प्रीमियम १,२०० रु० चुकाये। वह राशि जो कि उसके वेतन में से उस वर्ष में काटी जानी चाहिए थी निकालिए।

इस दशा में आय-कर पर सरचार्ज के लिए सीमावर्ती छूट मिलेगी। ७,५२० रु० पर आय-कर २११ रु० ८० होगा। २११ रु० ८० पर ५% सरचार्ज १० ५६ रु० होता है जो कि ७,५२० रु० तथा ७,५०० रु० के अन्तर के आये से अधिक है। इसलिये सरचार्ज १० रु० तक सीमित है।

यह सीमावर्ती छूट कुल आय ७,५२१ रु० तक स्वीकृत की जायेगी। विवाहित व्यक्ति, जिसके एक बच्चा है, की दशा में यह छूट ७,५२० रु० तथा विवाहित व्यक्ति, जिसके दो बच्चे हैं, की दशा में यह छूट ७,५१६ रु० तक मिलेगी।

प्रॉविडेंट फण्ड चन्दे तथा जीवन बीमा प्रीमियम की छूट कुल आय ७,५२० रु० के एक-चौथाई तक अर्थात् १,८८० रु० तक सीमित होगी।

आय-कर ७,५२० रु० पर	रु० २११ ८०
आय-कर पर सरचार्ज जैसा कि ऊपर कहा गया है	१० ००
	<hr/> २२१ ८०
घटाया—आय-कर की छूट १,८८० रु० पर =	
$\frac{२२१.८० \times १,८८०}{७,५२०} = ५५.४५$	५५ ४५
उद्गम स्थान पर आय-कर कटा	<hr/> १६६ ३५

(७) ३१ मार्च १९५६ को समाप्त होने वाले गत वर्ष में एक व्यक्ति को, जिसके दो बच्चे हैं, निम्न कर-योग्य आय है

जायदाद से आय	रु० २,५६०
व्यापार लाभ	५,०००
साधारण अशो पर लाभांश (आय कर उद्गम स्थान पर दिया ३०० रु०)	१,५००

१९५६-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिये चुकाये जाने वाले आय-कर की गणना कीजिये।

	रु०	रु०
(१) जायदाद से आय (न कमाई हुई)	२,५६०	
(२) व्यापार से लाभ (कमाई हुई)	५,०००	
(३) साधारण अशो से लाभांश (न कमाई हुई)	१,५००	
	<hr/> कुल आय ९,०६०	
कमाई हुई आय पर आय-कर ३,६०० रु० पर	कुछ नहीं	
१,४०० रु० पर ३%	४२ ००	४२ ००
	<hr/>	
न कमाई हुई आय पर आय-कर २,५०० रु० पर ६%	१५० ००	
१,५६० रु० पर ६%	१४० ४०	२९० ४०
	<hr/>	<hr/>
		३३२ ४०

सामान्य सरचार्ज ३३२ ४० रु० (जो कि ६०६० रु० तथा ७,५०० रु० के अन्तर के आधे से कम हैं) पर ५%	१६ ६२
विशेष सरचार्ज २६० ४० रु० पर १५% = ४३ ५६	
इसलिये यह ६० रु० के आधे (जो कि ६,००० रु० से ६,०६० रु० का आधिक्य है) तक सीमित होगा	३० ००
वाजिब (Due) कुल आय-कर तथा सरचार्ज	३७१ ०२
घटाया—लाभांश पर दिया गया आय कर	३००,००
	<hr/>
चुकाया जाने वाला आय-कर	७१ ०२

क्योंकि दोनों सरचार्ज एक स्थान लेते हुए (१६ ६२ रु० + ३० रु० = ४६ ६२ रु०) कर मुक्ति सीमा ७,५०० रु० से आधिक्य के आधे से कम है, इसलिये चुकाया जाने वाला सरचार्ज ४६ ६२ रु० होगा।

(८) ३१ मार्च १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एक विवाहित व्यक्ति को उसके कपड़े के व्यापार से १५,००० रु० की कर-योग्य आय है तथा उसने ६,००० रु० विनियोगों की बिक्री पर पूँजी लाभ प्राप्त किया। उसके द्वारा १९५६-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए चुकाने जाने वाले आय-कर की रकम निकालिये।

पूँजी लाभ पर आय-कर अन्य आय—पूँजी लाभ की तिहाई पर लागू होने वाली दरों पर लिया जाता है। इसलिये १८,००० रु० पर (१५,००० रु० + पूँजी लाभ का तिहाई ३,००० रु०) आय कर निम्न होगा—

कमाई हुई आय पर आय-कर १५,००० रु० पर	१,१२०
न कमाई हुई आय पर आय-कर ३,००० रु० पर	५४०
	<hr/>
	१,६६०
सामान्य सरचार्ज १,६६० रु० पर ५%	८३
विशेष सरचार्ज, ५४० रु० पर १५%	८१
	<hr/>
	१,८२४
	<hr/>
	१,१२०
	५६
सामान्य सरचाज १,१२० रु० पर ५%	
आय-कर तथा सरचार्ज पूँजी लाभ ६,००० रु० पर	
उस दर से जो १८,००० रु० पर लागू हो रही है	
अर्थात् १,८२४ रु० का आधा	९१२
	<hr/>
१९५६-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिये देय आय-कर	२ ०८८

(६) अ (विवाहित व्यक्ति जिसके दो बच्चे हैं) जिसने वर्षान्त ३१ मार्च १९५६ में निम्न प्राप्त किया, को वापस (refund) होने वाली राशि की गणना कीजिये — (अ) प्रतिभूतियों पर ब्याज ₹, ५०० रु० (नैट) तथा (ब) लाभांश एक ऐसी कम्पनी से जिसकी ४०% आय पर लगता है, ४०% कर-मुक्त है तथा २०% कृषि आय है, ₹, ३७० रु० ।

अ का १९५६-६० के लिए कर-निर्धारण	रु०
(१) प्रतिभूतियों पर ब्याज (ग्राँस), उद्गम स्थान पर ३०% आय-कर के कटे ₹, ५०० रु० ।	५,०००
(२) लाभांश (ग्राँस), इस पर लागू होने वाला आय-कर ₹३० रु० होता है, जैसा कि नीचे निकाला गया है ।	५,०००

कुल आय १०,०००

आय-कर १०,००० रु० पर १९५६-५६ की दरों से	४१७००
सामान्य सरचार्ज ४१७ रु० का ५%	२० ८५
विशेष सरचार्ज ४१७ रु० का १५%	६२ ५५

वाजिब (Due) आय-कर १९५६-६० कर निर्धारण वर्ष के लिए	५०० ४०
---	--------

उद्गम स्थान पर एकत्र आय-कर	
प्रतिभूतियों के ब्याज पर	१,५००
लाभांश पर	६३०
	२,१३० ००

घटाया—१९५६-६० कर निर्धारण वर्ष के लिये आय-कर	५०० ४०
--	--------

वापसी (Refund) की रकम १,६२९ ६०

टिप्पणियाँ

(१) प्रतिभूतियों पर ब्याज में से उद्गम स्थान पर आय-कर की कटौती कम्पनी की दशा में ३१ ५% (३०% + १ ५% सरचार्ज) तथा अन्य दशा में ३०% (२५% + ५% सरचार्ज) होगी ।

(२) लाभांश (₹३७० रु०) निम्न फार्मूले को लगा कर ग्राँस किया गया है ।

$$\frac{₹, ३७०}{१ - \left[\frac{४०}{१००} \times \frac{३१ ५}{१००} \right]} = ₹, ५०० रु० ।$$

(१०) ३१ मार्च १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में एक कम्पनी के कर्मचारी ने ₹०, ००० रु० वेतन तथा भत्तों के प्राप्त किये तथा कम्पनी द्वारा रखे गये स्वीकृत

प्रॉविडेंट फण्ड में ₹५,००० रु० अपने चन्दे के दिये, जिसमें कि मालिक ने भी उतना ही धन दिया। प्रॉविडेंट फण्ड खाते पर ₹५,००० रु० ब्याज के जमा हुए।

उसने अपनी जीवन बीमा पॉलिसी ₹५,००० रु० की पर ₹६,००० रु० प्रीमियम चुकाए।

₹१६५६-६० के लिए उसका कर-निर्धारण तैयार कीजिये।

₹१६५६-६० के लिए कर-निर्धारण

वेतन तथा भत्ते	₹०
मालिक का प्रॉ० फण्ड में अशदान कर्मचारी के वेतन के १०% से अधिक	₹०,०००
	₹१,०००
कुल आय	₹४१,०००
आय-कर ₹४१,००० रु० पर	₹७,२७० ००
सामान्य सरचाज ७,२७० रु० पर ५%	₹३६३ ५०
	₹७,६३३ ५०
घटाया—आय-कर की छूट ₹५,००० रु० पर $\frac{₹५,००० \times ₹७,६३३ ५०}{₹४१,०००} =$	₹१,४८६ ४६
चुकाया जाने वाला आय-कर	₹६,१४७ ०४
सुपर-टैक्स ₹४१,००० रु० पर	₹३,३०० ००
सामान्य सरचार्ज ₹३,३०० रु० पर ५%	₹१६५ ००
चुकाया जाने वाला सुपर-टैक्स	₹३,४६५ ००
आय कर तथा सरचार्ज	₹६,१४७ ०४
सुपर-टैक्स तथा सरचार्ज	₹३,४६५ ००
वाजिब (Due) कुल कर	₹९,६०६ ०४
घटाया—राशि जो उद्गम स्थान पर काटी गई	₹९,६०६ ०४
राशि जो अब देय है	कुछ नहीं

टिप्पणियाँ

(१) प्रॉविडेंट फण्ड खाते पर जमा ब्याज ₹५,००० रु० छोड़ दिया गया है क्योंकि यह वेतन के तिहाई से कम है तथा प्रस्तावित दर ६% से कम से लगाई गई है।

(२) आय-कर की छूट केवल कर्मचारी के स्वयं के चन्दे पर ही मिलती है, मालिक द्वारा दिये गये चन्दे पर नहीं।

(३) स्वीकृत प्रॉविडेंट फण्ड में कर्मचारी के स्वयं के चन्दे की उच्चतम राशि जिस पर छूट दी जा सकती है वेतन के पाँचवें भाग या ८,००० रु० जो भी दोनों में से कम हो, है। स्वीकृत प्रॉविडेंट फण्ड के चन्दे तथा जीवन बीमा प्रीमियम दोनों को एकत्र लेते हुए यह छूट वेतन के चौथाई भाग या ८,००० रु० जो भी दोनों में से कम हो, के लिए स्वीकृत की जाती है।

(४) सुपर-टैक्स के लिए जीवन बीमा प्रीमियम तथा प्रॉविडेंट फण्ड में चन्दों के लिए कोई छूट नहीं है।

(११) ३१ मार्च १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये एक विवाहित व्यक्ति (जिसके तीन बच्चे हैं) की निम्न आय थी—

- (अ) प्रतिभूतियों पर ब्याज (ग्रॉस) ४०० रु०, उद्गम स्थान पर आय-कर की कटौती हुई १०० रु०।
- (आ) प्रतिभूतियों पर ब्याज (कर-मुक्त) १०० रु०।
- (इ) जायदाद से आय २,००० रु०।
- (ई) कपड़ा व्यापार से लाभ २,५०० रु०।
- (उ) एक अनरजिस्टर्ड फर्म में आधा भाग १५,००० रु०।
- (ऊ) एक सहकारी समिति से लाभांश ५०० रु०।
- (ए) एक कम्पनी से लाभांश जो अपनी आय पर कोई कर नहीं चुकाती १,००० रु०।
- (ऐ) एक कम्पनी से लाभांश जिसकी सम्पूर्ण आय पर कर लगता है, ३,४२५ रु०।

उसने अपनी जीवन बीमा पॉलिसी पर जो २०,००० रु० की है पर २,५०० रु० प्रीमियम चुकाया तथा १,००० रु० एक यूनीवर्सिटी को दान दिया।

१९५६-६० के लिये उसका कर-निर्धारण तैयार कीजिये।

	आय रु०	उद्गम स्थान पर कटौती रु०
१ प्रतिभूतियों पर ब्याज (ग्रॉस)	४००	१२०
प्रतिभूतियों पर ब्याज (कर-मुक्त)	१००	
२ जायदाद से आय	२,०००	
३ व्यापार स्वयं का कपड़ा व्यापार	२,५००	
अनरजिस्टर्ड फर्म से हिस्सा	१५,०००	
४. अन्य साधन		
सहकारी समिति से लाभांश	५००	
लाभांश ऐसी कम्पनी से जो अपनी आय पर कर नहीं देती	१,०००	

लाभाश ऐसी कम्पनी से जो अपनी
सम्पूर्ण आय पर कर देती है

५,०००

१,५७५

कुल आय २६,५००

१,६६५

रु०

कमाई हुई आय पर आय-कर २५०० रु० पर

४५ ००

न कमाई हुई आय पर आय-कर २४,००० रु० पर

३,६०० ००

सामान्य सरचार्ज ३,६४५ रु० पर ५%

१८२ २५

विशेष सरचाज ३,६०० रु० पर १५%

५४० ००

४,३६७ २५

कर-मुक्त आय

रु०

प्रतिभृतियों (कर-मुक्त) पर व्याज

१००

सहकारी समिति से लाभाश

५००

अनरजिस्टर्ड फर्म से हिस्सा

१५,०००

जीवन बीमा प्रीमियम—बीमित राशि

के १०% तक सीमित

२,०००

पुण्याथ दान कुल आय-कर-मुक्त

आय (२६,५००-१००-५००-१५,०००-

२०००) के ५% तक सीमित

४४५

१८,०४५

कुल आय पर लगने वाला आय-कर

४,३६७ २५

घटाया—१८,०४५ रु० कर-मुक्त आय पर छूट

 $\frac{१८०४५ \times ४३६७ २५}{२६५००} = २९७३ ८५$

२,९७३ ८५

२६५००

१९५६-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिये चुकाया जाने वाला

आय-कर

१,३६३ ४०

आय-कर उद्गम स्थान पर दिया

१,६६५ ००

वापसी (Refund) की रकम

३०१ ६०

कर-दाता सुपर-टैक्स के लिये दायी बही है। सुपर-टैक्स हेतु कुल आय में से अन-रजिस्टर्ड फर्म का हिस्सा १५,००० रु० घटा देना होगा। जब यह कर दिया जाता है तो शेष ११,५०० रु० रहता है जोकि सुपर-टैक्स सीमा से नीचे है।

(१) निम्न मदों को संक्षेप में समझाइए —

- (अ) आय
- (ब) कृषि आय
- (स) कमाई हुई आय
- (द) आकस्मिक आय
- (इ) पूँजी-लाभ
- (ई) गत-वष
- (उ) अशोधित ह्रास
- (ऊ) अतिरिक्त पाली उपयोग की छूट
- (ए) सतुलनीय ह्रास

आय—आय-कर अधिनियम में 'आय' मद्द को पूरी तरह से नहीं समझाया है। निश्चित साधनों द्वारा नियमित रूप से जो सामयिक द्राव्यिक आय होती है उसे आय कहते हैं। अगर कोई प्राप्ति विशेष ऐसी है जिसका साधन स्थिर नहीं किया जा सकता, तो इस प्राप्ति को कर-योग्य आय नहीं माना जा सकता। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी सड़क पर घूम रहा है और यदि मार्ग में उसे १,००० रु० की थैली पड़ी हुई मिले और वह उसे उठाकर अपने कब्जे में करले, तो उसकी यह प्राप्ति आय के अन्तर्गत शामिल नहीं की जा सकती, क्योंकि इसका साधन स्थिर नहीं है।

कृषि आय—कृषि आय उस जमीन की आय मानी जाती है जो कृषि के काम में लाई जाती हो तथा जिस पर सरकार को लगान या स्थानीय सत्ता को कर दिया जाता है। उस जमीन से प्राप्त होने वाली आय जो उपर्युक्त दोनों शर्तों को पूरा नहीं करती कृषि आय नहीं है।

कमाई हुई आय—वह आय जो कि व्यक्तिगत मेहनत से प्राप्त हो 'कमाई हुई आय' कहलाती है, जबकि व्यक्तिगत मेहनत से न वसूल होने वाली आय 'न कमाई हुई'

कही जाती है। तमाम वेतन, पेन्सन अथवा भूतपूर्व सेवाओं के लिए अन्य भत्ते 'कमाई हुई आय' है। व्यापार, पेशे अथवा व्यवसाय से लाभ भी 'कमाई हुई आय' है, यदि वह कर-दाता ने स्वयं चलाया है। 'अन्य स्रोतों से आय' भी कमाई हुई आय मानी जाएगी यदि वह व्यक्तिगत मेहनत (exertion) से प्राप्त हो जैसे संचालक-शुल्क तथा-किताबों से रॉयल्टी।

आकस्मिक आय—यह वह आय है जो कि आकस्मिक तरह की होती है तथा जोकि किसी व्यापार, पेशे अथवा व्यवसाय से प्राप्त न हो। यह 'आँधी के आम' की तरह है जैसे लौटरी में प्राप्त होने वाली राशि।

पूँजी-लाभ—यह पूँजी सम्पत्ति के विक्रय हस्तान्तरण, तबदीली आदि पर हुए लाभ है। पूँजी-सम्पत्ति का अर्थ कर-दाता द्वारा रखी गई किसी प्रकार की सम्पत्तियों से है चाहे वे व्यापार से सम्बन्धित हों या नहीं, लेकिन इसमें व्यापारिक-स्कन्ध, वैयक्तिक सम्पत्तियाँ तथा कृषि आय सम्मिलित नहीं है।

गत-वर्ष—गत वर्ष का अर्थ या तो पहला समाप्त हुआ आर्थिक वर्ष है या पहले समाप्त हुए वर्ष में जिस १२ माह की अवधि के लिए कर-दाता ने अपने हिसाब बनाये हैं वह अवधि है। इस तरह गत-वर्ष पहले आर्थिक वर्ष के साथ-साथ या उसके अन्दर ही समाप्त हो जाना चाहिये।

अशोधित ह्रास—जब अपर्याप्त लाभ के कारण वर्ष भर की पूरी ह्रास छूट नहीं माँगी जा सकती तो उस बचे हुए शेष को कि इस कारण से नहीं माँगा जा सका है अशोधित ह्रास कहते हैं और यह अशोधित ह्रास भविष्य के कर-निर्धारणों में अनिश्चित-काल तक आगे ले जाया जा सकता है।

अतिरिक्त पाली उपयोग की छूट—प्लाण्ट और मशीन की स्थिति में दुहरी तथा तिहरी पाली के उपयोग के लिए एक 'अतिरिक्त पाली उपयोग की छूट' ह्रास में दी जाती है। यह अतिरिक्त छूट दुहरी पाली उपयोग की दशा में साधारण ह्रास की ५०% तथा तीहरी पाली उपयोग में साधारण ह्रास की १००% होती है। अतिरिक्त पाली उपयोग की छूट की गणना करने के लिए वर्ष में ३०० दिन "कार्य करने के दिन" माने जाएँगे।

संतुलनीय ह्रास—जबकि भवन, प्लाण्ट अथवा मशीन, जो कि व्यापार के हेतु प्रयोग की जाती है, बेच दी जाय या समाप्त कर दी जाय या नष्ट हो जाय तब विक्रय-मूल्य या स्कैप-मूल्य से अपलिखित-मूल्य की जो अधिकता हो वह संतुलनीय या टर्मिनल (terminal) ह्रास के रूप में दी जाती है।

(२) एक निवासी किन दशाओं में भारत का निवासी तथा पक्का निवासी कहा जाता है ?

एक व्यक्ति भारत में गत वर्ष में निवासी माना जाता है

- (१) यदि वह उस वर्ष में १८२ या अधिक दिनों के लिए रहा है, या
- (२) यदि उसने भारत में अपने रहने के लिए निवास-स्थान कम से कम १८२ दिनों के लिए रखा है तथा वह उस वर्ष में किसी समय भारत में भी था, या
- (३) यदि वह भारत में उस वर्ष में कम से कम एक दिन के लिए तो अवश्य ही आया हो परन्तु उसका यह आगमन आकस्मिक न हो तथा वह भारत में पहले चार वर्षों के अन्दर कम से कम ३६५ दिन उपस्थित रहा हो, या
- (४) यदि वह भारत में उस वर्ष आया हो तथा इनकम टैक्स आफिसर को यह विश्वास हो गया हो कि वह भारत में आने की तिथि से कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए रहने के इरादे से आया है ।

पक्का निवासी अर्थात् 'निवासी और साधारण निवासी' होने के लिए उसे निम्न दो शर्तों को और पूरा करना होगा .—

- (१) वह उस वर्ष से दस वर्षों में कम से कम नौ वर्षों में उपर्युक्त शर्तों के अनुसार भारत में निवासी रहा हो, तथा
- (२) वह उस वर्ष के पहले ७ वर्षों के दौरान में दो वर्षों से अधिक अवधि तक भारत में रहा हो ।

(३) आय की वे कौनसी श्रेणियाँ हैं जिन पर आय-कर अधिनियम लागू नहीं होता ?

आय की निम्न श्रेणियों पर आय-कर अधिनियम लागू नहीं होता, अर्थात् यह आय-कर-दाता की कुल आय में नहीं जोड़ी जाती हैं .

१. धार्मिक अथवा पुण्यार्थ रखी गई जायदाद से आय जैसे शिक्षा, बीमारी सेवा या अन्य उद्देश्य से जो कि सामान्य जनता के लाभ के लिए हो ।
२. धार्मिक या पुण्यार्थ सस्थाओं जैसे मन्दिर की आय ।
३. स्थानीय सत्ता जैसे म्यूनिसिपल बोर्ड की आय ।
४. वधानिक अथवा स्वीकृत प्रॉवीडेण्ट फण्ड द्वारा किये गए विनियोगों से आय ।
५. विशेष भत्ता (मनोरजन भत्ते की छोड़कर) जो कि कार्यालय के कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिए दिए जाय लेकिन केवल उस सीमा तक जहाँ तक

- कि वे वास्तव में व्यय किए जाय । यात्रा भत्ता तथा कनवियेन्स भत्ता इस छूट के उदाहरण हैं ।
- ६ भारतीय मालिक से प्राप्त अन्धकारी कर्मचारी को भारत से बाहर अपने घर छुट्टी पर जाने के लिए मुफ्त अथवा छूट के पैसेज की राशि ।
 - ७ आकस्मिक आय ।
 - ८ कृषि आय ।
 - ९ भूतपूर्व भारतीय स्टेट के नरेश को प्रिवी पर्स की रकम ।
 - १० एक स्वीकृत अनुसन्धान सन्स्था की आय ।
 - ११ विदेशी सन्स्था के भारत में डिप्यूट किये गये कर्मचारी का पारिश्रमिक ।
 - १२ पोस्टल बचत खाते, सेविंग्स सर्टिफिकेट तथा ट्रेजरी सेविंग्स डिपॉजिट पर ब्याज ।

Que (४) उन आयों को बतलाइए जो कि आय-कर से मुक्त हैं (लेकिन सुपर-टैक्स से नहीं) तथा जो कर-दाता की कुल आय में सम्मिलित की जायेगी ।

Ans निम्न वे आय हैं जो कि आय-कर से मुक्त हैं (लेकिन सुपर-टैक्स से नहीं) तथा जो कर-दाता की कुल आय में सम्मिलित की जाएँगी —

(१) डेफर्ड एन्प्टी या उसकी पत्नी तथा बच्चों के आयोजन के लिए किसी सरकारी कर्मचारी के वेतन से सरकार द्वारा काटी गई राशि लेकिन यह राशि वेतन के पाँचवे भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(२) कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज ।

(३) 'अनरजिस्टर्ड फर्म' या 'व्यक्तियों के समूहों' से प्राप्त होने वाली वह आय जिस पर कर लग चुका है से मिले लाभ का भाग ।

(४) करदाता या उसकी पत्नी या उसके पति (या हिन्दू अविभाजित परिवार की दशा में किसी पुरुष सदस्य अथवा उसकी पत्नी) के जीवन पर जीवन बीमा प्रीमियम बशर्ते कि वार्षिक प्रीमियम बीमित राशि के १०% से अधिक न हो ।

(५) स्टैथ्यूटरी प्रॉविडेन्ट फण्ड में कर्मचारी द्वारा किया गया अशदान ।

(६) स्वीकृत प्रॉविडेन्ट फण्ड में कर्मचारी द्वारा किया गया अशदान बशर्ते कि अशदान की राशि वार्षिक वेतन के एक-तिहाई या ८,००० रु० से, जो कम है, से अधिक न हो ।

(७) स्वीकृत सुपर एन्पूशन फण्ड में कर्मचारी द्वारा किया गया अशदान ।

नोट — छूट (१), (४), (५), (६) तथा (७) को एक साथ लेते हुए राशि, व्यक्ति की दशा में, कुल आय के एक-चौथाई या ८,००० रु० में से जो कम हो उससे तथा

हिन्दू अविभाजित परिवार की दशा में, कुल आय के एक-चौथाई या १६,००० रु० में से जो कम हो उससे अधिक न हो ।

(५) पुण्याथ दान किन स्थितियों में और कहाँ तक कर-मुक्त है ?

Ans. कर-दाता को पुण्यार्थ उद्देश्य से भारत में स्थित किसी सस्था या फण्ड को, दिये गये पुण्यार्थ दान पर कर की छूट दी जाती है । यह छूट केवल जब मिलती है जबकि चुकाए गए दान की कुल राशि २५० रु० से कम तथा १,००,००० रु० से या कर-दाता की कुल आय (उसमें से कर-मुक्त आय, यदि कोई हो, घटा कर) के १/२० में से जो कम हो, उससे अधिक न हो ।

कर-मुक्त दान की राशि कर-दाता की कुल आय में जुड़ेगी । कम्पनियों को छोड़कर कर-दाताओं की दशा में पुण्यार्थ दान आय-कर तथा सुपर-टैक्स दोनों से मुक्त है लेकिन कम्पनियों में यह केवल आय-कर से मुक्त है ।

(६) वेतन से कर योग्य आय निकालने के लिए किन कटौतियों की स्वीकृति दी जाती है ?

वेतन से कर-योग्य आय निकालने के लिए निम्न कटौतियाँ स्वीकार की जाती हैं —

(१) कर्मचारी द्वारा अपने कर्तव्यों की पूर्ति के हेतु खरीदी गई किताबों पर ५०० रु० तक की राशि ।

(२) सरकारी कर्मचारी की दशा में जिसे मनोरजन भत्ता मिल रहा है उसके वेतन का (विशेष भत्ते, लाभ तथा अन्य सुविधाओं को निकाल कर) पाँचवे भाग या ५,००० रु० जो भी दोनों में से कम हो, की राशि ।

अन्य किसी कर्मचारी की दशा में जिसे कि मनोरजन भत्ता मिल रहा है उसके वेतन का (विशेष भत्ते, लाभ तथा अन्य सुविधाओं को निकाल कर) पाँचवे भाग या ७,५०० रु०, जो भी दोनों में से कम हो, की राशि बशर्ते कि उसे वर्तमान मालिक से मनोरजन भत्ता १ अप्रैल १९५५ से मिल रहा है ।

किसी भी दशा में मनोरजन भत्ते की कटौती मनोरजन भत्ते की राशि से नहीं बढ़ सकती ।

(३) कर-दाता द्वारा रखी गई तथा उसकी नौकरी में प्रयोग की गई कनवेयन्स (Conveyance) पर हुई साधारण टूट-फूट का वह भाग जो कि उसकी नौकरी के सिलसिले में प्रयोग पर निकाला जाए ।

यदि कर-दाता को अपने मालिक से कनवेयन्स भत्ता मिलता है तो उसे यह कटौती नहीं मिलेगी ।

(४) कर्मचारी द्वारा अपनी सेवाओं की शर्तों पर सम्पूर्ण रूप से तथा आवश्यक रूप से अपने कर्त्तव्यों की पूर्ति हेतु (मनोरजन भत्ते को छोड़ते हुए) किए गए व्यय की राशि ।

(७) मकान जायदाद से आय के सम्बन्ध में मद 'वार्षिक मूल्य' का क्या अर्थ है ?

मकान जायदाद से कर-योग्य आय निकालने के लिए वार्षिक मूल्य की एक काल्पनिक राशि निकालनी होती है जो कि वास्तव में प्राप्त होने वाले किराये की राशि होना जरूरी नहीं है ।

वार्षिक मूल्य जायदाद का वास्तविक किराये का मूल्य है अर्थात् वह मूल्य जिस पर कि वह खुले बाजार में किराये पर उठाई जा सकती हो । म्यूनिसिपल शहरों में प्रायः म्यूनिसिपल मूल्यांकन मूल्य ही वार्षिक मूल्य लिया जाता है । लेकिन जहाँ वास्तव में प्राप्त किराया इस म्यूनिसिपल मूल्यांकन से अधिक हो वहाँ वार्षिक मूल्य वास्तव में प्राप्त किराया लिया जाता है ।

वार्षिक मूल्य की राशि निम्न समायोजनों के बाद आती है —

(१) जब जायदाद किरायेदार के पास हो और इस पर स्थानीय कर लगते हों तो, वार्षिक मूल्य निकालते समय ऐसे करों का आधा घटाया जाएगा ,

(२) जब जायदाद मालिक के अपने रहने के लिए प्रयोग की जाए तो पहले तो उसका वार्षिक मूल्य उसी प्रकार निकाला जाएगा जैसे कि वह किरायेदार को उठी है और उसके बाद इस राशि में से इसका आधा या १,८०० रु०, जो भी दोनों में से कम है, घटा दिया जाता है । लेकिन इस तरह घटायी हुई राशि यदि मालिक को कुल आय के १०% से अधिक है तो वार्षिक मूल्य कुल आय का १०% लिया जाएगा ।

(३) जब कर-दाता के पास केवल एक मकान है जो उसने अपने रहने के लिए रख छोड़ा है और यदि वह गत वर्ष में बिलकुल खाली रहा है तो इसका वार्षिक मूल्य कुछ नहीं (Nil) लिया जाएगा और यदि वह कुछ अवधि के लिए खाली रहा हो तो अनुपातिक (Proportionate) लिया जाएगा । यदि मकान किराए को उठा दिया गया हो या इससे कर-दाता ने अन्य कोई लाभ उठाया हो तो यह छूट नहीं मिलेगी ।

que (८) जायदाद से कर योग्य आम निकालते समय वार्षिक मूल्य में से कौन-सी कटौतियाँ स्वीकार की जायेंगी ? कौन-सी मकान-सम्पत्ति कर से मुक्त है ?

148 जायदाद से कर योग्य आय निकालते समय वार्षिक मूल्य में से निम्न कटौतियाँ स्वीकार की जाती हैं :—

१ मरम्मत के लिए वार्षिक मूल्य का छटा भाग, चाहे वास्तव में मरम्मत की गई हो या नहीं। हाँ, यदि किरायेदार ने स्वयं मरम्मत को वहन करने के लिए सविदा कर लिया है तो मरम्मत के लिए वार्षिक मूल्य तथा चुकाये गये किराये का अन्तर ही दिया जाएगा लेकिन यह अन्तर भी वार्षिक मूल्य के छूटे भाग से नहीं बढ़ना चाहिए।

२ नष्ट होने या नुकसान के खतरो से जायदाद को हानि से बचाने के लिए कराये गये बीमे का प्रीमियम।

३ जायदाद के रहन पर ब्याज या कोई अन्य पूँजी प्रभार जो जायदाद पर हो। धन किस उद्देश्य के लिए उधार लिया गया था यह विचारणीय नहीं होगा।

४ जायदाद पर कोई ऐसा वार्षिक भार जो पूँजीगत भार नहीं है।

५ जायदाद के खरीदने, बनवाने या मरम्मत कराने के लिए जो ऋण लिया गया है उसका ब्याज।

६ यदि जायदाद की जमीन का कोई किराया दिया जाता है तो ऐसे किराये की रकम।

७ जायदाद पर दी जाने वाली किसी मालगुजारी की रकम।

८ जायदाद खाली पड़े रहने की छूट जो वार्षिक मूल्य का वह भाग है जो जायदाद खाली पड़े रहने की अवधि के अनुपात में हो।

९ संग्रहण व्यय, जो वार्षिक मूल्य का ६% या वास्तविक राशि (दोनों में जो कम हो)।

१० न वसूल हुआ किराया, यदि कर दाता ने कर वसूली के लिए तमाम उचित कदम उठा लिये हैं।

यदि मिलने वाली छूटे जायदाद के वार्षिक मूल्य से अधिक बँटें तो यह जायदाद से हुई हानि दूसरे शीर्षको के अन्तर्गत होने वाली आय में से काटी जा सकती है।

कर-मुक्त जायदाद की आय—निम्न स्थितियों में जायदाद से आय-कर मुक्त है —

(अ) वह मकान जो कृषि आय में काम आने वाली भूमि के निकट स्थित है और कृषि कार्यों की देखभाल के हेतु रहने के लिए आवश्यक हो।

(ब) कर-दाता द्वारा अपने व्यापार के लिए, जिसके लाभों पर कर लगता है, प्रयोग किया जाने वाला मकान या जायदाद।

प्र. (६) व्यापार के कर-योग्य लाभ निकालने के लिए स्वीकार किये जाने वाले

व्ययों तथा उन व्ययों एवं हानियों को भी जो कि स्वीकार नहीं किये जाते पूर्ण रूप से समझाइए ।

स्वीकृत व्यय

- १ उस भवन का किराया जहाँ व्यापार चलाया जाता है ।
- २ उस भवन की मरम्मत का व्यय, जिसमें कर-दाता किरायेदार के रूप में रहता है, और उसकी मरम्मत का उसने दायित्व ले रखा है ।
- ३ व्यापार के लिए उधार ली गई पूँजी का ब्याज ।
- ४ व्यापार में काम आने वाले गोदाम, भवन, प्लांट और मशीन, फर्नीचर, स्कंध अथवा स्टोर्स की हानि के खतरे के लिए बीमा कराने का प्रीमियम ।
- ५ व्यापार में काम आने वाले मकान, मशीन, फर्नीचर एवं सयन्त्र के सम्बन्ध में चालू मरम्मत ।
- ६ व्यापार के काम में आने वाले भवन, मशीन, प्लांट, मशीन का ह्रास ।
- ७ हिस की पूरी छूट प्राप्त होने से पूर्व किसी भवन मशीन या प्लांट के बेचने पर हुई हानि ।
- ८ व्यापार के काम में आने वाले मृतक या बेकार जानवरों को बेच देने पर हुई हानि ।
९. व्यापारिक स्थान के ऐसे भाग के सम्बन्ध में मालगुजारी, स्थानीय महसूल या म्यूनिसिपल कर जो व्यापार के काम में आता हो ।
- १० कमचारियों को दिया गया बोनस या कमीशन वशतः उसकी राशि उचित हो ।
- ११ डूबे ऋण (Bad Debts) ।
- १२ व्यापार से सम्बन्धित किसी वैज्ञानिक खोज पर किया गया कोई रिवेन्यू व्यय ।
- १३ किसी वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाली संस्था को दिया गया चन्दा, जो व्यापार से सम्बन्धित अनुसंधान कार्य करती हो ।
- १४ वह सारा पूँजी व्यय, जो व्यापार से सम्बन्धित किसी वैज्ञानिक अनुसंधान पर किया गया हो, लगातार और बराबर की किस्तों में व्यय, करने के वर्ष से आगामी पाँच वर्षों तक घटाने दिया जायगा ।
- १५ अन्य व्यापारिक व्यय जो व्यापार के लिए पूर्णतः और मूलतः व्यापारिक कार्यों के लिए किये जावें ।

अस्वीकृत व्यय तथा हानियाँ :

१ किसी परदेशी को दिया हुआ कोई ब्याज या वेतन जब तक कि इसमें से कर न काटा गया हो ।

२ किसी फर्म द्वारा फर्म के साभेदारों को दिया हुआ कोई ब्याज, वेतन, कमीशन या पुरस्कार ।

३ अस्वीकृत प्रॉविडेण्ट फण्ड अथवा कर्मचारी के लाभों के लिए रखे गए फण्ड में दिया गया चन्दा ।

४ कम्पनी द्वारा अपने किसी संचालक को या ऐसे व्यक्ति को जो कि कम्पनी में समुचित हित रखता हो दिया गया अत्यधिक पारिश्रमिक, लाभ या सुविधा ।

५ किसी कम्पनी की सम्पत्तियों के सम्बन्ध में, जो कि उपर्युक्त व्यक्तियों द्वारा पूर्णतः या अंशतः अपने निजी कार्यों के लिए प्रयोग की जाती हो दिया गया अत्यधिक अलाउन्स ।

६ मालिक या साभेदारों द्वारा निकाले गये आहरण ।

७ मालिकों के निजी या व्यक्तिगत व्यय

८ दान-पुण्य के रूप में किये गये व्यय ।

९ सदिग्ध ऋण कोष या अन्य कोष ।

१० आय पर लगे तमाम कर ।

११ पूँजीगत व्यय ।

१२ किसी मकान जायदाद का किराया जो व्यापार के स्वामित्व में हो और व्यापार के प्रयोग में आती हो ।

१३ पिछली हानियाँ ।

१४ स्वीकृत रकम से ह्रास का आधिक्य ।

१५ अन्य व्यय, जो पूर्णतः व्यापार के लिये नहीं किए जायें, जैसे कर्मचारियों को कर बचाने के लिये चुकाया गया अधिक पारिश्रमिक ।

१६ कोई ऐसी हानि जो व्यापार से सम्बन्धित नहीं है ।

(१०) व्यापार के लाभ निकालने के लिए आय-कर के लिए क्या निम्न व्ययों की कटौती की जा सकती है—कारण सहित बतलाइए .—

(अ) आय कर चुकाने के लिए लिये गए ऋण पर ब्याज ।

(ब) कर्मचारियों की सेवाओं के लिए दी गई भेंट (Gifts) लेकिन ये भेंट कर्मचारी कानून से प्राप्त नहीं कर सकते थे ।

(स) प्रासवदिक तिथि (contracted date) से पूर्व रिटायर किये जाने वाले कर्मचारी को चुकाया गया हर्जाना ।

(द) ग्राहको को दिये गये ऋण तथा पेशगियो के सम्बन्ध में डूबा ऋण ।

(ई) विज्ञापन व्यय ।

(अ) यह स्वीकार योग्य कटौती है, क्योंकि व्यापार के हेतु उधार ली गई पूँजी पर ब्याज दिया गया है ।

(ब) कर्मचारियों को स्वेच्छा से दी गई भेंट ताकि वे व्यापार में रहे और उनकी कार्यकुशलता बढ़े स्वीकार योग्य कटौती है, क्योंकि यह सम्पूर्णतः तथा मूलतः व्यापार के लिए है ।

(स) यह स्वीकार योग्य कटौती है क्योंकि इससे चुकाने वाला आगे के वेतन चुकाने के दायित्व से बच जाएगा ।

(द) यह केवल बैंकर या ऋण देने वाले की दशा में स्वीकार योग्य कटौती है लेकिन अन्य किसी व्यापार में नहीं । जहाँ ऋण व्यापारिक एक्सपिडियेंसी (commercial expediency) के लिये दिये जाँएँ यह व्यापार के सम्बन्ध में नहीं है ।

(ई) विज्ञापन व्यय स्वीकार किये जाते हैं यदि वे माल को साधारण रूप से बेचने तथा वर्तमान व्यापार को बढ़ाने के लिए हो । लेकिन नये व्यापार को शुरू करने तथा व्यापार को नई दिशा में बढ़ाने में हुआ विज्ञापन व्यय पूँजीगत व्यय है ।

(११) “अन्य स्रोतों से आय” मद में कर लगने वाली आय के कुछ उदाहरण दीजिए ।

“अन्य स्रोतों से आय” मद में कर लगने वाली आय के निम्न उदाहरण हैं ।—

१ एक कर्मचारी द्वारा अपने मालिक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से कमाई हुई कोई फीस या कमीशन ।

२ प्रतिभूतियों पर ब्याज के अतिरिक्त तमाम ब्याज ।

३. भवन तथा कृषि आय वाली भूमि से लगी (attached) भूमि के अतिरिक्त जमीन से आय ।

४ कम्पनियों से लाभांश ।

५ प्राप्त होने वाला कोई जमीन का किराया (Ground-Rent) ।

६. मकान ज़ायदाद को सब-लैट (sub-letting) करने से आय ।

७ राँयल्ली, संचालक-शुल्क, कमीशन आदि से आय ।

- ८ बाजारो, हाटो तथा फिशरियो (Fisheries) से मिली आय ।
- ९ विदेशी सरकार से प्राप्त वेतन अथवा पेंशन ।
- १० भारत से बाहर स्थित जमीन से कृषि आय ।

(१२) विकास सम्बन्धी छूट क्या है ? वे क्या शर्तें हैं जिनके आधीन विकास सम्बन्धी छूट दी जाती है ?

एक कर-दाता को ३१ मार्च १९५४ के बाद प्राप्त किये हुए जहाज अथवा नई मशीन तथा प्लान्ट प्रतिस्थापित करने के लिए, जो कि पूर्णरूप से व्यापार के काम में लाई गई है, (लेकिन व्यवसाय या पेशा में नहीं) निम्न दरों से विकास सम्बन्धी छूट पाने का अधिकार है —

(अ) जहाज जो ३१ दिसम्बर १९५७ के बाद प्राप्त किये — लागत का ४०% ।

(ब) जहाज जो १ जनवरी १९५८ से पहले प्राप्त किये तथा मशीन एवं प्लान्ट की दशा में — लागत का २५% ।

विकास सम्बन्धी छूट केवल नई मशीन तथा प्लान्ट के लिए ही जो कि पूर्णतः व्यापार के लिए प्रयोग में आती है, मिलती है। अतः नई मोटर कार, मोटर साइकिल, साइकिल, टाइपराइटर, हिसाब लगाने की मशीनें आदि के लिए विकास सम्बन्धी छूट नहीं माँगी जा सकती क्योंकि ऐसी सम्पत्तियाँ अन्य कार्यों में भी प्रयोग हो सकती हैं।

विकास सम्बन्धी छूट ह्रास छूट का भाग नहीं है। कुल लागत का ह्रास के रूप में पूरी हो जाने के अतिरिक्त भी विकास सम्बन्धी छूट दी जाती है।

विकास सम्बन्धी छूट निम्न शर्तें पूरी होने पर ही मिलती है —

(१) कर दाता द्वारा जहाज या प्लान्ट तथा मशीन के सम्बन्ध में ह्रास सम्बन्धी छूट के लिए आवश्यक विवरण प्रस्तुत कर दिया जाए।

(२) गत वर्षों के खातों में प्राप्त होने वाली छूट का ७५% लाभ-हानि खाते से रिजर्व खाते में हस्तांतरित कर दिया जाये।

(३) जिस वर्ष में यह प्राप्त की गई है उससे आगे दस वर्षों में यह किसी व्यक्ति, सरकार को छोड़ कर, को हस्तांतरित नहीं की जाए।

(१३) आय-कर अधिनियम के घाटे की पूर्ति तथा आगे ले जाने के क्या नियम हैं ?

घाटे की पूर्ति :—एक कर-दाता की कुल आय निकालने के लिए आय के एक शीर्षक के अन्तर्गत होने वाली हानि उस कर-निर्धारण वर्ष में अन्य किसी मद की आय से

पूरी (set off) की जा सकती है। पूँजीगत हानि की पूर्ति केवल पूँजीगत लाभो से तथा सट्टे की हानि की पूर्ति केवल सट्टे के लाभो से की जा सकती है।

व्यापारिक हानियो को आगे ले जाना — यदि व्यापार मे किसी वष हानि हो और वह उस वष की किसी अन्य आय से पूरी न हो सके, तो हानि की यह रकम आगे ले जाई जा सकती है और व्यापार के लाभो मे भावी ८ वर्षों तक यह पूरी की जा सकती है। आगे लाई हुई व्यापारिक हानियाँ न केवल इसी व्यापार के लाभो से अपितु कर-दाता के अन्य व्यापारो के लाभ से भी पूरी की जा सकती है बशर्ते कि हानि उठाने वाला व्यापार अब भी चालू है।

जहाँ सट्टे की हानि उसी वष के सट्टे के लाभो से पूर्णतः काटी न जा सके तो उस दशा मे उसे अगले ८ वर्षों तक आगे ले जा कर उसे भावी सट्टे के लाभ से पूरा कर सकते हैं।

यदि किसी वर्ष की पूँजी हानियाँ उसी वर्ष के पूँजी लाभो से पूर्णतः पूरी न की जा सके, तो उन्हें भावी पूँजी लाभो से अगले ८ वर्षों तक आगे ले जा कर भावी पूँजी लाभो मे पूरा कर सकते हैं। ऐसे अप्रॉनयन की अनुमति के लिए यह आवश्यक है कि गैर कम्पनी कर दाताओ की दशा मे किसी गत वर्ष के दौरान मे उठाई गई पूँजी हानि ५,००० रु० से अधिक हो।

(१४) निवासी तथा पक्के निवासी व्यक्ति की दशा मे निम्न आय को किस प्रकार विचार मे लाया जायगा ?

- (अ) हिन्दू अविभाजित परिवार की आय का भाग।
- (ब) एक अनरजिस्टर्ड फर्म के लाभ का भाग।
- (स) भूमि (Land) से आय।
- (द) व्यापार मे प्रयोग की गई मशीन की बिक्री पर लाभ।
- (ई) प्राप्त हुई भेंटें (Gifts)।

(अ) हिन्दू अविभाजित परिवार की आय का मिला हुआ भाग पूर्णतः कर-मुक्त है। न इस पर कर लगता है और न ही यह कुल आय मे सम्मिलित किया जाता है।

(ब) जहाँ कि अनरजिस्टर्ड फर्म पर कर लगता है वहाँ पर साझेदार द्वारा प्राप्त किये गये लाभ के भाग पर फिर कर नहीं लगेगा। आय-कर के हेतु यह उसकी कुल आय में सम्मिलित किया जाता है ताकि उसकी अन्य आय पर कर लगने के लिए दर निकाली जा सके। सुपर-टैक्स के हेतु यह कुल आय से छोड़ दिया जाता है।

(स) जहाँ कि भूमि कृषि उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जाय तथा ऐसी भूमि पर या तो सरकार द्वारा मालगुजारी या किसी स्थानीय सत्ता द्वारा स्थानीय दरें लगे तो ऐसी

भूमि से प्राप्त आय कृषि आय है तथा यह प्राप्त करने वाले की कुल आय से बिलकल छोड़ दी जाती है ।

जहाँ भूमि कृषि उद्देश्य के लिए प्रयोग न की जाए या ऐसी भूमि पर सरकार की मालगुजारी या म्युनिसिपैलिटी की स्थानीय दरें न लगे तो ऐसी भूमि से आय कृषि आय नहीं है तथा यह प्राप्त करने वाले के हाथों में कर-देय है ।

हाँ, यदि भूमि भारत से बाहर स्थित है तो इसकी आय हमेशा कर-देय है ।

(द) मशीन पर भूत में मिले हुए ह्रास की सीमा तक हुए व्यापार में प्रयुक्त मशीन की बिक्री का लाभ व्यापार के लाभ की तरह ही कर-योग्य है, लेकिन लाभ की राशि जो कि ऐसे ह्रास से अधिक है पूँजी लाभ है जो कि विभिन्न दर से कर-योग्य भी है ।

(ई) अपने निर्जा कारणों से मिली भेंटें (जैसे जन्मदिन तथा विवाह की भेंट) आकस्मिक आय है तथा कर से पूर्णतः मुक्त है । लेकिन एक कर्मचारी को मिली भेंट, जो कि कार्यालय में की गई सेवाओं का परिश्रमिक है, कर-योग्य हैं ।

(१५) सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर कर-निर्धारण (Best Judgment Assessment) क्या है ? क्या यह दुबारा खोला जा सकता है ?

जबकि कर-दाता आय का रिटर्न दाखिल न करके या आवश्यक सबूत प्रस्तुत न करके या माँगे गए हिसाब-किताबों को पेश न करके आय-कर अधिकारी के साथ असहयोग करता है तो ऐसी स्थिति में आय-कर अधिकारी को अपने उत्तम निर्णय के अनुसार एक-तरफा (ex-parte) कर-निर्धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा ।

हाँ, एक सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर कर-निर्धारण दुबारा खोला जा सकता है । यह भी सम्भव हो सकता है कि कर-दाता की गलती जानबूझ कर नहीं हो और ऐसा कुछ उन कारणों से, जो कि उसके नियन्त्रण से बाहर है, हुआ है । ऐसी स्थिति में कर-दाता कर-निर्धारण आदेश की प्राप्ति के एक माह के अन्दर ही आय-कर अधिकारी को इसकी समाप्ति का, कुछ विशेष कारण देते हुए जिनसे कर-दाता नोटिसों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ रहा है, प्रार्थना पत्र देगा ।

यदि आय कर अधिकारी इस बात से सतुष्ट हो जाए कि कर-दाता के पास नोटिस पूरे न करने के पर्याप्त कारण हैं तो वह पहले कर-निर्धारण को समाप्त करके नए कर-निर्धारण का कार्य करेगा । यदि आय-कर अधिकारी सतुष्ट नहीं होता तो प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा । इस अस्वीकृति के लिए कर-दाता के पास अपील का अधिकार है ।

(१६) स्वीकृत प्रॉविडेंट फण्ड तथा अस्वीकृत प्रॉविडेंट फण्ड में अन्तर बतलाइए तथा हर एक के लिए आय-कर अधिनियम के संक्षेप में नियम बतलाइए ।

एक फर्म द्वारा विवाहित व्यक्ति ४०० रु० मासिक वेतन पर रखा गया । उसने मालिक द्वारा रखे गए प्रॉविडेंट फण्ड में ८% चन्दा दिया तथा उसके मालिक का चन्दा १२% है । ३१ मार्च १९५९ को समाप्त हुए गत वर्ष में उसके प्रॉविडेंट फण्ड में ५% वार्षिक ब्याज से ४५० रु० क्रेडिट हुए ।

उसने अपनी जीवन पॉलिसी पर १,५०० रु० प्रीमियम दिया ।

आय कर से मुक्त आय निकालिए (अ) जब कि स्वीकृत प्रॉविडेंट फण्ड है तथा (ब) जब कि अस्वीकृत प्रॉविडेंट फण्ड है ।

स्वीकृत प्रॉविडेंट फण्ड वह है जो कि आय-कर अधिनियम में दी गई शर्तों को पूरा करता है तथा जो कि आय-कर कर्मिन्तर द्वारा स्वीकार कर लिया गया है । अस्वीकृत प्रॉविडेंट फण्ड वह फण्ड है जो इस प्रकार स्वीकार न किया जाए । इन प्रॉविडेंट फण्डों से सम्बन्धित नियम निम्न हैं :—

स्वीकृत प्रॉविडेंट फण्ड —मालिक द्वारा कर्मचारी के वेतन के १०% से अधिक का चन्दा वेतन के भाग के रूप में कर्मचारी की कुल आय में सम्मिलित होगा ।

कर्मचारी के प्रॉविडेंट फण्ड पर क्रेडिट हुए ब्याज का वह भाग, जो कि उसके वेतन के एक-तिहाई से अधिक तथा ६% वापक से अधिक हो, वेतन के भाग के रूप में कर्मचारी की कुल आय में सम्मिलित होगा ।

कर्मचारी द्वारा प्रॉविडेंट फण्ड में चन्दा उसके वार्षिक वेतन के पाँचवे भाग या ८,००० रु०, जो भी दोनों में से कम हो, तक आय-कर से (सुपर-टैक्स से नहीं) मुक्त है ।

रिटायर होने पर कर्मचारी को प्राप्त हुई प्रॉविडेंट फण्ड की राशि भी आय-कर तथा सुपर-टैक्स दोनों से मुक्त है तथा यह उसकी कुल आय में भी सम्मिलित नहीं की जाएगी, बशर्ते कि कर्मचारी ने मालिक के लिए लगातार पाँच वर्षों तक सेवा की है ।

कर्मचारी को अपने जीवन बीमा प्रीमियम के लिए भी आय-कर की छूट मिलेगी, बशर्ते कि उसका प्रॉविडेंट फण्ड में अपना स्वयं का चन्दा तथा जीवन बीमा प्रीमियम दोनों मिलाकर उसकी कुल आय के चौथाई भाग या ८,००० रु०, जो भी दोनों में से न बड़े, से अधिक न हो ।

अस्वीकृत प्रॉविडेंट फण्ड :—आय-कर कर्मिन्तर द्वारा न स्वीकार किए गए प्रॉविडेंट फण्ड में कर्मचारी का चन्दा आय-कर से मुक्त नहीं है, तथा अस्वीकृत प्रॉविडेंट फण्ड के जुड़े हुए शेष (accumulated balance) के भुगतान के समय मिली राशि

पर (इसमें से कमचारी का स्वयं का चन्दा तथा उस पर ब्याज घटाकर) प्राप्ति के वर्ष में वेतन के भाग के रूप में भी कर लगेगा । कमचारी द्वारा चुकाए गए जीवन बीमा प्रीमियम के लिए कुल आय के चौथाई भाग या ८,००० रु०, जो भी दोनों में से कम हो, पूरा छूट मिलेगी ।

(अ) वेतन ४०० रु० प्रति माह	४०
मालिक का अशदान २% से	४,८००
	६६
	<hr/>
कुल आय	४,८६६
	<hr/>
कर-मुक्त आय	
प्रॉविडेंट फण्ड में स्वयं का अशदान जीवन बीमा प्रीमियम (प्रॉविडेंट फण्ड अशदान तथा प्रीमियम दोनों मिला कर ४,८६६ रु० के चौथे भाग तक सीमित)	३८४
	८४०
	<hr/>
	१,२२४
	<hr/>
(ब) वेतन-कुल आय	४,८००
कर मुक्त आय	
जीवन बीमा प्रीमियम-कुल आय के चौथे भाग तक सीमित	१,२००
	<hr/>

(१७) ३१ मार्च १९५६ को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए एक व्यक्ति की आय के निम्न विवरण हैं :—

(अ) वेतन ३०० रु० प्रति माह ।

मकान किराया भत्ता ५० रु० प्रति माह ।

अस्वीकृत प्रॉविडेंट फंड में स्वयं का अशदान २४ रु० प्रति माह ।

मालिक द्वारा प्रॉविडेंट फंड में अशदान ३०० रु० ।

प्रॉविडेंट फंड पर ५% प्रति वर्ष की दर से ब्याज २५० रु० ।

(ब) विनियोगों से आय

१ अक्टूबर १९५८ को बैंक में स्थायी जमा खाते में रखे गये १०,००० रु० पर ४% प्रति वर्ष से ब्याज ।

४०,००० रु० की सरकारी प्रतिभूतियों पर ३% ब्याज ।

एक कम्पनी के प्रीफेरेन्स शेयरों से लाभांश ५०० रु० ।

(स) अपने पितामह (Grandfather) से प्राप्त भेंट ५,००० रु० ।

(द) उसके पास एक मकान है जिसके आधे में उसका पुत्र रहता है तथा दूसरा आधा ५० रु० प्रति माह किराए पर चढ़ा है।

उसने अपनी बीमा पॉलिसी पर २५० रु० चुकाये।

१९५६-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिये उसकी कुल आय निकालिये तथा वह राशि बतलाइए जिस पर उसे आय-कर की छूट मिलेगी।

		रु०	
१. वेतन—मकान भत्ता सहित		४,२००	
२. जायदाद से आय			
वार्षिक किराया मूल्य (किराये के बराबर)	१,२००		
घटाया—मरम्मत के लिए छूटा भाग	२००	१,०००	
३ प्रतिभूतियों से ब्याज (उद्गम स्थान पर कर-कटौती ३६० रु०)		१,२००	
४ अन्य स्रोत			
ग्राँस लाभांश (इन पर लगा आय-कर २२६ रु०)		७२६	
बैंक की स्थायी जमा पर ब्याज		२००	
		कुल आय ७,३२६	

उसे जीवन बीमा प्रीमियम २५० रु० पर आय-कर की छूट मिलेगी।

(१८) अ को जो कि बम्बई की एक कम्पनी में १० वर्ष से अधिक से नौकर है, अप्रैल १९५८ से १,००० रु० मासिक वेतन मिलता है। १० दिसम्बर १९५८ को उसने वेतन में से ३,००० रु० की पेशगी (Advance) ली जो कि उसके दिसम्बर १९५८ तथा आगे के वेतन में से १०० रु० की किश्तों में कटनी थी।

१ जनवरी १९५९ से वह कम्पनी की ईरान में शाखा का मैनेजर १,५०० रु० मासिक वेतन पर रूँहो गया, जिसका अर्धमाह वह ईरान में लेता था तथा आधे में से पेशगी की किश्त काट कर उसके बम्बई के बैंक खाते में जमा होता था।

यह मानते हुए कि हर माह का वेतन अगले माह की पहली तारीख को चुकाया गया १९५६-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए उसकी कर-योग्य आय निकालिए।

धारा ७ (१) के अन्तर्गत वेतन की आय पर वाजिब हुए (accrual) आधार पर कर लगता है। जिस वर्ष में वह चुकाई जाए उस वर्ष की आय मान कर उस पर कर लगाने का कोई प्रश्न नहीं आता। अतएव १९५६-६० के लिए अ पर एक पक्के निवासी की स्थिति में निम्न आय पर कर लगेगा :—

बम्बई में की गई ६ माह की सेवाओं का वेतन (चाहे जहाँ प्राप्त हुई है)
वेतन के लिए ली गई पेशगी

रु०
६,०००
३,०००

घटाया—दिसम्बर के वेतन से पेशगी का पुनर्भुगतान

१२,०००
५००

११,५००

वेतन जो ईरान में कमाया लेकिन भारत में

प्राप्त किया (१-२-१९५६ को २५० रु० तथा १-३-१९५६ को २५० रु०)

५००

विदेशी आय . ईरान में ३ माह का १,५०० रु० मासिक से

वेतन

४,५००

घटाया—बम्बई में प्राप्त राशि

५००

घटाया—वैधानिक छूट

४,०००

४,५००

कुल आय

१२,०००

नोट विदेशी वेतन से आय, जो कि भारत भेजी जाए, की दशा में ४,५०० रु० की वैधानिक छूट १९६०-६१ कर-निर्धारण वर्ष से समाप्त कर दी गई है। हाँ, यदि अनरैमिटेड विदेशी आय वेतन के अतिरिक्त अन्य किसी साधन से हो तो ४,५०० रु० की वैधानिक छूट १९५६-६० कर-निर्धारण वर्ष से समाप्त कर दी गई है।

(१६) क ने जो कि एक लिमिटेड कम्पनी का कर्मचारी है ३१ मार्च १९५६ को समाप्त हुए वर्ष के लिए अपनी आय के निम्न विवरण दिए हैं —

(अ) वेतन १-४ १९५८ से ३०-६-१९५८ तक १,००० रु० प्रति माह।

(ब) मनोरजन भत्ता १-४-१९५८ से ३०-६-१९५८ तक २५० रु० प्रति माह।
१ अप्रैल १९५५ से पहले उसे १५० रु० प्रति माह मनोरजन भत्ता मिलता था।

(स) बीमा कम्पनी को उसके जीवन पर तथा उसके हेतु कम्पनी द्वारा सीधे चुकाया गया प्रीमियम २४० रु०।

(द) क द्वारा अपने जीवन बीमा पर स्वयं द्वारा चुकाया गया जीवन बीमा प्रीमियम २,००० रु०।

(इ) कम्पनी से अपनी स्वेच्छा से छोड़ी गई नौकरी के लिए अगले दो वर्षों तक अन्य कार्य न करने के हेतु क द्वारा प्राप्त राशि २४,००० रु०।

(फ) बैंक के बचत खाते पर ब्याज ३४० रु०।

- (ग) नेशनल सर्विसेस सर्टीफिकेट से ब्याज ५०० रु० ।
 (घ) अपने शहर में उसका एक मकान है जिसमें उसके भाई मुफ्त में रहते हैं ।
 इस मकान का वार्षिक मूल्य म्यूनिसिपल रजिस्टर के अनुसार १,८०० रु० है तथा वर्ष के लिए म्यूनिसिपल कर ४०० रु० है ।
 (ङ) १ अप्रैल १९५८ से ३० सितम्बर १९५८ तक मालिक ने उसे अपने निजी प्रयोग के लिए एक कार दी थी जिसका ७५ रु० मासिक का व्यय मालिक के ऊपर था तथा शेष के लिए 'क' उत्तरदायी था ।

१९५९-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए क की कुल आय निकालिए तथा न मदी तथा राशियों को बतलाइए जिन पर उसे कर की छूट स्वीकार की जायेगी ।

१	वेतन	रु०	रु०
	६ माह के लिए १,००० रु० मासिक	६,०००	
	६ माह के लिए मनोरजन भत्ता	१,५००	
	क के जीवन तथा लाभ के लिए कराये गए जीवन बीमा पर मालिक द्वारा चुकाया प्रीमियम	२४०	
	स्वेच्छा से छोड़ने पर मालिक द्वारा प्राप्त राशि	२४,०००	
	मालिक द्वारा वहन किए कार के व्यय-का क के निजी प्रयोग के लिए दी गई थी—	४५०	
		<hr/>	
		३२,१९०	
	घटाया—मनोरजन भत्ता—क के वेतन (भत्ते लाभ तथा अन्य सुविधाओं को छोड़कर) का पाँचवा भाग अर्थात् ६००० रु० का $\frac{1}{5}$	१,२००	३०,९९०
		<hr/>	
२	जायदाद से आय—		
	वार्षिक किराया (letting) मूल्य	१,८००	
	घटाया—म्यूनिसिपल करों का आधा	२००	
		<hr/>	
		१,६००	
	घटाया—मरम्मत के लिए छूटा भाग	२६६	१,३३४
३.	अन्य स्रोत .		
	बैंक खाते पर ब्याज		३४०
		<hr/>	
	कुल आय		३२,६६४

क को औसत दर से जीवन बीमा प्रीमियम २२४० रु० पर आय-कर की छूट मिलेगी ।

क के मकान का कान्पनिक मूत्य (notional value) कर-योग्य है। इससे कोई अन्नर नहीं पडता कि वह भाई द्वारा मुफ्त मे रखा गया है।

(२०) अ.एक चारटर्ड एकाउन्टेन्ट है जो अपना हिसाब गेकडी पद्धति पर रखता है। उसका गन वष ३१ मार्च को समाप्त होता है। १९५६-६० कर-निर्धारण वष के लिए आय के नकसे मे उसने ७५,००० रु० की शुद्ध पेशे की प्राप्तियाँ दिखलाई। उसकी ग्राँस प्राप्तियाँ ८५,००० रु० थी तथा उसने १०,००० रु० की व्ययो की कटौतियाँ माँगी।

जनवरी १९५८ मे उसके पुत्र के विवाहोत्सव मे उसे २०,००० रु० की लागत की बहुमूत्य भेटे (Gifts) प्राप्त हुई। उसने आय के नकसे मे इसकी कामत नहीं दिखलाई।

उसने गत वर्ष मे ऐसी कम्पनी मे जिसके लाभो पर अशोधित ह्दाम के कारण कर नहीं लगता १,००० रु० लाभान के प्राप्त किए।

उसने १ अक्टूबर १९५८ को ४०,००० रु० की ३% सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदी जिस पर प्रति वष १ जनवरी तथा १ जूलाई को व्याज मिलता है। उसने १ जनवरी १९५६ को १८० रु० आय-कर की कटौती के बाद ४२० रु० शुद्ध व्याज के प्राप्त किए। खरीद के समय उसने ६० रु० की उन पर आय कर की कटौती के बाद विक्रेता को २१० रु० वाजिव हुए व्याज के लिए दिए थे।

१९५६-६० वष के लिए आप अ का कर-निर्धारण कैसे करेगे ?

	रु०
१ प्रतिभूतियों पर व्याज (ग्राँस)	६००
२ पेशे की आय	७५,०००
३ लाभान	१,०००
	<hr/>
कुल आय	७६,६००

कुल आय पर १८० रु० की उद्गम स्थान पर कर-कटौती की क्रेडिट देते हुए कर-निर्धारण किया जाएगा।

लाभान से प्राप्त राशि को ग्राँस नहीं करना है क्योंकि लाभान देने वाली कम्पनी के उन लाभो पर कर नहीं लगा है।

अ द्वारा अपने पुत्र के विवाहोत्सव पर मिली २०,००० रु० की भेटे कर-देय नहीं है क्योंकि ये तो अपने निजी कारणो से प्राप्त हुई है।

अ द्वारा प्रतिभूतियों को खरीदते समय दिए गए २१० रु० से उसकी प्रतिभूतियों की लागत बढ़ गई है। ब्याज चुकाने की तारीख पर प्रतिभूतियाँ जिसके हाथ में होती हैं कर उसी पर लगता है। इसलिए १ जनवरी १९५६ को अ द्वारा प्राप्त हुआ ग्राँस ब्याज ६०० रु० अ के हाथों में ही कर देय है।

(२१) ३१ मार्च १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में एक व्यक्ति को निम्न साधनों से आय है —

(अ) उसने अपने किराएदार अ, जिसे उसने अपनी कृषि भूमि किराए पर दे रखी है, से १०,००० रु० किराये के प्राप्त किए। अ इस जमीन को गद्दी जोत रहा है बल्कि उसने उस पर दुकाने बना ली हैं। १०,००० रु० में से ६,००० रु० दुकानों का किराया तथा उसके चारों तरफ की जमीन के ४,००० रु० बताए गये।

(ब) उसने वर्ष में ५०० रु० मासिक वेतन पर एक फर्म के मैनेजर पद पर कार्य किया। ३१ मार्च १९५८ को समाप्त हुए वर्ष में लिए गए ३,००० रु० के ऋण की अदायगी २५० रु० की मासिक किस्तों में इस वर्ष की गई। स्वीकृत प्रॉबीडेण्ट फण्ड में उसने २५ रु० प्रति माह चन्दा दिया, मालिक ने भी उतना ही चन्दा दिया। ३१ मार्च १९५६ को उसके खाते में २०० रु० ब्याज के क्रेडिट हुए।

(स) उसने वर्ष में हिन्दु अविभाजित परिवार, जिसमें वह तथा उसका अवयस्क (minor) पुत्र है, से आय के अपने भाग के १०,००० रु० प्राप्त किये।

उसे अपने जीवन के १५,००० रु० के बीमे पर २,००० रु०, अपनी पत्नी के जीवन के १५,००० रु० के बीमे पर २,००० रु० तथा अपने अवयस्क पुत्र के जीवन के ५,००० रु० के बीमे पर ५०० रु० प्रीमियम दिया।

१९५६-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिये उसकी कुल आय तथा आय-कर से मुक्त आय की राशि निकालिए।

	रु०	रु०
१ वेतन		
१९५८-५९ वर्ष के लिए वाजिब धन	६,०००	
घटाया — १९५७-५८ के ऋण के लिए भुगतान	३,०००	३,०००

२ अन्य स्रोतों से आय •

भूमि का किराया जो कि कृषि उद्देश्यों
के लिए प्रयोग नहीं की गई

१०,०००

कुल आय

१३,०००

आय कर से मुक्त आय •

(अ) स्वीकृत प्रॉविडेंट फण्ड में स्वयं का अशदान

३००

(ब) अपने जीवन बीमे पर प्रीमियम बीमित राशि
के १०% तक सीमित

१,५००

(स) अपनी पत्नी के जीवन बीमे पर प्रीमियम-
बीमित राशि के १०% तक सीमित

१,५००

३,३००

नोट—मालिक द्वारा प्रॉविडेंट फण्ड में दिया गया चन्दा, जो कि कर्मचारी के वेतन के १०% से अधिक नहीं है, कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जायगा।

यह मान लिया गया है कि प्रॉविडेंट फण्ड में जमा हुआ ब्याज ६% प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है अतएव ब्याज कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा।

अवयस्क पुत्र के जीवन के बीमे पर चुकाया गया प्रीमियम ५०० रु० पर कोई छूट नहीं मिलेगी। हाँ, कर-दाता तथा उसके पुत्र के हिन्दु अविभाजित परिवार के कर-निर्धारण में इसके लिए छूट मिलेगी।

(२२) ३१ दिसम्बर १९५८ को समाप्त हुए वर्ष में एक कम्पनी का लाभ, जैसा कि लाभ-हानि खाते से दिखलाया गया है, ७,५०,००० रु० था। लाभ-हानि खाते में कुछ निम्न मदें थी —

(अ) स्टोर्स का प्रारम्भिक एवं अन्तिम स्कन्व ४,५०,००० रु० तथा ४,८०,००० रु० क्रमशः था।

(ब) किराया प्राप्त हुआ १०,००० रु०।

(स) कर्मचारियों को बोनस ५०,००० रु०।

(द) सदस्य ऋण के लिए आयोजन २५,००० रु०।

(ई) बिक्री कर ४५,००० रु०।

(फ) ह्रास १,२०,००० रु०।

(ग) मैनेजिंग एजेंटों का कमीशन ६५,००० रु०।

नोचे की सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए १९५६-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए कम्पनी का कर-योग्य लाभ तथा इसकी कुल आय निकालिए —

१ १९५७ में स्टोर्स का प्रारम्भिक एव अन्तिम स्कन्ध १०% से कम अंकित किया गया, इसलिए इसका समायोजन १९५८-५९ के कर-निर्धारण में भी पडा। इस वर्ष का (१९५८) अन्तिम स्कन्ध ठीक मूल्यांकित किया गया है।

२ दुकान के किराए में विक्रय एजेंट को किराए पर दी गई दुकान का किराया ३,००० रु० तथा शेष मिल से दो मील पर बने क्वाटरो के किराये के मजदूरी से प्राप्त हुए।

३ वर्ष के अन्तर्गत सदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन में से ५,००० रु० का हूबा ऋण अपलिखित किया गया। यह उस व्यक्ति पर बाजिब था जिसे फैक्टरी भवन के प्रसविदे के सिलसिले में पेशगी दिए गये थे।

४ स्वीकार किए जाने वाला ह्रास ६५,००० रु० आता है।

विक्रय एजेंटों को किराए पर दी गई दुकान तथा मील से दो मील पर बने क्वार्टरों को कम्पनी की व्यापारिक सम्पत्तियाँ नहीं माना जा सकता। इसलिए किराये से आय व्यापारिक लाभ के भाग की तरह कर योग्य नहीं है, बल्कि यह जायदाद से आय ली जायगी।

		रु०
लाभ—लाभ-हानि खाते से		७,५०,०००
घटाया—प्राप्त किराया जो कि जायदाद की आय है		१०,०००
		<hr/>
		७,४०,०००
जोडो—सदिग्ध ऋणों के लिये आयोजन	२५,०००	
ह्रास	१,२०,०००	१,४५,०००
	<hr/>	<hr/>
		८,८५,०००
घटाया—स्टोर्स के प्रारम्भिक स्कंध के कम मूल्यांकन के कारण समायोजन (४,५०,००० रु० का १/६)		५०,०००
		<hr/>
		८,३५,०००
घटाया—स्वीकृत ह्रास		६५,०००
		<hr/>
	कर-योग्य लाभ	७,४०,०००

१ जायदाद से आय
प्राप्त किराया

१०,०००

घटाया—मरम्मत के लिए छुटा भाग
२ व्यापारिक लाभ

१,६६६

८,३३४

७,४०,०००

कुल आय

७,४८,३३४

५,००० रु० का डूबा ऋण स्वीकार नहीं किया जाएगा क्योंकि यह फैक्टरी भवन के प्रसविदे से एक व्यक्ति को पेशगी दिए गए थे ।

(२३) ३१ दिसम्बर १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में एक लिमिटेड कम्पनी, जोकि बिजली के सामान के निर्माण में लगी है, ने १२,५०,००० रु० का लाभ दिखलाया । १९५९-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए निम्न सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए, कम्पनी की कुल आय की गणना कीजिए —

(अ) १९५८ वर्ष में कम्पनी का एक गोदाम, जिसमें २,५०,००० रु० का स्कध था, आग से नष्ट हो गया । बीमा कम्पनी से प्राप्त हुए ढाई लाख रुपये (नष्ट हुए भवन के लिए १,००,००० रु० तथा नष्ट हुए स्कध के लिए १३ लाख रु०) भवन खाते को क्रेडिट किए गए । ३१ दिसम्बर १९५७ को नष्ट हुए गोदाम का अपलिवित मूल्य १,१५,००० रु० था ।

(ब) कम्पनी द्वारा लन्दन की एक प्रदर्शनी में की गई बिक्री का लाभ ५,००० रु०, जो कि लन्दन बैंक में जमा किया गया, सायोगिक सचय (Contingencies Reserve) में क्रेडिट किया गया ।

(स) ८३,००० रु० ब्याज के लाभ-हानि खाते में डेबिट में रखे गए, जिसका विवरण निम्न है

उधारो पर चुकाया गया ब्याज

६८,७००

घटाया—प्रतिभूतियों पर ब्याज, आय-कर की कटौती के बाद

१३,७००

८५,०००

(द) लाभ-हानि खाते में ह्रास के २,५०,००० रु० चार्ज किए गए लेकिन स्वीकार योग्य ह्रास ३,००,००० रु० की राशि है

(ई) प्रबन्ध सचालक के पुत्र ने, जिसकी अवस्था २२ वर्ष है, जून १९५८ में बी काम परीक्षा पास करके कम्पनी में असिस्टेंट की नौकरी ५०० रु० मासिक वेतन पर करली । लेकिन १ अक्टूबर १९५८ से उसका वेतन १,५०० रु० तक बढ़ा दिया गया ।

(फ) १९५७ में कुछ मैकेनिकल यूनिटों पर व्यय ३५,००० रु० रिवेन्यू को चार्ज किया गया था जिसे आय-कर अधिकारी ने उसे विशेष रूप का बतला कर अस्वीकार कर दिया । इसलिये कम्पनी ने १९५८ के हिसाबों में मशीन मरम्मत खाते को ३५,०००

₹० से क्रेडिट कर के तथा मशीन खाते को इसी राशि से डेबिट करके हस्तांतरण की प्रविष्टि पास की।

लाभ—लाभ-हानि खाते के अनुसार		₹०
घटाया—प्रतिभूतियों पर व्याज—आगे विचारा गया		१२,५०,०००
		१३,७००
		<hr/>
		१२,३६,३००
जोड़ो—बीमा कम्पनी से आग से नष्ट हुए स्कंध की प्राप्ति हुई		
राशि जोकि भवन खाते में क्रेडिट की गई	१,५०,०००	
डेबिट किया गया ह्रास	२,५०,०००	
प्रबन्ध संचालक के पुत्र के वेतन का भाग		
जोकि कम्पनी के व्यापार के लिए न होने के		
कारण अस्वीकार किया गया	३,०००	४,०३,०००
	<hr/>	<hr/>
		१६,३९,३००
घटाया—आग से नष्ट हुए गोदाम का सतुलनीय ह्रास	१५,०००	
स्वीकार किया गया ह्रास	३,००,०००	
मशीन की मरम्मत जो पूँजीगत है	३५,०००	३,५०,०००
	<hr/>	<hr/>
		१२,८९,३००
जोड़ो—भारत से बाहर कमाई हुई आय भारत में नहीं लाई गई		५,०००
		<hr/>
	कर योग्य लाभ	१२,९४,३००
		<hr/>
१ प्रतिभूतियों पर व्याज (प्रॉस)		२०,०००
२ व्यापारिक लाभ		१२,९४,३००
		<hr/>
	कुल आय	१३,१४,३००
		<hr/>

प्रबन्ध संचालक के पुत्र का वेतन तो उसके लिए ५०० ₹० मासिक भी बहुत ज्यादा था। इसे चार माह बाद ही १५०० ₹० मासिक तक बढ़ाना किसी भी तरह व्यापारिक हितों की दृष्टि से बिलकुल भी ठीक नहीं है। इसलिए व्यापार के उद्देश्यों के लिए न होने के कारण यह ३ माह तक १००० ₹० मासिक वेतन अत्याधिक है जो कि स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(२४) कर-दाता एक लिमिटेड कम्पनी। कर-निर्धारण वर्ष १९५९-६०।
हिस्साबी वर्ष कलेन्डर वर्ष १९५८। व्यापार . जर्निंग तथा प्रेसिंग फैक्टरी।

१९५८ के लिए लाभ-हानि खाता

	₹		₹
तेल, ई धन तथा अन्य स्टोर्स	१,००,०००	जिनिंग तथा प्रेसिंग	
वेतन तथा मजदूरिया	८०,०००	चार्जेंस प्राप्त हुए	३,००,०००
ह्रास	४०,०००		
विविध व्यय	४०,०००		
लाभ अ/d	४०,०००		
	<u>३,००,०००</u>		<u>३,००,०००</u>

निम्न सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए, १९५९-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए कम्पनी की कुल आय निकालिए —

(अ) ३१ दिसम्बर १९५७ को स्थायी सम्पत्ति की लागत ८,००,००० ₹ थी तथा जून १९५९ में ये नई वृद्धियाँ की गई हैं भवन (प्रथम श्रेणी की लेकिन कारखाने की नहीं) १,००,००० ₹ तथा मशीन १,००,००० ₹ ।

१९५८-५९ कर-निर्धारण वर्ष के अन्त में फैक्टरी भवन का (प्रथम श्रेणी) तथा मशीन प्रत्येक का अपलिखित मूल्य २,००,००० ₹ था, ह्रास की प्रस्तावित दर ५% क्रमश है ।

१९५८ वर्ष में फैक्टरी ने वर्ष पर्यन्त दुहरी पाली में काम किया ।

(ब) २०,००० ₹ जिनिंग तथा प्रेसिंग खाते से सायोगिक सचय को सीधे ही हस्तांतरण किए गए ।

(स) १०,००० ₹ के डूबत ऋण से जो कि पहले कर-निर्धारण में अस्वीकृत कर दिए गए थे उन से ५,००० ₹ वसूल हुए जो कि सामान्य सचय (General Reserve) को क्रेडिट कर दिए हैं ।

(द) तेल, ई धन तथा अन्य स्टोर्स की राशि १,००,००० ₹ में ५०,००० ₹ की प्रयोग में आई स्टोर्स की, नीचे गणन की गई, लागत सम्मिलित है —

	₹
१-१-१९५८ को लागत पर स्टोर्स का स्टॉक	५०,०००
१९५८ के अन्तर्गत क्रय	६०,०००
	<u>१,१०,०००</u>
घटाया—३१-१२-१९५८ को १०,००० ₹ ह्रास के काट कर	
स्टोर्स का स्टॉक	६०,०००
	<u>५०,०००</u>

(ई) वेतन तथा मजदूरी में (१) ६०० रु० मृतक मैनेजर की विधवा को पेन्शन, तथा (२) वर्तमान मैनेजर को १९५६ के ६ माह के लिए ५०० रु० प्रति माह पेशगी भी सम्मिलित हैं।

(फ) विविध व्यय में (१) कर्मचारियों के बच्चों के लिए सितम्बर १९५८ में बनाए गए नए स्कूल की लागत २०,००० रु० तथा स्कूल के अध्यापकों का वेतन ६००० रु० तथा (२) कर्मचारियों के मनोरंजन बजट के लिए अप्रैल १९५८ को खरीदे गए १,००० रु० के रेडियो सेट की लागत सम्मिलित है।

	रु०	
लाभ—लाभ-हानि खाते के अनुसार	४०,०००	
जोड़ो—जिनिंग तथा प्रसिंग आय जो कि लाभ-हानि खाते में नहीं दिखलाया गया	२०,०००	
स्टोर्न के अन्तिम स्क्व का मूल्यांकन	१०,०००	
मैनेजर को पेशगी वेतन	३,०००	
स्कूल भवन की लागत जो पूँजीगत व्यय है	२०,०००	
रेडियो सेट की लागत जो पूँजीगत व्यय है	१,०००	
काटा गया हानि	६०,०००	६४,०००
		१,३४,०००

घटाया—जून १९५८ में प्रतिस्थापित मशीन पर विकास सम्बन्धी छूट (१,००,००० रु० का २५%)	२५,०००	
हाह जैसा कि नीचे निकाला गया	४५,२२५	७०,२२५
	कुल आय	६३,७७५

ह्रास छूट

	रु०	
फैक्टरी भवन . २,००,००० रु० पर ५%	१०,०००	
नोन-फैक्टरी भवन १,००,००० रु० पर २½%, ६ माह के लिए	१,२५०	
स्कूल-भवन २०,००० रु० पर २½%, ३ माह के लिए	१२५	
मशीन . २०,००० रु० पर ६%	१८,०००	
१,००,००० रु० पर ६%, ६ माह के लिए	४,५००	
दुहरी पाली उपयोग की छूट (२२,५०० रु० पर ५०%)	११,२५०	
रेडियो : १००० रु० पर १५%, ८ माह के लिए	१००	
		४५,२२५

तमाम स्टॉक का मूल्यांकन युनिफोर्म आधार (uniform basis) पर होना चाहिए। जब स्टोर्स का प्रारम्भिक स्कन्ध लागत पर मूल्यांकित किया गया था तब अन्तिम स्कन्ध का मूल्यांकन भी लागत पर होना चाहिए। इसलिए अन्तिम स्कन्ध के मूल्य में १०,००० रु० का ह्रास स्वीकार नहीं किया जा सकता।

रेडियो सेट पर ह्रास की प्रस्तावित दर १५% है।

१९५८ हिसाबी वर्ष का कर-योग्य लाभ निकालते समय पिछले या अगले वर्ष के व्यय बेकार हैं। अतएव, १९५९ के लिए दी गई सैनेजर को ६ माह की वेतन की पेशगी काटने योग्य नहीं है।

(२५) एक रजिस्टर्ड फर्म, जिसमें तीन समान अ, ब और स साझेदार हैं, के पास आगरा में सूती मिल है जिसका ३१ दिसम्बर १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ-हानि खाता ५,३४,००० रु० लाभ दिखाता है।

१९५९-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए, निम्न सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए फर्म की कुल आय निकालिए —

(अ) साझेदारों के व्यक्तिगत खाते निम्न प्रविष्टियाँ दिखाती हैं —

१ फर्म से साझेदारों ने कपड़े खरीदने की लागत के हर साझेदार के खाते में १५,००० रु० डेबिट हुए। पूछने पर यह पता लगा कि यह बिक्री लागत से १०% कम पर की गई है।

२ अ को १०,००० रु० तथा ब को १२,००० रु० पूँजी पर ब्याज के क्रेडिट किए गए जब कि स को ब्याज के ६,००० रु० डेबिट किए गए।

३ स के खाते को १ जुलाई १९५८ को कुछ कृषि भूमि को खरीदने के लिए दिए गए ४% प्रति वर्ष ब्याज के ऋण पर ३,००,००० रु० डेबिट किए गए। उसी रोज फर्म ने वह राशि बैंक से ६% प्रति वर्ष ब्याज पर उधार ली।

(ब) वर्ष के अन्तर्गत फर्म ने रुई में सट्टे का व्यापार किया, जिसमें प्राप्त हुआ लाभ ७,५०,००० रु० तथा बुकाई गई हानि ५,५०,००० रु० हुई। यह २,००,००० रु० का शेष रुई के अन्तिम स्कन्ध से घटा दिया गया है।

(स) लाभ-हानि खाते को डेबिट हुए विविध व्यय में (१) २०० रु० एक स्वीकृत दान के तथा (२) स्ट्राइक को रोकने के लिए मजदूरों के नेताओं को दिए गए १,००० रु० भी सम्मिलित हैं।

लाभ जैसा कि १९५८ के लाभ हानि खाते के अनुसार है	₹०	
जोड़ो—साम्भेदारो को बिक्री १०% लागत से कम पर		५,३४,०००
(४५,००० ₹० का १/९)	५,०००	
साम्भेदारो को चुकाया गया ब्याज	२२,०००	
बैंक को चुकाया गया ब्याज जो व्यापार के लिए न हो कर एक साम्भेदार के लिए ऋण पर है (३,००,००० ₹० पर ६ माह के लिए २%)	३,०००	
स्वीकृत दान	२००	
श्रमिक नेताओं को भुगतान जो कि व्यापार के लिए नहीं माना जाएगा	१,०००	३१,२००
		<hr/>
मिल का कर-योग्य लाभ		५,६५,२००
		<hr/>
१ सूती मिल का कर-योग्य लाभ		५,६५,२००
२. सट्टे का लाभ		२,००,०००
		<hr/>
कुल आय		७,६५,२००
		<hr/>

क्योंकि पुण्यार्थ दान २५० ₹० से कम है अतएव साम्भेदारो को इसपर कर की कोई छूट नहीं मिलेगी । ~

(२६) एक फर्म है जिसके अ, ब और स $\frac{३}{४}$ के अनुपात में तीन साम्भेदार हैं । इसका लाहौर में कपड़े का व्यापार ब साम्भेदार द्वारा तथा बम्बई में रुई का व्यापार तथा सट्टे का व्यापार स साम्भेदार द्वारा देखा जाता है । अ साम्भेदार केवल आर्थिक (Financial) साम्भेदार है ।

३१ मार्च १९५६ को समाप्त हुए गत वर्ष के लिए व्यापार की लाभ-हानियाँ निम्न थीं .—

कपड़ा व्यापार से शुद्ध लाभ . ५०,००० ₹० ।

रुई व्यापार से शुद्ध लाभ ८०,००० ।

सोना चादी के सट्टा व्यापार से हानि ५०,००० ।

ये राशियाँ हिंसाबी वर्ष के अन्त में किताबों में निम्न समायोजनों से पहले हैं .—

अ को चुकाया गया ब्याज ४,००० ₹० ।

ब को वेतन ३,००० ₹० ।

ब को किराया ६०० ।

स को वेतन २,४०० ₹० ।

सामेदार अ का बम्बई मे लेन-देन का व्यापार है । उसकी ३१ दिसम्बर १९५८ को समाप्त हुए वर्ष की शुद्ध आय १,५०,००० रु० थी । उसके पास अपने रहने के लिए एक मकान है जिसका वार्षिक किराया मूल्य ६,००० रु० है, इसके लिए ५०० रु० म्युनिसिपल कर दिये गए हैं ।

सामेदार ब जो कि गत वर्ष पर्यन्त लाहौर मे रहा, के पास बम्बई मे एक मकान है, उसने इस मकान का एक भाग फर्म को ५० रु० प्रति माह की दर से किराए पर दे रखा है । दूसरा भाग उसने अपने निवास के लिए रख रखा है । बम्बई मे उसके बैंक खाते मे ५,००० रु० जमा हुए पाये गये । यह राशि पाकिस्तान मे समामेलित कम्पनी से लाभांश है ।

सामेदार स का अपना स्वयं का सट्टे का व्यापार है । ३१ मार्च १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष मे उसकी उस व्यापार से ९०,००० रु० की आय है ।

फर्म तथा सामेदारो की कुल आय निकालिए ।

फर्म की कुल आय .		रु०
पाकिस्तान मे कपडा व्यापार .		
हिसाब किताब से शुद्ध आय	५०,०००	
घटाया ब को वेतन	३,०००	
	४७,०००	
जोडो ब को वेतन (अस्वीकृत)	३,०००	५०,०००
बम्बई मे रुई व्यापार		
हिसाब किताब से शुद्ध आय	८०,०००	
घटाया अ को ब्याज	४,०००	
ब को किराया	६००	
स को वेतन	२,४००	
	७३,०००	
जोडो अस्वीकृत अ को ब्याज	४,०००	
स को वेतन	२,४००	
	६,४००	७९,४००
कुल आय		१,२९,४००

क्योकि सट्टे की हानि अन्य व्यापारिक आय से समाप्त नही की जा सकती अतः सट्टे की ५०,००० रु० की हानि ऊपर की कुल आय से नही काटी जाएगी । यह सट्टे

के व्यापार की हानि ८ वर्ष तक आगे के सट्टे के व्यापार के लाभो से काटने के लिए आगे ले जाई जाएगी ।

फर्म की कुल आय सामेदारो में निम्न तरह से बाँटी जाएगी

	अ	ब	स
	रु०	रु०	रु०
वेतन	—	३,०००	२,४००
व्याज	४,०००	—	—
शेष ($\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$)	६०,०००	३०,०००	३०,०००
	<u>६४,०००</u>	<u>३३,०००</u>	<u>३२,४००</u>

सामेदार अ की कुल आय

१ बम्बई में स्वयं के व्यापार से आय १,५०,०००
फर्म की आय का भाग ६४,०००

२ जायदाद से आय :
रिहाइसी मकान का वार्षिक किराया मूल्य ६,०००
घटाया—म्युनिसिपल कर २५०

घटाया—वैधानिक छूट

वार्षिक मूल्य ५,७५०
१,८००
घटाया—मरम्मत के लिए छटी भाग ३,९५०
६५८
३,२९२
२,१७,२९२

सामेदार ब की कुल आय

१ फर्म की आय का भाग ३३,०००

२ जायदाद से आय
फर्म को किराए पर दिए गए भाग का वार्षिक मूल्य ६००
घटाया—मरम्मत के लिए छटी भाग १००
५००
५,०००

३ भारत में प्राप्त लाभांश

३८,५००

सामेदार ब की कुल आय .

१. फर्म की आय का भाग ३२,४००
सट्टे का लाभ ६०,५००
९२,९००
१,२२,४००

नोट —क्योंकि साभेदार ब परदेशी है तथा पाकिस्तान में रह रहा है उसका फर्म की आय का भाग फर्म पर कर-निर्धारण किया जाएगा तथा इस से वाजिब कर फर्म से वसूल किया जाएगा ।

(२७) १९५६-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए, जिसकी आय निम्न है, एक विवाहित व्यक्ति द्वारा चुकाये जाने वाले कर की गणना कीजिए :—

व्यापार से कर-योग्य आय ४०,००० रु० ।

जायदाद से कर-योग्य आय ५,००० रु० ।

जीवन बीमा के लिए उसने १०,००० रु० प्रीमियम चुकाया ।

	रु०	रु०
आय-कर—कमाई हुई आय ४०,००० रु० पर	७,०२० ००	
आय-कर—न कमाई हुई आय ५,००० रु० पर	१,२५० ००	
	<hr/>	
सामान्य सरचार्ज—८,२७० रु० पर ५%	८,२७० ००	
विशेष सरचार्ज— १,२५० रु० पर १५%	४१३-५०	
	१८७ ५०	८,८७१
	<hr/>	
सुपर-टैक्स—कमाई हुई आय ४०,००० रु० पर	३,००० ००	
सुपर-टैक्स—न कमाई आय ५,००० रु० पर	१,५०० ००	
	<hr/>	
सामान्य सरचार्ज—४,५०० रु० पर ५%	४,५०० ००	
विशेष सरचार्ज—१,५०० रु० पर १५%	२२५ ००	
	२२५ ००	४,९५०
	<hr/>	
कुल वाजिब कर		१३,८२१
घटाया—जीवन बीमा प्रीमियम पर आय की रिबेट (८,००० रु० पर)		
$\frac{८,००० \times ८,८७१}{४५,०००} =$		१,५७७
चुकाया जाने वाला कर		<hr/> १२,२४४

नोट—जीवन बीमा प्रीमियम जिस पर आय कर की छूट मिलती है वह कुल आय के चौथे भाग या ८,००० रु०, जो भी दोनों में से कम हो, से नहीं बढ़नी चाहिए । इसलिए इस स्थिति में छूट केवल ८,००० रु० तक ही मिलेगी ।

(२८) एक लिमिटेड कम्पनी ने अपना व्यापार १ अप्रैल १९५८ को प्रारम्भ किया तथा अपनी किताबें ३१ मार्च १९५९ को बन्द की। निम्न विवरणों से १९५९-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए ह्रास की छूट की राशि निकालिए —

	रु०	दर
फैक्टरी भवन (प्रथम श्रेणी) नया	५०,०००	५%
नोन-फैक्टरी भवन (प्रथम श्रेणी) नया	२५,०००	२½%
प्लांट तथा मशीन (१ अप्रैल १९५८ को नई प्रतिस्थापित)	१,००,०००	१०%
अतिरिक्त प्लांट तथा मशीन (१ अगस्त १९५८ कोई नई प्रतिस्थापित)	२०,०००	१०%
मोटर कारें (नई)	२२,०००	२०%
टाइपराइटर्स (नई)	५,०००	१५%
फर्नीचर	२,०००	६%
फर्नीचर जो १ सितम्बर १९५८ को बढ़ाया गया	५००	६%

१९५९-५० के लिए ह्रास की छूट

	रु०
फैक्टरी भवन ५०,००० रु० पर ५%	२,५००
नोन-फैक्टरी भवन : २५,००० रु० पर २½%	६२५
प्लांट तथा मशीन १,००,००० रु० पर १०%	१०,०००
प्लांट तथा मशीन . २०,००० रु० पर १०%, ८ माह के लिए	१,६६७
मोटर कारें २२,००० रु० पर २०%	४,४००
टाइपराइटर्स . ५,००० रु० पर १५%	७५०
फर्नीचर . २,००० रु० पर ६%	१२०
फर्नीचर . ५०० रु० पर ६%, ७ माह के लिए	१७

२०,०७९

कम्पनी को प्लांट तथा मशीन पर ३०,००० रु० (१,२०,००० रु० पर २५%) विकास सम्बन्धी छूट मिलेगी। मोटर कारों तथा टाइपराइटर्स पर कोई विकास सम्बन्धी छूट नहीं मिलेगी।

(२९) कर-निर्धारण वर्ष १९५८-५९। व्यापार के लिए हिसाबी वर्ष . दिवाली वर्ष।

क एक विवाहित व्यक्ति है जिस पर १५ जनवरी १९५९ को निम्न आधार पर कर-निर्धारण हुआ .—

	₹०
१ वेतन (उद्गम स्थान पर कर कटा ६५० ₹०)	१२,०००
२ मालिक (एक लिमिटेड कम्पनी) से भत्ता	
अपनी सेवाओं की शर्तों के अनुसार	४,०००
३ व्यापार से आय	२०,०००

कर-दाता ने अपील की, लेकिन आय-कर अधिकारी द्वारा की गई माँग का ३० जनवरी १९५६ को चुका दिया था ।

अपील के आदेश के अनुसार जो कि १५ मई १९५६ को हुआ उसे निम्न छूटे
(अ) भत्ते से आय ४,००० ₹० से कम हो गई, तथा
(ब) व्यापार से आय ५,००० ₹० से कम हो गई ।

कर-दाता को अपील आदेश के अनुसार अब आगे चुकाये जाने वाली या उसे वापिस होने वाली राशि की गणना कीजिए ।

	₹०
३६,००० ₹० की कुल आय पर	
आय-कर	६,०२० ००
सरचार्ज ५%	३०१ ००
सुपर-टैक्स	२,२०० ००
सरचार्ज ५%	११० ००
चुकाया जाने वाला कुल कर	८,६३१ ००
२७,००० ₹० की कुल आय पर	
आय-कर	३,७७० ००
सरचार्ज ५%	१८८ ५०
सुपर-टैक्स	५५० ००
सरचार्ज ५%	२७ ५०
	४,५३६ ००
३० जनवरी १९५६ को चुकाया गया कर	८,६३१ ००
कुल आय पर (अपील के कारण कम हुई) वाजिब कर	४,५३६ ००
वापिसी वाजिब रकम (Amount of Refund due)	४,०९५ ००

(३०) १९५८-५९ कर-निर्धारण वर्ष के लिए एक व्यक्ति पर ६०,००० ₹० की कमाई हुई आय पर कर-निर्धारित हुआ । इसमें १५,००० ₹० की छिपी हुई कमाई

हुई आय भी सम्मिलित है। कर-दाता द्वारा चुकाये जाने वाले कुल कर की तथा लगाये जाने वाली अधिकतम पेनल्टी की राशि की गणना कीजिए।

आय-कर ६०,००० रु० पर सामान्य सरचार्ज ५% से	रु० १२,०२० ०० ₹ १ ००
चुकाये जाने वाला आय-कर	१२,६२१ ००
सुपर-टैक्स ६०,००० रु० पर सामान्य सरचार्ज ५% से	₹ ५०० ०० ₹ ७५ ००
चुकाये जाने वाला सुपर-टैक्स	₹ ६७५ ००
चुकाये जाने वाला कुल कर	२२,५९६ ००
आय-कर ४५,००० रु० पर सामान्य सरचार्ज ५% से सुपर-टैक्स ४५,००० रु० पर सामान्य सरचार्ज ५% से	₹ ८,७७० ०० ₹ १३ ५० ₹ ५,५०० ०० ₹ २२५ ००
चुकाये जाने वाला कुल कर	₹ १३,४०८ ५०

छिपाये जाने वाला कर = २२,५९६ रु० - १३,४०८ ५० रु० = ₹ ९,१८७ ५० रु०।
इसलिए धारा २८ (१) (d) के अन्तर्गत पेनल्टी छिपाये गए कर का $\frac{१}{२}$ गुणा अर्थात् १३,७८१*२५ रु० होगी।

(३१) २५ मार्च १९५६ को एक भारतीय कम्पनी ने ३१ दिसम्बर १९५८ का समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभान्वित घोषित किया।

एक अशुभकारी अ ने अप्रैल १९५६ में इस कम्पनी के १०,००० रु० लाभान्वित प्राप्त किया। १९५६-६० कर-निर्धारण में अ द्वारा प्राप्त किये जाने वाले कर-क्रेडिट की, निम्न दो स्थितियों में, गणना कीजिए।

(अ) यदि कम्पनी की पूर्ण आय पर कर लगता है।

(ब) यदि कम्पनी की ५०% आय पर कर लगता है, ४०% कृषि आय है तथा १०% सरकारी प्रतिभूतियों से कर-मुक्त व्याज है।

एक अश्वधारी द्वारा प्राप्त किया गया लाभांश उस गत वर्ष की आय मानी जायगी जिसमें कि यह घोषित किया गया है न कि जब वह प्राप्त हुआ है। इसलिए, अप्रैल १९५६ को प्राप्त हुआ लाभांश भी ३१ मार्च १९५६ को समाप्त हुए गत वर्ष की आय है क्योंकि लाभांश २५ मार्च १९५६ को घोषित किया गया था।

अ को दोनो स्थितियों में निम्न टैक्स क्रेडिट दी जायगी

	शुद्ध लाभांश रु०	ग्रॉस लाभांश रु०	टैक्स क्रेडिट रु०
(अ)	१०,०००	१४,५६८	४,५६८
(ब)	१०,०००	११,८६६	१,८६६

अ की कुल आय में ग्रॉस लाभांश की राशि सम्मिलित की जायगी।